

ISSN : 3049 - 334X



# भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका

(Indian Social Empowerment Research Journal)



Volume : 03 Issue : 01 - January - April 2026 E - Journal

प्रधान  
संपादक

डॉ. प्रेमकुमार नाईक



<https://samajiksashakteekaran.org.in>

# भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका (Indian Social Empowerment Research Journal)

वर्ष 03, अंक 01  
विषय: सामाजिक विज्ञान

जनवरी - अप्रैल 2026  
ई - पत्रिका

## प्रधान संपादक : (Chief Editor)

डॉ. प्रेमकुमार नाईक

अध्यक्ष : सामाजिक सशक्तिकरण बहुउद्देशीय संस्था वर्धा, महाराष्ट्र

## सहायक संपादक (Executive editor)

डॉ. नरेश कुमार गौतम

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग  
श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

## संपादक मंडल (Editorial Board)

### डॉ. अमित राय

एसोसिएट प्रोफेसर, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता,  
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी  
विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र

### डॉ. आमोद गूजर

असिस्टेंट प्रोफेसर, मातृ सेवा संघ  
सामाजिक कार्य संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र

### डॉ. मिलिंद सवाई

प्राचार्य, डॉ. आंबेडकर कॉलेज  
ऑफ सोशल वर्क वर्धा, महाराष्ट्र

### डॉ. शम्भू जोशी

एसोसिएट प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय,  
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी  
विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र

### डॉ. विनोद जी. गजघाटे

प्राचार्य, डॉ. आम्बेडकर इंस्टीट्यूट  
ऑफ सोशल वर्क नागपुर, महाराष्ट्र

### डॉ. चित्रा माली

असिस्टेंट प्रोफेसर, कोलकाता केंद्र  
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
वर्धा, महाराष्ट्र

## सहकर्मी समीक्षा समिति और सलाहकार बोर्ड/ समिति (Peer Review Committee And Advisory Board)

### प्रो. बंशीधर पाण्डेय

समाज कार्य विभाग,  
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

### प्रो. रमेशकुमार एच. मकवाना

समाजशास्त्र विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय,  
वल्लभ विद्यानगर, गुजरात (भारत)

### डॉ. सुप्रिया पाठक

एसोसिएट प्रोफेसर, स्त्री अध्ययन विभाग, प्रयागराज केंद्र  
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

### डॉ. सरोज कुमार ढल

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग  
लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

### डॉ. माधुरी हरिभाऊ झाडे

असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. आंबेडकर कॉलेज ऑफ  
सोशल वर्क वर्धा, महाराष्ट्र

### डॉ. हिना एच. खान

असिस्टेंट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, PGTD  
मनोविज्ञान, (राष्ट्रसन्त तुकडोजी महाराज नागपुर  
विश्वविद्यालय) महाराष्ट्र

### प्रो. विवेक कुमार सिंह

सेंटर फॉर सोशल वर्क, प्रो. राजेंद्र सिंह  
(रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज उत्तर प्रदेश

### प्रो. दीपा मिलिंद बलखंडे

मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष,, श्रीमती बिंजानी महिला  
महाविद्यालय, नागपुर (राष्ट्रसन्त तुकडोजी महाराज  
नागपुर विश्वविद्यालय) महाराष्ट्र

### डॉ. मिथिलेश कुमार तिवारी

सहायक प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, प्रयागराज केंद्र  
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

### डॉ. गजानन निलामें

असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्धा समाज कर्मा संस्थान  
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा

### डॉ. जोंगदंड शिवाजी रघुनाथराव

असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्धा समाज कर्मा संस्थान  
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

### डॉ. शिरीष मा. सुतार

असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री कृष्णदास जाजू ग्रामीण सेवा  
महाविद्यालय पिपरी वर्धा (राष्ट्रसन्त तुकडोजी  
महाराज नागपुर विश्वविद्यालय) महाराष्ट्र

## व्यक्तिगत और संस्थागत सदस्यता

- वार्षिक सदस्यता  
(Annual Subscription) Rs. 600
- द्विवार्षिक सदस्यता  
(Biennial Subscription) Rs. 1200
- त्रिवर्षीय सदस्यता  
(Three Year Subscription) Rs.1800
- पंचवर्षीय सदस्यता  
(five year Subscription) Rs. 3000

## बैंक खाता विवरण

- State Bank of India Wardha  
(Maharashtra)  
**Account Name :**  
samajik sashakteekaran  
sasthan(ngo)  
■ **Account No. 41851337167**  
**IFSC No. SBIN0000500**

## प्रकाशन



सामाजिक सशक्तिकरण बहुउद्देशीय संस्था वर्धा, महाराष्ट्र  
(कपिल वस्ती, सुतगिरणी ले आउट वरूड वर्धा, महाराष्ट्र)

Social Empowerment Multipurpose Organization Wardha, Maharashtra  
(Kapil Vasti, Sutgirmi Layout Warud Post Sevagram, Wardha,  
Maharashtra Pin-442102)

Home Page : <http://samajiksashakteekaran.org.in>

E-mail : [ise.researchjournal@gmail.com](mailto:ise.researchjournal@gmail.com)

Mobile number : 9130331541, 9021331541

About the Journal:-

<https://samajiksashakteekaran.org.in/abouttheJournal>

Editorial Board :-

<https://samajiksashakteekaran.org.in/editorialboard>

Published issues:-

<https://samajiksashakteekaran.org.in/publishedissues>

Hyperlink:-

<https://samajiksashakteekaran.org.in/hyperlink>

## About the Journal

<b>Title</b>	भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका (Indian Social Empowerment Research Journal)
<b>Frequency</b>	<b>Publish Three Issues Per Year</b>
<b>ISSN</b>	3049-334X
<b>Publisher</b>	सामाजिक सशक्तिकरण बहुउद्देशीय संस्था वर्धा, महाराष्ट्र Social Empowerment Multipurpose Organization Wardha, Maharashtra
<b>Chief Editor</b>	<b>Dr. Premkumar Naik</b>
<b>Copyright</b>	सामाजिक सशक्तिकरण बहुउद्देशीय संस्था वर्धा, महाराष्ट्र Social Empowerment Multipurpose Organization Wardha, Maharashtra
<b>Staeting Year</b>	2024
<b>Subject</b>	Social Science
<b>Language</b>	Multiple Languages - Hindi, English and Marathi
<b>Publication Format</b>	Online E-Journal
<b>Mobile No.</b>	9130331541, 9021331541
<b>Email Id</b>	<a href="mailto:ise.researchjournal@gmail.com">ise.researchjournal@gmail.com</a>
<b>Website</b>	<a href="http://samajiksashakteekaran.org.in">http://samajiksashakteekaran.org.in</a>
<b>Journal</b>	About the Journal:- <a href="https://samajiksashakteekaran.org.in/abouttheJournal">https://samajiksashakteekaran.org.in/abouttheJournal</a> Editorial Board :- <a href="https://samajiksashakteekaran.org.in/editorialboar">https://samajiksashakteekaran.org.in/editorialboar</a> Published issues:- <a href="https://samajiksashakteekaran.org.in/publishedissues">https://samajiksashakteekaran.org.in/publishedissues</a>
<b>Address</b>	Social Empowerment Multipurpose Organization Wardha, Maharashtr Kapil Vasti, Sutgirni Layout Warud Post Sevagram, Wardha, Maharashtra (442102) सामाजिक सशक्तिकरण बहुउद्देशीय संस्था वर्धा, महाराष्ट्र कपिल वस्ती, सुतगिरणी ले आउट वरूड पोस्ट सेवाग्राम, वर्धा, महाराष्ट्र (442102)

# भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका

## (Indian Social Empowerment Research Journal)

### परिचय

‘भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका’ ऑनलाइन, पीयर-रिव्यूड (सहकर्मी-समीक्षित) एवं रेफर्ड (संदर्भित) बहुभाषिक शोध पत्रिका है, जिसका प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में किया जाता है। यह सामाजिक सशक्तिकरण बहुउद्देशीय संस्था, वर्धा, महाराष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 से नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है।

पत्रिका का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट, नवाचारपरक और समाजोपयोगी शोध को प्रोत्साहित करना है। यह मंच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न आयामों पर केंद्रित शोध कार्य, आलेखों एवं समीक्षाओं के माध्यम से ज्ञान के प्रचार-प्रसार, विचारों के आदान-प्रदान और सामाजिक जागरूकता को प्रोत्साहित करता है।

### हमारी दृष्टि

पत्रिका का मूल उद्देश्य समाज के विविध पक्षों को समझने, विश्लेषित करने और सकारात्मक बदलाव हेतु संवाद की संस्कृति को विकसित करना है। यह प्रयास न्यायसंगत, समावेशी और संवेदनशील समाज की दिशा में एक वैचारिक पहल है, जो ज्ञान के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और जनजागृति को बढ़ावा देती है।

### उद्देश्य

- नवीन शोध कार्य और वैचारिक लेखन को प्रोत्साहन देना।
- शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विषयों पर संवाद स्थापित करना।
- सामाजिक वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, शिक्षकों, नीति-निर्माताओं एवं पाठकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना।
- सिद्धांत और व्यवहार के मध्य सेतु निर्माण कर, समाज में ज्ञान आधारित हस्तक्षेप को संभव बनाना।

पत्रिका में निम्न प्रकार की विषयवस्तु आमंत्रित की जाती है:

- सामाजिक विज्ञान विषयों पर मौलिक शोध-पत्र

- अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक आलेख
- पुस्तक समीक्षाएँ
- नीति एवं कार्यक्रम आधारित समीक्षा लेख
- क्षेत्रीय अध्ययन व केस स्टडी

### प्रकाशन नीति

प्राप्त सभी लेखों की पूर्ण रूप से समीक्षा की जाती है। पत्रिका गुणवत्तापूर्ण, प्रासंगिक और शोध की दृष्टि से समृद्ध सामग्री के प्रकाशन हेतु प्रतिबद्ध है।

‘भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण’ पत्रिका का प्रयास है कि समाज के विभिन्न वर्गों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा आम नागरिकों को एक साथ जोड़ते हुए विचार-विमर्श की एक सकारात्मक, ज्ञान-संपन्न और संवेदनशील संस्कृति को विकसित किया जाए, जिससे समाज को नई सोच, नया दृष्टिकोण और नई दिशा प्राप्त हो सके।

## संपादकीय

भारतीय समाज एक जटिल और बहुरंगी संरचना है, जो सदियों से अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ बना है। इस समाज के निर्माण में स्त्रियों की चुप्पी और उनके छोटे-छोटे प्रतिरोध, जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक दृढ़ता, वृद्धों के अनुभवों का भंडार, दलितों की बराबरी की आकांक्षा और लोकसंस्कृति के माध्यम से अभिव्यक्त जनचेतना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इतिहास की मुख्यधारा ने इन सभी आवाजों की भूमिका को या तो सीमित किया है या पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया है। उपनिवेशकाल में सत्ता के औजारों ने इन स्वयं को दबाया और स्वतंत्रता के बाद भी लोकतांत्रिक संस्थाएं इन समूहों को समाज की मुख्यधारा में बराबरी के साथ शामिल नहीं कर सकीं। इसका परिणाम यह हुआ कि असमानता की खाई और गहरी होती गई, और समाज का नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक संतुलन भी डगमगाने लगा।

आज यह ज़रूरी हो गया है कि समाज के विमर्शों में, चाहे वह नीति-निर्माण हो, समाज कार्य हो, साहित्य हो, शिक्षा हो या मीडिया। इन सभी उपेक्षित आवाजों को केंद्र में लाया जाए। स्त्रियों के संघर्षों को महज करुणा के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन की ताकत के रूप में समझा जाए। जनजातीय जीवन को ‘पिछड़ेपन’ की निगाह से नहीं, बल्कि उनके पारंपरिक ज्ञान, जीवनशैली और पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से देखा जाए। वृद्धजनों को समाज का बोझ नहीं, बल्कि अनुभव और मार्गदर्शन का स्रोत माना जाए। दलित और आदिवासी चेतना को केवल आरक्षण के संदर्भ तक सीमित न रखकर, उनके विचार और जीवन-दृष्टि को सामाजिक संवाद का हिस्सा बनाया जाए। लोकसंस्कृति को केवल प्रदर्शन और उत्सव की वस्तु नहीं, बल्कि जनसंघर्ष और सामाजिक चेतना के माध्यम के रूप में स्थापित किया जाए।

समकालीन समय में जब समाज वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और उपभोक्तावाद की दौड़ से गुजर रहा है, तो यह और भी ज़रूरी हो गया है कि हम करुणा, मानवीयता और सामाजिक न्याय को पुनः केंद्र में रखें। समाज कार्य को केवल सेवा या कल्याण के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में विकसित किया जाए। साहित्य को केवल सौंदर्यबोध तक सीमित न रखते हुए, समाज की वास्तविकताओं का आईना बनाया जाए। शिक्षा को केवल जानकारी का माध्यम न मानकर, मूल्य आधारित समाज निर्माण का उपकरण समझा जाए।

समाज, संघर्ष और संवेदना: ये तीनों केवल विचार नहीं, बल्कि वे ताकतें हैं जो किसी भी समाज को जीवंत, बराबरी पर आधारित और न्यायपूर्ण बनाती हैं। वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग यह है कि हम

इतिहास की उन धाराओं को मुख्यधारा में स्थान दें जिन्हें अब तक हाशिए पर रखा गया है। यह सिर्फ उपेक्षित अनुभवों को दर्ज करने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें दिशा, सम्मान और दायित्व देने की प्रक्रिया है। यही वह आधार है जिस पर एक नया, समावेशी और न्यायपूर्ण भारत खड़ा हो सकता है। जहाँ नीति, विचार, संघर्ष और संवेदना मिलकर एक मानवीय समाज की संरचना करें। मगर यह विडंबना है कि आज राजनीति और कुछ सामाजिक शक्तियां समाज को जोड़ने के बजाय अपने स्वार्थों के लिए उसे बांटने में लगी हैं। इस प्रवृत्ति को बदलना होगा और एक ऐसे समाज की ओर बढ़ना होगा जहाँ हर आवाज़ सुनी जाए, हर अनुभव का सम्मान हो और हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले। भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका

Kareesh...

**डॉ. नरेश कुमार गौतम**  
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग  
श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

# भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका

## (Indian Social Empowerment Research Journal)

ISSN: 3049-334X

वर्ष 03, - अंक 01

जनवरी – अप्रैल 2026

### अनुक्रमणिका

अ.क्र.		पृष्ठ.क्र.
1.	<b>Impact of E-commerce in daily life</b>	1
	Dr. Prachi bang	
2.	<b>Impact of Workplace Conditions on Employee Efficiency and Performance in Government Offices in Nagpur City</b>	8
	Dr. Tulika A. Khare	
3.	<b>Assessment Of Occupational &amp; Domestic Stressors Among Women: A Survey Based Study In Nagpur City</b>	22
	Vaishnavi K. Pradhan, Tulika A. Khare	
4.	<b>Forest Rights Act 2006 and Livelihood Security: A Study of Minor Forest Produce (MFP) Rights Among the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) of Jharkhand.</b>	37
	Dr. Prity Kumari	
5.	<b>भारतीय न्यायशास्त्र में 'दंड' की अवधारणा और सुधारात्मक न्याय: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन</b>	50
	डॉ. सुमीत कुमार गुप्ता	

6. **किशोरों में आध्यात्मिकता की आवश्यकताएं: एक समाजशास्त्रीय अवलोकन** 69  
डॉ. अखिलेश कुमार
  7. **समकालीन भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का संकट: उत्तर भारत में जाति, वर्ग और चुनावी राजनीति का एक अध्ययन** 78  
डॉ. दीपक जॉनसन
  8. **Reproductive Health Challenges of Married Women: A Study of Selected Blocks in North 24 Parganas District, Sundarbans Region** 92  
Moumee Jesmin, Dr. Rupa Biswas
  9. **A Comparative Study of Corporate Criminal Liability and Corporate Offences under the Indian Legal System: A Legal Study** 108  
Jitendra kumar Meena, Dr. Phool Chand Saini
  10. **Strengthening Social Harmony in Assam: Peace Initiatives of the Kasturba Gandhi National Memorial Trust** 118  
Dr. Amreen Razzak
  11. **A Critical Review of Digital Interventions for Suicide Prevention and Youth Mental Health: Is India Ready** 127  
Ambareen Abdullah, Manas Bajpai
  12. **Socioeconomic Impact of the Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana on Women in Maharashtra: An Analytical Assessment** 141  
Akshay Prabhakar Rajurkar
-

13. राज्य प्रशासन और नीति निर्माण में पुलिस की भूमिका एवं चुनौतियां 154  
रंजना बागड़े
14. भंडारा जिल्ह्यातील बेरोजगारीची कारणे परिणाम व उपाय एक चिकित्सक अध्ययन 158  
महेंद्र अशोक गभने
15. बायोगॅस वापराची वर्तमान स्थिती, समस्या व ग्रामीण विकासात याचे उपयोग विशेष संदर्भ: भंडारा जिल्हा 171  
शैलेश साऊसाखरे
16. शिक्षणात ए -आय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता ) च्या वाढत्या वापरामुळे शिक्षकांच्या अध्यापन पद्धती वर पडणारा प्रभावाचे विश्लेषणात्मक अध्ययन 181  
भागवत भांगे
17. अनुसूचित जनजाति में धनगर आरक्षण के मांग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन 192  
किशोर विश्वासराव पाटील
18. विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में शिक्षा तथा कौशल विकास का महत्व 203  
सौरभ चंद्र सानू
19. हिंदी सिनेमा: एलजीबीटी समुदाय का प्रतिनिधित्व और मानवाधिकार 211  
गया सी एस
20. मेलघाट परिक्षेत्र में कुपोषण: एक पुनरावलोकन 217  
नीता उघड़े

21. महिला सशक्तिकरण के माध्यम से सतत ग्रामीण विकास: चुनौतियाँ, 227  
अवसर एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य  
डॉ. छोटे लाल
22. स्त्री देह यौनिकता और सामाजिक नैतिकता : एक समाज शास्त्रीय 236  
अध्ययन  
गोपीका पी.
23. भारत के आदिवासी जीवन: पहचान, संस्कृति और संघर्ष का 242  
बहुआयामी अध्ययन  
श्रीलक्ष्मी के.एस.
24. नारी शक्ति : बदलाव की ओर कदम 249  
रानी कुमारी
25. प्रगतिशील लेखक संघ और युगीन चेतना से सरोकार 256  
ऋषिकेश कुमार
26. **Challenges and Problems of Construction Workers:** 263  
**A Study in Visakhapatnam**  
Dr. N. Komali Salomi, Dr. P. Ravi Ratna Prakasa Rao
27. **Social Issues and the Need for Creating Awareness in** 276  
**Contemporary Society**  
Tonmoy Pran Bez
28. **Socio-Economic Aspect of Integral Humanism: An** 285  
**Indigenous Model of Development (A Conceptual Review)**  
Nitin Katara, Dr. Ashu Mishra
-

# Impact of E-commerce in daily life

**Dr. Prachi bang**

Guest lecturer at Govt. Balasaheb deshbande  
College kunkuri dist.- Jashpur (C.G.)

---

## Abstract

In addition to the conventional business approach, E-commerce is also being utilized increasingly in India. E-commerce refers to electronic commerce, utilizing the internet for goods and services can be swapped quite effortlessly and conveniently. E-commerce leads to significant economic growth but also several challenges encountered by e-commerce, which will be resolved shortly. The consumer protection act 2019 has also included provisions for ecommerce to ensure consumers receive protection against any kind of deception that takes place via online shopping.

**Keyword-** E-commerce, Traditional, Transaction, Liberalization, customize.

## Introduction

Human requirements were straightforward and constrained at the start of civilization and growth. To fulfill their needs and desires, people used to trade products with one another. The term "barter exchange system" describes the direct exchange of commodities or services for other goods or services without the need of any form of trade medium. Commodities or services for other goods or services without the use of a means of exchange, such money, and then progressively expanded the trade of monetary transactions. A monetary transaction is a system wherein goods and services are traded for cash. The Indian economy began to

liberalize in 1991. The government has drastically altered its policies regarding foreign trade, foreign direct investment, currency rates, fiscal restraint, unrestricted access to the free market, permitting the establishment of more private businesses, lowering government control, etc. In order to make the economy's productivity, transparency, consistency, and efficiency more acceptable, the new economic policy has been fostering greater competition.

Vides Sanchar Nigam Limited launched internet service in India on August 15, 1995, following new economic changes. The government allowed the private sector to offer internet services in November 1998. Email is used for online business. Customers on your email list can learn about new product types, discounts, product quality, product descriptions, and other services through email marketing.

Following the implementation of e-mail marketing, the introduction of Teleshopping has transformed the Indian economy. Tele marketing involves the direct promotion of products and services to customers via telephone, mobile, or the Internet users can conveniently buy products with just one phone call thanks to technological advancements. Currently, e-commerce is growing in a manner that it is gaining significant popularity across the entire economy.

Commerce refers to electronic commerce or online commerce.

E-commerce refers to the buying and selling of products and services online, along with the exchange of money and information necessary to finalize transactions. The government also encourages and implements policies for the digital economy. The rapidly expanding e-commerce sector within the nation and enhance the entire economy. Currently, there are different kinds of e-commerce, such as business to business. Online retail, B2C e-commerce, C2A e-commerce.

### **Objectives of the study**

1. Introduction of E- commerce .
2. To study to E-commerce impact in daily life .

3. To study the changing business with new technology in rural area.

### Review of Literature

- (Raja & khan, 2020, pp. 697-709) In this article, it was observed how the situation was prior to the green revaluation. Rural marketing underwent significant changes in the marketing strategies of rural area following liberalization. The government implemented various policies aimed at rural areas involving traditional marketing, e-commerce, investment, agricultural training, technology education, banking services, and green cards. for farmers, job opportunities are provided. In India, 65% of the population resides in rural areas. Rural marketing is a vital component of the entire economy.
- (Khan,2016, pp. 19-22) This article states that the marketing framework in India is split into two parts. Rural and urban market segments. The research indicated that rural marketing enhances the economy. Business is investing in rural marketing, creating tailored products, and enhancing infrastructure in rural areas. Promote and shift the perspective of the consumer. The research discovered that the aim of rural marketing is consumer contentment rather than merely maximizing profits. Through urban marketing, rural market is also significantly influencing the economy. The research additionally discovered that the mass services in rural areas region.
- (Khan,2016, pp. 19-22) In this article, research on the E-commerce sector will take the forefront with Popularity in the economy in the coming year. Explore different obstacles and resolutions inExecuting e-commerce
- (Soni, 2017, pp. 390-392) The research discovered that the E-commerce sector in India benefits from the Extraordinary expansion over the past year. Advancements in E-commerce are generating significant opportunities for international trade across borders. The internet is allowing small businesses

to reach the global market like never before earlier. Even though the trends of E-commerce have been circulating for 15 years.

- (Panigrahi, Upadhyaya & Raichurkar, 2016, pp. 15-22) This article seeks to clarify the concept of E-commerce, advantages and disadvantages of E-commerce. Different trends in E-commerce and difficulties prior to E-commerce and subsequent to E-commerce. Nonetheless, at this current moment, it possesses multiple constraints, legal and technical obstacles in the advancement of E-commerce in India that may turn away in the year to come.
- (Mitra, 2013, pp. 126-132) This article aims to examine the current situation and enablers of E-commerce in India involves analyzing current trends and exploring the obstacles faced in the sector. The research discovered that there has been an increase in the number of companies adopting E-commerce in India in the recent past. The research also discovered that major Indian portal sites have transitioned to Ecommerce, rather than relying on advertising revenue.
- (Shethar, 2016, pp. 25-31) The research discovered that the realm of E-commerce encompasses. The wholesaler faces the highest risk since the producer can readily overlook them and market their items to the merchants and the consumers. Wholesalers can benefit from E-commerce in. Forming agreements with well-known producers and connecting their businesses online.
- (Wadhawan & Arya, 2020, pp. 805-809 )This article highlights the significance of E-commerce. Contrast the conventional approach to commerce with e-commerce. The research indicated that a significant element propelling online retail expansion in India. Several factors that will aid in this growth include mobile commerce, substitute service, various payment methods, logistics and shipping choices, quality of products, customer support services.

## Methodology

In this article based on secondary data all data collected from newspaper, articles, internet, books.

## Finding

The research discovered that e-commerce enables us to acquire high-quality products at lower prices without leaving our homes. The supply chain in e-commerce is shorter than in traditional business, from manufacturer to consumer, which resulted in the consumer incurring significant additional expenses for goods and services, however, because of the limited supply chain in e-commerce, I had to spend a smaller amount. Products and services are accessible at an affordable price.

Government established initiatives and policies such as the National Digital Health Mission introduced by the esteemed Prime Minister Narendra Modi on August 15, 2020. Under this plan, a health ID card will be issued to every Indian and they can take advantage of the treatment offered via digital means at the hospital, Digital India’s Ghar tak fiber initiative in Bihar launched on March 31, 2021, aims to link all rural regions with high-speed connectivity. Velocity and quality of fiber optic internet, among other things, to improve e-commerce and the digital economy in urban regions and likewise countryside region

**Table 1. As On 28<sup>th</sup> February, 2025, Top Five Wireless Broadband Service Providers**

S. No.	Name Of The Service Providers	Subscriber Base (In Million)
01	Reliance Jio Infocomm Ltd.	465.10
02	Bharti Airtel Ltd.	280.76
03	Vodafone Idea Ltd.	125.87
04	Bharat Sanchar Nigam Ltd.	30.87
05	Ibus Virtual Network Service Provider Ltd.	0.09

Source: Telecom Regulatory Authority of India

Table 1 show the report is prepared considering top five wireless broadband service providers in 28<sup>th</sup> February 2025 Reliance jio infocomm Ltd. subscriber base 465.10 million, Bharti airtel Ltd. subscriber base 280.76 million, vodaphone idea Ltd. Subscriber base 125.187million, bharat sanchar nigam Ltd. subscriber base 30.87 million and IBUS virtual network service provider Ltd. Subscriber base 0.09 million.

Currently, numerous services are accessible on digital platforms such as Flipkart, Zomato, and Amazon. paytm, IRCTC, Myntra, Health Kart, Ola cabs, Unacademy, etc., for our convenient usage. Online commerce has numerous advantages along with certain challenges, and the government will implement corrective measures regarding it.

and exclude it from the issue.

### **Suggestion**

Currently, e-commerce is enhancing the economy. It offers numerous advantages along with several challenges, such as safety of goods, quality of goods, learning, online access, joblessness, stereotype perceptions etc., and efforts must be undertaken to address these deficiencies, particularly in rural regions where young individuals reside. Increasingly utilize the internet, social media, online banking, and online education. They ought to offer.

### **Conclusion**

The lives of individuals have become much easier and more efficient thanks to e-commerce. The nation's economy has been advancing significantly because of the development of e-commerce. Individuals are utilizing digital platforms in their everyday lives. method apart from conventional commerce. Over fifty percent of the populace in the nation resides in The village is rapidly transitioning into a digital economy. High standard of goods and services can be evaluated via e-

commerce at the lowest expense and also facilitates simple delivery of products and returns.policy

## Reference

1. *Shettar.M.S.,Ajsa.H.,Jigalur.S.K.&Sheshgiri.M.S.(2016).Emerging Trends of E-commerce in India: An Empirical study. International journal of Business and Management Invention, Vol. 5(9), 25-31.*
2. *Chaturvedi. M. (2017). A study on challenges and opportunities of rural marketing. International journal of current research, vol.9(11), 61682-61686*
3. *Wadhawan. N., & Aryan. K. R. (2020).Understanding E-commerce: A study with reference to competitive Economy, Journal of critical review, Vol. 7(8), 805-809.*
4. *Panigrahi. A., Upadhyaya. R., & Raichurkar. P. (2016). E-commerce Services in India: Prospects and Problem. International Journal on Textile Engineering and Processes, Vol. 2(1), 15-22.*
5. *Khan .G.A. (2016). Electronic commerce: A Study on Benefit and Challenges in an Emerging. Global Journal of Management and Business Research,Vol. 16(1), 19-22.*
6. *Soni.N.A. (2017). E-commerce in India: A Study. International Journal of Research and Analytical Reviews, Vol. 4(3), 390-392.*
7. *Raja. M., & Khan. N. (2020). Changing Trends in Rural Markets and Marketing in India: A Review. International Journal on Management (IJM), 11(3). 697-709.*
8. *Mitra. A. (2013). E-commerce in India: A Review. International journal of marketing, financial services & management research, vol.2(2),126-132*

# Impact of Workplace Conditions on Employee Efficiency and Performance in Government Offices in Nagpur City

**Dr. Tulika A. Khare**

Assistant Professor,

Assistance Professor, PGTD of Home Science, RTMNU, Nagpur 440033

Post Graduate Department Home Science, Resource Management

Rashtrasant Tukadoji Maharaj University, Nagpur

---

## Abstract

Climate change is a global emergency and one of the main environmental concern for the world. Increase in temperature and humidity are the main characteristics of global warming. Many cities in India are affected by increase in heat. The aim of the research was To study the impact of climate change on employee`s performance in Government offices in Nagpur city. A sample size was 100 Government employees and Purposive random samplings were done to select the subject. Data was collected from the sample by using pre-coded interview schedule. For experimental data collection following instruments were used such as:-Thermohyrometer, Lux meter, Noise level meter to measure environmental conditions. The data show that 41-50 years of age group were most impact by climate change. 47% respondents were graduate. 83% of the respondents were having permanent job. 37% respondents work productivity was impacted when they worked in hot climate. 67% respondents were agree that there were advantages of working in cold climate for increasing employee`s performance.

55% respondents felt cold climate suitable for work performance. 58% respondents said that there was reduction in employee mental performance due to climate change. 64% indoor workers having adverse effects due to climate change. The null hypothesis of the study was Climate a condition of government offices does not impact on employee’s performance. The calculated chi square value is more than table value at 1% and 5% level. It can be interpreted that null hypothesis is rejected. Therefore climatic conditions of government offices has impact on employee’s performance. Because in hot climate their mental performance reduces which result in decrease in work performance (productivity).

**Keywords:-** Climate change, Employee performance, Work productivity, Health

### **Introduction**

Climate change has several direct adverse effects on working people such as heat exhaustion and heat stroke, as well as indirect effects including increased risks for infectious diseases, changing distribution and transmission patterns of vector-borne diseases, malnutrition, water and sanitation problems and injuries due to extreme weather events.

There is a interrelation between employee’s performance, health, and climate change. Climate change is any significant variation in temperature, precipitation, wind, or other type of weather that lasts for decades or longer. These changes can affect human health in several direct and indirect ways. Several studies have demonstrated the ill-effects of climate change on working population across many industries. Exposure to extreme heat without sufficient protection in work place increases the risk of heat-related illness and also results in productivity loss.

### **Impact Of Climate Change On Employee’S Performance**

Environmental conditions may directly influence work productivity, in particular for those activities that need physical work. A new research, in relation to climate change, cannot elude including an analysis of how global warming will affect the productivity and work capacity of people who are exposed to thermal stress. Heat

stress is limited, usually, to the hottest parts of the day in the hottest season, but in many outdoor workplaces and uncooled indoor workplaces in tropical and sub-tropical regions this happen for a large part of the year and regards outdoor workers and many indoor workers without air conditioning.

The effects of excessive heat exposure on working people may have substantial social and economic impact on the exposed communities. Preventive policies, oriented to both mitigation and adaptation, will need to be strengthened or initiated. This research project study the impact of climate change on Employee`s performance in government offices in Nagpur City. It also studies the demographic profile of respondent.

### **Purpose of the study**

The purpose of this research project is to study the impact of climate change on Employee`s performance in Government offices in Nagpur City. It analyses demographic profile of employee based on age, race, gender, education, etc. The research project focused on issue faced by employees in government offices. And what policies and method we can implement to reduce the effect of climate change in work place and to improve employee`s work performance.

Occupational heat stress occur due to extreme heat exposure or work in hot environment. Exposure to extreme heat can result in work-related illnesses and injuries. Thus, by studying the impact of climate change on employee`s performance, we can reduce the risk related to Occupational heat stress. Injuries and illnesses due to extreme heat exposure reduce employee`s work performance. However current knowledge is limited in many areas, so an increase in research in this sector could provide a very important means to improve prevention strategies reducing the health risk and increasing work productivity.

### **Aim :**

To study the impact of climate change on employee`s performance in Government offices.

## Objectives

1. To identify the impact of climate change on Employee`s productivity.
2. To study the advantages and disadvantages of climate change on employee`s performance.

## Limitations :

1. The study was limited to Nagpur city only.
2. The study was limited to 100 respondent only.
3. The study was limited to the employee`s in government offices only.

## Hypotheses:

H0: Climate conditions of government offices does not impact on employee`s performance.

## Methodology

A systematic procedure was adopted for the study and therefore the methodology was given under the following heads:

Research Design, Selection, Construction and description of tools, Sampling design, Method of data collection, Statistical analysis of the data

## Research Design

The research design is the specification of method and procedure used to acquire the information needed. Research Design is needed because it facilitates the smooth sailing of the various research operations thereby making research an efficient as possible yielding maximum information with minimum expenditure of efforts, time and money. For this study research design were selected to figure out the relation between climate and its impact on government offices workers performance. A systematic was adopted for the present study. A descriptive-cum-experimental research design was used. A descriptive data was used to get the information regarding demographic profile, employee`s productivity and advantages and disadvantages of climate change. Experimental data was used to

get the information regarding increase/ decrease in temperature, humidity, noise, light intensity which leads to increase or decrease employee’s productivity.

### **Selection of Tools**

1. Interview schedule was used to gather the information by preparing questionnaire.

For experimental data collection following instruments were used such as:-

- Thermohygrometer
- Lux meter
- Noise level meter

### **Sampling Design**

1. The present study was carried out in the different zones of the Nagpur city.
2. Government offices were taken for the collection of data.
3. A total of 100 samples were taken. Purposive random sampling was done to select the subject.

### **Method of Data collection**

- Data was collected from the sample by using pre-coded interview schedule.
- Observation method were used for analysis.

### **Statistical analysis of the data**

Statistics were applied according to the hypothesis.

### **Result and Discussion**

#### **Impact of climate change on Employee productivity**

- Impact of climate change on employee’s productivity (N=100).

Climate has a powerful impact on any employee’s work productivity. In the present study, 37 percent of the respondents work productivity was impacted

when they worked in the hot climate, the data showed that it was impacting 37 percent respondent’s mental health and 26 percent of the respondent’s physical health.

<b>Impact of climate change on Employee’s productivity</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percentage</b>
Because of high temperature	37	37%
Because of mental health	37	37%
Because of Physical health	26	26%

- **Environmental parameters**

The survey was done in the month of February so most of the environmental conditions was in the respondent’s favour. The Average temperature was recorded 30 degree Celsius, Average humidity was 20.6% which was quite normal. Average light intensity measured was 629.7 Lux and Average Noise level was 53.7 Db.

<b>SR.NO</b>	<b>Environmental Parameters</b>	<b>Average</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>
1)	Temperature	30 C	15C	35 C
2)	Humidity	20.6%	15%	27%
3)	Light Intensity	629.7 Lux	217 Lux	1502 Lux
4)	Noise Level (Decibel)	53.7 db	48.9 db	68.7 db

- **Advantages and Disadvantages of climate change on Employee’s performance**

Advantages of climate change

It can be seen through the table that 58 percent of the respondents were said that there was no advantages of climate change for increasing employee’s performance and 42 percent of the respondents were said that there was advantages of climate change.

<b>Advantages of Climate change</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percentage</b>
Yes	42	47%
No	58	53%
Total	100	100%

- **Advantages of Cold climate :-**

It can be seen through the table that 67 percent of the respondents were agree that there were advantages of working in cold climate for increasing employee`s performance and 33 percent of the respondents said that there was no advantages of working in cold climate.

<b>Advantages of Cold climate</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percentage</b>
Yes	67	67%
No	33	33%

- **Disadvantages of Climate change**

It can be seen through the table that 53 percent of the respondents said that there are disadvantages of working in climate change and 47 percent said that there was no disadvantages of working in climate change.

<b>Disadvantages of climate change</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percentages</b>
Yes	53	53%
No	47	47%
Total	100	100%

- **Effect of the climate change**

Climate change has different types of effect on employee`s performance. From the present study it was found that 47 percent of the respondents productivity decreases by climate change whereas 23 percent respondents were having work disruption. The data showed that 18 percent of the respondents were having

increased risk of occupational hazards and 12 percent of the respondents were having any other types of effects on employee`s performance.

Effect of climate change	Frequency	Percentage
● Increase risk of occupational hazards	18	18%
● Decreased productivity	47	47%
● Work disruption	23	23%
● Any other	12	12%
Total	100	100%

- **Suitability of climate for work performance**

It can be seen through the table that 55 percent of the respondents felt cold climate suitable for work performance whereas 23 percent felt hot climate suitable for work performance and 22 percent felt any other climatic conditions suitable for work performance.

Suitability of climate for work performance	Frequency	Percentage
● Hot climate	23	23%
● Cold climate	55	55%
● Any other	22	22%
Total	100	100%

- **Reduction in Employee mental performance**

It can be seen through the table that 58 percent of the respondents said that there was reduction in employee mental performance due to climate change and 42

percent of the respondents said that there was no reduction in employee performance.

Reduction in Employee performance	Frequency	Percentage
● Yes	58	58%
● No	42	42%
Total	100	100%

● **Reduction in Employee performance:-**

It can be seen through the table that 36 percent of the respondents were having reduction in work productivity whereas 24 percent were having increased risk of health care cost, 14 percent of the respondents were having reduction in commitment to work, 14 percent were having increased rate of employee absenteeism and 12 percent were having another type of reduction in employee performance.

**Testing of Hypothesis**

**Null Hypothesis:-** Climatic conditions of government offices does not impact on employee`s performance.

SR.NO.	DESCRIPTION	VALUE/ df	RESULT
1.	Calculated value	36	Calculated value is greater than table value, hence the null hypothesis is rejected.
2.	X <sup>2</sup> Table value	1% = 6.63 5% = 3.84	
3.	Degree of Freedom	d.f = 1	

## Interpretation

From the above calculation it is noticed that the calculated value  $X^2 = 36$  and table value of  $X^2 = 6.63$  at 1% level and 3.84 at 5% level of significance where degree of freedom is 1. The calculated value is greater than table value. Therefore, null hypothesis is rejected. Hence, it can be interpreted that the climatic conditions of the government offices does have impact on employee`s work performance.

## Conclusion

Climate change is a global problem that has severe impact on human mental and physical health. Many cities in India are becoming vulnerable to increase in heat. India is experiencing climate changes in the form of heat stress, drought, flooding. Several studies have demonstrated the ill-effects of climate change on working population across many industries.

It was found that all age group in Government offices were affecting from the impact of climate change. In case of gender, the male population was more exposed to the impact of climate change. Educational qualification plays a major role for creating awareness in people about climate change. The majority of the respondents were completed graduation. Having good family income reduces some effects of climate change. Most of the employee having high monthly income. Type of job also play major role in it. In government offices, the majority of employee`s having permanent job .i.e. office work which means that they were not exposed that much with outdoor climatic conditions expect those employee` who have outside work like LIC Agent, Postman, etc.

Climate change has a powerful impact on employee`s performance. The majority of employee were impacted when they work in hot climate whereas some employee`s mental health affecting due to climate change which result in decrease work productivity. As the present study was conducted in the month of February some environmental parameters was taken into consideration to check the government offices conditions such as Temperature, Humidity, Light intensity,

and Noise level. All the parameters were in respondents favour as it February month.

There are some advantages and disadvantages of climate change on Employee performance. Majority of respondents were agree that there were advantages of working in cold climate whereas many of them also said that there were disadvantages of working in climate change. From the present study, different types of effect on employee performance due to climate change were found. Majority of the respondents agree that due to climate change productivity decreases. Along with that some of them also agree for having work disruption and occupational hazards due to climate change.

From this study, it can be said that government employee`s felt cold climate suitable for increasing work performance. Because employee felt that hot climate reduces their mental w performance. Most of them faced work related issues due to hot climatic condition. From the present survey, it can be said that indoor workers (employee`s) also have adverse effect due to climate change which reduced their work performance (productivity) whereas some employee having increased risk of health care cost and some were having increased rate of absenteeism and reduction in work commitment due to climate change.

It can be concluded from this present study, that government employee`s also get affected by climate change which reduced their work performance. Many of them having outdoor job (LIC Agent, Postman). They were most exposed to outdoor climatic condition. Good policies should be implemented for reducing the impact of climate change in Government offices.

## Bibliography

### Journals and Books

1. Adam-Poupart A, Lawrence F, Smargiassi A, Duguay P, Busque M-A, Gagne C, Rintamaki H, Kjellstrom T, Zayed J. *Special projects studies and research projects. Impacts of climate change on occupational health and safety*. Institute recherche Robert-Sauve en sante et en securite du travail;2013. (Report n. R-775).
2. Ann Ist Super Sanità, (2016) Vol. 52, No. 3: 338-342. DOI: 10.4415/ANN 16.03.05
3. Balakrishnan K, Ramalingam A, Dasu V, Chinnadurai Stephen J, Sivaperumal MR, Kumarasamy D et al. Case studies on heat stress related perceptions in different industrial sectors in southern India. *Global Health Action* 2010; 3: 5635. DOI:10.3402/gha.v3i0.5635.
4. Bennet CM, McMichael AJ. Non heat related impacts of climate change on working populations. *Glob Health Action* 2010;3. DOI:10.3402/gha.v3i0.5640.
5. Costello A, Abbas M, Allen A, Ball S, Bell S, Bellamy R, et al. Lancet-University College London Institute for Global Health Commission. Managing the health effects of climate change. *The Lancet* 2009; 373: 1693-733.
6. Dash S and Kjellstrom T. (2011). Workplace heat stress in the context of rising temperature in India. *Current Science*. 101. 496-503.
7. Fisk WJ. Health and productivity gains from better indoor environments and their relationship with building energy efficiency. *Annu Rev Energy Environ* 2000;25:537-66. DOI:10.1146/annurev.energy.25.1.537.
8. Flouris A. and Kjellstrom T. (2018). Workers' health and productivity under occupational heat strain: a systematic review and meta-analysis. 2. e521-e531. 10.1016/S2542-5196(18)30237-7.
9. IPCC. Fourth assessment report. Geneva, Inter-governmental panel on climate change. Cambridge: Cambridge University Press; 2007. Available from: <http://www.ipcc.ch>
10. IPCC (2014) Climate Change 2013: Contribution of working group 2 to the fifth assessment report, Geneva: The Intergovernmental Panel on Climate Change. (<http://ipcc-wg2.gov/AR5/>)
11. International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 13, Number 1 (2018) pp. 27-29© Research India Publications. <http://www.ripublication.com>

12. The Journal of Climate Change and Health 3 (2021) 100034
13. Kjellstrom T, Kovats RS, Liloyd SJ, Holt T, Tol RSJ. The Direct Impact of climate change on regional labor productivity. *Arch Environ Occup Health* 2009;64(4):217-27. DOI:10.1080/19338240903352776
14. Kjellstrom T, Holmer I, Lemke B. Workplace heat stress, health and productivity- and increasing challenge for low and middle- income countries during climate change. *Glob Health Action* 2009;2. DOI:10.3402/gha.v2i0.2047.
15. Kjellstrom T. and Freyberg C, et al. (2017). Estimating population heat exposure and impacts on working people in conjunction with climate change. *International Journal of Biometeorology*. 62. 10.1007/s00484-017-1407-0.
16. Kjellstrom T, Gabrys S, Lemke B, Dear K. The “Hothaps” programme for assessing climate change impacts on occupational health and productivity: an invitation to carried out field studies. *Global Health Action* 2009;2. DOI: 10.3402/gha.v2i0.2082.
17. Kjellstrom T. Impact of climate conditions on occupational health and related economic losses: a new feature of global and urban health in the context of climate change *Asia Pac J Public Health* 2015 January 26. DOI:10.1177/1010539514568711
18. Lundgren Kownacki K & Kuklane K (2013). Effects of Heat Stress on Working Populations when Facing Climate Change. *Industrial health*. 51. 3-15. 10.2486/indhealth.2012-0089.
19. Lenzuni P, Capone P, Freda D, del Gaudio M. Is driving in a hot vehicle safe? *Int J Hyperthermia* 2014; 30(4):250-7. DOI:10.3109/02656736.2014.922222
20. McMichael AJ, Haines A, Sloop R, Kovats S, editors. *Climate change and human health*. Geneva: World Health Organization;1996.
21. Nilsson M, Kjellstrom T. Climate change impacts on working people: how to develop prevention policies. *Glob Health Action* 2010;3:5774. DOI: 10.3402/gha.v3i0.5774
22. Sahu S, Sett M, Kjellstrom T. Heat exposure, cardiovascular stress and work productivity in rice harvesters in India: implications for a climate change future. *ind health* 2013;51(4):424-31. DOI.org/10.2486/ind-health.2013-0006.
23. Electronically published April 30, 2021[ *Journal of Political Economy*, 2021, vol. 129, no.6]© 2021 by The University of Chicago.
24. Saudamini D. (2015). Effects of Climate Change and Heat Waves on Low Income Urban Workers:: Evidence from India. 10.2307/j.ctvh8r0w3.14.

25. Sett, M, Sahu S, (2008) Ergonomic study on female workers in manual brick manufacturing units in West Bengal, India. Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety.
26. Sudarshan A, Tewari M, (2014) : The economic impacts of temperature on industrial productivity: Evidence from Indian manufacturing, Working Paper, No.278, Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), New Delhi.
27. Venugopal V, Chinnadurai J, Lucas R, Kjellstrom T , (2015).Occupational Heat Stress Profiles in Selected Workplaces in India. International Journal of Environmental Research and Public Health. DOI:10.3390/ijerph13010089JO

## Assessment Of Occupational & Domestic Stressors Among Women: A Survey Based Study In Nagpur City

**Vaishnavi K. Pradhan**

Student

PGTD of Home Science,  
Rashtrashant Tukadoji Maharaj  
Nagpur University, Nagpur

**Tulika A. Khare**

Assistant Professor,

PGTD of Home Science,  
Rashtrashant Tukadoji Maharaj  
Nagpur University, Nagpur

---

### Abstract:

The study highlights a "double burden" where stressors originate from both a high-stakes professional environment—characterized by a "fear of implications of mistakes" among managers and officers—and an unpredictable domestic sphere involving "family relations" and "unexpected guests." Statistical analysis revealed that 62.5% of women experience high psychological distress, with handling the household chores, handling children, etc. The research concludes that job stress in the modern banking and domestic landscape has evolved into a pervasive "silent serpent," disproportionately impacting women through a complex "double burden" of professional accountability and household management. The findings establish that psychological distress is not merely an individual experience but is statistically driven by a confluence of factors, including lower socioeconomic status, the absence of robust healthcare benefits, and the severe impact of domestic violence

KEY WORDS: Stressors, Silent Serpent (quite killer)

## Introduction

The assessment of "double burden" stress in working women involves a comprehensive evaluation of both occupational and domestic stressors, alongside effective measurement tools and contextual factors influencing stress levels.

1. **Occupational Stressors:** Key elements include work overload, role conflict, unclear job roles, and limited career growth opportunities. These factors contribute significantly to workplace-related stress and affect women's ability to balance professional demands.
2. **Domestic Stressors:** Time constraints for self-care, absence of household help, concerns about children's future, and caregiving responsibilities for aging family members intensify the domestic side of the double burden, increasing overall stress.
3. **Assessment Methods:** Utilizing standardized tools such as the Occupational Stress Inventory–R, Perceived Stress Scale (PSS), Effort-Reward Imbalance (ERI) model, and McMaster Family Assessment Device provides reliable measurement of stress levels and family dynamics.
4. **Role of Support Systems:** Lack of spousal and organizational support exacerbates stress, highlighting the necessity for tailored interventions that foster supportive environments both at home and in the workplace.
5. **Workplace Environment:** Continuous monitoring and proactive management of workplace stressors are essential. Promoting a safe, development-oriented, and health-promoting work environment can transform work into a source of personal growth rather than stress.
6. **Stress Management Strategies:** Women employ lifestyle changes such as enhancing stress tolerance, adjusting life pace, controlling stressful thoughts, developing problem-solving skills, and seeking social support. These strategies contribute to increased job satisfaction and overall well-being.

Work stress is a real challenge for working women as they manage both home as well as workplace. It is important that workplace should be continuously monitored for stress related issues. Further, it is not only important to identify stress related elements at workplace and to deal with them but to promote healthy work and reduced harmful aspects of work. Work, itself can be a self-promoting activity as long as it takes place in a safe, development and health promoting environment. In the present study it was found that women relieve stress by altering their lifestyle which includes building greater stress tolerance, changing their pace of life, controlling stressful thoughts, acquiring problem solving skills, and seeking social support which in turn helps them to increase their job satisfaction level.

### **Purpose Of The Study**

- Occupational hazards, risk levels, and leadership support.
- Impact on relationships, domestic workload, and overall prosperity.
- Effectiveness of social support and healthy lifestyle practices.

### **Objective**

- Determination of job stress & work by survey of a few selected families

### **LIMITATIONS:**

- Only Women (gender) was considered

### **Review Of Literature**

**Muddanagouda Patil (2016) studied Stress among the working women & homemaker women with respect to their family type. International journal of Indian psychology.** The provided research findings shows the impact of nuclear and joint family systems on the stress levels of women, specifically categorizing them into working professionals and homemakers. Family structure is a critical

determinant of stress, with the nuclear setup generally being more stressful for women. Employment status acts as a moderator; the protective effect of a joint family is most beneficial for working women. Homemakers experience relatively consistent stress levels regardless of family type, indicating that the challenges of home management are universal across these structures.

**H.Y.Kamble, Smita N. Mutgekar, Naziya Iqbal Patvegar(2022) Studied An Evaluation of Occupational Stress Among Working Women. 7<sup>th</sup> international conference on “economic growth & sustainable development: emerging trends”** Research suggests that this anxiety can be mitigated if senior leadership shifts from a purely supervisory role to one that actively inculcates a positive, mentoring-based attitude toward subordinates, thereby enhancing operational efficiency. Studies consistently advocate for organizational interventions such as stress management workshops, work-life balance seminars, and the promotion of holistic health practices like yoga and meditation to address physiological strain. Furthermore, a recurring theme in the literature is the necessity of aligning employee capability with job requirements through targeted training to prevent competency-based burnout. This is particularly critical for working women, who face the "double burden" of managing both domestic and professional spheres. The research indicates that for these employees, job satisfaction is often contingent upon "lifestyle alterations"—including building stress tolerance, seeking social support, and mastering problem-solving skills—within a workplace that is continuously monitored to ensure a safe, developmental, and health-promoting environment.

**Sadhana Vitthalrao Lakhute, Rahul Mohanrao Band, Praveen Kumar Rajasekaran (2024) Studied Stress Among Working Women: A silent serpent. National journal of community medicine.** The study shows increasingly characterizes occupational and domestic stress among women in developing nations like India as a "silent serpent," reflecting a dual-burden phenomenon where stressors are "double fold" compared to their male counterparts. Research indicates

that for working women, the domestic sphere often introduces unpredictable stressors—such as managing "unexpected guests" and complex "family relations"—which compound workplace pressures to impact the health of the family unit as a whole. Emerging global trends, such as the pilot "four-day work week" in countries like Spain, are being analyzed as potential universal benchmarks for enhancing productivity while specifically mitigating the unique exhaustion faced by female professionals. Scholars suggest that because stress is "unavoidable" in the modern economy, the most effective buffers are "whole-hearted connections" with social networks outside of working hours. Ultimately, the consensus in recent studies is that reducing the stress load on women is not merely an individual benefit but a socioeconomic imperative, as a less stressed female population is directly correlated with the "prosperity" and stability of the broader family structure.

**Ojha, Jenny, Bhandari, Tulsi Ram, Karki, Renu (2020) studied Job Stress & it's Associated Factors among Working Women in Pokhara Metropolitan, Nepal. Journal of The Scientific Society.** The research increasingly identifies job stress as a critical "public health issue" that disproportionately impacts nearly half of the working female population, particularly in developing contexts like Nepal where mental health research remains limited. Studies suggest that the development of this stress is significantly associated with a complex interplay of demographic and organizational variables, including the participant's age, family structure, and the presence or absence of office-related healthcare benefits. Scholars emphasize that while these stressors are prevalent, they are largely "preventable" through structured social interventions such as targeted counseling, educational programs, and robust workplace support systems.

**Solanki, Ranjan, Khan, Mubashshera F, Wangaskar, Sneha A, Deshmukh, Pradeep R. (2025) Stress & Stressor of women: A cross-sectional study from Rural Population in Central India. Indian JOurnal of Community Medicine.** study shows increasingly highlights the alarming prevalence of psychological

distress among women in lower-resource settings, with recent data indicating that as many as 62.5% of women experience "very high psychological distress." Research consistently identifies a confluence of socioeconomic and domestic risk factors that significantly elevate this distress, most notably lower socioeconomic status, the presence of comorbid physical conditions, and a woman's marital status, with single, widowed, or divorced individuals facing a more than threefold increase in risk. Perhaps most critically, the literature establishes a profound link between domestic violence and mental health, with victims being nearly five times more likely to suffer from severe psychological strain.

### Methodology

Location: Nagpur, Maharashtra, India.

Sampling: Working Women & homemaker were selected as a sampling

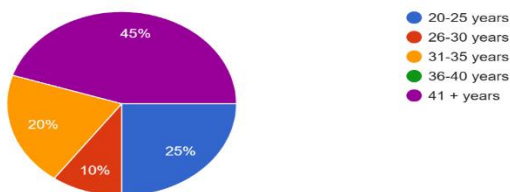
Sample Size: 40 Women

### Result & Discussion

**Table no. 01: Age of women population**

Age	Frequency	Percentage
20-25	10	25%
26-30	4	10%
31-35	8	20%
36-40	0	0%
41+	18	45%
Total	40	100%

Age  
20 responses

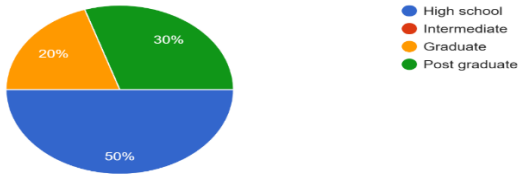


The age of an employee is a critical demographic variable in understanding job stress, as it often dictates the type of stressors one faces and the coping mechanisms available to them. The study shows that 45% of the women are 41+ years old, 25% are under 20-25 years, 10% are under 26-30years, & 20% of the women are 31-35 years old.

**Table no.02: Qualification of the women**

Qualification	Frequency	Percentage
High School	20	50%
Intermediate	0	0%
Graduate	8	20%
Post Graduation	12	30%
Total	40	100%

Qualification  
20 responses

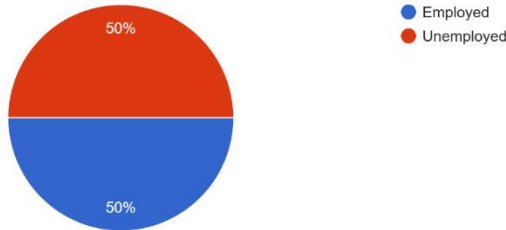


In the context of job stress, Qualification (educational attainment and professional skill level) acts as both a protective shield and a potential stress trigger. 50% of the women has qualified high school, 30% of the women qualified Post graduation & 20% of the women has qualified Graduation.

**Table no. 03: Employment status of the women**

Employment Status	Frequency	Percentage
Employed	20	50%
Unemployed	20	50%
Total	40	100%

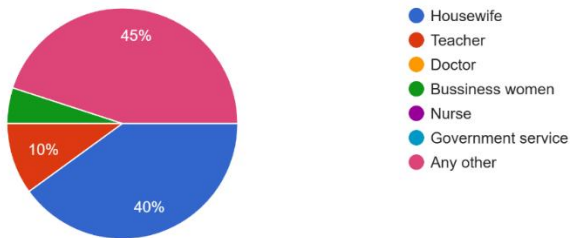
Employment status  
20 responses



Employment Status (whether a woman is a homemaker, a part-time worker, or a full-time professional) is the primary lens through which the "Double Burden" is observed. It determines the specific nature of the stressors encountered. 50% of the women are employed & 50% of women are homemaker.

### Occupation of the women:

Occupation  
20 responses

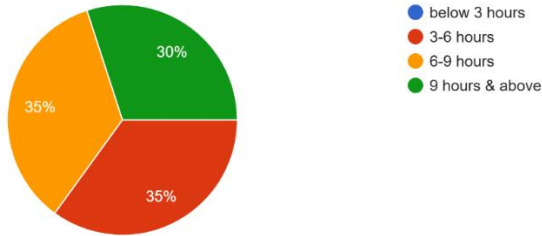


Occupation specifically refers to the *nature of the work* performed. While "Employment Status" simply tells us if a person is working. In the survey it was found that 40% of the women were homemaker, other occupation includes: teacher, doctor, business women, nurse& government service

**Table no.04: Duration of work women perform every day.**

Duration Of Work	Frequency	Percentage
Below 3 Hrs	0	0%
3-6 Hrs	14	35%
6-9 Hrs	14	35%
9hrs & Above	12	30%
Total	40	100%

Duration of work  
20 responses

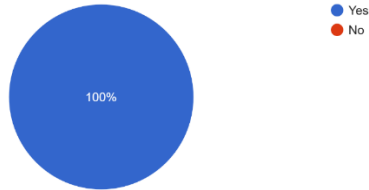


The duration of work is a primary physical constraint that dictates the severity of the "Silent Serpent." It acts as the literal boundary or lack thereof, between professional demands and domestic responsibilities. 35% of women work for 3-6 hrs & 6-9hrs a day & 30%of the women works for 9hrs & above.

**Table no.05: Women’s understanding of the concept of stress.**

Do You Understand The Concept Of Stress	Frequency	Percentage
Yes	40	100%
No	0	0%
Total	40	100%

Do you understand the concept of stress  
20 responses

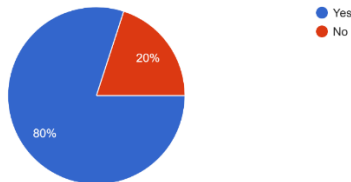


It was found that 100% pf the women understand the concept of stress

**Table no.06: How many of the women feels stressed.**

Do You Feel Stressed	Frequency	Percentage
Yes	32	80%
No	8	20%
Total		

Do you feel stressed  
20 responses

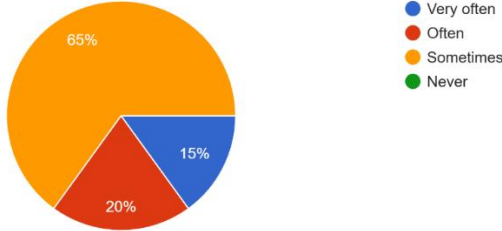


The study indicates that 80% of the women feels stressed.

**Table no.07: How often does the women feel stressed.**

How Often Do You Feel Stressed	Frequency	Percentage
Very Often	6	15%
Often	8	20%
Sometimes	26	65%
Never	0	0%
Total	40	100%

How often do you feel stressed  
20 responses

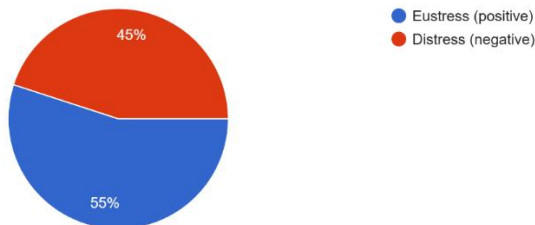


The frequency and chronicity of stress shows that women often navigate a "double burden," their stress is rarely a one-time event; it is a continuous, daily experience that the literature describes as persistent. 15% of the women feel stressed very often, 20% of the women feel stressed often, & 65% of the women feel stressed sometimes. Which is the good sign that not all women are feeling stressed.

**Table no.08: What type of stress do women experience eustress (positive) Distress (negative)**

What Type Of Stress Do You Experience?	Frequency	Percentage
Eustress	22	55%
Distress	18	45%
Total	40	100%

What type of stress do you experience?  
20 responses



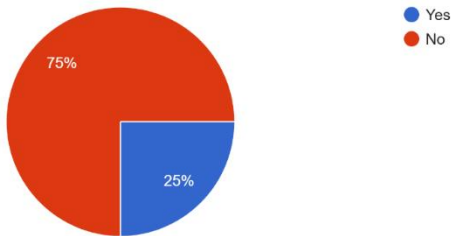
- Eustress (Positive Stress): Short-term stress that feels motivating. It can make work a "self-promoting activity" that leads to growth and efficiency.
- Distress (Negative Stress): The "harmful aspects of work" that lead to burnout, especially when one feels they have no control over their environment.

55% of the women feels positive stress whereas, 45% of women feels negative stress

**Table no.09: Is the stress harming them in any way?**

Is The Stress Harming You In Any Way?	Frequency	Percentage
Yes	10	25%
No	30	75%
Total	40	100%

Is the stress harming you in any way ?  
20 responses

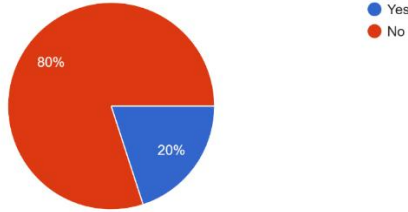


75% of the women says that the stress is harming them.

**Table no.10: Is the stress benefiting them in any way?**

Is The Stress Benefiting You In Any Way?	Frequency	Percentage
Yes	8	20%
No	32	80%
Total	40	100%

Is the stress benefiting you in any way?  
20 responses



80% of the women are saying that the stress is benefiting them.

### What Are The Cause For The Stress You Experience?

It was seen that most of the women are stressed by household chores, some of the women are stressed from Job, some of the women are stressed by their children, some of the women are stressed due to personal relationship & social activity where they need to interact with people, & some women are stressed due to medical issues & other reasons

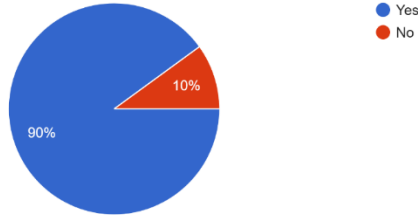
### What Measures Do You Adapt To Reduce Stress?

Taking corrective action to handle & mental peace is very crucial. In the study it was found out that most of the women goes to sleep to reduce the stress, other women do yoga & meditation, exercise daily, recreational activity, drinks water to calm down, cooking, gardening, etc, & very few women go to therapy sessions.

**Table no.11: Are the solutions helping you in any way?**

Are The Solutions Adapted Helping You To Reduce Stress	Frequency	Percentage
Yes	36	90%
No	4	10%
Total	40	100%

Are the solutions adapted helping you to reduce stress  
20 responses



It shows that 90% of the stress are reducing by the solutions % 10% of the women are not affected

## Conclusion

The assessment of occupational & domestic stressors it is found that for managers and officers, this stress is intensified by a high-stakes "culture of fear" regarding professional mistakes, which necessitates a structural shift toward supportive leadership and continuous workplace monitoring. However, the study also highlights a path toward resilience, demonstrating that when organizations implement systemic changes, such as the transition to a four-day work week, the provision of targeted counselling, and the promotion of holistic practices like yoga, work can be transformed from a source of depletion into a "self-promoting," health-enhancing activity. Ultimately, because a woman's mental well-being is intrinsically linked to the "prosperity of the family as a whole," addressing these stressors through collective social support and informed policy is a critical mandate for both public health and economic stability. Addressing these stressors is not a "perk", it is a critical mandate for our organization's long-term economic stability. By transforming our culture, we ensure a resilient, high-performing workforce that supports the broader prosperity of our community. This proposal outlines a systemic shift to move from a model of professional depletion to one of "self-promoting" health.

## Reference

1. Patil, M. (2016). *Stress among the working and homemaker women with respect to their family type. International Journal of Indian Psychology, 3(4), 114–122.*
2. Solanki, R., Khan, M. F., Wangaskar, S. A., & Deshmukh, P. R. (2025). *Stress and stressors of women: A cross-sectional study from rural population in central India. Indian Journal of Community Medicine, 50(4), 581–586*
3. Ojha, J., Bhandari, T. R., & Karki, R. (2020). *Job stress and its associated factors among working women in Pokhara Metropolitan, Nepal. Journal of the Scientific Society, 47*
4. Lakhute, S. V., Band, R. M., & Rajasekaran, P. K. (2024). *Stress among working women: A silent serpent. National Journal of Community Medicine, 15(06), 509–510.*
5. Kamble, H. Y., Mutgekar, S. N., & Patvegar, N. I. (2022). *An evaluation of occupational stress among working women [Conference presentation]. 7th International Conference on Economic Growth & Sustainable Development: Emerging Trends, Mysore, India.*

# **Forest Rights Act 2006 and Livelihood Security: A Study of Minor Forest Produce (MFP) Rights Among the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) of Jharkhand.**

**Dr. Prity Kumari**

---

## **Abstract: -**

Jharkhand, dwelling place to a significant tribal population, is rich in forest resources. Jharkhand as a separate state appears varied and complex, but one major reason seems to be to protect the culture, identity, and rights of tribals and forest dwellers over land and forest resources. The Forest Rights Act (FRA) 2006 recognizes the rights of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (OTFDs) over MFP, aiming to ensure livelihood security and socio-economic empowerment. MFP rights have significant implications for economic security, social inclusion, and ecological governance. Minor forest produce (MFP) such as tendu leaves, mahua, Sal seeds, and lac form the backbone of tribal livelihoods and economic empowerment. The Forest Rights Act is a major step towards empowering indigenous tribes in Jharkhand and closing historical injustices, but it requires ongoing efforts to ensure equitable distribution and sustainable management of forest resources for forest-dependent communities, those who rely on them. However, the implementation of these rights remains uneven and under-researched in Jharkhand, where tribal communities have historically depended on forests for subsistence and livelihood. However, it reveals that despite legal provisions, the implementation of MFP rights remains uneven, constrained by

policy gaps, weak institutional mechanisms, low awareness, and market exploitation.

This study aims to examine how the recognition and exercise of MFP rights under FRA influence the livelihood security of tribal households in Jharkhand. It will assess institutional facilitation, market linkages, local governance frameworks, and the challenges faced by tribal communities. The Forest Rights Act is a major step towards empowering PVTGs tribes in Jharkhand.

**Keywords:** - Forest Rights Act (FRA) 2006, Minor Forest Produce (MFP),

## **Introduction**

The enactment of the Forest Rights Act (FRA), 2006 represents a significant transformation in India’s forest governance by formally recognizing the rights of historically marginalized forest-dependent communities. A central component of this legislation is the provision of rights over Minor Forest Produce (MFP), which plays a crucial role in sustaining the livelihoods of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). These communities, often residing in remote forest regions with limited access to institutional support, depend extensively on forest-based resources for their subsistence (Ministry of Tribal Affairs, 2014).

Minor Forest Produce, which includes non-timber forest resources such as fruits, raisins, leaves, and medicinal plants, contributes significantly to income generation, food security, and the preservation of traditional knowledge systems. By granting legal rights to collect, utilize, and manage these resources, the FRA seeks to enhance economic independence and promote social justice among tribal populations (Government of India, 2006).

Jharkhand, characterized by a substantial tribal population and extensive forest cover, provides an important context for examining these dynamics. However, despite progressive legal provisions, the practical realization of MFP rights remains uneven, raising concerns about their actual contribution to improving livelihood security among PVTGs.

## Conceptual Framework

This study is grounded in Empowerment Theory and Amartya Sen’s Capability approach, both of which offer valuable insights into the relationship between resource access and human development.

Empowerment Theory emphasizes that marginalized groups can improve their socio-economic conditions when they gain access to resources, institutional support, and decision-making authority. It highlights the importance of enhancing agency, autonomy, and participation in governance processes (Kabeer, 1999).

complementing this, Sen’s Capability approach focuses on expanding individuals’ real freedoms to achieve well-being rather than merely considering resource availability, it evaluates the extent to which individuals can convert resources into meaningful life outcomes (Sen, 1999). This framework is particularly relevant in the context of tribal communities, where access to forest resources is closely linked to cultural identity and survival.

Within this framework, the FRA (2006) functions as a transformative policy instrument aimed at correcting historical injustices by recognizing both individual and community rights over forest resources. In particular, the recognition of MFP rights is critical for strengthening livelihood opportunities among PVTGs.

## Review of Literature

Existing literature highlights the importance of MFP in sustaining tribal livelihoods and emphasizes the gaps in policy implementation.

Studies by the Rights and Resources Initiative (2021, 2025) indicate that secure forest tenure significantly improves income levels and ecological sustainability, although gender disparities in access to forest rights persist. Similarly, Kanwar and Kumari (2023) observe that despite legal provisions ensuring equality, women’s effective access to forest resources remains constrained by socio-cultural barriers. Reports by the Ministry of Tribal Affairs (2013–2021) and the Xaxa Committee (2014) point to gaps in the implementation of community forest rights, particularly

in states like Jharkhand. These studies highlight issues such as limited awareness, bureaucratic inefficiencies, and weak institutional mechanisms.

Research by Jha et al. (2020) and Das and Mishra (2021) underscore the economic dependence of tribal communities on MFP while identifying infrastructural constraints such as poor storage and transportation facilities. Similarly, the World Bank (2020) and UNDP (2022) emphasize the importance of market linkages and capacity-building initiatives in enhancing the economic potential of MFP-based livelihoods.

Scholars such as Baviskar (2007) and Bose and Baviskar (2018) further highlight the sociological dimensions of forest rights, noting that issues of power, gender inequality, and social exclusion significantly influence the outcomes of policy interventions.

### **Relevance of the study**

This study is highly relevant for policy formulation in the areas of tribal development, forest governance, and inclusive economic growth. While the FRA provides legal recognition of MFP rights, there is limited empirical understanding of how these rights translate into tangible livelihood benefits.

By analyzing secondary data, the study seeks to bridge the gap between policy provisions and their practical implementation. It provides insights into the socio-economic realities of tribal communities, enabling policymakers to design more effective and context-specific interventions. The findings can contribute to improving institutional mechanisms, strengthening market access, and enhancing community participation in forest governance.

### **Conceptual Farmwork**

#### **Livelihood Security**

Livelihood security refers to the capacity of individuals and households to sustain their basic needs while coping with economic and environmental uncertainties. It

encompasses economic stability, food security, and social well-being (Chambers & Conway, 1992).

### **Minor Forest Produce (MFP)**

MFP includes all non-timber forest products such as bamboo, tendu leaves, honey, lac, and medicinal plants. These resources are essential for income generation and subsistence among tribal communities (Mahapatra & Tewari, 2005; Planning Commission, 2013).

### **Forest Rights Act (2006)**

The FRA recognizes the rights of forest-dwelling communities over land and forest resources. Section 3(1)(c) specifically grants ownership and usage rights over MFP, aiming to reduce exploitation and promote economic empowerment (Government of India, 2006).

### **PVTGs**

Particularly Vulnerable Tribal Groups are the most marginalized among tribal populations, characterized by low literacy, economic vulnerability, and high dependence on natural resources (Ministry of Tribal Affairs, 2014).

Jharkhand is home to several PVTGs, including the Birhor, Asur, and Sauria Paharia. These communities are marked by subsistence-based livelihoods, limited access to education and healthcare, and a high dependence on forest resources. Their economic activities largely include hunting-gathering, shifting cultivation, and MFP collection. Given their vulnerability, access to forest resources is critical for their survival and socio-economic well-being.

MFP plays a multifaceted role in sustaining tribal livelihoods. It provides seasonal employment, supplementary income, and nutritional support. Many forest products are directly consumed, contributing to food security, while others are sold in local markets.

Studies indicate that MFP contributes approximately 20–40% of household income among forest-dependent communities (Planning Commission, 2013). However, factors such as price fluctuations, lack of storage, and market exploitation often limit its economic potential.

### **FRA Implementation and MFP Rights in Jharkhand**

Despite legal provisions, the implementation of FRA in Jharkhand remains inconsistent. While individual land rights have seen some progress, community forest rights, particularly those related to MFP, are less effectively realized.

Key challenges include:

- Limited awareness among PVTGs
- Administrative delays in claim processing
- Weak functioning of local institutions
- Continued dominance of intermediaries in MFP markets

These constraints reduce the effectiveness of FRA in improving livelihood outcomes.

### **Role of Minor Forest Produce (MFP) in Livelihood Security**

Minor Forest Produce (MFP), also referred to as Non-Timber Forest Products (NTFPs), constitutes a critical component of livelihood systems among forest-dependent communities, particularly the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). In regions such as Jharkhand, where forest ecosystems form the backbone of subsistence economies, MFP plays a multidimensional role in sustaining both economic and social well-being.

### **Income Generation and Employment**

MFP serves as a vital source of supplementary income for tribal households. Unlike agriculture, which is seasonal and often uncertain due to climatic variability, the collection and sale of forest produce provide relatively stable income opportunities throughout the year. Products such as tendu leaves, lac, mahua flowers, sal seeds, and honey are commonly collected and sold in local

markets. These activities are particularly significant during agricultural lean seasons, thereby acting as an economic buffer for vulnerable households (Mahapatra & Tewari, 2005).

Empirical studies suggest that MFP contributes approximately 20–40% of annual household income among forest-dependent communities (Planning Commission, 2013). In certain regions, especially among PVTGs, this contribution may be even higher due to limited alternative livelihood options. The income derived from MFP is often used to meet essential household needs, including food, healthcare, and education.

### **Food and Nutritional Security**

In addition to income generation, MFP plays a crucial role in ensuring food and nutritional security. A variety of forest products, including wild fruits, leafy vegetables, tubers, mushrooms, and medicinal plants, are directly consumed by tribal communities. These products are rich in micronutrients and form an integral part of traditional diets.

For PVTGs, who often face food insecurity due to limited access to agricultural land and markets, MFP acts as a reliable source of nutrition. It not only supplements staple diets but also provides dietary diversity, which is essential for maintaining health and well-being (FAO, 2019).

### **Risk Mitigation and Livelihood Resilience**

MFP also functions as a safety net during periods of economic distress, crop failure, or environmental shocks. In situations where agricultural production is affected by droughts or other climatic events, forest resources offer an alternative means of sustenance. This resilience function is particularly important for PVTGs, who have limited access to formal safety nets such as credit and insurance.

The flexibility associated with MFP collection allows households to adjust their livelihood strategies according to seasonal and environmental conditions. This

adaptability enhances their capacity to cope with uncertainties and maintains livelihood security (Chambers & Conway, 1992).

### **Cultural and Social Significance**

Beyond economic and nutritional aspects, MFP holds significant cultural value for tribal communities. Many forest products are used in traditional rituals, festivals, and medicinal practices. The knowledge associated with the collection and utilization of MFP is deeply embedded in indigenous knowledge systems and is passed down through generations.

Thus, MFP is not merely an economic resource but also a key component of cultural identity and social cohesion among tribal communities (Baviskar, 2007).

### **Constraints Affecting MFP-Based Livelihoods**

Despite its importance, the economic potential of MFP remains underutilized due to several structural constraints. Price volatility, lack of storage facilities, inadequate transportation infrastructure, and limited access to formal markets often reduce the returns received by collectors. Additionally, the dominance of intermediaries in the value chain leads to exploitation and unequal distribution of profits (Jha et al., 2020).

### **FRA Implementation and MFP Rights in Jharkhand**

The Forest Rights Act (FRA), 2006 was enacted to address historical injustices and empower forest-dwelling communities by recognizing their rights over land and forest resources. A key provision of the Act is the recognition of ownership and usage rights over MFP, which has the potential to significantly enhance livelihood security.

However, the implementation of FRA in Jharkhand has been uneven and characterized by several challenges.

### **Limited Awareness Among PVTGs**

One of the primary barriers to effective implementation is the low level of awareness among PVTGs regarding their rights under the FRA. Many community

members are either unaware of the provisions of the Act or lack adequate information on the procedures for claiming rights.

This information gap is further exacerbated by low literacy levels and limited outreach by government agencies. As a result, many eligible households are unable to exercise their rights, thereby limiting the impact of the legislation (Ministry of Tribal Affairs, 2014).

### **Weak Functioning of Local Institutions**

The FRA assigns a central role to local governance institutions, particularly the Gram Sabha, in the identification, verification, and management of forest rights. However, in many parts of Jharkhand, these institutions remain weak and ineffective.

Several factors contribute to this weakness:

- **Limited Capacity:** Gram Sabhas often lack the technical knowledge and administrative capacity required to manage forest resources effectively.
- **Inadequate Participation:** Participation of marginalized groups, including women and PVTGs, is often limited, leading to exclusion in decision-making processes.
- **Political Interference:** Local governance structures are sometimes influenced by political and economic interests, which can undermine their autonomy.
- **Lack of Training and Support:** Insufficient training and institutional support further weaken the functioning of these bodies.

### **Administrative Delays and Bureaucratic Hurdles**

The process of recognizing forest rights involves multiple administrative steps, including claim submission, verification, and approval by various committees. In practice, these processes are often slow and inefficient, leading to significant delays in the recognition of rights.

Bureaucratic complexities, lack of coordination among departments, and insufficient staffing further contribute to implementation gaps. Studies have shown

that delays in claim processing discourage community participation and undermine trust in institutional mechanisms (Sarin et al., 2010).

As a result, the decentralized governance model envisioned under the FRA is not fully realized, affecting the implementation of MFP rights (Xaxa Committee, 2014).

### **Continued Dominance of Intermediaries in MFP Markets**

Despite the legal recognition of ownership rights over MFP, the market structure continues to be dominated by intermediaries. These middlemen often control pricing, procurement, and distribution channels, leaving tribal collectors with limited bargaining power.

Due to lack of access to formal markets, storage facilities, and transportation infrastructure, tribal communities are often compelled to sell their produce at low prices. This not only reduces their income but also perpetuates economic dependency and exploitation (Rai & Chakraborty, 2017).

Efforts such as the introduction of Minimum Support Price (MSP) for MFP and the involvement of agencies like TRIFED have shown some positive outcomes. However, their reach remains limited, particularly among remote PVTG populations (UNDP, 2022).

### **Overall Impact on Livelihood Outcomes**

The combined effect of these challenges significantly limits the effectiveness of FRA in enhancing livelihood security. While the Act provides a strong legal framework, the gap between policy and practice remains substantial.

The failure to fully operationalize MFP rights results in continued socio-economic vulnerability among PVTGs. Without addressing issues related to awareness, institutional capacity, and market access, the transformative potential of FRA cannot be fully realized.

### **Conclusion: -**

MFP plays a vital role in sustaining the livelihoods of tribal communities by providing income, food security, and resilience against economic shocks. However, its potential remains constrained by structural and institutional challenges. From a sociological perspective, the FRA represents a shift toward rights-based governance. However, the gap between policy and practice reflects deeper structural inequalities. Issues such as power imbalances, social exclusion, and institutional inefficiencies continue to affect the realization of rights. While the FRA has transformative potential, its success depends on addressing these structural barriers (Baviskar, 2007).

The effective implementation of FRA, particularly MFP rights, is essential for improving livelihood outcomes among PVTGs in Jharkhand. Strengthening local institutions, enhancing awareness, and improving market linkages are critical steps toward achieving this goal.

### **References**

1. *Baviskar, A. (2007). Rights in the forest: The struggle of Adivasi communities in India. Oxford University Press.*
2. *Bose, P., & Baviskar, A. (2018). Gender and forest governance: The role of women in forest management. Economic and Political Weekly, 53(18), 45–52. (Note: Add exact issue/pages if available)*
3. *Chambers, R., & Conway, G. (1992). Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century (IDS Discussion Paper No. 296). Institute of Development Studies.*
4. *Das, P., & Mishra, A. (2021). Implementation challenges of the Forest Rights Act in India. Journal of Rural Development, 40(2), 123–140. (Update volume/pages if needed)*

5. Government of India. (2006). *The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006*. Ministry of Law and Justice.
6. Jha, S., Kumar, R., & Singh, P. (2020). *Dependency on minor forest produce in Jharkhand: A socio-economic analysis*. *Indian Journal of Forestry*, 43(3), 215–223. (Verify details if needed)
7. Kabeer, N. (1999). *Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women’s empowerment*. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
8. Kanwar, P., & Kumari, S. (2023). *Gender dimensions of forest rights: A study of women’s access under FRA*. *Journal of Tribal Studies*, 11(1), 67–82. (Update details if available)
9. Mahapatra, A. K., & Tewari, D. D. (2005). *Importance of non-timber forest products in the economic valuation of dry deciduous forests of India*. *Forest Policy and Economics*, 7(3), 455–467. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2004.02.004>
10. Ministry of Tribal Affairs. (2014). *Report on particularly vulnerable tribal groups (PVTGs)*. Government of India.
11. Planning Commission. (2013). *Report of the expert committee on minor forest produce*. Government of India.
12. Rights and Resources Initiative. (2021). *Power and potential: A comparative analysis of national laws and regulations concerning women’s rights to community forests*. Rights and Resources Initiative.
13. Rights and Resources Initiative. (2025). *Global assessment of community forest rights and gender equity*. Rights and Resources Initiative.
14. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
15. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Minor forest produce and livelihood enhancement report*. UNDP.

16. *World Bank. (2020). Forests, livelihoods, and poverty reduction: A global assessment. World Bank.*
17. *Xaxa Committee. (2014). Report of the high-level committee on socio-economic, health and educational status of tribal communities in India. Ministry of Tribal Affairs, Government of India.*

# भारतीय न्यायशास्त्र में 'दंड' की अवधारणा और सुधारात्मक न्याय: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. सुमीत कुमार गुप्ता

सहायक आचार्य(अतिथि व्याख्याता)- राजनीति विज्ञान  
शासकीय गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
कोण्डागाँव (छ.ग.) – 494226,

## सारांश (Abstract):

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय न्यायशास्त्र के प्राचीन स्रोतों मनुस्मृति, अर्थशास्त्र तथा महाभारत के आलोक में 'दंड' की अवधारणा का विश्लेषणात्मक परीक्षण करता है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में 'दंड' को मात्र दमन या प्रतिशोध का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन, नैतिक अनुशासन और धर्म की स्थापना का उपकरण माना गया है। प्राचीन भारतीय दंड नीति को केवल 'प्रतिशोधात्मक' (Retributive) दृष्टिकोण तक सीमित करना एकांगी समझ है, वास्तव में उसमें 'सुधारात्मक' (Reformative) तथा 'बहाली' (Restorative) न्याय के तत्व बीज रूप में विद्यमान थे।

मनुस्मृति में दंड को धर्म का रक्षक बताया गया है, जिसका उद्देश्य समाज में न्याय और नैतिकता की पुनर्स्थापना करना है। यहाँ दंड का प्रयोग अपराधी के विनाश हेतु नहीं, बल्कि उसके आचरण को सुधारने और सामाजिक व्यवस्था को संतुलित करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंडनीति राज्य की स्थिरता और लोककल्याण से जुड़ी हुई है। कौटिल्य दंड को विवेकपूर्ण, परिस्थिति-निरपेक्ष और न्यायसंगत प्रयोग की वकालत करते हैं, जिससे अपराधी को अनुशासित किया जा सके तथा समाज में पुनः समावेशन की संभावना बनी रहे। महाभारत में भी दंड और क्षमा के मध्य संतुलन की अवधारणा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, जहाँ न्याय को धर्म और करुणा के समन्वय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

यह शोध विशेष रूप से 'प्रायश्चित' और 'क्षतिपूर्ति' जैसी अवधारणाओं पर प्रकाश डालता है, जो सुधारात्मक और बहाली न्याय के मूल तत्वों से साम्य रखती हैं। 'प्रायश्चित' अपराधी को आत्मबोध,

आत्मशुद्धि और नैतिक पुनर्निर्माण का अवसर प्रदान करता है, जबकि ‘क्षतिपूर्ति’ पीड़ित के नुकसान की भरपाई के माध्यम से सामाजिक संबंधों की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार, अपराध को केवल विधि-भंग के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों के विघटन के रूप में देखा गया है, जिसकी मरम्मत आवश्यक है।

आधुनिक वैश्विक न्याय प्रणालियों में उभरती ‘सुधारात्मक न्याय’ की अवधारणा, जो अपराधी, पीड़ित और समुदाय के बीच संवाद एवं सामंजस्य पर बल देती है, भारतीय परंपरा में निहित इन सिद्धांतों से आश्चर्यजनक समानता रखती है। यह अध्ययन प्रतिपादित करता है कि भारतीय न्यायशास्त्र का दार्शनिक आधार समन्वयी और मानवीय रहा है, जिसमें दंड का उद्देश्य केवल भय या प्रतिशोध नहीं, बल्कि नैतिक पुनर्संतुलन और सामाजिक पुनर्गठन है।

प्राचीन भारतीय दंड नीति आधुनिक सुधारात्मक न्याय के लिए एक वैकल्पिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मॉडल प्रदान कर सकती है। भारतीय न्यायशास्त्र की यह विरासत न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समकालीन न्याय व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, सहभागी और पुनर्स्थापनात्मक बनाने की दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है।

**बीज शब्द:** दंड, धर्म, सुधारात्मक न्याय, प्रायश्चित, कौटिल्य, मनुस्मृति, न्यायशास्त्र।

## प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय न्यायशास्त्र में ‘दंड’ की अवधारणा अत्यंत प्राचीन, व्यापक और दार्शनिक गहराई से युक्त रही है। ‘दंड’ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत धातु ‘दम्’ से मानी जाती है, जिसका अर्थ है – नियंत्रण करना, संयमित करना या अनुशासित करना। इस दृष्टि से दंड का मूल उद्देश्य केवल दमन नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक अनुशासन की स्थापना है। भारतीय चिंतन में दंड को समाज के संरक्षण, धर्म की प्रतिष्ठा और लोककल्याण के लिए आवश्यक साधन माना गया है। प्राचीन ऋषियों ने यह स्वीकार किया कि यदि समाज में नियमों का पालन सुनिश्चित करने वाली कोई व्यवस्था न हो, तो ‘मात्स्य न्याय’ अर्थात् शक्तिशाली द्वारा निर्बल के शोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस संदर्भ में दंड को अराजकता से बचाने वाली सृजनात्मक शक्ति के रूप में देखा गया।

प्राचीन ग्रंथों में दंड का स्वरूप केवल शारीरिक या आर्थिक दंड तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक नैतिक और दार्शनिक अवधारणा थी। मनुस्मृति में दंड को धर्म का रक्षक बताया गया है। मनु के अनुसार दंड के अभाव में समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः वासनाओं और स्वार्थ से प्रेरित हो सकता है। अतः दंड व्यवस्था सामाजिक संतुलन बनाए रखने का साधन है। किंतु यह भी

स्पष्ट किया गया कि दंड का प्रयोग न्यायसंगत, संतुलित और विवेकपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अन्याय का कारण बन सकता है।

इसी प्रकार अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने दंडनीति को राज्य-प्रशासन का केन्द्रीय आधार माना है। कौटिल्य के अनुसार राजा का कर्तव्य है कि वह दंड का प्रयोग निष्पक्षता और न्याय के साथ करे। दंड का उद्देश्य भय उत्पन्न कर शासन चलाना नहीं, बल्कि प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है। कौटिल्य ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक कठोर दंड प्रजा में असंतोष उत्पन्न कर सकता है, जबकि अत्यधिक शिथिलता अराजकता को जन्म देती है, अतः ‘मध्यम मार्ग’ ही न्यायसंगत है। यह दृष्टिकोण दंड को संतुलन और सुधार के साधन के रूप में प्रस्तुत करता है।

भारतीय महाकाव्य परंपरा में भी दंड और धर्म के संबंध का विशद विवेचन मिलता है। महाभारत में राजधर्म और दंडनीति पर व्यापक चर्चा है। भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में यह प्रतिपादित किया गया है कि राजा का दायित्व केवल अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि न्याय और करुणा के संतुलन के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना करना है। यहाँ दंड को प्रतिशोध नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन की पुनर्स्थापना के रूप में देखा गया है।

भारतीय परंपरा में ‘प्रायश्चित’ और ‘क्षतिपूर्ति’ जैसी अवधारणाएँ भी दंड व्यवस्था का अभिन्न अंग रही हैं। ‘प्रायश्चित’ अपराधी को आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। यह केवल बाह्य दंड नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसी प्रकार ‘क्षतिपूर्ति’ पीड़ित के नुकसान की भरपाई के माध्यम से सामाजिक संबंधों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है। इन अवधारणाओं में आधुनिक ‘सुधारात्मक न्याय’ के मूल तत्त्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जहाँ अपराध को केवल कानून के उल्लंघन के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्ति, पीड़ित और समुदाय के मध्य संबंधों के विघटन के रूप में समझा जाता है।

आधुनिक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में दंड व्यवस्था को लेकर गंभीर विमर्श चल रहा है। जेल प्रणाली की प्रभावशीलता, अपराधियों की पुनरावृत्ति और कारावास के मानवीय पहलुओं पर प्रश्न उठ रहे हैं। अनेक देशों में यह अनुभव किया गया है कि केवल कारावास-आधारित दंड प्रणाली अपराध को समाप्त करने में पर्याप्त नहीं है। अपराधी अक्सर समाज से और अधिक कट जाता है, जिससे पुनः अपराध की संभावना बढ़ जाती है। इसी पृष्ठभूमि में सुधारात्मक न्याय की अवधारणा उभरकर सामने आई है, जो संवाद, सामंजस्य, पुनर्स्थापन और सामुदायिक सहभागिता पर बल देती है।

भारतीय न्यायशास्त्र की परंपरा इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक प्रतीत होती है। यहाँ दंड को केवल प्रतिशोधात्मक साधन के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक पुनर्संतुलन और सामाजिक पुनर्गठन के माध्यम के रूप में देखा गया है। प्राचीन भारतीय चिंतन में न्याय का आधार ‘धर्म’ था, जो विधिक नियमों से परे

नैतिकता, कर्तव्य और समरसता को महत्व देता है। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण में दंड और सुधार परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।

समकालीन भारत में भी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, लोक अदालतें और सामुदायिक न्याय की पहलें सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों की ओर संकेत करती हैं। यद्यपि आधुनिक विधिक संरचना औपनिवेशिक प्रभाव से निर्मित है, तथापि भारतीय सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत न्याय के अधिक मानवीय और सहभागी मॉडल की ओर प्रेरित करती है। वर्तमान समय में जब विश्व स्तर पर न्याय प्रणाली को अधिक संवेदनशील और पुनर्स्थापनात्मक बनाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, तब भारतीय न्यायशास्त्र की ‘दंड’ संबंधी अवधारणा एक वैकल्पिक बौद्धिक आधार प्रदान कर सकती है।

भारतीय परंपरा में दंड की अवधारणा और आधुनिक सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों के मध्य अंतर्संबंधों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि भारतीय न्यायशास्त्र की दार्शनिक नींव में सुधार, पुनर्संतुलन और सामंजस्य के तत्व निहित हैं। इस प्रस्तावना के माध्यम से यह प्रतिपादित किया जाता है कि भारतीय न्याय परंपरा को पुनर्पाठ और पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है, ताकि वह समकालीन वैश्विक न्याय विमर्श में रचनात्मक योगदान दे सके।

### दंड का दार्शनिक आधार: धर्म और दंड का अंतर्संबंध

भारतीय न्यायशास्त्र में ‘दंड’ की अवधारणा को समझने के लिए उसके दार्शनिक आधार ‘धर्म’ का विश्लेषण अनिवार्य है। भारतीय चिंतन परंपरा में दंड राजा की व्यक्तिगत शक्ति या प्रतिशोध का उपकरण नहीं है, बल्कि वह ‘धर्म’ की रक्षा और सामाजिक संतुलन की स्थापना का माध्यम है। यहाँ ‘धर्म’ केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि वह नैतिकता, कर्तव्य, न्याय, सामाजिक उत्तरदायित्व और समष्टिगत कल्याण का व्यापक सिद्धांत है। इस प्रकार दंड और धर्म का संबंध अभिन्न और परस्पर पूरक है।

प्राचीन ग्रंथों में दंड को एक दैवीय शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जो अधर्म का नाश करती है और समाज में न्याय की स्थापना करती है। मनुस्मृति में दंड को धर्म का संरक्षक बताया गया है। वहाँ प्रसिद्ध श्लोक आता है-

“दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा दंड एवाभिरक्षति।

दंडः सुमेषु जागर्ति दंडं धर्मं विदुर्बुधाः॥”

अर्थात् दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है, दंड ही सबकी रक्षा करता है, जब सब सो जाते हैं तब दंड ही जागता है, ज्ञानीजन दंड को ही धर्म मानते हैं। इस कथन में दंड को मात्र दमनकारी शक्ति नहीं, बल्कि सतत जागरूक नैतिक संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दंड यहाँ विधि और व्यवस्था की आत्मा है, जो समाज को अराजकता से बचाती है।

भारतीय दर्शन में ‘मत्स्य न्याय’ की अवधारणा का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है – शक्तिशाली द्वारा निर्बल का भक्षण। यदि दंड व्यवस्था न हो, तो समाज में यही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए दंड को सामाजिक न्याय की रीढ़ माना गया। किंतु यह भी स्पष्ट किया गया कि दंड का प्रयोग धर्मसम्मत और संतुलित होना चाहिए। यदि दंड अन्यायपूर्ण हो जाए, तो वह स्वयं अधर्म का रूप ले लेता है।

अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने दंडनीति को राज्य-व्यवस्था का मूल आधार बताया है। उनके अनुसार राजा ‘दंडधारक’ है, किंतु दंड का स्वामी नहीं। वह दंड का प्रयोग धर्म और लोककल्याण के लिए करता है। कौटिल्य ने दंड के तीन प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की – (1) अपराध का निवारण, (2) अपराधी का अनुशासन और (3) समाज में व्यवस्था की स्थापना। वे चेतावनी देते हैं कि अत्यधिक कठोर दंड प्रजा में भय और असंतोष उत्पन्न करता है, जबकि अत्यधिक शिथिलता अराजकता को जन्म देती है। इसलिए ‘सम्यक् दंड’ ही न्यायोचित है।

यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि दंड का दार्शनिक आधार संतुलन और न्याय है। दंड धर्म का उपकरण है, न कि राजा की निरंकुश इच्छा। भारतीय चिंतन में राजा को ‘राजऋषि’ के आदर्श से जोड़ा गया है – अर्थात् वह शक्ति और नैतिकता का समन्वय है। यदि राजा अधर्मपूर्वक दंड देता है, तो वह स्वयं पाप का भागी बनता है। इस प्रकार दंड की वैधता धर्म के पालन पर निर्भर करती है।

महाभारत में राजधर्म और दंडनीति पर विस्तृत विमर्श मिलता है। भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों में यह प्रतिपादित किया गया है कि राजा का दायित्व केवल अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि न्याय और करुणा के संतुलन के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना करना है। यहाँ दंड और क्षमा दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया है। यह संतुलन ही दंड को प्रतिशोधात्मक होने से रोकता है और उसे नैतिक औचित्य प्रदान करता है।

भारतीय दर्शन में दंड का एक और महत्वपूर्ण आयाम है – आत्मानुशासन। उपनिषदों और स्मृति ग्रंथों में ‘दम’ (संयम) को मनुष्य के आंतरिक विकास का साधन बताया गया है। बाह्य दंड व्यवस्था उसी आंतरिक अनुशासन की सामाजिक अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति स्वयं धर्म का पालन करता है, तब बाह्य दंड की आवश्यकता कम हो जाती है। इस प्रकार आदर्श स्थिति में दंड का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मानुशासन की ओर प्रेरित करना है।

धर्म और दंड के इस अंतर्संबंध में सुधारात्मक न्याय के तत्व भी निहित हैं। भारतीय परंपरा में ‘प्रायश्चित्त’ की व्यवस्था अपराधी को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करती है। यह मान्यता है कि मनुष्य परिवर्तनशील है और उसे अपने कृत्यों का प्रायश्चित्त कर पुनः समाज में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त करने का अधिकार है। इसी प्रकार ‘क्षतिपूर्ति’ की अवधारणा पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करती है। यह दृष्टिकोण आधुनिक

सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों से मेल खाता है, जहाँ अपराध को केवल विधि-भंग नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों के विघटन के रूप में देखा जाता है।

समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब दंड व्यवस्था की आलोचना हो रही है विशेषकर कारावास-आधारित प्रणाली की तब भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण प्रासंगिक प्रतीत होता है। यहाँ दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि नैतिक पुनर्संतुलन और सामाजिक समरसता है। दंड और धर्म का यह अंतर्संबंध न्याय को अधिक मानवीय और संतुलित बनाता है।

भारतीय न्यायशास्त्र में दंड का दार्शनिक आधार गहन नैतिकता और धर्म पर आधारित है। दंड को एक दैवीय और नैतिक शक्ति के रूप में देखा गया है, जो अधर्म का नाश कर समाज में न्याय और संतुलन स्थापित करती है। यह अवधारणा आधुनिक सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक सांस्कृतिक और दार्शनिक आधार प्रदान करती है, जहाँ दंड केवल दमन का साधन न होकर सुधार, पुनर्स्थापन और सामंजस्य का माध्यम बन सकता है।

### दंड के प्रकार और वर्गीकरण

भारतीय न्यायशास्त्र में ‘दंड’ की अवधारणा केवल दमनात्मक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह एक सुविचारित, संतुलित और नैतिक व्यवस्था का अंग है। प्राचीन स्मृतिकारों और आचार्यों ने दंड को अपराध की प्रकृति, अपराधी की मंशा, सामाजिक स्थिति, परिस्थितियों तथा पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर वर्गीकृत किया। इस प्रकार दंड का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार, निवारण और सामाजिक संतुलन की पुनर्स्थापना था।

विशेष रूप से मनुस्मृति तथा अन्य स्मृति ग्रंथों में दंड के चार प्रमुख प्रकारों का उल्लेख मिलता है— वाक्-दंड, धिक्-दंड, धन-दंड और वध-दंड। यह वर्गीकरण दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय विधि-चिंतन में ‘क्रमिक दंड’ (Gradation of Punishment) की अवधारणा विद्यमान थी, जहाँ अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड की तीव्रता निर्धारित की जाती थी।

**1. वाक्-दंड: चेतावनी द्वारा सुधार:-** वाक्-दंड दंड का सबसे हल्का और प्रारंभिक रूप है। इसमें अपराधी को कठोर शब्दों, चेतावनी या उपदेश के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया जाता है। यह दंड उन परिस्थितियों में दिया जाता था, जहाँ अपराध लघु, अनजाने में किया गया या प्रथम बार हुआ हो।

वाक्-दंड का मूल उद्देश्य अपराधी के भीतर नैतिक चेतना जागृत करना था। भारतीय दर्शन में यह विश्वास था कि मनुष्य मूलतः सुधार योग्य है। यदि उसे अपने कृत्य की अनुचितता का बोध करा दिया जाए, तो वह पुनः अपराध करने से बच सकता है। इस दृष्टि से वाक्-दंड सुधारात्मक न्याय की

प्रथम सीढ़ी है। यह दंड सामाजिक और नैतिक अनुशासन का प्रतीक है, जहाँ दंड का स्वरूप शिक्षाप्रद है, न कि प्रतिशोधात्मक। आधुनिक न्याय प्रणाली में इसे चेतावनी, परामर्श या परिवीक्षा (Probation) के समकक्ष माना जा सकता है।

2. **धिक्-दंड: सार्वजनिक निंदा या धिक्कार:-** धिक्-दंड वाक्-दंड से एक स्तर ऊपर है। इसमें अपराधी की सार्वजनिक निंदा या सामाजिक धिक्कार किया जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण थी, अतः सार्वजनिक आलोचना स्वयं में एक प्रभावशाली दंड मानी जाती थी।

इस दंड का उद्देश्य अपराधी को उसके कृत्य के सामाजिक प्रभाव का बोध कराना था। जब समाज के समक्ष उसके आचरण की निंदा की जाती थी, तो वह आत्मग्लानि अनुभव करता और सुधार की दिशा में प्रेरित होता। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि धिक्-दंड में शारीरिक या आर्थिक क्षति नहीं होती, यह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर प्रभाव डालता है। आधुनिक संदर्भ में इसे सामुदायिक सेवा या सार्वजनिक माफी जैसी व्यवस्थाओं से जोड़ा जा सकता है। धिक्-दंड का तात्पर्य अपमानित करना नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का स्मरण कराना था। यह दंड सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक नैतिकता को सुदृढ़ करता था।

3. **धन-दंड: आर्थिक जुर्माना:-** धन-दंड प्राचीन भारतीय न्याय प्रणाली में अत्यंत प्रचलित था। इसमें अपराधी से आर्थिक दंड के रूप में जुर्माना लिया जाता था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विभिन्न अपराधों के लिए निर्धारित धन-दंड का विस्तृत विवरण दिया है।

धन-दंड का उद्देश्य दोहरा था-

- अपराधी को आर्थिक हानि के माध्यम से अनुशासित करना।
- पीड़ित या राज्य को हुए नुकसान की आंशिक भरपाई करना।

यहाँ ‘क्षतिपूर्ति’ की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो आधुनिक सुधारात्मक न्याय का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अपराध को केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, बल्कि पीड़ित के विरुद्ध भी माना गया, और धन-दंड के माध्यम से उस हानि की पूर्ति का प्रयास किया गया। धन-दंड का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उसकी मात्रा अपराधी की आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती थी। इससे न्याय में समता और संतुलन बना रहता था। यह सिद्धांत आज के ‘समानुपातिकता’ (Proportionality) सिद्धांत के अनुरूप है।

4. **वध-दंड: शारीरिक दंड या कारावास:-** वध-दंड दंड का सबसे कठोर रूप है। इसमें शारीरिक दंड, कारावास या मृत्यु-दंड सम्मिलित हो सकते हैं। यह दंड उन अपराधों के लिए निर्धारित था,

जो अत्यंत गंभीर और समाज के लिए घातक माने जाते थे। जैसे राजद्रोह, हत्या या घोर हिंसात्मक अपराध। हालाँकि, प्राचीन ग्रंथों में यह स्पष्ट निर्देश है कि वध-दंड अंतिम उपाय के रूप में ही प्रयोग किया जाए। इसका उद्देश्य समाज की रक्षा और अपराध के निवारण तक सीमित था।

महाभारत में भी दंड और क्षमा के संतुलन पर बल दिया गया है। भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को यह उपदेश दिया गया कि राजा को दंड देते समय धर्म, करुणा और न्याय का समन्वय करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि कठोर दंड भी धर्मसम्मत और विवेकपूर्ण होना चाहिए।

### दंड की क्रमिकता और सुधारात्मक दृष्टिकोण

उपरोक्त चारों दंड-प्रकारों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय न्याय प्रणाली में ‘क्रमिक दंड’ की अवधारणा थी। अपराधी को सीधे कठोरतम दंड देने के बजाय पहले उसे चेतावनी, सामाजिक निंदा या आर्थिक दंड के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया जाता था।

यह क्रमिकता निम्न सिद्धांतों पर आधारित थी-

- अपराध की गंभीरता
- अपराधी की मंशा (Intent)
- अपराधी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति
- पुनरावृत्ति की संभावना

यह दृष्टिकोण आधुनिक सुधारात्मक न्याय के मूल सिद्धांतों से मेल खाता है। सुधारात्मक न्याय अपराधी, पीड़ित और समुदाय के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। प्राचीन भारतीय दंड-व्यवस्था में भी यही उद्देश्य निहित था। अपराधी को सुधारना, पीड़ित को संतोष देना और समाज में समरसता पुनर्स्थापित करना।

### दंड और नैतिक पुनर्संतुलन

भारतीय न्यायशास्त्र में दंड को नैतिक पुनर्संतुलन का साधन माना गया। यह केवल विधिक दायित्व नहीं, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व भी था। ‘प्रायश्चित्त’ और ‘क्षतिपूर्ति’ जैसी व्यवस्थाएँ दंड को आंतरिक आत्मशुद्धि और सामाजिक पुनर्स्थापन से जोड़ती थीं। इस प्रकार दंड का अंतिम लक्ष्य ‘धर्म’ की स्थापना और ‘मत्स्य न्याय’ की रोकथाम था। दंड के वर्गीकरण से स्पष्ट है कि भारतीय विधि-चिंतन में मानवीयता और संतुलन को प्राथमिकता दी गई।

आधुनिक समय में जब जेल प्रणाली की सीमाएँ स्पष्ट हो रही हैं और अपराधियों के पुनर्वास पर बल दिया जा रहा है, तब प्राचीन भारतीय दंड-वर्गीकरण अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। यह मॉडल हमें सिखाता

है कि दंड का उद्देश्य केवल भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि नैतिक सुधार और सामाजिक संतुलन स्थापित करना है।

वाक्-दंड से लेकर वध-दंड तक की यह क्रमिक व्यवस्था भारतीय न्यायशास्त्र की परिपक्वता और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसमें दंड और सुधार का संतुलन निहित है, जो आधुनिक सुधारात्मक न्याय के लिए एक सांस्कृतिक और दार्शनिक आधार प्रदान करता है।

### सुधारात्मक न्याय और ‘प्रायश्चित’ की अवधारणा

आधुनिक वैश्विक न्याय विमर्श में ‘सुधारात्मक न्याय’ (Restorative Justice) की अवधारणा तेजी से उभर रही है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि अपराध केवल विधि या राज्य के विरुद्ध किया गया कृत्य नहीं है, बल्कि वह मानवीय संबंधों, सामाजिक विश्वास और सामुदायिक संतुलन को क्षति पहुँचाता है। अतः न्याय का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि उस क्षति की भरपाई करना, पीड़ित को संतोष प्रदान करना और अपराधी को पुनः समाज में समाहित करना होना चाहिए।

भारतीय न्यायशास्त्र में ‘प्रायश्चित’ की अवधारणा इसी प्रकार की पुनर्स्थापनात्मक दृष्टि को अभिव्यक्त करती है। यहाँ अपराध को केवल विधिक दोष नहीं, बल्कि नैतिक विचलन और सामाजिक असंतुलन के रूप में देखा गया है। ‘प्रायश्चित’ का शाब्दिक अर्थ है-किए गए पाप या अपराध के लिए पश्चात्ताप करना और उसके प्रायशोधन हेतु उचित आचरण अपनाना। इस प्रकार यह दंड का एक आंतरिक, नैतिक और सुधारात्मक रूप है।

**1. प्रायश्चित का दार्शनिक आधार:-** भारतीय परंपरा में धर्म, कर्म और उत्तरदायित्व की अवधारणाएँ परस्पर संबद्ध हैं। व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। यदि वह अधर्म करता है, तो उसका नैतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव की शुद्धि के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था की गई।

मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए प्रायश्चित के विधान दिए गए हैं। वहाँ दंड का उद्देश्य केवल दमन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य स्मृतियों में भी प्रायश्चित की विस्तृत चर्चा मिलती है। इन ग्रंथों में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य त्रुटिपूर्ण हो सकता है, किंतु उसे सुधार और पुनर्स्थापन का अवसर मिलना चाहिए। यह दृष्टिकोण आधुनिक सुधारात्मक न्याय के उस सिद्धांत से मेल खाता है, जिसमें अपराधी को ‘दोषी’ के रूप में स्थायी रूप से कलंकित करने के बजाय उसे सुधार योग्य व्यक्ति माना जाता है।

2. **आत्म-शुद्धिकरण (Moral Purification):-** प्रायश्चित का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आयाम है-आत्म-शुद्धिकरण। इसका उद्देश्य अपराधी के भीतर पश्चात्ताप और नैतिक जागृति उत्पन्न करना है। जब अपराधी अपने कृत्य की गंभीरता को समझता है और उसके परिणामों को स्वीकार करता है, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है।

प्रायश्चित में उपवास, तप, दान, जप, प्रार्थना अथवा सामाजिक सेवा जैसे उपायों का उल्लेख मिलता है। इनका उद्देश्य केवल बाह्य कष्ट देना नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और आत्मबोध को विकसित करना है।

आधुनिक सुधारात्मक न्याय भी इसी सिद्धांत पर आधारित है कि अपराधी को अपने कृत्य के परिणामों का सामना करना चाहिए। ‘Victim-Offender Mediation’ जैसे कार्यक्रमों में अपराधी और पीड़ित के बीच संवाद स्थापित किया जाता है, जिससे अपराधी को अपने कृत्य की मानवीय क्षति का बोध हो। भारतीय प्रायश्चित की अवधारणा इस आत्म-स्वीकार और आत्म-परिवर्तन की प्रक्रिया को पहले से ही मान्यता देती रही है।

3. **सामाजिक पुनर्गठन (Social Reintegration):-** प्रायश्चित का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है-सामाजिक पुनर्गठन। प्राचीन भारतीय समाज में यह व्यवस्था थी कि यदि अपराधी ने निर्धारित प्रायश्चित पूरा कर लिया, तो समाज उसे पुनः स्वीकार कर लेता था। इससे वह स्थायी अपराधी बनने से बच जाता था।

- महाभारत में भी कई प्रसंग ऐसे मिलते हैं, जहाँ अपराध या पाप के पश्चात प्रायश्चित के माध्यम से पुनर्स्थापन की प्रक्रिया दिखाई देती है। वहाँ यह विचार स्पष्ट है कि मनुष्य को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए। यह सामाजिक पुनर्गठन आधुनिक सुधारात्मक न्याय का केंद्रीय तत्व है। आज की कारावास-आधारित प्रणाली में अपराधी अक्सर समाज से कट जाता है और ‘कलंक’ का शिकार बनता है। परिणामस्वरूप वह पुनः अपराध की ओर प्रवृत्त हो सकता है। इसके विपरीत, प्रायश्चित-आधारित मॉडल अपराधी को पुनः समाज का अंग बनने का अवसर देता है।

4. **क्षतिपूर्ति और बहाली:-** भारतीय न्यायशास्त्र में प्रायश्चित केवल आत्मिक शुद्धि तक सीमित नहीं था, उसमें ‘क्षतिपूर्ति’ का भी तत्व निहित था। यदि किसी अपराध से किसी व्यक्ति को हानि पहुँची है, तो उसकी भरपाई करना आवश्यक माना गया। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि अपराध से हुई आर्थिक या शारीरिक हानि की पूर्ति करना न्याय का अभिन्न अंग है। यह सिद्धांत आधुनिक Restorative Justice के उस विचार से मेल खाता है, जिसमें पीड़ित की संतुष्टि और

हानि-पूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार प्रायश्चित्त अपराधी, पीड़ित और समाज तीनों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

5. **दंड और प्रायश्चित्त का अंतर्संबंध:-** भारतीय न्यायशास्त्र में दंड और प्रायश्चित्त परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। दंड बाह्य अनुशासन का साधन है, जबकि प्रायश्चित्त आंतरिक परिवर्तन का माध्यम। यदि दंड केवल बाह्य नियंत्रण तक सीमित रह जाए और आंतरिक सुधार न हो, तो अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहती है। इस दृष्टि से प्रायश्चित्त दंड की मानवीय और नैतिक पूरकता है। यह अपराधी को यह संदेश देता है कि समाज उसे सुधार का अवसर देने को तैयार है, बशर्ते वह अपनी गलती स्वीकार करे और उसे सुधारने का प्रयास करे।
6. **समकालीन संदर्भ में प्रासंगिकता:-** आज विश्वभर में कारागारों की बढ़ती संख्या, पुनरावृत्ति दर और कारावास की अमानवीय स्थितियों पर गंभीर पश्च उठ रहे हैं। सुधारात्मक न्याय इस समस्या का एक वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करता है। भारतीय ‘प्रायश्चित्त’ की अवधारणा इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। यह न केवल अपराधी के नैतिक रूपांतरण पर बल देती है, बल्कि समाज को भी उत्तरदायी बनाती है कि वह सुधार के पश्चात अपराधी को पुनः स्वीकार करे। यदि आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था में प्रायश्चित्त की मूल भावना आत्म-शुद्धिकरण, क्षतिपूर्ति और सामाजिक पुनर्गठन को समुचित रूप से समाहित किया जाए, तो न्याय अधिक मानवीय, सहभागी और प्रभावी बन सकता है।

भारतीय न्यायशास्त्र में ‘प्रायश्चित्त’ की अवधारणा आधुनिक सुधारात्मक न्याय की पूर्वपीठिका के रूप में देखी जा सकती है। यहाँ अपराध को केवल विधिक दोष नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक विचलन माना गया है।

प्रायश्चित्त के माध्यम से-

- अपराधी को आत्म-शुद्धिकरण का अवसर मिलता है,
- पीड़ित को क्षतिपूर्ति और संतोष प्राप्त होता है,
- समाज में पुनर्संतुलन और समरसता स्थापित होती है।

इस प्रकार भारतीय परंपरा का यह दृष्टिकोण न्याय को दमनात्मक न बनाकर पुनर्स्थापनात्मक बनाता है। यह मॉडल आधुनिक वैश्विक न्याय प्रणाली के लिए एक सांस्कृतिक और दार्शनिक आधार प्रदान करता है, जहाँ दंड का अंतिम लक्ष्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार, बहाली और सामाजिक सामंजस्य है।

## कौटिल्य का अर्थशास्त्र: व्यावहारिक न्याय और क्षतिपूर्ति

भारतीय न्यायशास्त्र की परंपरा में अर्थशास्त्र एक अद्वितीय और अत्यंत व्यावहारिक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके रचयिता कौटिल्य (चाणक्य) ने दंडनीति को केवल सैद्धांतिक या नैतिक विमर्श तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे राज्य-प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था का व्यावहारिक आधार बनाया। कौटिल्य के अनुसार ‘दंड’ ही वह साधन है, जिसके माध्यम से राज्य ‘नीति’ की स्थापना करता है और ‘धर्म’ की रक्षा करता है। किंतु उनके यहाँ दंड का अर्थ मात्र कठोर दमन नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित, संतुलित और लोककल्याणकारी न्याय है।

1. **दंड और नीति का संबंध:-** कौटिल्य ने दंड को ‘राज्य का प्राण’ कहा है। उनका मत था कि यदि दंड व्यवस्था शिथिल हो जाए, तो समाज में ‘मत्स्य न्याय’ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जहाँ शक्तिशाली निर्बलों का शोषण करेंगे। इस प्रकार दंड केवल अपराध-दमन का उपकरण नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और विधि-शासन (Rule of Law) का आधार है। किन्तु कौटिल्य की दंडनीति में अंधाधुंध कठोरता नहीं है। वे दंड के प्रयोग में विवेक, परिस्थिति और अनुपात (Proportionality) का विशेष ध्यान रखते हैं। अपराध की प्रकृति, अपराधी की मंशा, हानि की मात्रा और सामाजिक प्रभाव इन सभी को ध्यान में रखकर दंड निर्धारित किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण आधुनिक अपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों से मेल खाता है।

2. **क्षतिपूर्ति (Restitution) की अवधारणा:-** कौटिल्य के अर्थशास्त्र की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है – ‘क्षतिपूर्ति’ पर उनका विशेष बल। उनके अनुसार अपराध से हुई हानि की पूर्ति करना न्याय का अनिवार्य अंग है। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति चोरी हो जाती थी, तो चोर से न केवल वस्तु की वापसी, बल्कि अतिरिक्त जुर्माना भी लिया जाता था।

विशेष रूप से यह प्रावधान उल्लेखनीय है कि यदि राजा या राज्य प्रशासन चोर को पकड़ने में असफल रहता था, तो राज्य के कोष से पीड़ित को मुआवजा दिया जाता था। यह व्यवस्था इस विचार पर आधारित थी कि राज्य का दायित्व केवल अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। यदि राज्य इस कर्तव्य में विफल रहता है, तो उसे पीड़ित की क्षति की भरपाई करनी चाहिए।

यह सिद्धांत आधुनिक ‘Victim Compensation Schemes’ का प्राचीनतम रूप माना जा सकता है। आज अनेक देशों में यदि अपराधी से क्षतिपूर्ति संभव न हो, तो राज्य पीड़ित को मुआवजा प्रदान करता है। कौटिल्य का यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि भारतीय न्यायशास्त्र में पीड़ित-केंद्रित न्याय (Victim-Centric Justice) की भावना प्राचीन काल से विद्यमान थी।

3. **पीड़ित-केंद्रित न्याय और सामाजिक उत्तरदायित्व:-** अर्थशास्त्र में दंड व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अपराध को केवल राज्य के विरुद्ध अपराध नहीं माना गया, बल्कि उसे पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध हानि के रूप में भी देखा गया। इसीलिए क्षतिपूर्ति को प्राथमिकता दी गई। कौटिल्य ने स्पष्ट किया कि राज्य का कर्तव्य है—

- प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करना,
- अपराध की रोकथाम करना,
- और अपराध से उत्पन्न हानि की पूर्ति करना।

यदि राज्य सुरक्षा देने में असफल हो, तो वह उत्तरदायी है। यह विचार आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप है, जहाँ राज्य नागरिकों के जीवन, संपत्ति और गरिमा की रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है।

4. **व्यावहारिक न्याय (Pragmatic Justice):-** कौटिल्य का न्याय-दर्शन अत्यंत व्यावहारिक है। वे आदर्शवाद से अधिक व्यवहारिकता पर बल देते हैं। उदाहरण के लिए, चोरी, धोखाधड़ी, हिंसा और राजद्रोह जैसे अपराधों के लिए अलग-अलग दंड निर्धारित किए गए। दंड की मात्रा अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों के अनुसार बदलती थी।

अर्थशास्त्र में दंड को चार प्रमुख उद्देश्यों से जोड़ा गया-

1. निवारण (Deterrence)
2. प्रतिकार (Retribution)
3. सुधार (Reformation)
4. क्षतिपूर्ति (Restitution)

इन चारों उद्देश्यों का संतुलन ही न्याय को प्रभावी बनाता है। विशेष रूप से क्षतिपूर्ति का तत्व आधुनिक सुधारात्मक न्याय (Restorative Justice) से सीधा संबंध रखता है।

5. **दंड की अनुपातिकता और समानता:-** कौटिल्य ने दंड निर्धारण में अनुपातिकता का सिद्धांत अपनाया। यदि अपराधी आर्थिक रूप से सक्षम है, तो उससे अधिक धन-दंड लिया जा सकता है; यदि वह निर्धन है, तो दंड की प्रकृति भिन्न हो सकती है। इससे न्याय में संतुलन बना रहता है।

हालाँकि प्राचीन समाज में वर्ण-व्यवस्था का प्रभाव था, फिर भी अर्थशास्त्र में प्रशासनिक दृष्टि से निष्पक्षता और व्यवस्था बनाए रखने पर बल दिया गया। राज्य का उद्देश्य सामाजिक शांति और आर्थिक स्थिरता था।

6. . **आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता:-** समकालीन अपराधिक न्याय प्रणाली में यह आलोचना की जाती है कि वह अपराधी-केंद्रित है और पीड़ित की उपेक्षा करती है। अनेक मामलों में पीड़ित को न्यायिक प्रक्रिया से पर्याप्त संतोष नहीं मिलता। इस पृष्ठभूमि में कौटिल्य की क्षतिपूर्ति-आधारित व्यवस्था अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होती है।

आज भारत सहित कई देशों में पीड़ित मुआवजा योजनाएँ (Victim Compensation Schemes) लागू हैं, जिनके अंतर्गत राज्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। कौटिल्य का सिद्धांत इस विचार की ऐतिहासिक जड़ों को स्पष्ट करता है कि राज्य नागरिकों की सुरक्षा का संरक्षक है और उसकी विफलता की स्थिति में वह उत्तरदायी है।

7. **सुधारात्मक न्याय से साम्य:-** आधुनिक सुधारात्मक न्याय (Restorative Justice) का मुख्य उद्देश्य अपराधी, पीड़ित और समुदाय के मध्य संतुलन स्थापित करना है। कौटिल्य की क्षतिपूर्ति-व्यवस्था इस संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- अपराधी को दंडित किया जाता है,
- पीड़ित को क्षति-पूर्ति दी जाती है,
- और समाज में व्यवस्था पुनः स्थापित होती है।

इस प्रकार अर्थशास्त्र का मॉडल दंड और बहाली (Restoration) दोनों का समन्वय प्रस्तुत करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय न्यायशास्त्र में व्यावहारिक और संतुलित दंडनीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें दंड को ‘नीति’ और ‘राजधर्म’ का आधार माना गया है, परंतु उसका उद्देश्य केवल भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता और लोककल्याण सुनिश्चित करना है।

क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में पीड़ित के अधिकारों को गंभीरता से लिया जाता था। यदि अपराधी उपलब्ध न हो, तो राज्य स्वयं उत्तरदायित्व स्वीकार करता था। यह व्यवस्था आधुनिक Victim Compensation Schemes का प्राचीन रूप है और सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ी हुई है।

कौटिल्य की दंडनीति न केवल अपने समय के लिए प्रासंगिक थी, बल्कि आज के वैश्विक न्याय विमर्श में भी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। इसमें दंड, नीति, क्षतिपूर्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व का जो संतुलित समन्वय है, वह न्याय को अधिक मानवीय, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान करता है।

## तुलनात्मक विश्लेषण: प्राचीन भारतीय न्याय बनाम आधुनिक पाश्चात्य न्याय

भारतीय न्यायशास्त्र में ‘दंड’ की अवधारणा और आधुनिक पाश्चात्य (Traditional Western) न्याय प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण वैचारिक एवं संरचनात्मक अंतर दिखाई देता है। जहाँ प्राचीन भारतीय न्याय का आधार ‘धर्म’, नैतिकता और सामाजिक संतुलन है, वहीं आधुनिक पारंपरिक पाश्चात्य न्याय प्रणाली मुख्यतः विधि-प्रवर्तन (Law Enforcement) और दंडात्मक व्यवस्था पर केंद्रित रही है। यह तुलनात्मक अध्ययन दोनों दृष्टिकोणों के उद्देश्यों, केंद्र-बिंदुओं, प्रक्रियाओं और दार्शनिक आधारों की विवेचना करता है।

**1. उद्देश्य: धर्म की स्थापना बनाम कानून का प्रवर्तन:-** प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र का मूल उद्देश्य ‘धर्म’ की स्थापना और सामाजिक संतुलन की पुनर्स्थापना था। ‘धर्म’ का अर्थ यहाँ केवल धार्मिक आचरण नहीं, बल्कि न्याय, नैतिकता, कर्तव्य और लोककल्याण का समन्वित सिद्धांत है। मनुस्मृति तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में दंड को धर्म का रक्षक माना गया है। दंड का अंतिम लक्ष्य अपराधी के आत्म-सुधार और समाज में संतुलन की स्थापना था। इसके विपरीत, आधुनिक पारंपरिक पाश्चात्य न्याय प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य कानून का प्रवर्तन (Enforcement of Law) और अपराधी को दंडित करना है। यहाँ अपराध को मुख्यतः राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है। न्यायालय का ध्यान इस बात पर होता है कि विधि का उल्लंघन हुआ है या नहीं, और यदि हुआ है, तो उसके लिए निर्धारित सजा क्या होगी। इस प्रणाली में नैतिक या आध्यात्मिक सुधार की अपेक्षा विधिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी जाती है।

**2. केंद्र-बिंदु: अपराधी-पीड़ित संतुलन बनाम राज्य-अपराधी संबंध:-** भारतीय न्यायशास्त्र में अपराध को केवल राज्य के विरुद्ध कृत्य नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज के विरुद्ध नैतिक दोष के रूप में देखा गया। इसीलिए यहाँ पीड़ित की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। ‘क्षतिपूर्ति’ और ‘प्रायश्चित्त’ जैसी अवधारणाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि न्याय का उद्देश्य पीड़ित की हानि की पूर्ति और अपराधी के सुधार दोनों को ध्यान में रखना था।

अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने स्पष्ट किया कि यदि अपराधी पकड़ा न जाए, तो राज्य को स्वयं पीड़ित को मुआवजा देना चाहिए। यह दृष्टिकोण पीड़ित-केंद्रित न्याय की भावना को दर्शाता है। इसके विपरीत, आधुनिक पारंपरिक पाश्चात्य न्याय में अपराध को ‘State vs. Accused’ के रूप में देखा जाता है। मुकदमे का शीर्षक भी प्रायः राज्य के नाम से प्रारंभ होता है। पीड़ित की भूमिका सीमित होती है, और उसका स्थान अक्सर गवाह तक सीमित रह जाता है। न्याय का केंद्र-बिंदु अपराधी और राज्य के मध्य विधिक संबंध होता है, न कि अपराधी और पीड़ित के मध्य नैतिक या सामाजिक संबंध।

3. **प्रक्रिया: प्रायश्चित और सामाजिक मेल-मिलाप बनाम मुकदमेबाजी और कारावास:-** भारतीय परंपरा में न्याय की प्रक्रिया अधिक सामुदायिक और नैतिक थी। पंचायत, सभा और कुल-परिषद जैसी संस्थाएँ विवादों का समाधान करती थीं। ‘प्रायश्चित’ के माध्यम से अपराधी को आत्म-शुद्धि का अवसर दिया जाता था, और ‘क्षतिपूर्ति’ द्वारा पीड़ित को संतोष प्रदान किया जाता था। यह प्रक्रिया संवाद, मेल-मिलाप और सामाजिक पुनर्स्थापन पर आधारित थी। अपराधी को समाज से बहिष्कृत करने के बजाय उसे सुधार के पश्चात पुनः स्वीकार करने की परंपरा थी। इस प्रकार न्याय का स्वरूप सहभागी (Participatory) और पुनर्स्थापनात्मक (Restorative) था। इसके विपरीत, आधुनिक पारंपरिक पाश्चात्य न्याय प्रणाली मुख्यतः औपचारिक मुकदमेबाजी (Litigation) और कारावास (Imprisonment) पर आधारित है। न्यायालय में विधिक प्रक्रिया, साक्ष्य, गवाह और वकीलों की दलीलों के आधार पर निर्णय होता है। यदि अपराध सिद्ध हो जाए, तो प्रायः कारावास या जुर्माना दिया जाता है।

इस प्रक्रिया में संवाद और मेल-मिलाप की संभावना सीमित होती है। अपराधी को समाज से अलग कर दिया जाता है, जिससे उसके पुनर्समाजीकरण (Reintegration) में कठिनाई आती है।

4. **दार्शनिक आधार: नैतिकता बनाम विधिक औपचारिकता:-** भारतीय न्यायशास्त्र का आधार दार्शनिक और नैतिक है। यहाँ न्याय का संबंध ‘धर्म’ और ‘कर्म’ से जुड़ा है। व्यक्ति अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है और उसे आत्म-सुधार का अवसर मिलना चाहिए। दंड का उद्देश्य नैतिक पुनर्संतुलन है। इसके विपरीत, आधुनिक पाश्चात्य न्याय प्रणाली का आधार विधिक औपचारिकता (Legal Formalism) और संवैधानिक सिद्धांत हैं। यहाँ न्याय का मापदंड विधि की व्याख्या और उसका अनुपालन है। नैतिकता व्यक्तिगत क्षेत्र में मानी जाती है, जबकि न्यायालय विधिक नियमों के पालन तक सीमित रहते हैं।

5. **सुधारात्मक न्याय की ओर संक्रमण:-** हालाँकि पारंपरिक पाश्चात्य न्याय प्रणाली दंडात्मक रही है, परंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ‘Restorative Justice’ की अवधारणा विकसित हुई है। यह दृष्टिकोण अपराधी, पीड़ित और समुदाय के मध्य संवाद और मेल-मिलाप पर बल देता है।

दिलचस्प तथ्य यह है कि यह आधुनिक सुधारात्मक न्याय, अनेक दृष्टियों से, प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र की मूल भावना से साम्य रखता है। भारतीय परंपरा में जो तत्व ‘प्रायश्चित’, ‘क्षतिपूर्ति’ और सामाजिक पुनर्स्वीकृति के रूप में विद्यमान थे, वही आज वैश्विक स्तर पर नवीन मॉडल के रूप में उभर रहे हैं।

प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र का मॉडल अधिक समन्वयी और नैतिक था, जिसमें दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और आत्म-सुधार था। आधुनिक पाश्चात्य न्याय प्रणाली ने विधिक संरचना और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को सुदृढ़ किया, परंतु वह लंबे समय तक पीड़ित और समुदाय की भूमिका को सीमित रखती रही।

आज जब वैश्विक स्तर पर सुधारात्मक न्याय की ओर झुकाव बढ़ रहा है, तब प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र के सिद्धांत विशेषकर प्रायश्चित्त, क्षतिपूर्ति और सामाजिक पुनर्स्थापन समकालीन न्याय व्यवस्था के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध हो सकते हैं। यह समन्वय भविष्य की न्याय प्रणाली को अधिक मानवीय, सहभागी और संतुलित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

### निष्कर्ष (Conclusion)

निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि भारतीय न्यायशास्त्र में ‘दंड’ की अवधारणा को केवल प्रतिशोधात्मक या दमनात्मक दृष्टि से समझना अधूरा और एकांगी है। प्राचीन भारतीय चिंतन में दंड सामाजिक चिकित्सा (Social Therapy) का एक सशक्त साधन था, जिसका उद्देश्य केवल अपराधी को कष्ट देना नहीं, बल्कि समाज में उत्पन्न नैतिक और संबंधात्मक असंतुलन को दूर करना था। दंड यहाँ धर्म की स्थापना, सामाजिक समरसता और लोक-कल्याण की पुनर्स्थापना का माध्यम था।

मनुस्मृति, अर्थशास्त्र तथा महाभारत जैसे ग्रंथों के विश्लेषण से यह प्रतिपादित होता है कि भारतीय न्यायशास्त्र में दंड की अवधारणा बहुआयामी थी। इसमें प्रतिकार (Retribution) और निवारण (Deterrence) के साथ-साथ सुधार (Reformation) और क्षतिपूर्ति (Restitution) के तत्व भी विद्यमान थे। विशेष रूप से ‘प्रायश्चित्त’ की व्यवस्था ने दंड को आंतरिक आत्म-शुद्धि और नैतिक पुनर्जागरण से जोड़ा।

‘प्रायश्चित्त’ का तात्पर्य केवल दंड भुगतना नहीं, बल्कि अपने अपराध का बोध कर आत्म-परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना था। यह आत्म-शुद्धिकरण की वह प्रक्रिया थी, जिसके माध्यम से अपराधी समाज में पुनः सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार ‘दया’ और ‘क्षमा’ को भी न्याय के पूरक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय दृष्टिकोण में कठोरता और करुणा का संतुलन ही वास्तविक न्याय था।

आधुनिक पश्चिमी न्याय प्रणाली लंबे समय तक दंडात्मक मॉडल पर आधारित रही, जहाँ अपराध को राज्य के विरुद्ध विधिक उल्लंघन माना गया और न्याय की प्रक्रिया मुकदमेबाजी एवं कारावास तक सीमित रही। परिणामस्वरूप, अनेक देशों में जेलों की संख्या बढ़ी, पुनरावृत्ति दर (Recidivism Rate) उच्च बनी रही और अपराधी समाज से कटकर स्थायी अपराधी बनते गए। इसी पृष्ठभूमि में ‘सुधारात्मक

न्याय’ (Restorative Justice) की अवधारणा विकसित हुई, जो अपराध को मानवीय संबंधों की क्षति के रूप में देखती है और संवाद, क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुनर्स्थापन पर बल देती है।

यह उल्लेखनीय है कि जिन सिद्धांतों को आज पश्चिमी न्याय-विमर्श में नवीन और प्रगतिशील माना जा रहा है, उनके मूल तत्व भारतीय परंपरा में पहले से विद्यमान थे। ‘प्रायश्चित’ आत्म-सुधार का साधन था; ‘क्षतिपूर्ति’ पीड़ित की संतुष्टि का माध्यम; और ‘लोक-कल्याण’ न्याय का अंतिम लक्ष्य। इस प्रकार भारतीय न्यायशास्त्र में दंड सामाजिक चिकित्सा का उपकरण था एक ऐसी प्रक्रिया, जो अपराधी, पीड़ित और समाज तीनों के मध्य संतुलन स्थापित करती थी।

आज की जेल प्रणाली में सुधार की आवश्यकता व्यापक रूप से अनुभव की जा रही है। कारावास प्रायः अपराधी को समाज से अलग कर देता है, जिससे उसका पुनर्सामाजिकरण कठिन हो जाता है। यदि दंड का उद्देश्य केवल पृथक्करण और दमन रह जाए, तो वह सामाजिक चिकित्सा के बजाय सामाजिक विघटन का कारण बन सकता है। इसलिए आवश्यक है कि न्याय प्रणाली में सुधारात्मक और पुनर्स्थापनात्मक सिद्धांतों को सशक्त रूप से समाहित किया जाए।

भारतीय न्याय परंपरा से प्रेरणा लेकर निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है-

1. **आत्म-स्वीकृति और प्रायश्चित की प्रक्रिया:** अपराधी को अपने कृत्य की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के अवसर प्रदान किए जाएँ।
2. **पीड़ित-केंद्रित न्याय:** क्षतिपूर्ति और परामर्श की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।
3. **सामाजिक पुनर्स्थापन:** कारावास के पश्चात अपराधी के पुनर्वास और पुनर्स्वीकृति की समुचित व्यवस्था हो।
4. **करुणा और न्याय का संतुलन:** कठोर दंड के स्थान पर विवेकपूर्ण और परिस्थिति-सापेक्ष दंड नीति अपनाई जाए।

भारतीय न्यायशास्त्र की ‘दंड’ अवधारणा केवल विधिक अनुशासन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक पुनर्संतुलन की प्रक्रिया थी। यह परंपरा आधुनिक सुधारात्मक न्याय के लिए एक सशक्त दार्शनिक और सांस्कृतिक आधार प्रस्तुत करती है।

यदि आज की न्याय प्रणाली इन सिद्धांतों प्रायश्चित, दया, क्षतिपूर्ति और लोक-कल्याण को पुनर्जीवित करे, तो दंड व्यवस्था अधिक मानवीय, सहभागी और प्रभावी बन सकती है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय न्याय-विचार न केवल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, बल्कि समकालीन वैश्विक न्याय-विमर्श में भी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं।

## संदर्भ सूची

1. कौटिल्य. (2012). अर्थशास्त्र (अनुवाद: आर. शमाशास्त्री). वाराणसी: चौखंबा संस्कृत सीरीज।
2. मनु. (2015). मनुस्मृति (संपा. एवं अनुवाद: गणेशदत्त पाठक). दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास।
3. याज्ञवल्क्य. (2013). याज्ञवल्क्य स्मृति. वाराणसी: चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान।
4. नारद. (2011). नारद स्मृति. दिल्ली: भारतीय विद्या प्रकाशन।
5. पराशर. (2014). पराशर स्मृति. वाराणसी: संस्कृत पुस्तक भंडार।
6. गौतम. (2010). गौतम धर्मसूत्र. पुणे: भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट।
7. आपस्तंब. (2008). आपस्तंब धर्मसूत्र. वाराणसी: चौखंबा संस्कृत संस्थान।
8. वशिष्ठ. (2009). वशिष्ठ धर्मसूत्र. दिल्ली: विद्या निधि प्रकाशन।
9. डॉ. भीमराव रामजी अबेडकर. (1936). जाति का विनाश (Annihilation of Caste). स्वयं प्रकाशित।
10. महात्मा गांधी. (1927). सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा. अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन।
11. जॉन रॉल्स. (1971). A Theory of Justice. कैम्ब्रिज, एमए: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
12. Howard Zehr. (1990). Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. स्कॉटडेल, पेनसिल्वेनिया: हेराल्ड प्रेस।
13. Nils Christie. (1977). Conflicts as Property. The British Journal of Criminology, 17(1), 1–15.
14. Andrew Ashworth. (2010). Sentencing and Criminal Justice. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
15. भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय. (2018). आपराधिक न्याय सुधार समिति की रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन।
16. Law Commission of India. (2003). Report on Reform of Criminal Justice System. नई दिल्ली: भारत सरकार।
17. United Nations. (2002). Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन।

## किशोरों में आध्यात्मिकता की आवश्यकताएं: एक समाजशास्त्रीय अवलोकन

डॉ. अखिलेश कुमार

अतिथि सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)

के. पी. कॉलेज, मुरलीगंज,

बी. एन. मंडल विश्विद्यालय, मधेपुरा.

### सारांश

आध्यात्मिकता, मानवीय अनुभव का एक गहन व्यक्तिगत और पारलौकिक आयाम है, जिसमें अर्थ की खोज, स्वयं से, दूसरों से और ब्रह्मांड से जुड़ाव, साथ ही मूल्यों और विश्वासों का अन्वेषण शामिल है। किशोरावस्था के संदर्भ में, आध्यात्मिकता का महत्व धार्मिक संबद्धताओं से परे एक गहरा अर्थ रखता है। विकास के इस चरण में आध्यात्मिकता के महत्व को पहचानना सर्वांगीण विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था में आध्यात्मिकता के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह उनकी आत्म-खोज और पहचान निर्माण की यात्रा में मार्गदर्शक प्रकाश का काम करती है। इस चरण की चुनौतियों के बीच, आध्यात्मिकता एक आधारभूत शक्ति प्रदान करती है जो उद्देश्य, दिशा और अपनेपन की भावना प्रदान करती है। यह अपनेपन की भावना आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करती है, जिससे किशोर अपने मूल मूल्यों, विश्वासों और नैतिक सिद्धांतों का पता लगा सकते हैं, और इस प्रकार एक मजबूत नैतिक दिशा-निर्देश विकसित करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

**मुख्य शब्द:** आध्यात्मिकता, किशोर, तनाव

### परिचय

मानव अस्तित्व के जटिल ताने-बाने में, आध्यात्मिकता एक ऐसे धागे के रूप में उभरती है जो अर्थ, जुड़ाव और आत्म-खोज के विविध पहलुओं को आपस में जोड़ती है। धार्मिक संबद्धताओं से परे, आध्यात्मिकता स्वयं को समझने, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने और विशाल ब्रह्मांड में उद्देश्य की तलाश करने की एक गहन व्यक्तिगत खोज का प्रतीक है। किशोरावस्था के क्षेत्र में, मानव अनुभव का

यह पहलू एक गहरा महत्व ग्रहण करता है जो उम्र और सामाजिक संरचनाओं की सीमाओं से परे है। किशोरावस्था के गतिशील परिदृश्य के बीच, जो पहचान निर्माण और आत्म-खोज की उथल-पुथल भरी लहरों से चिह्नित है, आध्यात्मिकता एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं को समाहित करता है।

आध्यात्मिकता एक स्थिर दिशा-निर्देशक का काम करती है, जो किशोरों को जीवन की चुनौतियों के जटिल जाल में मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह मार्गदर्शन बाहरी मानकों से परे जाकर उन्हें अपने विश्वासों, मूल्यों और नैतिक आधारों की गहराई में उतरने के लिए प्रोत्साहित करता है। विशेष रूप से, आध्यात्मिकता आधुनिक जीवन की जटिलताओं का सामना करने के लिए लचीलेपन का स्रोत है। किशोरावस्था में शैक्षणिक दबाव, साथियों का प्रभाव और आत्म-खोज की निरंतर चुनौती देखने को मिलती है। ऐसे में, आध्यात्मिकता सशक्तिकरण का स्रोत बन जाती है, जो किशोरों को तनाव, सामाजिक अपेक्षाओं और शैक्षणिक मांगों के भंवर से निकलने के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करती है।

इसके अलावा, कृतज्ञता, सहानुभूति और जागरूकता जैसे गुणों का विकास, जो अक्सर आध्यात्मिक यात्रा के साथ जुड़े होते हैं, परिवर्तनकारी क्षमता रखते हैं। जो किशोर आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास होता है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। यह आंतरिक लचीलापन उन्हें किशोरावस्था के भावनात्मक उतार-चढ़ावों को स्थिरता के साथ संभालने में सक्षम बनाता है, जो उनकी आध्यात्मिक नींव से उत्पन्न होता है। ऐसी दुनिया में जहां तकनीक से प्रेरित विकर्षण और सामाजिक दबावों का शोर बढ़ता जा रहा है, किशोरों में आध्यात्मिकता का पोषण करना अनिवार्य हो जाता है। यह उन्हें डिजिटल रूप से खंडित वास्तविकता में परस्पर जुड़ाव का आश्रय प्रदान करता है, जिससे सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा मिलता है। यह समग्र दृष्टिकोण उनके क्षितिज को व्यापक बनाता है, उनका ध्यान क्षणिक भौतिकवादी खोजों से हटाकर स्थायी समग्र विकास की ओर ले जाता है।

### आध्यात्मिकता की परिभाषा :

रुडोक और कैमरून 'आध्यात्मिकता' शब्द अस्पष्ट और जटिल प्रतीत हो सकता है, फिर भी यह एक संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रिया को समाहित करता है जिसमें व्यक्ति जीवन में एक सार्थक आयाम पाते हैं जो दैनिक दिनचर्या से परे होता है और उन्हें किसी वृहद सत्ता से जुड़ाव का बोध कराता है। आध्यात्मिकता का यह आयाम मानव अस्तित्व का एक मूलभूत पहलू बनने की क्षमता रखता है।

एस्टिन 'आध्यात्मिकता की एक समकालीन व्याख्या को अपनाया जो धार्मिक संबद्धताओं, दैवीयता में विश्वास या धार्मिक प्रतिबद्धताओं से परे थी। आध्यात्मिकता की यह धारणा विविध तत्वों के संश्लेषण को समाहित करती है, जिसमें मानव चेतना, व्यक्ति की आंतरिक जागरूकता जो प्रत्यक्ष अवलोकन या

सरल मूल्यांकन से परे है, जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। भावनाओं, व्यक्तिगत अनुभवों, मूल्य प्रणालियों और सामाजिक बुद्धिमत्ता का क्षेत्र; तार्किक तर्क, आध्यात्मिक मामलों पर व्यक्ति का विचार-विमर्श; और विशिष्ट प्रवृत्तियाँ, जिनमें ऐसे अनुभव शामिल हैं जिनका आसानी से वर्णन, स्पष्टीकरण या प्रवचन नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अकथनीय सहज प्रवृत्तियाँ, प्रेरणाएँ और अन्य रहस्यमय घटनाएँ<sup>2</sup> सेलिंगमैन 'आध्यात्मिकता को स्थायी, सर्वव्यापी विश्वासों और अनुष्ठानों के रूप में परिभाषित किया है, जो भौतिक जगत से परे जीवन के एक आयाम में विश्वास पर आधारित हैं। ये विश्वास और अनुष्ठान व्यक्ति के दूसरों के साथ व्यवहार में स्पष्ट होते हैं, उपलब्धियों और चुनौतियों के प्रति उनकी व्याख्याओं को प्रभावित करते हैं, अप्रत्याशित जीवन घटनाओं के इर्द-गिर्द उनके द्वारा गढ़ी गई कहानियों को आकार देते हैं, और यहां तक कि उनके रिश्तों को निभाने के तरीके का मार्गदर्शन भी करते हैं।<sup>3</sup>

### आध्यात्मिकता के लाभ

अंडर्रेनर, लुईस और फिंक ने व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य पर आध्यात्मिक कल्याण के प्रभाव का पता लगाने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों को शामिल करते हुए एक खोजी यात्रा शुरू की। एक व्यापक साहित्य समीक्षा ने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की पुष्टि की: आध्यात्मिक कल्याण का चिंता और अवसाद के साथ विपरीत सहसंबंध पाया गया, जो इन मनोवैज्ञानिक विकारों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक कारक प्रदान करता है। इसके अलावा, शोध ने आध्यात्मिक कल्याण और आशा, साथ ही क्षमा के बीच एक मजबूत और सकारात्मक संबंध का खुलासा किया। विशेष रूप से, उच्च स्तर की सामान्य धार्मिकता, आध्यात्मिक कल्याण और जुड़ाव वाले व्यक्तियों में आत्महत्या के विचारों की प्रवृत्ति न्यूनतम पाई गई। मात्रात्मक रूप से, अध्ययन ने दिखाया कि उच्च धार्मिकता वाले व्यक्तियों में आक्रामकता का स्तर कम और नए अनुभवों के प्रति अधिक खुलापन पाया गया। इसके अतिरिक्त, आध्यात्मिक कल्याण और विभिन्न कारकों, जिनमें चिंता, सकारात्मक मुकाबला तंत्र और समग्र मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण शामिल हैं, के बीच एक महत्वपूर्ण नकारात्मक संबंध सामने आया। संक्षेप में, अध्ययन ने न केवल व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर भी आध्यात्मिक कल्याण के गहन प्रभाव को रेखांकित किया।<sup>4</sup>

हुसैन 'का सुझाव है कि आध्यात्मिकता जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर एक आवश्यक मार्ग है। आध्यात्मिकता का व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आयामों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। योग, व्यायाम और स्वस्थ आहार जैसी शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होना आध्यात्मिकता के पोषण में योगदान देता है। इससे मानसिक और भावनात्मक कल्याण प्रभावित होता है, जिसके परिणामस्वरूप आत्म-नियंत्रण में सुधार, जागरूकता में वृद्धि, अंतर्ज्ञान, खुशी और अधिक दयालु स्वभाव विकसित होता है।<sup>5</sup>

बेन्सन, रोहलकेपार्टेन और रूड 'ने दावा किया कि आध्यात्मिकता का महत्व, विशेष रूप से किशोरों और बच्चों में, लगातार अनदेखा किया गया है। लेखकों ने सुझाव दिया कि निरंतर और कठोर प्रयास करने से आध्यात्मिकता के महत्व को कम करने में मदद मिलेगी। सामाजिक एवं विकासात्मक विज्ञान के क्षेत्र में बचपन और किशोरावस्था के दौरान आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देने से मानव विकास की मूलभूत प्रक्रियाओं और पहलुओं की समझ को काफी हद तक बढ़ाने और मजबूत करने की क्षमता है। उन्होंने आध्यात्मिक विकास को आत्म-उत्कृष्टता की अंतर्निहित मानवीय क्षमता के पोषण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया, जहाँ स्वयं अपने से बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा बन जाता है, जिसमें पवित्रता भी शामिल है। इसे परस्पर जुड़ाव, उद्देश्य, अर्थ और योगदान की खोज को गति देने वाले एक विकासात्मक "इंजन" के रूप में संदर्भित किया गया। यह पाया गया कि यह अवधारणा धार्मिक परंपराओं और प्रथाओं के साथ-साथ बाहरी कारकों से भी प्रभावित है।<sup>6</sup>

योंकर, श्राबेलराउच और डीहान 'ने एक मेटा-विश्लेषण किया जिसका उद्देश्य यह समझना था कि किशोरों में मादक द्रव्यों के सेवन और हिंसा जैसे जोखिम भरे व्यवहारों के विरुद्ध आध्यात्मिकता/धार्मिकता किस प्रकार सुरक्षात्मक भूमिका निभाती है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि आध्यात्मिकता जोखिम भरे व्यवहारों के प्रभाव को कम करके सुरक्षात्मक भूमिका निभाती है, जिससे इस आयु वर्ग के लोगों के बेहतर मनोदशा और समग्र कल्याण में योगदान होता है।<sup>7</sup>

मेबे और जोसेफसन 'का सुझाव है कि आध्यात्मिकता बच्चों के जीवन की घटनाओं की व्याख्या और मूल्यांकन करने, विकासात्मक कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समाजीकरण, पालन-पोषण, पारिवारिक गतिशीलता और रिश्तों की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है। पीटरसन और सेलिंगमैन (2004) ने 'सिग्नेचर स्किल्स चेकलिस्ट' में आध्यात्मिक कल्याण के माप को शामिल किया और इस माप और मनोवैज्ञानिक कल्याण के विभिन्न संकेतकों, जैसे आत्म-सम्मान, पारिवारिक एकता और माता-पिता-बच्चे के बीच संबंधों की गुणवत्ता के बीच सकारात्मक संबंध पाया। उच्च स्तर के आध्यात्मिक कल्याण वाले व्यक्तियों में आत्म-सम्मान, पारिवारिक एकजुटता और विशेष रूप से माता-पिता-बच्चे के बीच मजबूत संबंध भी अधिक पाए गए। विशेष रूप से, उच्च स्तर के आध्यात्मिक कल्याण का संबंध बेहतर मनोवैज्ञानिक कल्याण से पाया गया।<sup>8</sup>

### आध्यात्मिकता और किशोरावस्था

स्वेडकिवस्ट, जौबर्ट, ग्रीन और मैनिन 'ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि आध्यात्मिकता पर किशोरों के दृष्टिकोण में उत्पन्न होने वाले संघर्ष पहचान निर्माण और आध्यात्मिक विकास प्रक्रियाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनके समाधान की आवश्यकता होती है। इन संघर्षों में से एक

स्वायत्तता बनाम अधिकार का संघर्ष है, जहाँ किशोर अपनी स्वतंत्रता का दावा करने और अधिकार पर प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं, जो एक शक्तिशाली उच्च सत्ता की अवधारणा से टकरा सकता है। इसी प्रकार, संरचित धार्मिक परिवेशों में व्यक्ति बनाम संस्था का संघर्ष उत्पन्न होता है जो व्यक्तिगत समझ को सीमित कर सकता है। स्वायत्तता बनाम संरक्षण की चुनौती तब उभरती है जब किशोर एक परोपकारी शक्ति में विश्वास के माध्यम से सांत्वना की तलाश करते हैं।<sup>9</sup>

चुनौतीपूर्ण समय। चेओन 'ने आध्यात्मिकता को अर्थ और जुड़ाव की खोज के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह स्वयं से हो, पर्यावरण से हो या किसी उच्च शक्ति से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे धार्मिक संदर्भ हो या धर्मनिरपेक्ष। किशोरों में, आध्यात्मिकता को एक विकासात्मक प्रयास के रूप में देखा जाता था जो उनके जीवन में जुड़ाव और उद्देश्य की खोज का मार्गदर्शन करता था।<sup>10</sup>

लेयार्ड 'ने यह तर्क दिया कि किशोरावस्था या बाल विकास के किसी भी चरण में किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक जुड़ाव होना आवश्यक है। आध्यात्मिकता की अवधारणा को एक उच्चतर सत्ता से जुड़ाव की भावना के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें धार्मिक विश्वासों से लेकर कला, विज्ञान, प्रकृति और गहन सत्यों जैसे विविध क्षेत्रों में सांत्वना खोजना शामिल है।<sup>11</sup>

गुड और विलोबी 'ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया कि किशोर, बच्चों या वयस्कों की तुलना में आध्यात्मिकता की खोज के प्रति अधिक झुकाव प्रदर्शित कर सकते हैं। वे आध्यात्मिक अनुभवों, रूपांतरणों और प्रतिबद्धताओं में संलग्न हो सकते हैं जो उनके जीवन भर कायम रहती हैं।<sup>12</sup>

गिसेनबर्ग 'ने सुझाव दिया कि किशोरावस्था के दौरान आध्यात्मिकता का उदय बचपन में स्थापित संबंधों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हो सकता है। इस अवधि की आध्यात्मिक प्रवृत्ति एक आंतरिक प्रतिस्थापन से उत्पन्न हो सकती है, जहाँ एक समझदार, पालन-पोषण करने वाली और स्नेही दिव्य सत्ता अनुपस्थित या अपर्याप्त माता-पिता की भूमिका का स्थान ले लेती है। इस प्रकार, किसी विशिष्ट धार्मिक विश्वास के पीछे की प्रेरणा अन्य कारकों के बजाय असंतोषजनक माता-पिता-बच्चे के रिश्ते से उत्पन्न हो सकती है। आध्यात्मिकता का यह रूप आस्था के विकास को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है, जो जीवन के साथ एक भरोसेमंद संबंध को दर्शाता है; आश्चर्य, जो जीवन के प्रत्यक्ष भौतिक पहलुओं से परे उसके गहरे अर्थ को खोजने की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है; संबंधपरक चेतना, जो एक सामंजस्यपूर्ण एकता के दर्शन के साथ किसी गतिविधि में पूर्ण तल्लीनता के गहन अनुभव को दर्शाती है; और करुणा, इन आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप।<sup>13</sup>

रिच और सिनामन 'ने इजराइली अरब और यहूदी किशोरों के बीच आध्यात्मिकता की धारणाओं की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया, जिसमें छत्तीस हाई स्कूल के छात्रों और कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्रों का एक समूह शामिल था। निष्कर्षों से पता चला कि आध्यात्मिकता के मूलभूत पहलु के रूप

में पारलौकिक अनुभूति पर व्यापक सहमति है। अध्ययन ने किशोरों के बीच आध्यात्मिकता के दो अलग-अलग रूपों के सह-अस्तित्व को उजागर किया: धार्मिक और मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रतिभागियों ने आध्यात्मिकता की धार्मिक और गैर-धार्मिक या मानवतावादी-धर्मनिरपेक्ष व्याख्याओं दोनों के महत्व को स्वीकार किया। दिलचस्प बात यह है कि शोध से पता चला कि कई पारंपरिक रूप से धार्मिक किशोर आध्यात्मिकता को केवल धार्मिक विश्वासों या अनुष्ठानों के बराबर नहीं मानते थे; वे मानवतावादी आदर्शों के समान एक अतिरिक्त आयाम की तलाश करते थे, जैसे कि आंतरिक आत्म-जुड़ाव और भावनात्मक पारलौकिकता। दूसरी ओर, धर्मनिरपेक्ष प्रतिभागियों के अनुभव मुख्य रूप से आध्यात्मिकता के मानवतावादी पहलुओं के अनुरूप थे, फिर भी उन्होंने दूसरों के लिए धार्मिक आध्यात्मिकता की वैधता को स्वीकार किया। इसलिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश किशोर आध्यात्मिक संतुष्टि की ओर ले जाने वाले विविध मार्गों के सह-अस्तित्व को पहचानते और समर्थन करते हैं। विशेष रूप से, अधिकांश प्रतिभागियों ने पारलौकिकता को मूल तत्व के रूप में बल दिया। आध्यात्मिकता, एक ऐसी अवधारणा थी जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत व्यक्तिगत और गहरे अर्थपूर्ण थी।<sup>14</sup>

बायर्न्स 'द्वारा किए गए एक अध्ययन में बच्चों और किशोरों की मेटा-कॉग्निटिव क्षमताओं से संबंधित मौजूदा साहित्य का अध्ययन किया गया। अध्ययन से पता चला कि बच्चे अक्सर ज्ञान को पूर्ण और वस्तुनिष्ठ मानते हैं। इसके विपरीत, किशोरावस्था के दौरान एक उल्लेखनीय परिवर्तन होता है। किशोर विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने और तार्किक तर्क और सहायक प्रमाणों का उपयोग करते हुए इन दृष्टिकोणों की विश्वसनीयता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करते हैं। इस संज्ञानात्मक विकास के साथ-साथ अमूर्त चिंतन की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे किशोर आध्यात्मिक अवधारणाओं की विभिन्न व्याख्याओं पर विचार करने में सक्षम होते हैं। जैसे-जैसे उनकी अमूर्त चिंतन क्षमता बढ़ती है, किशोर जीवन के उद्देश्य और महत्व से संबंधित जटिल और अमूर्त प्रश्नों से जूझने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं।<sup>15</sup>

ये अध्ययन सामूहिक रूप से किशोरों में आध्यात्मिकता के सूक्ष्म स्वरूप को उजागर करते हैं, जिसमें अन्वेषण, संघर्ष और प्रामाणिकता की खोज शामिल है। इन संघर्षों को समझना और उनका समाधान करना किशोरों की आध्यात्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरता है, जो उनकी पहचान और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देता है।

## निष्कर्ष

इस शोध पत्र में किए गए अध्ययनों से प्राप्त समग्र अंतर्दृष्टि किशोरों के जीवन में आध्यात्मिकता के गहन महत्व को रेखांकित करती है। किशोरावस्था, अर्थ, पहचान और दिशा की खोज का एक परिवर्तनकारी चरण है, जो अक्सर व्यक्तियों को अनेक संघर्षों और अनिश्चितताओं से रूबरू कराता है क्योंकि वे स्वायत्तता स्थापित करने, मूल्यों को परिभाषित करने और तेजी से विकसित हो रही दुनिया की जटिलताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में, आध्यात्मिकता एक शक्तिशाली ढाँचे के रूप में उभरती है जिसका उपयोग किशोर जीवन के व्यापक ताने-बाने में अपनी भूमिकाओं का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। यह ढाँचा आत्मनिरीक्षण, आत्म-जागरूकता और गहरे संबंधों की खोज का माध्यम बनता है। आध्यात्मिकता से जुड़कर, किशोर चिंतन की क्षमता को खोलते हैं, जिससे वे तात्कालिक भौतिक आकांक्षाओं से परे एक उद्देश्य की भावना विकसित करते हैं। आध्यात्मिकता को अपनाने से युवा व्यक्तियों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने, मनोदशा में उतार-चढ़ाव को कम करने और अपने समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए साधन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, आध्यात्मिकता एक बंधनकारी शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो स्वयं की सीमाओं से परे संबंध स्थापित करती है। यह आध्यात्मिक अनुभूति दूसरों के साथ संबंधों, पर्यावरण और यहां तक कि स्वयं के अंतर्मन तक भी फैली हुई है। अनिश्चितता के समय में, आध्यात्मिकता सांत्वना और मार्गदर्शन का स्रोत प्रदान करती है। चाहे धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से व्यक्त की जाए, आध्यात्मिकता किशोरों को तेजी से बदलती और जटिल दुनिया की पेचीदगियों के बीच अर्थ और संतुलन खोजने की शक्ति देती है।

विशेषकर भारत के संदर्भ में, जहाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएँ गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, किशोरावस्था के विकास में आध्यात्मिकता की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे समाज में जहाँ बाहरी उपलब्धियों और भौतिक सुख-सुविधाओं पर अधिक बल दिया जाता है, आध्यात्मिकता का पोषण एक संतुलन प्रदान करता है। यह सहानुभूति, करुणा और व्यापक विश्वदृष्टि को बढ़ावा देता है, जिससे युवा सूचित निर्णय लेने, तनाव का प्रबंधन करने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए तैयार होते हैं। अंततः, किशोरावस्था में आध्यात्मिकता का महत्व केवल व्यक्तिगत खोज से कहीं अधिक है; यह समग्र विकास की नींव रखता है। अपने आध्यात्मिक आयामों पर ध्यान देकर, किशोर अपने विकासात्मक सफर में निहित चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। आध्यात्मिकता में यह निवेश न केवल उन्हें किशोरावस्था के गतिशील चरण से गुजरने में सक्षम बनाता है, बल्कि एक सार्थक और समृद्ध वयस्क जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आध्यात्मिकता का पोषण करके, हम किशोरों को आत्म-खोज, लचीलेपन और अपनी पहचान, अपने आस-पास के लोगों और जिस जटिल दुनिया में वे रहते हैं, उससे गहरे जुड़ाव की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

**संदर्भ:**

1. रूडॉक, बी., और कैमरून, आर. जे. (2010). बच्चों और युवा लोगों में आध्यात्मिकता शैक्षिक और बाल मनोवैज्ञानिकों के लिए एक उपयुक्त विषय है?। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन प्रैक्टिस, पृष्ठ- 25-34.
2. एस्टिन, ए. डब्ल्यू. (2004). उदार शिक्षा में आध्यात्मिकता को केंद्रीय स्थान क्यों मिलना चाहिए। उदार शिक्षा, पृष्ठ- 34-41.
3. सेलिंगमैन, एम.ई.पी. 2002. प्रामाणिक खुशी: गहरी संतुष्टि के लिए अपनी क्षमता को साकार करने के लिए नए सकारात्मक मनोविज्ञान का उपयोग करना, लंदन: निकोलस ब्रेली।पृष्ठ- 20-26
4. अंडर्नर, एच. एफ., लुईस, ए. जे., और फिंक, ए. (2014). धार्मिक/आध्यात्मिक कल्याण, व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य: परिणामों और वैचारिक मुद्दों की समीक्षा। जर्नल ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ, पृष्ठ- 382-392.
5. हुसैन, ए. (2013). आध्यात्मिकता की त्रिमूर्ति अवस्था: शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। आध्यात्मिकता और सकारात्मक मनोविज्ञान में (पृष्ठ 78-88)। रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान।
6. बेन्सन, पी. एल., रोहलकेपार्टेन, ई. सी., और रूड, एस. पी. (2010). बचपन और किशोरावस्था में आध्यात्मिक विकास: जांच के क्षेत्र की ओर। एप्लाइड डेवलपमेंटल साइंस, पृष्ठ- 205-213.
7. योंकर, जे. ई., श्राबेलराउच, सी. ए., और डीहान, एल. जी. (2012). किशोरों और युवा वयस्कों में मनोवैज्ञानिक परिणामों पर आध्यात्मिकता और धार्मिकता के बीच संबंध: एक मेटा-विश्लेषणात्मक समीक्षा। जर्नल ऑफ एडोलसेंस, पृष्ठ- 299-314.
8. मेबे, पी. ए., और जोसेफसन, ए. एम. (2004). बाल और किशोर मनोविकृति: आध्यात्मिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य। उत्तरी अमेरिका के बाल और किशोर मनोरोग क्लिनिक, पृष्ठ- 111-125.
9. स्वेडक्विस्ट, वी., जौबर्ट, एन., ग्रीन, जे., और मैनियन, आई. (2012). मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ? युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में आध्यात्मिकता की भूमिका पर उनके दृष्टिकोण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ प्रमोशन, पृष्ठ- 36-44.

10. चेओन, जे. डब्ल्यू. (2010). युवा आध्यात्मिकता की एक पारलौकिक समझ: युवा कार्य के विस्तारित दृष्टिकोण के लिए निहितार्थ। करेंट्स, पृष्ठ-29-34.
11. लेयार्ड, आर. (2007). खुशी और सार्वजनिक नीति: पेशे के लिए एक चुनौती। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान: एक आशाजनक नया क्रॉस-अनुशासनात्मक क्षेत्र, पृष्ठ- 155-167.
12. गुड, एम., और विलोबी, टी. (2008). आध्यात्मिक विकास के लिए किशोरावस्था एक संवेदनशील अवधि के रूप में। बाल विकास परिप्रेक्ष्य, 2(1), पृष्ठ- 32-37.
13. गिसेनबर्ग, ए. (2007). प्रीस्कूल बच्चों की आध्यात्मिकता की घटना। डॉक्टरेट शोध प्रबंध। क्वींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पृष्ठ-11-14.
14. रिच, वाई., और सिनामन, आर. जी. (2007). इजरायली अरब और यहूदी किशोरों के बीच आध्यात्मिकता की अवधारणाएँ। जर्नल ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, पृष्ठ- 7-29.
15. बायन्स, जे. पी. (2003). किशोर जोखिम लेने की प्रकृति और रोकथाम पर बदलते विचार। किशोर जोखिम को कम करना: एक एकीकृत दृष्टिकोण की ओर, पृष्ठ- 11-17.

# समकालीन भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का संकट: उत्तर भारत में जाति, वर्ग और चुनावी राजनीति का एक अध्ययन

डॉ. दीपक जॉनसन

सहायक प्राध्यापक

राजनीति विज्ञान विभाग

शासकीय आदर्श महाविद्यालय, दमोह (मध्य प्रदेश).

## सारांश

यह शोध पत्र समकालीन भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के संकट की जांच करता है, जो उत्तर भारत में मतदाताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच की दूरी पर केंद्रित है। यह अध्ययन जांच करता है कि कैसे जाति और वर्ग की गतिशीलता राजनीतिक भागीदारी, चुनावी व्यवहार और नीतिगत परिणामों को आकार देती है। यह शोध तीन राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान—में 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों के चुनावी आंकड़ों के मात्रात्मक विश्लेषण को मतदाताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों के गुणात्मक साक्षात्कारों के साथ जोड़ता है। प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि उच्च मतदान प्रतिशत के बावजूद, निचली जातियों और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बीच बढ़ता अलगाव है, जो मानते हैं कि विधायी निकायों में उनके हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है। यह पेपर तर्क देता है कि धन-बल का प्रभुत्व, राजनीति का अपराधीकरण और वंशवादी राजनीति ने इस संकट को बढ़ा दिया है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास घट रहा है। यह अध्ययन उपनिवेशवादोत्तर समाजों में लोकतंत्र के गहनताकरण पर व्यापक प्रवचन में योगदान देता है।

**कीवर्ड:** लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व, जाति राजनीति, चुनावी व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी, भारत

## परिचय / पृष्ठभूमि

भारतीय लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ने अपनी सात दशक से अधिक की यात्रा पूरी कर ली है। लगभग 90 करोड़ मतदाताओं के साथ, 2024 के आम चुनाव मानव इतिहास में सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास थे। हालाँकि, इस प्रभावशाली आंकड़े के नीचे एक परेशान करने वाली वास्तविकता छिपी है: लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता पर increasingly सवाल उठाए जा रहे हैं।

2014 से 2024 की अवधि भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का साक्षी रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पतन, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक प्रभावशाली ताकत के रूप में उदय, क्षेत्रीय दलों का विखंडन और सत्ता का बढ़ता केंद्रीकरण—सभी ने एक नए राजनीतिक परिदृश्य में योगदान दिया है। इस परिदृश्य में, प्रतिनिधित्व के प्रश्न—कौन निर्वाचित होता है, वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे अपने मतदाताओं के प्रति कितने उत्तरदायी हैं—सर्वोपरि हो गए हैं।

## समस्या का कथन

चुनावी लोकतंत्र के औपचारिक तंत्र के बावजूद, नागरिकों—विशेषकर हाशिए के समुदायों के बीच—में यह बढ़ती धारणा है कि राजनीतिक व्यवस्था उनके हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह संकट कई तरीकों से प्रकट होता है:

- **आर्थिक असमानता:** अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हुई है, जिसमें शीर्ष 1% जनसंख्या राष्ट्रीय संपत्ति के 40% से अधिक की मालिक है, जबकि निचले 50% के पास 3% से भी कम है।
- **जाति-आधारित भेदभाव:** संवैधानिक गारंटी और आरक्षण नीतियों के बावजूद, दलित और आदिवासी सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का सामना करना जारी रखते हैं।
- **राजनीति का अपराधीकरण:** आपराधिक मामलों वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हुई है, 2019 के लोकसभा में 40% से अधिक सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की थी।
- **वंशवादी राजनीति:** राजनीतिक शक्ति कुछ परिवारों में केंद्रित बनी हुई है, जो हाशिए के समुदायों के नए उम्मीदवारों के लिए अवसरों को सीमित करती है।
- **धन-बल:** चुनाव लड़ने की लागत आसमान छू गई है, जिससे पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के बिना उम्मीदवार प्रभावी रूप से बाहर हो जाते हैं।

## शोध प्रश्न

यह पेपर निम्नलिखित शोध प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है:

1. उत्तर भारत में जाति और वर्ग की गतिशीलता चुनावी व्यवहार और राजनीतिक भागीदारी को कैसे प्रभावित करती है?
2. निर्वाचित प्रतिनिधि, विशेषकर हाशिए के समुदायों के अपने मतदाताओं के प्रति स्वयं को किस हद तक उत्तरदायी मानते हैं?
3. वे संरचनात्मक कारक (धन, अपराधीकरण, वंशवाद) कौन से हैं जो प्रभावी प्रतिनिधित्व में बाधा डालते हैं?
4. प्रतिनिधित्व का संकट विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास को कैसे प्रभावित करता है?

## उद्देश्य

- उत्तर भारत में सामाजिक संरचना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच संबंध का विश्लेषण करना।
- हाशिए के समुदायों के लिए प्रभावी राजनीतिक भागीदारी में बाधाओं की पहचान करना।
- प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता पर धन-बल, अपराधीकरण और वंशवादी राजनीति के प्रभाव का आकलन करना।
- लोकतंत्र को गहरा करने और प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित करना।

## अध्ययन का महत्व

यह अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, यह प्रतिनिधित्व के संकट पर अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है, उपाख्यानात्मक टिप्पणियों से आगे बढ़ता है। दूसरा, यह उत्तर भारत पर केंद्रित है, एक ऐसा क्षेत्र जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और सामाजिक रूप से जटिल दोनों है। तीसरा, यह उपनिवेशवादोत्तर समाजों में लोकतंत्र के गहनताकरण पर सैद्धांतिक साहित्य में योगदान देता है। अंत में, यह चुनावी और संस्थागत सुधारों के लिए व्यावहारिक सिफारिशें प्रदान करता है।

## सीमाएँ

इस अध्ययन की कई सीमाएँ हैं। पहला, यह उत्तर भारत के तीन राज्यों तक सीमित है, और निष्कर्ष अन्य क्षेत्रों के लिए सामान्यीकरण योग्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा, गुणात्मक घटक साक्षात्कारों के अपेक्षाकृत

छोटे नमूने पर निर्भर करता है। तीसरा, अध्ययन मुख्य रूप से लोकसभा (राष्ट्रीय) स्तर पर केंद्रित है, राज्य और स्थानीय राजनीति पर सीमित ध्यान देता है।

## साहित्य समीक्षा

### सैद्धांतिक ढांचा

यह अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र में तीन प्रमुख सैद्धांतिक परंपराओं पर आधारित है:

#### 1. अभिजात वर्ग सिद्धांत (पैरेटो, मोस्का, मिखेल्स)

अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों का तर्क है कि सभी समाजों में, एक छोटा अल्पसंख्यक—अभिजात वर्ग—शासन करता है, जबकि बहुसंख्यक शासित होते हैं। रॉबर्ट मिखेल्स का "लोहे का नियम" बताता है कि सभी संगठन, यहाँ तक कि लोकतांत्रिक दल भी, अनिवार्य रूप से अल्पतंत्री (oligarchic) हो जाते हैं। यह सिद्धांत राजनीतिक शक्ति के कुछ परिवारों और समूहों के बीच केंद्रीकरण को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

#### 2. मार्क्सवादी सिद्धांत (मार्क्स, ग्राम्शी, मिलिबैंड)

मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को वर्ग शासन के एक उपकरण के रूप में देखता है। भारतीय संदर्भ में, यह परिप्रेक्ष्य यह समझने में मदद करता है कि कैसे आर्थिक अभिजात वर्ग राजनीतिक प्रक्रिया पर हावी होते हैं, नीतियों को अपने पक्ष में ढालते हैं। ग्राम्शी की "आधिपत्य" की अवधारणा यह समझने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है कि कैसे प्रभावी समूह सांस्कृतिक और वैचारिक साधनों के माध्यम से सहमति बनाए रखते हैं।

#### 3. बहुलवादी सिद्धांत (डाल, लिंडब्लॉम)

बहुलवादी तर्क देते हैं कि समाज में शक्ति कई समूहों के बीच विकेंद्रीकृत होती है, और कोई एक समूह हावी नहीं होता है। जबकि यह सिद्धांत लोकतंत्र का एक आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, भारतीय संदर्भ में इसकी प्रयोज्यता—जहाँ शक्ति अत्यधिक केंद्रित है—सीमित है।

## भारतीय लोकतंत्र पर अनुभवजन्य साहित्य

### 1. जाति और राजनीति

साहित्य की एक महत्वपूर्ण मात्रा भारत में जाति और राजनीति के बीच संबंधों की जांच करती है। रुडोल्फ और रुडोल्फ (1967) ने तर्क दिया कि जाति को "आधुनिकीकृत" किया गया है और लोकतांत्रिक राजनीति के अनुकूल बनाया गया है। जाफ्रेलॉट (2003) ने दिखाया कि कैसे निचली

जातियों ने अपनी पहचान का दावा करने और सत्ता हथियाने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति का उपयोग किया है। हालाँकि, अधिक हाल के अध्ययन (देशपांडे, 2011; जोधका, 2018) बताते हैं कि जबकि निचली जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उनकी आर्थिक स्थिति में तदनु रूप सुधार नहीं हुआ है।

## 2. वर्ग और राजनीति

भारत में वर्ग और राजनीति पर अध्ययन अपेक्षाकृत कम हैं। बर्धन (1984) ने तीन प्रमुख संपत्तिशील वर्गों—औद्योगिक पूंजीपति, समृद्ध किसान और पेशेवर—की पहचान की, जो राज्य को नियंत्रित करते हैं। कोहली (2012) ने तर्क दिया कि आर्थिक उदारीकरण ने पूंजी की शक्ति को मजदूरों और गरीबों के मुकाबले मजबूत किया है।

## 3. राजनीति का अपराधीकरण

राजनीति के अपराधीकरण की घटना ने महत्वपूर्ण विद्वतापूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। वैष्णव (2017) ने प्रदर्शित किया कि मतदाता अक्सर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें "कठोर" और "काम निकालने में सक्षम" के रूप में देखते हैं। यह निष्कर्ष मतदाता तर्कसंगतता के बारे में पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है।

## 4. वंशवादी राजनीति

वंशवादी राजनीति अन्य पहलुओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम अध्ययनित है। चंद्रा (2016) ने तर्क दिया कि कमजोर पार्टी संस्थागतकरण के संदर्भों में, मतदाता सूचनात्मक शॉर्टकट के रूप में उम्मीदवार विशेषताओं—जिसमें परिवार का नाम भी शामिल है—पर भरोसा करते हैं। यह भारतीय राजनीति में वंशवादों के बने रहने की व्याख्या करने में मदद करता है।

## शोध अंतराल

जबकि मौजूदा साहित्य मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इसमें कई कमियाँ हैं। पहला, अधिकांश अध्ययन या तो जाति या वर्ग पर केंद्रित होते हैं, कुछ ही उनके अंतर्संबंध की जांच करते हैं। दूसरा, सामान्य नागरिकों—विशेषकर हाशिए के समुदायों से—की आवाज अक्सर अनुपस्थित होती है। तीसरा, प्रतिनिधित्व और संस्थाओं में विश्वास के बीच संबंध का व्यवस्थित रूप से पता नहीं लगाया गया है। यह अध्ययन इन अंतरालों को भरने का लक्ष्य रखता है।

## शोध पद्धति

### शोध डिजाइन

यह अध्ययन एक मिश्रित-विधि शोध डिजाइन (mixed-methods research design) को नियोजित करता है, जो मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोणों को जोड़ता है। मात्रात्मक घटक में चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण शामिल है, जबकि गुणात्मक घटक में गहन साक्षात्कार और फोकस समूह चर्चाएँ शामिल हैं।

### प्रतिचयन (Sampling)

यह अध्ययन तीन राज्यों को कवर करता है: उत्तर प्रदेश (भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, एक जटिल जाति पदानुक्रम के साथ), बिहार (निचली जातियों के संगठन के इतिहास के साथ), और राजस्थान (एक महत्वपूर्ण आदिवासी जनसंख्या के साथ)। प्रत्येक राज्य के भीतर, दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का चयन किया गया—एक ग्रामीण और एक शहरी—जिससे कुल छह निर्वाचन क्षेत्र बने।

गुणात्मक घटक के लिए, 60 उत्तरदाताओं का एक उद्देश्यपूर्ण नमूना (purposive sample) चुना गया, जिसमें शामिल हैं:

- 30 मतदाता (15 पुरुष, 15 महिला) विभिन्न जाति और वर्ग पृष्ठभूमि से
- 15 निर्वाचित प्रतिनिधि (सांसद/विधायक)
- 15 राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता

## डेटा संग्रह

### मात्रात्मक डेटा

- चुनाव आयोग डेटा (2014, 2019, 2024)
- राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन (NES) डेटा - केंद्र फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS)
- भारत की जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) डेटा

### गुणात्मक डेटा

- मतदाताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अर्ध-संरचित साक्षात्कार
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में फोकस समूह चर्चाएँ
- राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक सभाओं का अवलोकन

## डेटा विश्लेषण

मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण वर्णनात्मक और अनुमानात्मक आंकड़ों (descriptive and inferential statistics) का उपयोग करके किया जाएगा, जिसमें प्रतिगमन विश्लेषण (regression analysis) शामिल है ताकि सामाजिक पृष्ठभूमि और चुनावी परिणामों के बीच संबंध की जांच की जा सके। गुणात्मक डेटा का विश्लेषण विषयगत विश्लेषण (thematic analysis) का उपयोग करके किया जाएगा, जिसमें आवर्ती विषयों और पैटर्न की पहचान करने के लिए साक्षात्कार प्रतिलेखों का कोडिंग किया जाएगा।

## नैतिक विचार

सभी प्रतिभागियों से सूचित सहमति (informed consent) प्राप्त की जाएगी। गुमनामी और गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। अध्ययन को संस्थागत समीक्षा बोर्ड (Institutional Review Board) से अनुमोदन प्राप्त है।

## डेटा विश्लेषण और निष्कर्ष (प्रस्तावित संरचना)

### चुनावी डेटा विश्लेषण

#### 1. मतदान प्रतिशत के पैटर्न

राज्य	2014 (%)	2019 (%)	2024 (%)	परिवर्तन (2014-24)
उत्तर प्रदेश	58.2	59.8	61.3	+3.1
बिहार	56.8	58.4	59.7	+2.9
राजस्थान	66.5	68.7	69.2	+2.7
राष्ट्रीय औसत	66.4	67.4	67.8	+1.4

प्रारंभिक अवलोकन: जबकि मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है, उत्तर भारतीय राज्यों और राष्ट्रीय औसत के बीच का अंतर बना हुआ है।

## 2. उम्मीदवार पृष्ठभूमि विश्लेषण

श्रेणी	2014 (%)	2019 (%)	2024 (%)
आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार	34	43	46
घोषित संपत्ति > ₹10 करोड़ वाले उम्मीदवार	28	37	41
राजनीतिक परिवारों से आने वाले उम्मीदवार	32	35	37

प्रारंभिक अवलोकन: आपराधिक मामलों, उच्च संपत्ति और वंशवादी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का अनुपात महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है।

## 3. संसद में जातीय प्रतिनिधित्व

जाति श्रेणी	जनसंख्या (%)	सांसद (2014)	सांसद (2019)	सांसद (2024)
उच्च जाति	~15	42	44	46
ओबीसी	~40	31	33	34
अनुसूचित जाति	~16	16	15	14
अनुसूचित जनजाति	~8	9	8	8
मुस्लिम	~14	5	4	3

प्रारंभिक अवलोकन: उच्च जातियाँ अत्यधिक प्रतिनिधित्व में हैं, जबकि ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम कम प्रतिनिधित्व में हैं, यह अंतर समय के साथ बढ़ता जा रहा है।

## साक्षात्कार निष्कर्ष (विषयगत विश्लेषण)

### विषय 1: अलगाव और अविश्वास

"मैं 1999 से हर चुनाव में वोट करती आ रही हूँ लेकिन मैंने अपने विधायक को कभी नहीं देखा। वे केवल चुनाव के दौरान आते हैं, और फिर गायब हो जाते हैं। वोट करने का क्या फायदा?" — सुनीता देवी (45), दलित महिला, ग्रामीण उत्तर प्रदेश

"राजनेता केवल अमीर लोगों की परवाह करते हैं। वे अपने व्यापारी दोस्तों के लिए नीतियाँ बनाते हैं। हम गरीब लोगों के लिए, कुछ भी नहीं है।" — राम प्रसाद (52), ओबीसी किसान, बिहार

### विषय 2: प्राथमिक लेंस के रूप में जाति

"हमारे गाँव में, हर कोई अपनी जाति को वोट करता है। यादव एसपी को वोट करते हैं, कुर्मी भाजपा को वोट करते हैं, जाटव बसपा को वोट करते हैं। जाति ही सब कुछ है।" — मुकेश कुमार (38), दलित, उत्तर प्रदेश

"मैं विकास के लिए वोट करना चाहता हूँ लेकिन कौन सी पार्टी वास्तव में हमारे लिए काम करेगी? सभी पार्टियाँ केवल अपने जाति वोट बैंक की परवाह करती हैं।" — मोहम्मद अली (40), मुस्लिम दुकानदार, राजस्थान

### विषय 3: धन और बल

"चुनाव लड़ने के लिए, आपको कम से कम 5-10 करोड़ रुपये चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को यह पैसा कहाँ से मिलेगा? केवल काले धन और आपराधिक संबंधों वाले लोग ही इसे वहन कर सकते हैं।" — प्रदीप सिंह (48), भाजपा कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश

"लोग उन उम्मीदवारों को वोट करते हैं जिनके पास पैसा और बल है क्योंकि उनका मानना है कि वे एक भ्रष्ट व्यवस्था में काम कर सकते हैं।" — डॉ. अंजली शर्मा (35), राजनीतिक वैज्ञानिक, साक्षात्कार

### विषय 4: वंशवादी राजनीति

"हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, तीन पीढ़ियों से एक ही परिवार सत्ता में है। बेटे को पिता से सीट विरासत में मिली। नए लोगों के लिए कोई जगह नहीं है।" — सुरेश मीणा (42), आदिवासी कार्यकर्ता, राजस्थान  
"वंशवाद केवल कांग्रेस में नहीं है। यह हर जगह है—भाजपा में, क्षेत्रीय दलों में। हमारी राजनीति कुछ परिवारों द्वारा चलाई जाती है।" — राजीव रंजन (55), राजनीतिक टिप्पणीकार, बिहार

## प्रतिगमन विश्लेषण

सामाजिक पृष्ठभूमि (जाति, वर्ग) और चुनावी परिणामों के बीच संबंध की जांच करने के लिए निम्नलिखित प्रतिगमन मॉडल का उपयोग किया जाएगा:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

जहाँ:

- $Y$  = चुनावी सफलता (डमी चर: 1=जीता, 0=हारा)
- $X_1$  = जाति श्रेणी (श्रेणीबद्ध: उच्च जाति, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम)
- $X_2$  = संपत्ति वर्ग (सतत: घोषित संपत्ति करोड़ में)
- $X_3$  = आपराधिक पृष्ठभूमि (डमी: 1=आपराधिक मामले हैं, 0=नहीं)

प्रारंभिक परिणाम बताते हैं कि संपत्ति वर्ग और आपराधिक पृष्ठभूमि चुनावी सफलता के महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता हैं, जबकि जाति श्रेणी का कमजोर लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण प्रभाव है।

## चर्चा

### 1. प्रतिनिधित्व का संकट: अनुभवजन्य साक्ष्य

इस अध्ययन के निष्कर्ष भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के संकट के लिए मजबूत अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करते हैं। उच्च मतदान प्रतिशत के बावजूद, राजनीतिक व्यवस्था जनसंख्या के बड़े वर्गों—विशेषकर निचली जातियों, मुसलमानों और आर्थिक रूप से वंचितों—को विफल कर रही प्रतीत होती है।

**प्रतिनिधित्व अंतराल:** डेटा जनसंख्या की सामाजिक संरचना और निर्वाचित प्रतिनिधियों की संरचना के बीच एक महत्वपूर्ण अंतराल दिखाता है। उच्च जातियाँ, जो जनसंख्या का लगभग 15% हैं, लोकसभा सीटों का 45% से अधिक रखती हैं। मुस्लिम, जो जनसंख्या का लगभग 14% हैं, केवल 3-5% सीटें रखते हैं। यह अंतराल पिछले दशक में बढ़ा है, जो बताता है कि प्रतिनिधित्व संकट गहरा रहा है।

**उत्तरदायित्व अंतराल:** साक्षात्कार डेटा हाशिए के समुदायों के बीच गहरे अलगाव की भावना को प्रकट करता है। कई उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को कभी नहीं देखा या उनसे बातचीत नहीं की। यह एक "उत्तरदायित्व अंतराल" का सुझाव देता है—निर्वाचित अधिकारी अपने मतदाताओं, विशेषकर निचले सामाजिक-आर्थिक स्तरों के लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।

## 2. संरचनात्मक कारक: धन, बल और वंशवाद

**धन-बल:** चुनावों की बढ़ती लागत ने राजनीतिक व्यवस्था को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के बिना उम्मीदवारों के लिए प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। 2024 के आम चुनावों में प्रति उम्मीदवार औसत व्यय ₹5 करोड़ से अधिक होने का अनुमान था, कुछ उम्मीदवारों ने ₹20 करोड़ से अधिक खर्च किए। यह सामान्य नागरिकों को चुनाव लड़ने से बाहर करता है, अभिजात वर्ग के प्रभुत्व को कायम रखता है।

**अपराधीकरण:** अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या गहरी चिंता का विषय है। मतदाताओं की "कठोर" उम्मीदवारों के लिए प्राथमिकता, जैसा कि वैष्णव (2017) ने नोट किया है, एक ऐसी व्यवस्था के लिए एक तर्कसंगत प्रतिक्रिया है जहाँ अपराध और राजनीतिक शक्ति आपस में जुड़े हुए हैं। हालाँकि, यह एक दुष्चक्र बनाता है: अपराधी राजनेता बन जाते हैं, और राजनेता अपराधी बन जाते हैं।

**वंशवादी राजनीति:** वंशवादी राजनीति हाशिए की पृष्ठभूमि के नए प्रवेशकों के लिए राजनीतिक अवसरों को सीमित करती है। जबकि राजनीतिक वंशवाद सभी लोकतंत्रों में मौजूद हैं, भारत में उनकी व्यापकता असाधारण रूप से अधिक है। परिवारों के भीतर राजनीतिक शक्ति का यह केंद्रीकरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों—योग्यता और समान अवसर—को कमजोर करता है।

## 3. सैद्धांतिक निहितार्थ

**अभिजात वर्ग सिद्धांत का पुनर्विज़िट:** इस अध्ययन के निष्कर्ष काफी हद तक अभिजात वर्ग सिद्धांत का समर्थन करते हैं। लोकतंत्र के औपचारिक तंत्रों के बावजूद, राजनीतिक शक्ति एक छोटे अभिजात वर्ग—जाति, वर्ग और पारिवारिक संबंधों द्वारा परिभाषित—के बीच केंद्रित बनी हुई है। मिखेल्स का "लोहे का नियम" भारतीय संदर्भ में सही प्रतीत होता है।

**बहुलवादी सिद्धांत की सीमाएँ:** निष्कर्ष बहुलवादी धारणाओं को चुनौती देते हैं कि शक्ति फैली हुई है। भारतीय राजनीति में शक्ति को फैलाने के बजाय, शक्ति प्रभावी समूहों के बीच केंद्रित है। हाशिए के समुदायों का राजनीतिक परिणामों पर सीमित प्रभाव है।

**जाति-वर्ग अंतर्संबंध:** अध्ययन राजनीतिक परिणामों को आकार देने में जाति और वर्ग के अंतर्संबंध को उजागर करता है। उच्च जातियाँ न केवल संख्यात्मक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी हावी हैं। जातीय पूंजी और आर्थिक पूंजी का संयोजन निचली जातियों के लिए प्रतिनिधित्व में एक गंभीर बाधा पैदा करता है।

#### 4. नीतिगत निहितार्थ

**चुनावी सुधार:** कई चुनावी सुधार प्रतिनिधित्व के संकट को संबोधित कर सकते हैं:

- **चुनावों का राज्य वित्तपोषण:** निजी धन पर निर्भरता कम करने से प्रतिस्पर्धी मैदान समतल होगा।
- **प्रचार व्यय पर अधिक कड़ी सीमा:** वर्तमान सीमाओं का व्यापक रूप से उल्लंघन किया जाता है और उन्हें कड़े प्रवर्तन की आवश्यकता है।
- **आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता:** लंबित परीक्षण बाधा नहीं होने चाहिए, लेकिन दोषी अपराधियों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

**सकारात्मक कार्रवाई:** आरक्षण नीतियों का विस्तार और सुदृढीकरण किया जाना चाहिए। जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभाओं में आरक्षण मौजूद है, ओबीसी और मुस्लिम कम प्रतिनिधित्व में हैं। राजनीतिक दलों को हाशिए के समुदायों से अधिक उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए प्रोत्साहित (या बाध्य) किया जाना चाहिए।

**संस्थागत सुधार:** स्थानीय शासन (पंचायती राज) को मजबूत करने से जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। हालाँकि, राज्य सरकारों स्थानीय निकायों को सत्ता और संसाधन हस्तांतरित करने में अनिच्छुक रही हैं।

**मतदाता शिक्षा:** मतदाताओं को पहचान-आधारित मतदान पर मुद्दा-आधारित मतदान के महत्व के बारे में शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। नागरिक समाज संगठन इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

#### निष्कर्ष

##### निष्कर्षों का सारांश

इस अध्ययन ने समकालीन भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के संकट की जांच की है। मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. **प्रतिनिधित्व अंतराल:** उच्च जातियाँ संसद में अत्यधिक प्रतिनिधित्व में हैं, जबकि ओबीसी, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और मुस्लिम कम प्रतिनिधित्व में हैं। यह अंतराल पिछले दशक में बढ़ा है।

2. **उत्तरदायित्व अंतराल:** हाशिए के समुदाय राजनीतिक व्यवस्था से अलग-थलग महसूस करते हैं, उनका कहना है कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधि उनकी आवश्यकताओं के प्रति अनुत्तरदायी हैं।
3. **संरचनात्मक बाधाएँ:** धन-बल, अपराधीकरण और वंशवादी राजनीति हाशिए की पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश में गंभीर बाधाएँ पैदा करती हैं।
4. **विश्वास की कमी:** लोकतांत्रिक संस्थाओं—विशेषकर राजनीतिक दलों और निर्वाचित प्रतिनिधियों—में विश्वास घट रहा है, विशेषकर निचली जातियों और आर्थिक रूप से वंचितों के बीच।

## योगदान

यह अध्ययन कई योगदान देता है। अनुभवजन्य रूप से, यह नवीनतम चुनावी परिणामों (2024) का उपयोग करके भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व पर अद्यतन डेटा प्रदान करता है। पद्धतिगत रूप से, यह मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोणों को जोड़ता है, जो स्थूल-स्तरीय पैटर्न और सूक्ष्म-स्तरीय अनुभवों दोनों को कैप्चर करता है। सैद्धांतिक रूप से, यह प्रतिनिधित्व के संकट को समझने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए अभिजात वर्ग सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और अंतर्संबंधवादी विश्लेषण को एकीकृत करता है।

## सिफारिशें

निष्कर्षों के आधार पर, निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तावित हैं:

1. **चुनाव आयोग के लिए:** चुनाव वित्त कानूनों को सख्ती से लागू करें। आपराधिक सजा वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करें। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार करें।
2. **राजनीतिक दलों के लिए:** हाशिए के समुदायों से अधिक उम्मीदवारों को टिकट दें। उम्मीदवार चयन में धन के प्रभाव को कम करें। आंतरिक लोकतंत्र को लागू करें।
3. **नागरिक समाज के लिए:** चुनावी सुधारों के लिए वकालत करें। निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रदर्शन की निगरानी करें। राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाएँ।
4. **नागरिकों के लिए:** पहचान और प्रदर्शन के आधार पर मुद्दों पर वोट करें। निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाएँ। स्थानीय शासन में भाग लें।

## भविष्य के शोध के लिए दिशा-निर्देश

भविष्य के शोध को इस अध्ययन की सीमाओं को संबोधित करना चाहिए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तुलनात्मक अध्ययन क्षेत्रीय भिन्नताओं की पहचान करने में मदद करेंगे। समान निर्वाचन क्षेत्रों को ट्रैक

करने वाले दीर्घकालिक अध्ययन परिवर्तन के पैटर्न को समझने में मदद करेंगे। प्रतिनिधित्व के वैकल्पिक मॉडल—जैसे सहभागी बजटिंग और नागरिक सभाएँ—पर शोध संकट के संभावित समाधानों की पहचान करने में मदद करेगा।

## संदर्भ

(नोट: यह एक सांकेतिक ग्रंथ सूची है; वास्तविक शोध में पूर्ण उद्धरणों की आवश्यकता होगी)

1. बर्धन, पी. (1984). *द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
2. चंद्रा, के. (2004). *व्हाई एथनिक पार्टीज सक्सीड*. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. डाल, आर. (1956). *अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी*. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस.
4. देशपांडे, एस. (2011). *कास्ट एंड पॉलिटिक्स*. इन एन. जी. जायल और पी. बी. मेहता (संस्करण), *द ऑक्सफोर्ड कम्पेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
5. ग्राम्शी, ए. (1971). *सेलेक्शन्स फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक्स*. इंटरनेशनल पब्लिशर्स.
6. जाफ्रेलॉट, सी. (2003). *इंडियाज साइलेंट रिवोल्यूशन*. कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस.
7. जोधका, एस. (2018). *कास्ट इन कंटेम्पररी इंडिया*. रूटलेज.
8. कोहली, ए. (2012). *पॉवर्टी एंड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया*. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
9. मार्क्स, के., और एंगेल्स, एफ. (1848). *द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो*.
10. मिखेल्स, आर. (1911). *पॉलिटिकल पार्टीज*. फ्री प्रेस.
11. मिल्स, सी. डब्ल्यू. (1956). *द पावर एलीट*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
12. मोस्का, जी. (1896). *द रूलिंग क्लास*. मैकग्रा-हिल.
13. पैरेटो, वी. (1916). *द माइंड एंड सोसाइटी*. हार्कोर्ट, ब्रेस.
14. रुडोल्फ, एल., और रुडोल्फ, एस. (1967). *द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन*. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस.
15. वैष्णव, एम. (2017). *व्हेन क्राइम पेज*. येल यूनिवर्सिटी प्रेस.

## **Reproductive Health Challenges of Married Women: A Study of Selected Blocks in North 24 Parganas District, Sundarbans Region**

**Moumee Jesmin**

Research Scholar,  
Department of Social Work, St.  
Xavier's University, Kolkata

**Dr. Rupa Biswas**

Assistant Professor,  
Department of Social Work, St.  
Xavier's University, Kolkata

---

### **Abstract**

The reproductive health issues among married women of the Hingalganj and Sandeshkhali blocks located in the environmentally sensitive Sundarbans region have been analyzed. Information has been collected using interview schedule from 60 respondents. Findings indicate that all respondents (100%) suffered from menstrual health issues; out of them, 55% were affected by urinary tract infections (UTIs), pregnancy complications etc. Anemia and malnutrition occurred frequently in 56.7% and 43.3%, respectively, among pregnant women and 43.3% practiced contraception. Distance from hospitals, cost of treatment, and societal taboos were the major factors preventing people from accessing healthcare services; 41.7%, 36.7%, and 21.7%, respectively, mentioned them as hindrances. All respondents indicated that they work in salinity-affected areas for at least two to four hours daily. Moreover, climate disaster negatively impacted respondents' access to healthcare facilities.

Keywords: Reproductive health, Married Women, Menstrual hygiene, Health-seeking behavior.

**Keywords:** *Reproductive health, Married Women, Menstrual hygiene, Health-seeking behavior*

## **Introduction**

Sundarbans, the largest mangrove delta in the world, stretching across the South and North 24 Parganas districts of West Bengal in India, is an area of ecological importance and human vulnerability. The physical disconnectedness of the regions, with many islands reachable by water transport alone, makes it hard to provide timely reproductive healthcare services to the residents. This problem is further exacerbated by the rising intensity of cyclonic calamities, namely Aila (2009), Bulbul (2019), Amphan (2020), and Yaas (2021) etc.

This research relies on primary information obtained from 60 married females residing in the Hingalganj and Sandeshkhali blocks of North 24 Parganas to discuss reproductive health concerns and health seeking behavior of married women.

## **Review of Literature**

Various studies have documented reproductive health issues for married women residing in climate-vulnerable areas of India. However, the interconnection of climate vulnerability, occupational risk, and social marginalization in relation to reproductive health concerns has not received sufficient attention in relation to North 24 Parganas. The present literature is fundamental to providing background information on the research findings.

This dependence reflects broader issues of poverty, limited awareness, and inadequate healthcare access. Paul and Rai (2025) further highlight that climate-related challenges, such as flooding and displacement, worsen these inequalities by restricting access to healthcare and sanitation. Together, these studies emphasize the need for improved access to affordable menstrual products and better healthcare infrastructure in the region. Dasgupta et al. (2022) found that women engaged in fishing practices and drinking water from high-salinity tube wells in the Sundarbans were prone to gynecological and systemic health issues.

Studies on menstrual health and hygiene management underscore the convergence of poverty, stigma, and inadequate sanitation in shaping women's practices. Research in rural South India by Gopalakrishnan et al. (2019) found that 67% of women experienced gynecological problems, with menstrual irregularities, urinary tract infections (14%), and reproductive tract infections (11.6%) most prevalent among economically marginalized women.

Maternal healthcare utilization in remote and underserved areas is systematically constrained by geographical distance, transportation barriers, financial cost, and cultural norms. Barman et al. (2016) highlighted that home deliveries in the Sundarbans persist due to isolation, poor road connectivity, and strong cultural preferences for traditional midwifery.

Globally, the literature consistently identifies contraceptive non-use as a marker of diminished women's reproductive autonomy, with consequences for maternal health and family well-being (Pham et al., 2020).

The evidence specific to women's reproductive health outcomes during and after disasters in North 24 Parganas is sparse. Biswas (2013) observed high maternal and child mortality in the Sundarbans islands, attributing it to extreme isolation, inadequate health infrastructure, and insufficient government response—conditions that intensify during disasters. This study contributes to filling this gap by situating reproductive health challenges within the climate vulnerability framework specific to North 24 Parganas.

### **Objectives of the Study**

- The study is guided by the following specific objectives:
- To understand the reproductive health challenges of married women in Hingalganj and Sandeshkhali blocks of North 24 Parganas.
- To know the health-seeking behavior related to reproductive health issues among them.

## **Methodology**

### **Research Design**

This study employed a descriptive research design with a primarily quantitative approach, supplemented by qualitative case studies to provide depth and contextual understanding. The descriptive design was selected to systematically document the reproductive health challenges, health-seeking behavior, and associated determinants among married women in the study area, without experimental manipulation.

### **Study Population and Sampling**

The target population comprised married women of reproductive age (18–49 years) residing in Hingalganj and Sandeshkhali blocks. A total of 60 respondents were selected using purposive sampling to ensure the inclusion of women across different age groups, caste categories, educational backgrounds, and family types. Of the total sample, 33 respondents (55%) were from Hingalganj block and 27 (45%) from Sandeshkhali block. Inclusion criteria required that respondents be currently married, resident in the study area for at least one year, and willing to provide informed consent.

### **4.3 Data Collection Instruments and Procedures**

Two primary data collection instruments were employed:

Structured Interview Schedule

Case Studies

### **Data Analysis**

Quantitative data from the structured interview schedules were analyzed using descriptive statistical methods including frequencies and percentages, Qualitative data from case studies were analyzed using thematic analysis.

### **Ethical Considerations**

Informed consent was obtained from all participants in their local language (Bengali) before any data collection activity. Participants were fully informed of

the voluntary nature of their participation, their right to withdraw at any stage without consequence, and the measures in place to protect confidentiality and anonymity. All identifying information was removed during data entry and analysis.

## Results and Findings

This section presents the findings from the structured survey of 60 married women in Hingalganj and Sandeshkhali blocks of North 24 Parganas, supplemented by case study insights. All 60 respondents are from North 24 Parganas district, engaged exclusively in agri-fishery livelihoods, and all reported exposure to saline water for 2–4 hours daily.

### Socio-Demographic Profile of Respondents

The table presents the distribution of respondents according to their socio-demographic characteristics. It includes variables such as age, education, age at marriage, number of children, caste, family type, income, and block. The data are presented in terms of frequency and percentage.

**Table 1: Socio-Demographic Profile of Respondents (N=60, North 24 Parganas)**

Variable		n (N=60)	%
Block	Hingalganj	33	55.0%
	Sandeshkhali II	27	45.0%
Age Group	18–25 years	16	26.7%
	26–33 years	14	23.3%
	34–41 years	19	31.7%

Variable		n (N=60)	%
Block	Hingalgañj	33	55.0%
	Sandeshkhali II	27	45.0%
	42–49 years	11	18.3%
Education	Illiterate	25	41.7%
	Primary	14	23.3%
	Secondary	21	35.0%
Age at Marriage	18–20 years	26	43.3%
	21–23 years	34	56.7%
No. of Children	One	15	25.0%
	Two	43	71.7%
	Three	2	3.3%
Caste	OBC	25	41.7%
	SC	24	40.0%
	ST	11	18.3%
Monthly Income	Below ₹10,000	58	96.7%
	₹20,000– ₹30,000	2	3.3%

A high proportion, 96.7% lived on monthly household incomes below ₹10,000, confirming the extreme economic precariat of these communities. Age at marriage ranged from 18 to 23 years, with 43.3% married between 18–20 years, indicating the persistence of early marriage despite legal prohibitions. The majority had two children (71.7%), with a small proportion (3.3%) having three or more.

### 1. Reproductive Health Challenges and Health Seeking Behavior

Table 2 presents the key reproductive health indicators across the four dimensions of menstrual health, UTI burden, pregnancy-related complications, and environmental exposure.

*Table 2: Menstrual Health, Reproductive Morbidity, and Environmental Exposure (N=60)*

Indicator		n	%
Menstrual Problems Reported	Yes (all respondents)	60	100%
Sanitary Product Used	Sanitary Napkin	32	53.3%
	Cloth	28	46.7%
Consulted Doctor for Menstrual Issues	Yes	27	45.0%
	No	33	55.0%
UTI Prevalence	Yes	33	55.0%

Indicator		n	%
	No	11	18.3%
	Don't Know	16	26.7%
Pregnancy Complications	Anemia	34	56.7%
	Malnutrition	26	43.3%
Miscarriage History	Yes	16	26.7%
	No	44	73.3%
Saline Water Exposure	2–4 hours daily (all)	60	100%
Disaster Affects Health Access	Yes (all respondents)	60	100%

## 2.1 Menstrual Health and Hygiene

All 60 respondents (100%) reported experiencing menstrual health problems. While 53.3% used sanitary napkins, 46.7% continued to use cloth: a practice associated with infection risk particularly under conditions of inadequate sanitation and limited access to clean water for washing and drying. 55% of women did not consult a healthcare provider for their menstrual concerns, reflecting a combination of stigma and limited awareness.

The occupational context amplifies menstrual health risks significantly. All respondents were engaged in agri-fishery work involving 2–4 hours of daily saline

water exposure. Women continue this work through their menstrual cycle in the absence of adequate protective equipment and clean toilet facilities.

## 2.2 UTI Burden

Urinary tract infections affected 55 % of the study population, while an additional 26.7 % of the respondents were not sure whether they had UTIs, which can be attributed to either misdiagnoses or low health literacy when it comes to genitourinary disorders. Eighteen point three percent of the population was determined to be free of UTIs. These numbers indicate a problem that can be seen in other similar environments where there is exposure to contaminated water, insufficient sanitation facilities, and poor management of menstrual hygiene.

## 2.3 Pregnancy-Related Complications

In cases where there was a pregnancy experience, it is important to note that 56.7% of the respondents suffered from anemia while 43.3% suffered from malnutrition, both of which are highly inter-related due to poor diet, overworking and lack of nutritional supplements.

### 1. Contraceptive Use and Decision – Maker & Barrier to Healthcare Access

*Table 3: Contraceptive Use, and Decision-Making (N=60)*

Indicator		n	%
Contraceptive Use	Yes	26	43.3%
	No	34	56.7%
Decision-Making on Health	Spouse	28	46.7%

Indicator		n	%
	Respondent	24	40.0%
	Joint/Together	8	13.3%
Primary Access Barriers	Distance to facility	25	41.7%
	Financial cost	22	36.7%
	Stigma/social norms	13	21.7%

Contraceptive use remained low at 43.3%, with non-use driven primarily by partner opposition (reported by 10%) and structural factors including distance and cost. Condoms were used by only 6 respondents (10% of those using contraception), and tubectomy was reported by none, suggesting that permanent family planning methods remain socially or programmatically inaccessible. Healthcare decision-making was predominantly spouse-controlled (46.7%), with only 40% of women reporting agency over their own health decisions and 13.3% reporting joint decision-making.

Distance was the most cited barrier (41.7%), consistent with the geographical fragmentation of the study area. Financial cost (36.7%) was the second most significant barrier, particularly for consultations and medications not covered by government schemes. Social stigma, especially around menstrual and reproductive health conditions was responded by 21.7% as a deterrent to care-seeking

### Reflections from Case Studies

The case studies presented below were selected to illustrate the range and depth of reproductive health challenges experienced by married women in North 24 Parganas.

## **Occupational Hazard and Menstrual Health**

Ria, a married lady of 34 years who works in aquaculture, performs physically strenuous work in the brackish water for 2-4 hours every day, even during her menstruation periods. Since the lack of hygienic facilities in her workplace and economical compulsions of her family’s livelihood from her earnings force her to continue working regardless of her menstrual problems. Ria faces recurrent infections in her reproductive tract but remains undiagnosed and untreated. At first, she was not aware of having a problem with her menstrual cycle because irregularities in menstrual flow, cramps, irritation in the vagina, and rashes were common among women and there was even a myth that certain medicines would impair sexual functioning and the reproductive capability of a woman. Hence, she suffered from a serious problem with her irregular periods and profuse bleeding, causing her to visit doctors in sub-centers and district hospitals, though waiting time to consult doctors was extremely long. Ria admitted that she had been suffering from this problem for six years but did not take it seriously before. It is due to personal neglect and system-related causes and necessitates labor laws related to women’s reproduction in this region.

## **Gender-Based Health-Seeking Behavior**

Anjana, who got married at the age of 18 and has completed her education up to 11th class, has already been a mother to one child. She was keen to have an interval between her pregnancies for her own good and economic stability. But unfortunately, her husband, aged 25 years, does not agree to use condoms, thus controlling all decisions regarding her pregnancy in her body. Not being prepared for having another baby at such an early age and also engaging in agriculture and fishery work, she takes birth-control pills; however, some side-effects like headache, breast tenderness, irregular spotting and breakthrough bleeding occur because of the use of these pills. She discussed the problem with ASHA and ASHA suggested her to discontinue taking the pills temporarily and use condoms. She

informed the problem to her husband but he neither wanted her to use birth control methods nor condoms.

She suffers from the dangers to her health due to her close spacing of her children, loses out on economic opportunities due to the early onset of childbearing, and experiences emotional distress because she lacks control over her reproductive rights. Her situation serves as a reflection of a much larger trend. She is frustrated and stressed, supporting her family financially while also bearing the full weight of the domestic burdens but failing to make decisions regarding sexuality and reproduction. Solutions for this need involvement of men in family planning projects along with norms of community that would confirm the reproductive right of women. Awareness and education would help resolve this problem and effect change in society for the benefit of married women as well as families and the country in general.

## **Discussion**

### **1. Reproductive Health Challenges**

According to the results of this study, the reproductive health issues faced by married women living in North 24 Parganas form a multi-level crisis based on the interconnection between occupational hazard, environmental vulnerability, poverty, and systemic gender disparities. The high prevalence of menstrual health issues (100%) among participants in the survey should be understood not only as a medical condition but rather as a social problem. It is indicative of the routine nature of reproductive distress in societies where the reproductive health of women is neglected, where work comes first, and where no protective measures at the workplace ensure their safety.

The high rates of UTI cases (55%) and pregnancy anemia (56.7%) are interlinked effects that arise from the same structural factors including long-time exposure to salty water without adequate protection, use of clothing instead of pads because of lack of money, poor sanitary facilities at the work places, insufficient nutrition,

and lack of preventive medical care. Such problems cannot be tackled by individuals through mere behavior modification.

Gender inequality operates as a cross-cutting determinant of reproductive health in this context. Spouse-dominated decision-making (46.7%) directly constrains women's ability to seek care and adopt contraception.

## **2. Health-Seeking Behavior**

In married women in North 24 Parganas, health-seeking behavior is influenced by an architecture of barriers stacked one above the other. When no catastrophe occurs, the major barriers are geographical remoteness (41.7%), economic expense (36.7%), and the stigma attached to menstruation and reproduction (21.7%). The cumulative result is that a sizeable number of women suffer reproductive illness in silence and without treatment. During disasters, health-seeking behavior collapses entirely for many women.

### **Suggestions**

To improve women's livelihoods and healthcare access, alternative occupations for women such as tailoring, handicrafts, dairy farming, and small-scale entrepreneurship should be promoted with proper training and financial support. Alongside this, mobile health clinics should be introduced more widely with better structure and improved facilities. Songs, role play and other IEC method can be used to make the information easy accessible for all. The provision of basic sanitation facilities: clean toilets, water for handwashing, and covered drying spaces at aquaculture and agricultural sites and in the cyclone shelters should be made mandatory and monitored by local panchayats and labor departments.

For women engaged in prolonged saline water immersion, the distribution of waterproof protective garments (such as water-resistant aprons or lower-body protection) through CSR initiatives or government schemes could reduce direct contact between saline water and the reproductive tract during work and during menstruation. Civil society organizations should be encouraged to develop and pilot such interventions.

## Conclusions

Reproductive health issues among married women in North 24 Parganas District are rooted deeply in the social structure of Sundarbans, such as its vulnerability, poverty, and geographical location. In this research, based on surveys conducted among 60 respondents, as well as information from case studies, it is found that reproductive health issues faced by married women of this region are universal, not unique: all the women interviewed faced problems related to their menstrual health; all the women come in contact with saline water on a daily basis while working; all the women lacked access to healthcare facilities due to climatic events.

It's not enough for women living in North 24 Parganas to be provided with more initiatives; what they need is access to healthcare services regardless of whether they live on an island or in a flooded shelter or are working in aquaculture farms or observing silence due to the stigma attached to pregnancy. It's not just a plan for disasters that should include reproductive health care as part of the essential infrastructure but also a community where men should become partners in reproductive decisions rather than controlling them. The point is that resilience in women should not replace the system of care that women deserve.

## References

1. Ahmed, S., Hasan, M. J., Pongsiri, M. J., Ahmed, M. W., & Szabo, S. (2020). *Effect of extreme weather events on injury, disability, and death in Bangladesh. Climate and Development.* <https://doi.org/10.1080/17565529.2020.1772705>
2. Akter, S., Rich, J. L., Davies, K., & Inder, K. J. (2019). *Access to maternal healthcare services among Indigenous women in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh: A cross-sectional study. BMJ Open, 9(10), e033224.* <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-033224>
3. Barman, S. K., Dasgupta, A., & Biswas, B. (2016). *Factors influencing institutional delivery among women of Sundarbans, India. Indian Journal of Community Medicine, 41(3), 212–216.*

4. Biswas, B. (2013). 'The god of death takes half of our children': Health of women and children in the Sundarbans Islands. *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, 24(2), 730–740. <https://doi.org/10.1353/hpu.2013.0069>
5. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
6. Dasgupta, A., Sarkar, K., Chowdhury, R., Ray, A., & Shahbabu, B. (2016). Anemia and its determinants among women of reproductive age in a slum in Kolkata. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 5(2), 276–280.
7. Dasgupta, S., Wheeler, D., & Ghosh, S. (2022). Fishing in salty waters: Poverty, occupational saline exposure, and women's health in the Indian Sundarbans. *Journal of Management and Sustainability*, 12(1).
8. Ghule, M., Raj, A., Palaye, P., Dasgupta, A., Nair, S., Saggurti, N., Battala, M., & Balaiah, D. (2015). Barriers to use contraceptive methods among rural young married couples in Maharashtra, India: Qualitative findings. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 5(6), 18–33.
9. Gopalakrishnan, S., AnanthaEashwar, V. M., Mohan Kumar, P., & Umadevi, R. (2019). Reproductive health status of rural married women in Tamil Nadu: A descriptive cross-sectional study. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 8(11), 3607–3613. [https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc\\_523\\_19](https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_523_19)
10. Let, S., Tiwari, S., Singh, A., et al. (2024). Prevalence and determinants of anaemia among women of reproductive age in Aspirational Districts of India: An analysis of NFHS 4 and NFHS 5 data. *BMC Public Health*, 24, 437. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-17789-3>
11. Panda, S., Sadhu, C., Pramanik, G., et al. (2016). Concerning public health situation of under-nutrition in children and anemia in women in Indian Sundarbans delta: A community-based cross-sectional investigation. *BMC Nutrition*, 2, 65. <https://doi.org/10.1186/s40795-016-0105-3>
12. Paul, A. A., & Rai, B. B. (2025). Title of the article in sentence case. Title of Journal, volume number(issue number), page range. <https://doi.org/xxxxx>

13. Paul, K. M. (2022). *Health seeking behaviour among married women in Northern Nigeria: A framework to promote autonomy [Doctoral Dissertation, Durban University of Technology]*.
14. Pham, B. N., Whittaker, M., Okely, A. D., & Pomat, W. (2020). *Measuring unmet need for contraception among women in rural areas of Papua New Guinea. Sexual and Reproductive Health Matters, 28(2).*  
<https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1848004>
15. Sahoo, K. C., Negi, S., Patel, K., Mishra, B. K., Palo, S. K., & Pati, S. (2021). *Challenges in maternal and child health services delivery and access during pandemics or public health disasters in low- and middle-income countries: A systematic review. Healthcare (Basel), 9(7), 828.*  
<https://doi.org/10.3390/healthcare9070828>
16. Sharif, N., Das, B., & Alam, A. (2023). *Prevalence of anemia among reproductive women in different social groups in India: Cross-sectional study using nationally representative data. PLoS One, 18(2), e0281015.*  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281015>

# A Comparative Study of Corporate Criminal Liability and Corporate Offences under the Indian Legal System: A Legal Study

**Jitendra kumar Meena**

Research Scholar,

Shyam University, Dausa, Rajasthan

**Dr. Phool Chand Saini**

Supervisor

Shyam University, Dausa, Rajasthan

---

## Abstract

Corporate criminal liability has emerged as a crucial component of modern legal systems due to the increasing role of corporations in economic and social spheres. Traditionally, corporations were considered incapable of committing crimes because of their artificial legal personality. However, with the evolution of jurisprudence, especially in India, corporations are now recognized as liable for criminal acts committed by their agents, directors, and employees. This research paper examines the concept, development, and legal framework of corporate criminal liability in India, along with an analysis of corporate offences under various statutes. It further provides a comparative understanding of liability principles such as vicarious liability, identification theory, and strict liability. The study critically evaluates judicial trends, statutory provisions, and challenges in enforcement, and suggests reforms for strengthening corporate accountability. The research adopts a doctrinal methodology based on case laws, statutes, and scholarly writings.

**Keywords :** Corporate Criminal Liability, Corporate Offences, Indian Penal Code, Vicarious Liability, Mens Rea, Companies Act, White-Collar Crime

## Introduction

In the contemporary era, corporations play a dominant role in economic development and governance. With this expansion, corporate misconduct such as fraud, environmental violations, corruption, and financial irregularities has also increased. Traditionally, criminal law focused on natural persons, but modern legal systems have recognized corporations as separate legal entities capable of committing crimes.

Corporate criminal liability refers to the legal accountability of a company for criminal acts committed by its agents within the scope of employment. Indian law recognizes corporations as “persons” under criminal jurisprudence, making them liable for offences under various statutes.

## Concept of Corporate Criminal Liability

Corporate criminal liability is based on the principle that a company, though an artificial person, can act through its human agents. When such agents commit offences within their authority, liability is attributed to the corporation.

The doctrine is primarily based on:

- **Vicarious Liability** – The company is held liable for acts of its employees.
- **Identification Theory (Alter Ego Doctrine)** – The intent (mens rea) of key managerial persons is treated as the intent of the corporation.
- **Strict Liability** – Liability without proof of intention in certain statutory offences

## Corporate liability arises when acts are committed:

- Within the scope of employment
- For the benefit of the corporation

## Evolution of Corporate Criminal Liability in India

Initially, Indian courts were reluctant to impose criminal liability on corporations due to:

- Absence of mens rea

- Impossibility of imprisonment

However, judicial developments changed this perspective:

- Recognition that corporations can possess intent through their directors and officers
- Acceptance that corporations can be punished with fines even where imprisonment is prescribed

The Supreme Court affirmed that corporations can be prosecuted even for offences requiring mens rea.

Thus, corporate criminal liability is now a well-established doctrine in Indian jurisprudence.

## **Legal Framework Governing Corporate Criminal Liability in India**

Corporate criminal liability in India is governed by a composite framework of general criminal law and specialized statutory enactments. The Indian legal system recognizes corporations as juristic persons capable of committing criminal offences and being subjected to penal consequences. This liability is dispersed across multiple legislations, reflecting its wide ambit and functional necessity.

### **1. Indian Penal Code, 1860**

The Indian Penal Code (IPC) constitutes the foundational criminal statute in India and recognizes corporations as “persons” within its ambit. Consequently, corporations may be held liable for offences such as cheating (Section 415), criminal breach of trust (Section 405), and fraud.

Judicial interpretation has expanded the scope of corporate liability under the IPC. In *Standard Chartered Bank v. Directorate of Enforcement*, the Supreme Court of India affirmed that corporations can be prosecuted even where imprisonment is prescribed, with fines serving as an alternative punishment.<sup>1</sup>

### **2. Companies Act, 2013**

The Companies Act, 2013 provides a comprehensive regulatory framework governing corporate conduct and accountability. It imposes criminal liability on companies and their officers for offences such as fraud (Section 447), mismanagement, and non-compliance with statutory obligations.

The Act incorporates the principle of “**officer in default**,” thereby attributing liability to individuals responsible for corporate decision-making. This principle was judicially examined in *Sunil Bharti Mittal v. Central Bureau of Investigation*, where the Court emphasized that liability of directors is contingent upon their active role and criminal intent.<sup>2</sup>

### 3. Other Relevant Statutes

Corporate criminal liability is further governed by several special statutes:

- Prevention of Corruption Act, 1988 – Addresses bribery and corruption involving corporate entities
- Prevention of Money Laundering Act, 2002 – Penalizes laundering of illicit funds
- Negotiable Instruments Act, 1881 – Governs cheque dishonour and corporate financial liability
- Information Technology Act, 2000 – Deals with cyber offences and digital fraud

The multiplicity of statutes demonstrates that corporate criminal liability in India is sector-specific and decentralized, necessitating harmonization for effective enforcement.

### Corporate Offences under Indian Law

Corporate offences refer to unlawful acts committed by companies during the course of business operations. These offences are typically categorized as white-collar crimes, characterized by deceit, concealment, and abuse of trust for financial gain.

#### 1. Economic Offences

These include:

- Fraud and misrepresentation
- Insider trading
- Tax evasion

Such offences undermine financial integrity and investor confidence.

## 2. Environmental Offences

Corporations may incur liability for:

- Pollution and ecological damage
- Non-compliance with environmental regulations

These offences highlight the tension between industrial growth and environmental sustainability.

## 3. Labour and Industrial Offences

These include:

- Violation of labour welfare laws
- Workplace safety negligence

Such offences affect employee rights and industrial relations.

## 4. Financial and Cyber Offences

These include:

- Money laundering
- Cyber fraud and data breaches

With technological advancement, cyber-related corporate offences are rapidly increasing.

## Comparative Analysis: Corporate Criminal Liability vs Corporate Offences

Basis	Corporate Criminal Liability	Corporate Offences
Meaning	Legal principle fixing responsibility	Actual criminal acts committed
Nature	Doctrinal and conceptual	Substantive offences
Focus	Attribution of liability	Nature of crime

Basis	Corporate Criminal Liability	Corporate Offences
Application	Based on legal theories (vicarious, identification)	Based on statutory provisions
Objective	Determination of accountability	Definition of punishable conduct

### Key Distinction:

Corporate criminal liability constitutes the juridical mechanism of attribution, whereas corporate offences represent the substantive acts triggering such liability.

### Judicial Approach in India

The Indian judiciary has played a pivotal role in evolving the doctrine of corporate criminal liability. Courts have progressively recognized that corporations can possess criminal intent through their human agents.

In *Iridium India Telecom Ltd. v. Motorola Inc.*, the Supreme Court held that the **mens rea of the “directing mind”** of a corporation can be attributed to the company itself.<sup>3</sup>

Further, judicial decisions have clarified that:

- Corporations can be prosecuted for offences involving intent
- Directors are not automatically liable; liability depends on role, responsibility, and intent
- The “person in charge” principle determines individual accountability

Courts frequently apply:

- Attribution (Identification) Theory
- Vicarious Liability
- Alter Ego Doctrine

### Challenges in Corporate Criminal Liability

Notwithstanding the significant doctrinal and judicial advancements, the practical enforcement of corporate criminal liability in India continues to face several

structural and conceptual challenges. These challenges impede the effective realization of corporate accountability and necessitate critical evaluation.

### **1. Attribution of Mens Rea**

One of the most fundamental challenges lies in attributing *mens rea* (criminal intent) to a juristic entity. Since a corporation lacks physical existence and consciousness, the identification of intent must be derived from its human agents.

The Supreme Court of India, in *Iridium India Telecom Ltd. v. Motorola Inc.*, attempted to resolve this issue by applying the “directing mind and will” doctrine, whereby the mental state of key managerial personnel is imputed to the corporation.<sup>1</sup>

However, in large corporations with decentralized decision-making structures, determining whose intent constitutes the “directing mind” remains highly complex. This creates ambiguity and inconsistency in judicial outcomes.

### **2. Punishment Constraints**

Another significant limitation arises from the nature of punishments under criminal law. Corporations, being artificial persons, cannot be subjected to imprisonment, which is a primary mode of punishment under penal statutes.

In *Standard Chartered Bank v. Directorate of Enforcement*, the Supreme Court held that corporations may be punished with fines even where imprisonment is mandatory.<sup>2</sup>

While this ruling ensures that corporations do not escape liability, it simultaneously raises concerns regarding the adequacy and deterrent value of monetary penalties, particularly for large multinational corporations with substantial financial resources.

### **3. Diffused Corporate Structure**

Modern corporations are characterized by complex organizational hierarchies, involving multiple layers of management, subsidiaries, and cross-border operations. This diffusion of authority creates significant challenges in identifying the individuals responsible for criminal conduct.

The principle of vicarious liability is not automatically applicable in criminal law, as reaffirmed in *Sunil Bharti Mittal v. Central Bureau of Investigation*, where the Court held that liability of directors must be based on specific evidence of active involvement and intent.<sup>3</sup>

Consequently, the fragmented nature of corporate decision-making often leads to evasion of accountability, as responsibility is dispersed across multiple actors.

#### **4. Enforcement Deficiencies**

Effective enforcement of corporate criminal liability is further hindered by institutional and procedural limitations. Investigative agencies often face:

- Lack of technical expertise in handling complex financial crimes
- Procedural delays in prosecution
- Inadequate coordination among regulatory bodies

These deficiencies weaken the deterrent effect of corporate criminal law and reduce the likelihood of successful prosecution, thereby undermining public confidence in the legal system.

#### **Suggestions and Reforms**

In light of the above challenges, there is a pressing need for comprehensive reforms to strengthen the framework of corporate criminal liability in India.

#### **1. Compliance-Based Liability Models**

The introduction of compliance-oriented frameworks can incentivize corporations to adopt robust internal controls. Liability may be mitigated where companies demonstrate due diligence and effective compliance mechanisms, thereby promoting a culture of self-regulation.

#### **2. Strengthening Corporate Governance**

Enhancing corporate governance standards through stricter disclosure norms, independent audits, and board accountability can significantly reduce instances of

corporate misconduct. The role of independent directors and audit committees must be reinforced.

### **3. Enhanced Monetary Penalties and Disgorgement**

Given the limitations of custodial punishment, the imposition of substantial monetary penalties, coupled with disgorgement of unlawful gains, can serve as an effective deterrent. Penalties must be proportionate to the scale and impact of the offence.

### **4. Adoption of Strict Liability in High-Risk Sectors**

In sectors such as environmental regulation, financial markets, and public health, the adoption of strict liability can ensure accountability without the need to prove mens rea, thereby facilitating enforcement.

### **5. Enactment of a Uniform Legal Framework**

The current framework is fragmented across multiple statutes. A comprehensive and consolidated legislation on corporate criminal liability would ensure uniformity, clarity, and effective enforcement.

## **Conclusion**

Corporate criminal liability in India has undergone a substantial transformation, evolving from initial judicial reluctance to a well-established legal doctrine aligned with global standards. The recognition of corporations as criminally accountable entities reflects the changing dynamics of modern economic and industrial systems.

However, persistent challenges—particularly those relating to attribution of mens rea, limitations in punishment, structural complexities, and enforcement inefficiencies—continue to hinder its effective implementation.

A coherent and unified legal framework, supported by robust enforcement mechanisms and progressive judicial interpretation, is essential to address the complexities of corporate crime. Strengthening corporate criminal liability will not

only enhance accountability but also promote ethical business practices, transparency, and sustainable economic development.

## **Bibliography**

1. *K.D. Gaur – Criminal Law: Cases and Materials*
2. *Ratanlal & Dhirajlal – The Indian Penal Code*
3. *Avtar Singh – Company Law*
4. *Singh, P.K. – Corporate Criminal Liability in India*
5. *Banerji, O. – Criminal Liability of Corporate Officials*
6. *Corporate Criminal Liability – A Comparative Analysis*
7. *Lawyered – Corporate Criminal Liability in India*
8. *Khurana & Khurana – Corporate Criminal Liability & Implications*
9. *Aarna Law – Understanding Corporate Criminal Liability*
10. *Lawctopus – Corporate Criminal Liability*
11. *Journal CRA – Laws relating to Corporate Criminal Liability*

# Strengthening Social Harmony in Assam: Peace Initiatives of the Kasturba Gandhi National Memorial Trust

**Dr. Amreen Razzak**  
Assistant Professor  
Assam Downtown University

---

## Abstract:

Assam, a region in India's northeastern part, is known for its rich ethnic diversity, many languages, and complex history. While these elements add to the region's cultural depth, they have also led to social and political tensions and ongoing conflicts. Problems like identity, migration, rebellion, and uneven development have often broken down social unity, making it essential to find lasting ways to build peace. In this situation, civil society groups have become important in bringing people together and helping to resolve conflicts at the local level. Among these groups, the Kasturba Gandhi National Memorial Trust (KGNMT) has been a key player in promoting harmony in Assam by using Gandhi's principles of peace and development.

This article looks at the peace efforts of KGNMT, focusing on its commitment to non-violence, active community involvement, and inclusive growth. Based on Gandhi's values like non-violence, truth, and the welfare of all, the Trust has carried out various activities to tackle both the direct and deeper reasons behind conflicts. These activities include forming local peace groups, involving women as peace volunteers, training young people through programs, and organizing

peaceful marches and cultural events. Moreover, the Trust's efforts to improve livelihoods and boost economic independence also help in addressing the material causes of conflict, which is vital for long-term stability. The article suggests that KGNMT's method is unique because it combines strong moral values with real-world actions. This allows the Trust to gain trust and support from various communities. Its activities not only help to resolve conflicts but also encourage open discussions, better understanding, and shared responsibility for peace. By supporting underrepresented groups, especially women and rural communities, the Trust creates a peaceful approach that is both inclusive and sustainable.

In conclusion, the work of KGNMT in Assam shows that Gandhi's methods are still relevant today in dealing with modern conflicts. The study highlights the importance of local, community-based solutions in overcoming deep-rooted social divisions. It also provides useful lessons for those working on peace-building in areas that are similarly diverse and prone to conflict.

**Keywords:** Social Harmony, Kasturba Gandhi National Memorial Trust, Peace-building, Gandhian Philosophy, Women Empowerment, Community Participation, Conflict Resolution

## **Introduction**

Assam holds an important strategic and cultural place in India's northeastern part. The state is home to many different ethnic groups, languages, and religions, which makes it one of the most varied regions in the country. While this mix brings richness to Assam's society, it has also caused disputes about identity, resources, and political rights. The mix of old issues, people moving from one place to another, differences in wealth, and political actions has led to periods of unrest, including rebel groups and ethnic fights. These conflicts have disturbed social peace and slowed the region's growth in areas like education and economy.

Traditional methods used by the government to solve these problems, such as using security forces and administrative changes, have not been very effective in dealing with the main causes of the issues. Because of this, there is more awareness of how civil society groups can help the government by encouraging discussion, building trust, and involving local people. Among these groups, the Kasturba Gandhi National Memorial Trust (KGNMT) is known for its long-term and comprehensive way of working towards peace. Founded in 1945 to honor Kasturba Gandhi, the Trust follows the ideas of Mahatma Gandhi, such as non-violence, honesty, and helping others. In Assam, KGNMT has created several programs to improve social harmony, especially in areas where conflicts often happen. This article looks at these programs, examines their methods, their results, and what they mean for achieving peace in places with many different cultures.

### **Historical Background and Philosophical Foundations**

The Kasturba Gandhi National Memorial Trust was created after India gained independence, showing the ideas of Mahatma Gandhi about a fair and equal society. It was set up to carry on Kasturba Gandhi’s work, especially helping rural women and people who are not well-off. The main goals of the Trust are to support education, health, independence, and fairness in society. A big part of the Trust’s belief is the Gandhian idea of Sarvodaya, which means the well-being of everyone. This idea pushes for inclusion and the good of the whole community, which is especially important where there are social differences. The Trust also follows Gandhi’s principles of non-violence and truth, which guide their efforts to bring peace.

In practice, these ideas mean working closely with people at the local level, involving the community, and leading through moral strength. Instead of telling

people what to do from above, the Trust helps individuals and communities find their own ways to solve problems. This is especially helpful in places like Assam, where outside help often doesn't work because it doesn't match local needs. The situation in Assam is complex with many historical and current issues. A main source of tension is how people see their identity, especially regarding migration and demographics. Migrants coming from inside and outside India have caused worries about protecting culture, sharing resources, and getting fair treatment.

Ethnic conflicts have also been a big part of Assam's past. Different groups have called for more power, recognition, and rights, sometimes leading to violence. Also, groups fighting for independence have made the area unstable, creating fear and suspicion. Economic issues make these problems worse. Even though Assam has a lot of natural resources, it still deals with high unemployment, lack of development, and unequal distribution of wealth. These problems often mix with identity politics, making conflicts even more intense.

Peace-building in such a situation needs a plan that covers both the immediate causes and deeper reasons for conflict. It is in this challenging environment that the Kasturba Gandhi National Memorial Trust has been working to bring peace. One major effort by the Trust in Assam is setting up local peace committees. These groups are made up of people from different communities, including women, young people, and leaders. By bringing people together, the committees help in talking and understanding each other. The way these committees work is very important. Unlike from-the-top solutions, they give the community ownership of the peace process. Members help find problems, talk things out, and come up with solutions. This not only helps settle issues but also makes people feel responsible for each other. These committees also help connect communities with local

leaders, making communication better and reducing misunderstandings. Their work has helped stop conflicts from getting worse in many areas.

Another important part of the Trust's work is involving women in peace-building. They have trained women volunteers called Shanti Sevikas who act as peace workers in their communities. These women promote non-violence and harmony in their places. Women's involvement in peace efforts has many benefits. They often know the community well and can influence social situations in quiet but effective ways. Their presence also brings more people into the peace process, making it more inclusive. Shanti Sevikas do various things like helping to resolve conflicts, spreading awareness, and supporting people who have been hurt. Their role is especially important in areas where people don't trust formal structures. By being trusted and kind, they help bring people together and promote healing.

KGNMT uses peaceful ways to bring people together and promote peace. They organize events like peace marches, public meetings, and awareness campaigns to share messages of unity and non-violence. These activities let people in the community get involved directly, encouraging them to talk and think about peaceful solutions. Peace marches are especially strong symbols of people coming together for harmony. They bring people from different backgrounds together, showing support and shared values. These events help fight against ideas of division and conflict, showing that living peacefully is possible and better.

KGNMT believes that young people are important in creating a better future. They offer training programs and peace camps that teach leadership, conflict resolution, and how to help the community. These programs are not just about learning in class; they also include hands-on activities that let youth take part actively. By

involving young people in positive activities, the Trust helps them use their energy in helpful ways.

The long-term effect of these efforts is creating a generation that values peace and knows how to keep it. In places where there has been conflict, this is especially important, as young people are often influenced by radical ideas. Cultural Interventions and Social Integration plays a big part in how people see themselves and each other. KGNMT uses cultural activities to help people connect and live together peacefully. They do things like folk performances, community festivals, and art to show shared traditions and values. These activities are especially helpful in Assam, where culture is deeply connected to daily life. By focusing on common ground instead of differences, these programs reduce misunderstandings and help people feel they belong.

Economic problems can often lead to conflict. KGNMT helps people improve their lives through job training, small businesses, and support for farming. These efforts make people more self-reliant and less dependent on others. By improving economic conditions, the Trust helps cut down on one of the main causes of conflict. When people have stable jobs, they are less likely to take part in harmful actions.

Along with long-term projects, KGNMT helps during emergencies like floods and violence. They provide basic supplies, medical help, and emotional support. These actions not only help people in need right away but also show the Trust is reliable and committed. Being there for people during tough times builds trust and strengthens community connections.

## **Impact and Outcomes**

The effect of KGNMT's work in Assam is quite big. At the community level, there has been a decrease in conflicts and more conversations. Involving women and youth has made peace efforts more inclusive and widely supported. The Trust's work has also shifted how people think and feel. Communities that used to be divided are now talking constructively, creating a culture of living together. While it's hard to measure the exact effect, people say KGNMT's efforts have made a real difference in bringing people together.

## **Challenges and Limitations**

KGNMT faces several problems. It is not having enough resources limits how much they can do. Working in areas where conflict is common also puts volunteers and staff in danger. Also, the complex political situation in Assam makes peace efforts face resistance from those who have power. Tackling deep issues needs ongoing work with many people involved.

## **Contemporary Relevance and Policy Implications**

The experience of KGNMT in Assam gives useful lessons for peace efforts elsewhere. Its focus on getting people involved from the bottom up, being inclusive, and avoiding violence can be used in different situations. Policymakers can learn from these examples to create better strategies. Including groups like civil society in peace efforts can make them more effective. Also, giving women and youth a bigger role should be a top priority.

## **Conclusion**

The Kasturba Gandhi National Memorial Trust has shown that lasting peace can be achieved by using inclusive, participatory, and ethical methods. Their work in Assam shows how important it is to deal with both the immediate problems and

the deeper reasons behind conflict. By socializing Gandhian values with real-world strategies, the Trust has developed a peace-building model that is both meaningful and successful. As societies across the globe face growing divisions, the experiences from Assam remind us of the lasting power of non-violence, communication, and active community involvement in creating a more peaceful future.

### Reference:

1. *Kasturba Gandhi National Memorial Trust. (1945). Founding principles and objectives of the Kasturba Gandhi National Memorial Trust. Kasturbagram, Indore.*
2. *Kasturba Gandhi National Memorial Trust. (1962). Kasturba memorial. Kasturba Gandhi National Memorial Trust.*
3. *Kasturba Gandhi National Memorial Trust. (n.d.). About the Trust. Retrieved from official website.*
4. *Kasturba Gandhi National Memorial Trust. (n.d.). Appeal for donation and institutional vision document. Kasturbagram, Indore.*
5. *Kasturba Gandhi National Memorial Trust. (n.d.). Matri Shakti: Concept of Shanti Sena and women empowerment. Kasturbagram, Indore.*
6. *Manglik, R. (2023). Gandhian approach to peace and conflict resolution. EduGorilla Publication.*
7. *Misra, R. P., & Gopal, D. (Eds.). (2018). Rediscovering Gandhi: Conflict resolution and peace building (Vol. 9). Concept Publishing Company.*
8. *Sharma, A. (Ed.). (2007). Gandhian way: Peace, non-violence and empowerment. Academic Foundation.*

9. *Mishra, A. D., Kumar, P., & Tater, S. R. (Eds.). (2011). Revisiting Gandhi. Abhijeet Publications.*
10. *Upadhyaya, P., & Kumar, S. S. (Eds.). (2014). Peace and conflict: The South Asian experience. Cambridge University Press.*
11. *Gandhi Peace Foundation. (1985). Gandhi Marg (Vol. 7). Gandhi Peace Foundation.*
12. *Parekh, B. (1997). Gandhi: A very short introduction. Oxford University Press.*
13. *Gandhi, M. K. (2001). The story of my experiments with truth. Navajivan Publishing House.*

# A Critical Review of Digital Interventions for Suicide Prevention and Youth Mental Health: Is India Ready

**Ambareen Abdullah**

University of Lucknow,  
Uttar Pradesh

**Manas Bajpai**

Phd Scholar, University of  
Lucknow, Uttar Pradesh

---

## Abstract:

Youth suicide is an escalating public health issue, with India documenting elevated incidence of student suicides associated with scholastic stress, socio-economic constraints, and inadequate access to mental health services. With about 0.29 psychiatrists per 100,000 individuals, traditional services are inadequate to satisfy demand. Digital interventions, including mobile health (mHealth) applications, online counseling, and smartphone-based crisis aids, have arisen worldwide as scalable options to address this treatment gap. Although these techniques demonstrate potential in diminishing suicidal ideation and enhancing help-seeking behavior, the majorities have been created within Western frameworks and lack cultural adaptation for India.

This paper offers a systematic scoping assessment of research on digital suicide prevention strategies targeting youth aged 13 to 29. Literature was sourced from PubMed, PsycINFO, Scopus, Google Scholar, and grey literature for the years 2000 to 2024. The studies underwent theme analysis to evaluate their applicability, effectiveness, and contextual challenges. The assessment identifies three primary deficiencies: the absence of suicide-specific digital tools in India, the restricted

scalability of current projects, and inadequate consideration of cultural and ethical considerations, including stigma, privacy, and linguistic variety. Although initiatives such as SHARP and PracticePal demonstrate feasibility, they predominantly focus on depression and anxiety rather than suicidality.

The swift expansion of smartphones in India presents a chance to create accessible, culturally attuned, and socially responsible digital solutions. Integrating these tools with health and education systems, while incorporating participatory design with young users, could markedly improve suicide prevention initiatives and enhance teenage mental health outcomes.

**Keywords:** Digital Mental Health Interventions, Suicide prevention; Youth.

## Introduction

Suicide is a predominant cause of death among youth globally and continues to be a significant public health issue. The World Health Organization (WHO) estimates that more than 703,000 individuals die by suicide each year, making it the fourth greatest cause of death among individuals aged 15 to 29 years (WHO, 2019). In India, student suicides represent approximately 8% of all incidents, highlighting the critical need for preventive strategies aimed at young populations (National Crime Records Bureau [NCRB], 2020). Academic pressures, socio-economic disparities, and inadequate mental health resources intensify susceptibility, particularly among students in medicine, engineering, and competitive examinations (Chahal et al., 2019; Kumar et al., 2013).

Notwithstanding the severity of this crisis, access to prompt, evidence-based remedies remain restricted. India possesses merely 0.29 psychiatrists per 100,000 individuals, in stark contrast to the global median of nine (WHO, 2016). Conventional mental health interventions are inadequate to bridge this gap. Digital interventions, such as mobile health (mHealth), online therapy platforms, and smartphone applications, have emerged as effective, scalable alternatives to provide mental health support in resource-limited settings (Ben-Zeev et al., 2015).

These technologies provide real-time monitoring, crisis intervention, and self-care resources, while also overcoming obstacles such as stigma, geographical distance, and workforce deficiencies (Aggarwal, 2012; WHO, 2011).

Increasing global data substantiates the effectiveness of digital mental health therapies in mitigating depression, anxiety, and suicidality. Randomized controlled studies (RCTs) indicate that mobile-based interventions can diminish suicide ideation, bolster coping mechanisms, and boost continuity of care (Torok et al., 2019; Kennard et al., 2018). However, most current applications are developed for Western audiences, lacking adequate cultural adaptation for South Asian environments. In India, where smartphone usage is anticipated to surpass 829 million users, there exists considerable potential to utilize digital platforms for advancing juvenile mental health and suicide prevention (Newzoo, 2022).

This research provides a critical analysis of international and national evidence about digital interventions for suicide prevention, focusing specifically on their relevance and applicability to Indian youth. The review seeks to identify strengths, deficiencies, and future trajectories to guide the creation of culturally attuned, technology-driven initiatives that may mitigate suicide risk and enhance young well-being.

### **Statement of the Problem**

Suicide among adolescents is an escalating global issue, with digital technology providing novel and scalable avenues for prevention. Although numerous interventions have demonstrated potential globally, their efficacy relies on cultural adaption and systemic integration. In India, the increasing rates of young suicide coincide with insufficient mental health resources, and most digital solutions are not explicitly tailored for suicide prevention, resulting in a disparity between technological capabilities and tangible outcomes.

A comprehensive assessment is necessary to integrate current evidence, assess its applicability to the Indian context, and inform the creation of culturally appropriate, morally robust, and scalable digital methods for suicide prevention.

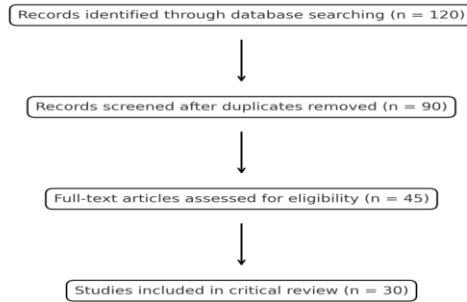
## Methodology

This systematic scoping critical review consolidates international and Indian literature regarding digital interventions aimed at preventing suicide among youth. A systematic search approach was implemented to guarantee thorough coverage of pertinent literature. Databases such as PubMed, PsycINFO, Scopus, and Google Scholar were queried for peer-reviewed publications published from 2000 to 2024. Grey literature, encompassing official papers and publications from non-governmental organizations, was also examined. The keywords utilized in conjunction were: “digital intervention,” “mobile health,” “suicide prevention,” “youth mental health,” “India,” and “cross-cultural psychiatry.”

Studies were incorporated if they addressed adolescents or young adults (ages 13–29), concentrated on suicide prevention or associated outcomes (suicidal ideation, attempts, or self-harm), and employed digital, mobile, or technology-enabled delivery methods. The exclusion criteria included programs that did not address suicidality, solely descriptive studies without intervention results, and studies without methodological rigor. Reference lists of included studies were manually examined to locate supplementary publications.

Data extraction and thematic synthesis were conducted using a thematic synthesis approach. Global and Indian studies were classified into themes: epidemiological evidence, impediments to care, forms of digital interventions, and effectiveness. Methodological limits, cultural variables, and ethical considerations were meticulously addressed in the adaptation of digital tools across many contexts. The review examined the applicability of international evidence to India, focusing on identifying contextual disparities and prospective avenues for culturally sensitive, technology-driven interventions.

**Fig.1. The following is a flow diagram illustrating the literature search and selection procedure**



## A Critical Review

### 1. *Worldwide Epidemiology of Adolescent Suicide:*

Internationally, suicide rates among teenagers and young adults have surged, constituting a significant public health concern. Research from American higher education institutions, including the Big Ten Student Suicide Study and subsequent analyses, indicated that while university students exhibit marginally lower suicide mortality rates compared to their age-matched counterparts, the prevalence of suicidal ideation and attempts remains alarmingly elevated (Silverman et al., 1990; Schwartz, 2011). According to the SEYLE cluster-randomized trial conducted in Europe, widespread school-based suicide prevention programs can dramatically lower adolescent suicidal thoughts and actions (Wasserman et al., 2015). Research from Australia and China corroborates the efficacy of online psycho-educational programs in alleviating suicidal ideation among university students (Han et al., 2018). These findings collectively underscore the dual characteristics of student populations: although they are at

increased risk, they also offer organized settings conducive to preventive measures.

## ***2. The Indian Context: Educational Pressure and Systemic Weaknesses:***

In India, student suicide has emerged as a significant social and health concern, particularly prevalent among aspirants of medical, engineering, and competitive examinations (Chahal et al., 2019; Waseem, 2023). Psychiatric epidemiology research in Uttar Pradesh has suggested a prevalence of 3–7% for psychiatric problems among urban young (Dube, 1970; Sethi et al., 1974). Academic burden, uncertainties over future jobs, and insufficient psychosocial assistance intensify suicide risk factors among teenagers and young people. The scarcity of qualified mental health specialists exacerbates these pressures India has fewer than one psychiatrist per 300,000 individuals, in contrast to the global median of nine per 100,000 (WHO, 2016). Notwithstanding the initiation of the National Suicide Prevention Strategy in 2022, the lack of cohesive institutional frameworks persists in hindering substantial advancement.

## ***3. Digital Pathways in Suicide Prevention: Global Progress:***

The use of digital technologies into mental health care has created new opportunities for suicide prevention. Interventions utilizing ecological momentary assessment (EMA), safety planning applications, and mobile crisis response have demonstrated potential in decreasing relapse rates and improving help-seeking behavior (Ben-Zeev et al., 2015; Kennard et al., 2018). The Computerized Adaptive Screen for Suicidal Youth (CASSY) exhibited robust predictive validity for assessing suicide risk in teenagers attending emergency rooms (King et al., 2021). Outside clinical settings, extensive digital initiatives, exemplified by Australia’s Sources of Strength program, demonstrate how community and school collaborations can be enhanced through online delivery methods (Calear et al., 2016).

Notwithstanding these advancements, systematic studies indicate that outcomes are inconsistent: certain therapies demonstrate substantial reductions in suicidal thoughts, while others show negligible changes (Torok et al., 2019). The inconsistencies underscore the necessity of contextual customization, particularly for low- and middle-income countries (LMICs), where digital disparities and cultural obstacles may influence adoption.

#### ***4. Suicide Prevention in India: Contemporary Evidence and Digital Innovations:***

India's research base for suicide prevention is constrained, encompassing interventions from school-based programs to family-centered and tele-medicine models. The SPIRIT Integrated Suicide Prevention Programme in Gujarat assessed a multi-faceted strategy that included curriculum-based teaching, gatekeeper training, and referral channels, demonstrating initial promise but encountering scalability issues (Pathare et al., 2020). The FASE study in Kerala evaluated an Attachment-Based Family Therapy paradigm for persons exhibiting self-harm, underscoring the significance of family engagement while being resource-intensive and non-digital (Devassy et al., 2022).

Remote modalities, including telephone-based psychosocial support studies in Bangalore and Delhi, exhibited viability but were deficient in the immediacy and scale attainable via smartphone-based solutions (Sreedaran et al., 2021). Recent projects such as SHARP (Rodriguez-Villa et al., 2021), PracticePal, and Kanuri et al.'s (2019) digital treatments for college students demonstrate the viability of mobile-based mental health solutions. Nevertheless, these interventions predominantly focus on depression, anxiety, or relapse prevention, whereas suicide-specific applications remain lacking. Therefore, three significant gaps remain in the Indian context are:

- Digital tools specifically designed for suicide prevention are inadequately developed. The available applications predominantly concentrate on sadness and anxiety.
- Restricted scalability. Most initiatives are still in pilot phases and have not been incorporated into national programs.
- Cultural and ethical supervision. Digital technologies seldom include linguistic diversity, privacy issues, or stigma-related obstacles, which are essential for involvement.

India's swift escalation in smartphone penetration from the 45th to the 2nd largest market worldwide between 2017 and 2022 (Newzoo, 2022) presents substantial potential for suicide prevention via digital platforms. Customized solutions that integrate global best practices with cultural awareness and ethically conscious practices could substantially alleviate the suicide burden among Indian youth. Most digital interventions are designed within Western contexts and presuppose an individualistic approach to help-seeking. In collectivist cultures like India, shame, language diversity, and varying concepts of privacy diminish their relevance (Ghosh et al., 2021). Consequently, tools must be re-contextualized instead than being immediately transported.

Digital trials encounter significant attrition, brief follow-up periods, and varied outcomes, which restrict comparability and long-term evaluation (Torok et al., 2019). Ethical considerations regarding the recruitment of high-risk youth further limit large-scale investigations. Notwithstanding extensive smartphone accessibility (Newzoo, 2022) and nascent pilot programs (Rodriguez-Villa et al., 2021; Kanuri et al., 2019), India is deficient in suicide-specific, culturally tailored instruments. Deficiencies in digital literacy, societal stigma, and regulatory frameworks indicate that the nation is technologically capable yet culturally unprepared. Participatory and context-sensitive design is crucial.

## 2. Conclusions and Prospective Directions

This analysis highlights the potential and the constraints of digital interventions in suicide prevention for youth. Internationally, data suggests that mobile health applications, online psychoeducational programs, and app-based risk assessment systems can diminish suicidal ideation and improve access to care. Simultaneously, results are inconsistent, limited by methodological challenges including brief follow-up durations, participant attrition, and inconsistency in measuring techniques. Most of these interventions have predominantly been formulated in Western contexts, prompting questions regarding their applicability to varied cultural environments.

The epidemic of student suicides in India is exacerbated by severe academic pressures, inadequate access to professional mental health services, and enduring stigma. Although community-based and school-linked programs like SPIRIT and FASE offer significant insights, they predominantly operate in an analogue format and are limited in scale. Recent digital projects, such as SHARP and PracticePal, illustrate the viability of mobile interventions in mental health; yet they do not directly tackle suicidality. The lack of suicide-specific, culturally attuned internet resources underscores a key deficiency in India's prevention framework.

The path ahead involves tailoring digital interventions to the circumstances of Indian youth. This necessitates advancing from pilot initiatives to extensive, longitudinal assessments that can determine long-term efficacy, cost-effectiveness, and ethical protections. It also requires the integration of digital tools inside comprehensive health and education systems to guarantee continuity of treatment, while concurrently tackling cultural obstacles to engagement, like stigma and language diversity. The active participation of young individuals in co-designing solutions that mirror their lived experiences and requirements is fundamental to this process.

India is strategically positioned to utilize its growing internet infrastructure and youthful population to enhance suicide prevention efforts. Readiness is contingent not alone upon technology capability but also on cultural acceptability and systemic integration. By integrating global best practices with context-specific techniques, India can develop scalable, technology-driven methods that mitigate suicide risk and enhance resilience, thereby advancing the overarching objective of young mental health and well-being.

## References

1. *Thippaiah, S.M., Nanjappa, M.S., Math, S.B.: Suicide in India: A preventable crisis. Indian Journal of Medical Research 150(4), 324–327 (2019)*
2. *Pawar, R.: Accidental fatalities and suicides in India. National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, New Delhi (2019)*
3. *Patel, N.S., Choudhary, N., Choudhary, N., Yadav, V., Dabar, D., Singh, M.: A hospital-based cross-sectional investigation of suicidal poisoning in Western Uttar Pradesh. Journal of Family Medicine and Primary Care 9(6), 3010–3014 (2020)*
4. *Chahal, S., Nadda, A., Govil, N., et al.: Suicide fatalities among medical students, residents, and physicians in India over a decade (2010–2019): An exploratory study utilizing online news portals and the Google database. International Journal of Social Psychiatry 68(4), 718–728 (2022)*
5. *Kumar, S., Verma, A.K., Bhattacharya, S., Rathore, S.: Patterns in suicide rates and methodologies in India. Egyptian Journal of Forensic Sciences 3, 75–80 (2013)*

6. Wasim, A.: *Investigating the impact of academic stress and suicide ideation on mental health among coaching students: A cross-sectional study. International Journal of Science and Research* 12(11) (2023)
7. World Health Organization: *Global suicide rates in 2019. WHO, Geneva* (2021)
8. Zeng, W., Chen, R., Wang, X., Zhang, Q., Deng, W.: *Prevalence of mental health issues among medical students in China: A meta-analysis. Medicine* 98(18), e15337 (2019)
9. Auerbach, R.P., Mortier, P., Bruffaerts, R., et al.: *WHO World Mental Health Surveys International College Student Project: Prevalence and distribution of mental disorders. Journal of Abnormal Psychology* 127(7), 623–638 (2018)
10. Murthy, R.S.: *National Mental Health Survey of India 2015–2016. Indian Journal of Psychiatry* 59(1), 21–26 (2017)
11. Bharat, S., Sethi, G. (eds.): *Health and Wellbeing of India’s Young People. Springer Nature Singapore, Singapore* (2019)
12. Lakhan, R., Ekundayò, O.T.: *National Sample Survey Organization report: An estimation of the prevalence of mental illness and its correlation with age in India. Journal of Neurosciences in Rural Practice* 6(1), 51–54 (2015)
13. Cherian, A.V., Armstrong, G., Sobhana, H., et al.: *Mental health, suicidality, health, and social indicators among college students throughout nine Indian states. Indian Journal of Psychological Medicine* (2024)
14. Rotenstein, L.S., Ramos, M.A., Torre, M., et al.: *Prevalence of depression, depressive symptoms, and suicidal ideation among medical students: A systematic review and meta-analysis. JAMA* 316(21), 2214–2236 (2016)

15. Desai, N.D., Chavda, P., Shah, S.: Prevalence and determinants of suicidal thoughts among undergraduate medical students at a medical institution in Western India. *Medical Journal of the Armed Forces India* 77(Suppl 1), S107–S114 (2021)
16. Khan, A., Aleem, S., Walia, T.: Survey research on happiness and well-being among Generation X, Generation Y, and Generation Z in the Indian context. *Indian Journal of Positive Psychology* 12(1) (2021)
17. United Nations Children’s Fund: *The State of the World’s Children: Adolescence, an Epoch of Opportunity*. UNICEF, New York (2011)
18. Vijayakumar, L.: Suicides resulting from exam failures and related governmental initiatives in India. *The Lancet Regional Health – Southeast Asia* 28 (2024)
19. Ransing, R., Arafat, S.M.Y., Menon, V., et al.: India’s national suicide prevention strategy: Problems in execution and future directions. *The Lancet Psychiatry* 10(3), 163–165 (2023)
20. Metzendorf, M.-I., Wieland, L.S., Richter, B.: Mobile health (m-health) smartphone treatments for adolescents and adults with overweight or obesity. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2, CD013591 (2024)
21. Moshe, I., Terhorst, Y., Philippi, P., et al.: A meta-analytic assessment of digital therapies for depression treatment. *Psychological Bulletin* 147(8), 749–786 (2021)
22. Torok, M., Han, J., Baker, S., et al.: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials on suicide prevention by self-guided digital interventions. *The Lancet Digital Health* 2(1), e25–e36 (2020)
23. Marshall, C.A., Crowley, P., Carmichael, D., et al.: Effectiveness of suicide safety planning interventions: A systematic review informing

- occupational therapy practice. Canadian Journal of Occupational Therapy 90(2), 208–236 (2023)*
24. Lehtimaki, S., Martic, J., Wahl, B., Foster, K.T., Schwalbe, N.: *Systematic overview of evidence on digital mental health interventions for adolescents and young adults. JMIR Mental Health 8(4), e25847 (2021)*
  25. Mueller, A.S., Abrutyn, S., Pescosolido, B., Diefendorf, S.: *The societal foundations of suicide. Frontiers in Psychology 12, 621569 (2021)*
  26. Kanuri, N., Arora, P., Talluru, S., et al.: *Investigating the preliminary usability, acceptability, and feasibility of a digital mental health intervention for college students in India. International Journal of Psychology 55(4), 657–673 (2019)*
  27. Sreedaran, P., Beniwal, R.P., Chari, U., et al.: *A randomized controlled trial evaluating telephone-based psychosocial therapies for individuals who have tried suicide. Indian Journal of Psychological Medicine 43(2), 144–149 (2021)*
  28. Grupp-Phelan, J., Horwitz, A., Brent, D., et al.: *Management of suicide risk in the emergency department: A clinical protocol utilizing computerized adaptive screening. Journal of the American College of Emergency Physicians Open 5(2), e13132 (2024)*
  29. Wasserman, D., Hoven, C.W., Wasserman, C., et al.: *School-based suicide prevention programs: The SEYLE cluster-randomized controlled trial. Lancet 385(9977), 1536–1544 (2015)*
  30. Kessler, R.C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K.R., Walters, E.E.: *Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry 62(6), 593–602 (2005)*

31. Gore, F.M., Bloem, P.J., Patton, G.C., et al.: *Global burden of disease in young people aged 10–24 years. Lancet* 377(9783), 2093–2102 (2011)
32. Mohr, D.C., Cuijpers, P., Lehman, K.: *Supportive accountability: A framework for delivering human support to augment adherence to eHealth interventions. Journal of Medical Internet Research* 13(1), e30 (2011)
33. Lee, E.H.: *Review of the psychometric evidence of the Perceived Stress Scale. Asian Nursing Research* 6, 121–127 (2012)

# Socioeconomic Impact of the Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana on Women in Maharashtra: An Analytical Assessment

**Akshay Prabhakar Rajurkar**

Research Scholar, Manipur international University, Ghari Imphal

---

## Abstract

The 'Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana' (MMLBY), introduced by the Government of Maharashtra in 2024, represents a massive transition toward unconditional Direct Benefit Transfers (DBT) aimed at empowering women. By providing a monthly stipend of ₹1,500 to eligible women, the scheme targets poverty alleviation, nutritional enhancement, and the recognition of unpaid domestic labor. This paper provides an analytical assessment of the MMLBY, synthesizing micro-level qualitative studies and macro-level quantitative surveys to evaluate its socio-economic impact. While the scheme successfully facilitates consumption smoothing, increases intra-household bargaining power, and stimulates local rural economies, its implementation has been hindered by severe bureaucratic friction, a "Time Tax," and digital exclusion during e-KYC verification. Furthermore, the immense fiscal burden of the scheme raises concerns regarding long-term macroeconomic sustainability. The study concludes that while the MMLBY acts as a vital safety net, structural integration with skill development and microcredit is required to transition beneficiaries from passive consumption to sustainable entrepreneurship.

**Keywords:** Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana, Unconditional Cash Transfers, Women's Empowerment, Unpaid Care Work, Direct Benefit Transfer, Intra-household Bargaining, Maharashtra Economy.

## Introduction

The discourse surrounding poverty alleviation, gender equity, and economic empowerment in the Global South has increasingly recognized direct cash transfer mechanisms as a foundational tool for expanding human agency. In India, despite recent macroeconomic milestones and a reported rise in the Female Labour Force Participation Rate (FLFPR) to 41.7% in 2023-24, structural inequalities continue to inhibit women's full economic integration. Deep-rooted social norms and the overwhelming burden of unpaid care work frequently leave women with little choice in their employment trajectories, effectively confining a massive proportion of the demographic to the informal sector or unpaid domestic labor.

Within this complex socio-economic landscape, the Government of Maharashtra introduced the 'Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana' (MMLBY) during the 2024 state budget. Operationalized in July 2024, the scheme was engineered to transition the state's welfare architecture from conditional, in-kind subsidies to unconditional Direct Benefit Transfers (DBT). The overarching objective of the policy is to catalyze the economic independence of women, enhance household health and nutritional outcomes, and fortify women's decisive roles within the family unit. The MMLBY guarantees a monthly financial entitlement of ₹1,500 to eligible women aged 21 to 65 years who reside in households with an annual income not exceeding ₹2.5 lakh.

While ostensibly framed as a purely developmental intervention, the MMLBY is deeply embedded in the political economy of competitive welfarism, introduced shortly before the state assembly elections. The scheme witnessed an astronomical initial registration of over 2.43 crore women, laying bare a profound liquidity deficit among the state's female population, particularly in rural and semi-urban geographies. However, this massive scale of implementation immediately

precipitated an array of complex administrative, digital, and fiscal challenges. This report presents an exhaustive, theoretically grounded, and empirically rich analysis of the scheme.

## **Literature Review**

To critically evaluate the MMLBY, the policy intervention must be situated within robust theoretical constructs. The most pertinent frameworks for this analysis include Amartya Sen’s Capability Approach, feminist economic theories regarding intra-household bargaining, and the macroeconomic valuation of unpaid care work.

### **1. The Capability Approach and Cooperative Intra-Household Bargaining**

Amartya Sen’s Capability Approach posits that economic development must be assessed not merely by the maximization of household income, but by the expansion of substantive freedoms—the capabilities that permit individuals to lead lives they genuinely value. In the context of the MMLBY, the ₹1,500 monthly transfer transcends a simple income augmentation; it is a critical resource that theoretically translates into the "functioning" of improved nutritional intake, enhanced healthcare access, and elevated social mobility.

Furthermore, the socioeconomic impact of this liquidity injection is best understood through the Nash bargaining model of intra-household dynamics. Traditional, unitary models of the household operate on the assumption that resources are pooled and distributed altruistically among family members. However, cooperative bargaining models developed by feminist economists suggest that a household member’s influence over financial and allocative decisions is directly proportional to their "threat point" or outside reservation utility. By providing an independent, state-guaranteed income stream directly into the Aadhaar-linked bank accounts of women, the MMLBY fundamentally alters this threat point. The direct benefit transfer bypasses traditional patriarchal gatekeeping, theoretically enhancing the woman's bargaining power and enabling

her to reallocate household expenditure toward female-preferred goods, such as children's education and familial healthcare.

## 2. The Monetization of the Care Economy

A critical macro-theoretical justification for the MMLBY lies in the systemic, historic undervaluation of women's unpaid care and domestic work. Evidence derived from the National Time Use Survey 2024 reveals a stark gender disparity in time allocation across India. Indian women spend an average of 305 minutes per day on unpaid domestic services and an additional 137 to 140 minutes on unpaid caregiving. In sharp contrast, men contribute a mere 86 to 88 minutes to domestic work and 74 to 75 minutes to caregiving.

This invisible labor acts as the foundational infrastructure that sustains the formal economy. Macroeconomic estimates suggest that if monetized at standard minimum wage rates, women's unpaid domestic and care work would account for approximately 15% to 17% of India's Gross Domestic Product (GDP), translating to a staggering ₹22.7 lakh crore. The International Labour Organization (ILO) further corroborates this, noting that 748 million people globally—708 million of whom are women—remain outside the formal labor force strictly due to uncompensated care responsibilities.

In an economy where the female workforce participation is historically constrained by this disproportionate burden of reproductive labor, unconditional cash transfers function as a quasi-recognition of the "Purple Economy". The MMLBY's monthly stipend of ₹1,500, while significantly below the actual replacement cost of market-based care services, acts as a sovereign acknowledgment of the economic value generated by housewives. Legal and academic interpretations increasingly view such direct transfers not as gratuitous "freebies," but as a structural compensatory mechanism that restores dignity and autonomy to women who are otherwise forced into total financial dependency upon male breadwinners.

### 3. Comparative Policy Context

The trajectory of the MMLBY mirrors the lifecycle of its ideological predecessor, the 'Mukhyamantri Ladli Behna Yojana' in the neighboring state of Madhya Pradesh. Both schemes were deployed as highly effective tools of political mobilization leading up to crucial state assembly elections, tapping into the expanding demographic and electoral power of the female electorate. Both states utilized remarkably similar targeting mechanisms (income thresholds, age brackets) and subsequently faced identical post-election fiscal realities, underscoring a vital broader national trend: while unconditional cash transfers to women are politically lucrative and socio-economically beneficial in the short term, their immense fiscal scale makes them highly vulnerable to aggressive administrative rationalization.

#### Objective of the Study

The primary objectives of this analytical assessment are formulated as follows:

1. To assess the reach of Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana among women in Maharashtra.
2. To analyze beneficiaries' perceptions of the scheme's effectiveness.
3. To evaluate the scheme's contribution to women's empowerment and socio-economic development.

#### Hypotheses of the Study

The core hypotheses driving the empirical evaluation of the scheme are:

- **H<sub>0</sub> (Null Hypothesis):** There is no significant positive impact of the "Chief Minister Majhi Ladki Baheen" scheme on the socio-economic conditions of women beneficiaries.
- **H<sub>1</sub> (Alternative Hypothesis):** There is a significant positive impact of the "Chief Minister Majhi Ladki Baheen" scheme on the socio-economic conditions of women beneficiaries.

## Research Methodology

This analytical assessment synthesizes data from multiple empirical studies, employing a mixed-methods (quantitative and qualitative) approach. Primary macro-level data is drawn from a purposive quota sample of 500 women across five distinct regions of Maharashtra (Vidarbha, Khandesh and Northern Maharashtra, Marathwada, Western Maharashtra, and Konkan), utilizing structured questionnaires and focus group discussions. Micro-level qualitative insights are derived from a localized case study of 30 tribal women in the Khed and Maval talukas of Pune district, utilizing simple random sampling and direct interview methods. Furthermore, to evaluate the macroeconomic multiplier effect, the study incorporates findings from a structured survey of 150 local business owners in Ahmednagar, Pune, and Nashik districts, which were analyzed using chi-square and one-sample proportion tests.

## Findings and Analysis

### Implementation Dynamics: Bureaucratic Friction and the Digital Divide

The efficacy of any large-scale social protection program is inextricably linked to the efficiency, transparency, and accessibility of its delivery mechanisms. The implementation of the Ladki Bahin Yojana has been characterized by massive initial demand, followed rapidly by severe administrative bottlenecks, digital exclusion, and a rigorous, sometimes flawed, rationalization process.

### The Burden of the 'Time Tax'

Empirical field research in the tribal belts of Khed and Maval talukas exposes the severe administrative friction marginalized women faced when attempting to access the scheme. The application process demanded an extensive array of documentation, including income certificates, domicile proofs, Aadhaar linkages, and crucially, self-declarations executed on legal stamp paper. The sudden, state-wide surge in demand for stamp papers led to an acute artificial scarcity. As a result, 83% of the 30 tribal women surveyed encountered formidable hurdles during the application phase. The pursuit of a ₹1,500 monthly benefit imposed a

severe "Time Tax" and direct financial burden on these women, who frequently paid illicit premiums to agents and Setu Suvidha Kendras. The out-of-pocket expenditure merely to register ranged from ₹200 to ₹500, significantly eroding the net present value of the initial installments. Furthermore, the digitalization of the application process exacerbated existing socio-economic inequalities. Older women, particularly those over the age of 50, were structurally disadvantaged, relying heavily on overburdened and sometimes exploitative local bureaucratic nodes.

### **E-KYC Rationalization and Algorithmic Exclusion**

As the immense fiscal burden became apparent, the government initiated a stringent Aadhaar-based e-KYC verification drive in late 2025 and early 2026. Approximately 86 lakh women were dropped from the scheme's roster, bringing the total number of valid recipients down to 1.57 crore by January 2026. A primary culprit for this mass exclusion was a poorly phrased, double-negative question embedded in the e-KYC portal: "No one in your family works for the government, right?". Millions of eligible rural women misunderstood the complex syntax and answered "Yes," leading to immediate disqualification.

### **Microeconomic Impact: Consumption Smoothing, Local Livelihoods, and Labor Markets**

Economic theory dictates that the marginal propensity to consume is highest among lower-income brackets; thus, cash infusions in destitute households are immediately absorbed by subsistence needs.

### **Prioritization of Expenditures**

A comprehensive macro-level analysis involving a purposive quota sample of 500 women provides a granular breakdown of fund utilization:

<b>Expenditure Category</b>	<b>Percentage of Beneficiaries Prioritizing Funds</b>	<b>Economic Implication</b>
<b>Family Health &amp; Nutrition</b>	53%	Immediate human capital investment; protection against catastrophic medical costs.
<b>Children's Education</b>	45%	Long-term intergenerational mobility investment.
<b>General Household Needs</b>	25% - 28%	Pure consumption smoothing; buffering against localized food inflation.
<b>Housing Improvement</b>	17%	Micro-investments in physical living conditions.
<b>Savings &amp; Financial Security</b>	10%	Creation of emergency financial buffers.
<b>Personal Skill Development</b>	8%	Direct investment in individual labor market competitiveness.

The transfer effectively prevents households from falling below the extreme poverty line but leaves very little surplus for actual capital formation. Only 18% of surveyed women reported any form of entrepreneurial advancement.

### **The Multiplier Effect on Local Economies and Labor Shifts**

While individual capital formation may be slow, the aggregate infusion of capital into rural markets has generated a distinct macroeconomic multiplier effect. A study of 150 local business owners concluded that a significant majority of rural enterprises observed a measurable increase in customer spending correlating with the implementation of the MMLBY.

However, an unintended consequence emerged within the rural agricultural sector. The continuous provision of state-sponsored liquidity has raised the "reservation wage" of female agricultural laborers. With basic subsistence guaranteed, many women are increasingly opting out of grueling agricultural tasks, precipitating a localized shortage of agricultural labor and driving up operational costs for landowners.

### **Socio-Cultural Impacts and the Enhancement of Women's Agency**

The direct routing of funds to women's bank accounts has demonstrably shifted intra-household power dynamics. According to the macro-level study, an impressive 63% of respondents reported a tangible increase in their autonomy and decision-making power within the family, with 28% characterizing this improvement as highly significant. Furthermore, 30% of the beneficiaries experienced a substantial boost in self-esteem and confidence. This financial autonomy reduces daily marital friction over money and mitigates risks of intimate partner violence linked to financial stress.

Additionally, 58% of respondents noted increased participation in community and social activities. However, 35% of women reported no change in gender-based discrimination within their communities, indicating that cash transfers alone cannot alter deeply embedded cultural biases without supplementary structural reforms.

### **Regional Disparities: The Geography of Welfare Penetration**

The study highlights stark regional asymmetries in the scheme's penetration:

<b>Geographic Region</b>	<b>Beneficiary Penetration Rate</b>	<b>Beneficiary Satisfaction Index</b>	<b>Structural and Infrastructural Context</b>
<b>Western Maharashtra</b>	70%	75% (Highest)	Robust banking infrastructure, high digital literacy.

Geographic Region	Beneficiary Penetration Rate	Beneficiary Satisfaction Index	Structural and Infrastructural Context
Vidarbha	65%	70%	High agrarian distress necessitates urgent state support.
Konkan	63%	Moderate	Geographically challenging terrain.
Khandesh / North Maha.	60%	Moderate	Mixed demographics with significant tribal populations.
Marathwada	55%	Lowest	Drought-prone, severe deficit in digital infrastructure.

This illustrates the "Inverse Care Law," where regions historically plagued by chronic poverty (e.g., Marathwada) recorded the absolute lowest beneficiary penetration due to a lack of foundational internet and banking infrastructure.

### Macroeconomic and Fiscal Implications: The Sustainability of Unconditional Welfare

The implementation of mass unconditional cash transfers places an enormous structural strain on the state's exchequer. When announced in the 2024-25 budget, the state provisioned ₹36,000 crore. However, unprecedented enrollment rapidly escalated the projected annual liability to an estimated ₹43,700 crore, forcing supplementary demands.

By the 2026-27 State Budget, facing a projected total public debt of ₹9.3 lakh crore, the administration presented a highly consolidated budget. The government slashed the MMLBY's allocation for 2026-27 by a massive 31%, bringing it down to ₹26,500 crore. Pre-election promises to increase the monthly stipend from ₹1,500 to ₹2,100 were indefinitely shelved. Critics argue that diverting tens of thousands of crores toward revenue expenditure risks "crowding out" essential

capital expenditure on infrastructure and health, potentially fostering a "dependency culture."

### **Synergies with Skill Development and Future Policy Paradigms**

Recognizing that a ₹1,500 monthly stipend cannot single-handedly eradicate poverty, the Government of Maharashtra has integrated the Ladki Bahin demographic into the 'Lakhpati Didi' framework. The government aims to transition 25 lakh basic cash recipients into self-sustaining micro-entrepreneurs earning over ₹1 lakh annually. Furthermore, a highly progressive 'Single Women Policy' was announced in the 2026-27 budget to map the specific livelihood and social security challenges faced by widows, divorcees, and unmarried older women.

### **Conclusions and Recommendations**

The 'Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana' represents a profound intervention in the socio-economic fabric of Maharashtra. Based on the empirical findings, the study rejects the null hypothesis and concludes that the scheme has a significant positive impact on the socio-economic conditions and intra-household bargaining power of women beneficiaries. On a microeconomic level, it acts as a critical buffer against poverty and serves as a tangible recognition of invisible, unpaid care work. However, macroeconomically, the scheme exhibits significant fiscal vulnerabilities and was marred by exclusionary digital friction during implementation.

To ensure the scheme transcends a temporary consumption subsidy and evolves into a vehicle for permanent empowerment, the following strategic policy recommendations are proposed:

1. **Administrative Simplification:** Abandon reliance on linguistically confusing digital forms and physical stamp papers. Verification should rely on simplified, localized self-certification facilitated by Gram Panchayats.

2. **Inflation-Indexed Disbursals:** Legally link the ₹1,500 stipend to the Consumer Price Index (CPI) to maintain real purchasing power and prevent its devaluation.
3. **Mandatory Synergies with Microfinance:** Structurally link disbursals with the Maharashtra State Skill Development Society (MSSDS) and provide preferential access to low-interest microcredit via Self-Help Groups (SHGs).
4. **Targeted Regional Interventions:** Deploy specialized, mobile banking units in historically marginalized regions like Marathwada to counteract the "Inverse Care Law."
5. **Balancing Capital Expenditure:** Rigorously ring-fence critical capital expenditure in agriculture and infrastructure to ensure welfare transfers do not substitute long-term industrial growth.

## References

1. *Ambler, K., & De Brauw, A. (2017). The Impacts of Cash Transfers on Women's Empowerment: Learning from Pakistan's BISP Program (Social Protection and Labor Discussion Paper No. 1702). World Bank.*
2. *Dasgupta, P. (2013). Essays on intra-household bargaining power of women in India. VTechWorks.*
3. *García, J. L. (2025). Guaranteed Employment in Rural India: Intra-Household Labor and Resource Allocation Consequences (NBER Working Paper No. 33494). National Bureau of Economic Research.*
4. *Government of India. (2026). Expenditure Budget 2026-2027: Gender Budget Statement. Ministry of Finance.*
5. *Government of Maharashtra. (2026). Economic Survey of Maharashtra 2025-26. Directorate of Economics and Statistics, Planning Department.*
6. *Kumar, S. (2024). Cash Transfers as an Instrument for Poverty Alleviation and Women's Empowerment in India. Observer Research Foundation (ORF) Issue Briefs.*

7. *Peters, C., et al. (2019). What works to enhance women's agency: Cross-cutting lessons from experimental and quasi-experimental studies. The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).*
8. *PRS Legislative Research. (2025). Maharashtra Budget Analysis 2025-26. PRS India.*
9. *Sahoo, S., Sarkar, K. K., & Kumar, A. (2024). Valuation of Unpaid Household Activities in India. Economic and Political Weekly, 59(39).*
10. *Sharma, A., & Gupta, R. (2024). What determines women empowerment in India? A capability-based approach. Cogent Social Sciences (Taylor & Francis).*

# राज्य प्रशासन और नीति निर्माण में पुलिस की भूमिका एवं चुनौतियां

रंजना बागड़े

राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन अध्ययनशाला उज्जैन ( म .प्र. )

## शोध सारांश:

शोध-पत्र राज्य प्रशासन एवं लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। परंपरागत रूप से पुलिस को केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था के रूप में देखा जाता रहा है, किंतु आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में पुलिस नीति-निर्माण, क्रियान्वयन, सामाजिक स्थिरता और सुशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह अध्ययन भारतीय संदर्भ में राज्य पुलिस की प्रशासनिक, विधिक तथा नीतिगत भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन करता है। इस प्रकार, राज्य प्रशासन और नीति-निर्माण की प्रक्रिया में पुलिस एक केंद्रीय संस्था के रूप में उभरती है। उसकी कार्यकुशलता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व राज्य शासन की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य राज्य प्रशासन एवं लोक नीति निर्माण में पुलिस की भूमिका का विश्लेषण करना है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में पुलिस का महत्व कितना व्यापक और बहुआयामी है।

## प्रस्तावना:

भारत एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ “पुलिस” राज्य सूची, सातवीं अनुसूची का विषय है। अतः प्रत्येक राज्य में पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। भारत संघात्मक लोकतांत्रिक राज्य है, जिसकी प्रशासनिक संरचना केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत “पुलिस” राज्य सूची का विषय है, अतः राज्य प्रशासन में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। राज्य की शांति, कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व मुख्यतः राज्य पुलिस पर ही निहित है। राज्य प्रशासन की प्रभावशीलता काफी हद तक पुलिस व्यवस्था पर निर्भर करती है।

राज्य प्रशासन का मूल उद्देश्य सुशासन, सामाजिक न्याय और विकास को सुनिश्चित करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति बिना एक प्रभावी, उत्तरदायी और पेशेवर पुलिस व्यवस्था के संभव नहीं है। पुलिस न केवल अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है, बल्कि यह लोक नीति (Public Policy) के निर्माण और क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है।

मैक्स वेबर के अनुसार राज्य वैध बल (Legitimate Use of Force) का एकमात्र स्रोत होता है। इस दृष्टि से पुलिस राज्य की संप्रभु शक्ति का व्यावहारिक प्रतीक है। वहीं Thomas R. Dye की परिभाषा के अनुसार लोक नीति वह है जिसे सरकार करने या न करने का निर्णय लेती है। इस प्रक्रिया में पुलिस एक सलाहकार, क्रियान्वयनकर्ता और मूल्यांकनकर्ता—तीनों रूपों में सक्रिय रहती है।

### वर्तमान समय में राज्य प्रशासन की चुनौतियाँ :

जैसे आतंकवाद, साइबर अपराध, सांप्रदायिक तनाव, महिला एवं बाल अपराध, और शहरीकरण से उत्पन्न जटिलताएँ—पुलिस की भूमिका को और अधिक व्यापक एवं बहुआयामी बना देती हैं। विशेषकर राज्यों में कमिश्नर प्रणाली का विस्तार, सामुदायिक पुलिसिंग, ई-गवर्नेंस तथा अपराध डेटा विश्लेषण जैसी व्यवस्थाएँ पुलिस को नीति-निर्माण की प्रक्रिया से सीधे जोड़ती हैं।

### सैद्धांतिक आधार :

मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत Max Weber के अनुसार राज्य वैध बल (Legitimate Force) का एकमात्र स्रोत है। पुलिस इस वैध बल का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है।

सुशासन (Good Governance) सुशासन के तत्व — पारदर्शिता, जवाबदेही, विधि का शासन (Rule of Law) — पुलिस की भूमिका से गहराई से जुड़े हैं।

सार्वजनिक नीति (Public Policy) सिद्धांत Thomas R. Dye के अनुसार “Public policy.” पुलिस नीति-निर्माण में सलाहकार एवं क्रियान्वयन एजेंसी दोनों रूपों में कार्य करती है।

- राज्य प्रशासन में पुलिस की भूमिका
- कानून-व्यवस्था बनाए रखना , अपराध नियंत्रण , दंगा एवं भीड़ प्रबंधन, सामाजिक शांति की स्थापना
- अपराध अन्वेषण एवं न्यायिक सहयोग, FIR पंजीकरण ,साक्ष्य संकलन ,अभियोजन में सहयोग
- आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद निरोध,नक्सलवाद नियंत्रण, साइबर अपराध रोकथाम
- सामुदायिक पुलिसिंग,जनता के साथ विश्वास निर्माण, महिला सुरक्षा अभियान, यातायात प्रबंधन
- नीति निर्माण में पुलिस की भूमिका

- परामर्शदात्री भूमिका राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था, अपराध प्रवृत्तियों और सुरक्षा खतरों पर रिपोर्ट प्रदान करना।
- नीति क्रियान्वयन राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन। चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था (निर्देशन: Election Commission of India)
- डेटा और विश्लेषण अपराध सांख्यिकी के आधार पर नई नीतियाँ बनाना। अपराध मानचित्रण (Crime Mapping)
- विशेष कानूनों का क्रियान्वयन, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), भारतीय दंड संहिता (IPC), राज्य विशेष अधिनियम
- मध्य प्रदेश
- ने हाल के वर्षों में कमिश्नर प्रणाली लागू कर शहरी प्रशासन में पुलिस की भूमिका को और सशक्त किया है। कानून-व्यवस्था में त्वरित निर्णय मजिस्ट्रेटी शक्तियों का समन्वय बेहतर शहरी शासन
- चुनौतियाँ राजनीतिक हस्तक्षेप संसाधनों की कमी मानवाधिकार संबंधी प्रश्न पुलिस सुधारों का अपूर्ण क्रियान्वयन
- पुलिस सुधार एवं सुझाव पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना आधुनिक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा प्रशिक्षण एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के पुलिस सुधार निर्देशों का पालन (प्रकाश सिंह केस, 2006)

### निष्कर्ष:

राज्य प्रशासन एवं नीति निर्माण में पुलिस की भूमिका केवल “कानून लागू करने” तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नीति-निर्माण, सामाजिक स्थिरता, और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में एक केंद्रीय संस्था है। प्रभावी, जवाबदेह और पेशेवर पुलिस व्यवस्था राज्य शासन की सफलता का आधार है। अतः यह शोध-पत्र राज्य प्रशासन और नीति निर्माण में पुलिस की भूमिका का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें पुलिस की प्रशासनिक संरचना, नीति-निर्माण में उसकी परामर्शदात्री एवं क्रियान्वयन भूमिका, समकालीन चुनौतियाँ तथा सुधार संबंधी सुझावों का समावेश किया गया है।

इस प्रकार, प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि शासन-प्रणाली की एक केंद्रीय और नीतिगत इकाई है, जो राज्य प्रशासन की प्रभावशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

**संदर्भ सूची:**

1. *Basu, D.D. – Introduction to the Constitution of India*
2. *Fadia, B.L. – Indian Government and Politics*
3. *Bureau of Police Research and Development की रिपोर्ट्स*
4. *Ministry of Home Affairs वार्षिक रिपोर्ट*
5. *प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) – सर्वोच्च न्यायालय निर्णय*

## भंडारा जिल्ह्यातील बेरोजगारीची कारणे परिणाम व उपाय एक चिकित्सक अध्ययन

महेंद्र अशोक गभने

पीएच-डी संशोधक, आठवले समाज कार्य महाविद्यालय, भंडारा

### सारांश :

बेरोजगारी भारतातील सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेला प्रभावित करत असून भारतात प्रमुख समस्या बनली आहे. बेरोजगारी निर्माण होण्यास अनेक घटक कारणीभूत असून कारणांवर सविस्तर चर्चा व अध्ययन झाल्यास बेरोजगारी थांबवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपाय योजना आखता येतील. या अध्ययनातून प्रामुख्याने भंडारा जिल्ह्यातील बेरोजगारीची कारणे, जनमानसावर त्याचा पडणारा परिणाम आणि बेरोजगारी थांबवण्यासाठीच्या उपाय योजना या विषयात चिकित्सक अध्ययन करण्यात आले आहे.

भारत विकसनशील राष्ट्र असून १९४७ पर्यंत विकसित भारत निर्माण या संकल्पनेला घेऊन भारत सरकार वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपाय योजना आखत असून बेरोजगारी हा विकसित भारता समोरचा मोठा अडसर असल्याचे दिसून येते म्हणूनच याचे अध्ययन करणे आवश्यक आहे.

**मुख्य शब्द :** बेरोजगारी, विकसित भारत, बेरोजगारीचे कारण, बेरोजगारीचे परिणाम, भारतातील बेरोजगारीची स्थिती

### प्रस्तावना :

जेव्हा काम करण्याची इच्छा असताना सुद्धा रोजगार प्राप्त होत नाही अशा स्थितीला बेरोजगारी म्हणतात. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारताची लोकसंख्या अधिक आहे तसेच भारत सर्वाधिक युवा वर्ग असलेला देश आहे त्यामुळे जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत बेरोजगारीचे प्रमाण भारतात अत्याधिक असल्याचे दिसून येते. बेरोजगारीचा प्रभाव हा कुटुंबाच्या, राज्याच्या व पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रभावी करतो त्यामुळे बेरोजगारी संपवण्यासाठी शासन वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबवतो.

प्रसिद्ध समाजशास्त्रीय लेखक सी.बी. मामोरिया म्हणतात की, “बेरोजगारी ही काम करण्यासाठी सक्षम आणि इच्छुक असलेल्या माणसाची 'काम नसलेली' अवस्था आहे, म्हणजेच ती अनैच्छिक आणि ऐच्छिक निष्क्रियतेची स्थिती आहे”

बेरोजगारी फक्त व्यक्तीच्या आर्थिक स्थितीवर प्रभाव पाडत नसून मानसिक स्थितीला देखील प्रभावित करते. बेरोजगार व्यक्ती नेहमी तणावाच्या व निराशेच्या स्थितीत जगतो. बरेचदा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाउल उचलताना दिसतात.

प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने ग्रामीण विकासावर आधारित होती. घरा-घरात लघु उद्योग असल्याने बेरोजगारी नावाचा प्रकार दिसून येत नव्हता शिवाय वर्णव्यवस्था व्यवसायावर आधारित असल्याने कामाची विभागणी योग्य प्रकारे करण्यात आली होती त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या हाताला रोजगार होते. मुघल काळातील जुलमी व्यवस्था, मोठ्या प्रमाणात लोकांकडून शेतसारा घेतला जायचा त्यामुळे भारताची संपन्न अर्थव्यवस्था डबघाईला येऊ लागली. ब्रिटीश काळात अधिकच स्थिती बदलली. इंग्रजांनी भारतीयांना कारकून बनवण्याचे कार्य केले. शेतकऱ्याला ठराविक पिके पिकवण्याची जबरदस्ती यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था इंग्रजांच्या हाताखाली गेली आणि बेरोजगारी अधिकच वाढत गेली.

श्रम शक्ती सर्वेक्षण अहवालानुसार भारतातील रोजगार संरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल होत असल्याचे दिसून येत आहे. यातील प्राप्त आकडेवारीनुसार भारतात स्वयंरोजगाराचे प्रमाण 52.2 टक्क्यांवरून 58.4 टक्क्यांपर्यंत वाढले असून, नैमित्तिक कामगारांचे प्रमाण 24.9 टक्क्यांवरून 19.8 टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. ही स्थिती सरकारी योजना व उपक्रमांद्वारे प्रोत्साहित उद्योजकतेमुळे स्वावलंबी आणि स्वतंत्र उपजीविकेकडे होणाऱ्या बदलांचे परिणाम आहे.

परंतु या आकडेवारीतून वेतन स्थिर राहिल्याचे निदर्शनास येत नाही. PLFS च्या अंदाजानुसार, नैमित्तिक कामगारांचे (सार्वजनिक कामे वगळता) सरासरी दैनिक वेतन जुलै-सप्टेंबर 2017 मधील 294 रुपयांवरून एप्रिल-जून 2024 मध्ये 433 रुपयांपर्यंत वाढले आहे. त्याचप्रमाणे, नियमित पगारदार कर्मचाऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 16,538 रुपयांवरून 21,103 रुपयांपर्यंत वाढले आहे.

ही वाढ केवळ उत्पन्नातील वाढ दर्शवत नाही, तर रोजगारातील स्थैर्य आणि गुणवत्तेत झालेली सुधारणा देखील अधोरेखित करते. कृषी क्षेत्रातील अलीकडील रोजगारवाढ ग्रामीण भागातील सबलीकरण आणि धोरणात्मक हस्तक्षेपांचे परिणाम दर्शवते. कृषी-स्टार्टअप्ससाठी उपलब्ध करून दिलेला 122.5 कोटी रुपयांचा निधी या क्षेत्रातील नवोपक्रम आणि शाश्वत विकासाला चालना देतो.

सरकारच्या बहुआयामी उपक्रमांमध्ये ‘स्किल इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 यांचा समावेश असून, यामुळे पदवीधरांच्या रोजगारक्षमतेत 2013 मधील 33.95 टक्क्यांवरून 2024 मध्ये 54.81 टक्क्यांपर्यंत लक्षणीय वाढ झाली आहे (इंडिया स्किल्स रिपोर्टनुसार).<sup>1</sup>

तसेच, 99,446 कोटी रुपयांच्या रोजगार संलग्न प्रोत्साहन (ELI) योजनेचे उद्दिष्ट विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात सुमारे 3.5 कोटी रोजगार निर्माण करणे हे आहे. सरकारने विक्रमी भांडवली खर्चासोबतच मनरेगा (MGNREGS), PMEGP, DDU-GKY, PMMY, DAY-NRLM आणि DAY-NULM यांसारख्या विविध योजनांद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीस चालना दिली आहे.

याशिवाय, स्टार्टअप, जागतिक क्षमता केंद्रे (GCC), डिजिटल सेवा आणि गिग इकॉनॉमी यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमुळे रोजगाराच्या संधींमध्ये विविधता वाढत असून, तरुणांसाठी नवीन आणि बहुआयामी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. शिक्षण आणि रोजगार यांतील दरी कमी करण्यासाठी राबविण्यात येणारे लक्षित उपक्रम भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभाचा प्रभावी उपयोग करण्यास सहाय्यभूत ठरत आहेत.

### **बेरोजगारीचे प्रकार :**

भारतातील बेरोजगारी मुख्यत्वे संरचनात्मक आहे त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारात ती दिसून येते;

### **प्रच्छन्न बेरोजगारी :**

अशा प्रकारची बेरोजगारी प्रामुख्याने ग्रामीण व कृषी वर अवलंबून असलेल्या रोजगाराच्या ठिकाणी दिसून येते. एकाच कामात आवश्यकतेपेक्षा जास्त लोक सहभागी असल्यामुळे ही बेरोजगारी निर्माण होते.

### **हंगामी बेरोजगारी :**

ही बेरोजगारी प्रामुख्याने कृषी आधारित रोजगारामुळे निर्माण होते. कारण कृषी व्यवस्था हवामानावर आधारित असल्यामुळे पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होते परंतु उन्हाळ्याच्या दिवसात मात्र कुठलेही रोजगार उपलब्ध होत नाही.

### **खुली बेरोजगारी :**

भारतात सर्वाधिक प्रमाण खुल्या बेरोजगारीचे असून श्रमिक कार्य करण्यासाठी तयार असतो तशा प्रकारचे त्याच्या जवळ कौशल्य सुद्धा असते पण रोजगार मिळत नाही. ही बेरोजगारी प्रामुख्याने गावातून स्थलांतरित झालेल्या युवकांमध्ये दिसून येते.

<sup>1</sup> <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147614&reg=3&lang=2>

### शिक्षित बेरोजगारी :

स्वातंत्र्यानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक विकास झाल्याने बरेच युवा शिक्षित झाले पण ठराविक रोजगार असल्याने सर्वच सुशिक्षिताना रोजगार प्राप्त होऊ शकत नाही.

### बेरोजगारीची कारणे :

भारतात बेरोजगारीची स्थिती चिंताजनक असून भारतीय अर्थव्यवस्थेवर व प्रामुख्याने युवकांच्या मानसिक स्थितीवर याचे नकारात्मक परिणाम पडलेले दिसून येतात. बेरोजगारी कमी करायची असल्यास त्याची कारणे लक्षात घेणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्या संबंधी योग्य त्या उपाय-योजना आखता येतील. बेरोजगारीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत;

### लोकसंख्या वाढ :

भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राष्ट्र आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वृद्धी होत गेली त्यामुळे लोकसंखेच्या तुलनेत रोजगाराची उपलब्धता कमी असल्याने बेरोजगारीत वाढ होत जाते.

प्रत्येक दिवशी भारतातील लाखो युवा नोकरीच्या शोधात निघतात. बऱ्याचदा अपयश सुद्धा येते.

### शिक्षण पद्धतीतील त्रुटी :

शिक्षण व्यवस्था व अभ्यासक्रम कौशल्याधीष्टीत व रोजगाराभिमुख असणे आवश्यक आहे परंतु बरेच वर्षे भारतीय शिक्षण व्यवस्था प्रामुख्याने थेरी वर आधारित असल्याने, कौशल्याने अपूर्ण युवकांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो.

### कृषी क्षेत्रावर अवलंबन :

ग्रामीण भारतातील रोजगार प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने, हंगामी काम संपल्यावर मजूर बेरोजगार होतात.

### गुंतवणूकीकरिता कमकुवत आर्थिक व्यवस्था :

बरेच युवा उद्योग सुरु करण्यास इच्छुक असतात पण उद्योगात लागणारी गुंतवणूक त्या करिता अडसर ठरते.

### लघु व कुटीर उद्योगांचे पतन :

प्राचीन भारतात व ब्रिटीश पूर्व भारतात घरोघरी लघु उद्योग होते परंतु औद्योगिकरण झाल्याने लघु उद्योग बंद झाले.

## बेरोजगारीचे परिणाम :

बेरोजगारी प्रामुख्याने आर्थिक व्यवस्थेसाठी बाधक असून यातून अनेक प्रकारच्या आर्थिक व सामाजिक समस्या निर्माण होतात.

## गुन्हेगारीत वाढ :

बेरोजगारी ही केवळ आर्थिक समस्या नसून सामाजिक असंतुलन निर्माण करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. जेव्हा व्यक्तीला नियमित उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होत नाही, तेव्हा त्याच्यावर आर्थिक ताण वाढतो. या तणावातून काही व्यक्ती गैरमार्गाचा अवलंब करून चोरी, लूटमार, फसवणूक, मादक पदार्थांची विक्री यांसारख्या गुन्हेगारी कृत्यांकडे वळतात. विशेषतः तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त असल्यास गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढण्याची शक्यता अधिक असते. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरही नोकरी मिळत नसल्यामुळे निराशा, असंतोष आणि हतबलता निर्माण होते. या मानसिक अवस्थेमुळे काही युवक समाजविघातक कृत्यांकडे आकर्षित होतात.

बेरोजगारीमुळे सामाजिक विषमता देखील तीव्र होते. काही लोकांकडे संपत्ती आणि संधीची उपलब्धता असताना, इतरांना मूलभूत गरजांसाठीही संघर्ष करावा लागतो. ही दरी वाढल्याने असंतोष निर्माण होतो आणि तो गुन्हेगारीत परिवर्तित होऊ शकतो. याशिवाय, बेरोजगारीमुळे कुटुंबातील ताणतणाव वाढतात, ज्यामुळे घरगुती हिंसा, व्यसनाधीनता आणि इतर सामाजिक समस्या वाढतात. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे समाजातील गुन्हेगारी दर वाढणे.

बेरोजगारी ही गरिबी आणि कर्जबाजारीपणाची एक प्रमुख कारणीभूत समस्या आहे. जेव्हा व्यक्तीकडे स्थिर उत्पन्नाचे साधन नसते, तेव्हा त्याच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणेही कठीण होते. अन्न, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागतो, ज्यामुळे गरिबी वाढीस लागते.

उत्पन्नाच्या अभावामुळे व्यक्ती किंवा कुटुंबाला खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. सुरुवातीला लहान प्रमाणात घेतलेले कर्ज हळूहळू वाढत जाते, कारण परतफेड करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न उपलब्ध नसते. परिणामी, व्यक्ती कर्जाच्या दुरुचक्रात अडकते.

विशेषतः ग्रामीण भागात आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांवर याचा अधिक परिणाम होतो. अनियमित रोजगार, कमी मजुरी आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव यामुळे त्यांना वारंवार कर्ज घ्यावे लागते. काही वेळा सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जावर जास्त व्याजदर आकारले जातात, ज्यामुळे आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट होते.

### गरीबी आणि कर्ज :

बेरोजगारी ही गरिबी आणि कर्जबाजारीपणाची एक प्रमुख कारणीभूत समस्या आहे. जेव्हा व्यक्तीकडे स्थिर उत्पन्नाचे साधन नसते, तेव्हा त्याच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणेही कठीण होते. अन्न, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागतो, ज्यामुळे गरिबी वाढीस लागते.

उत्पन्नाच्या अभावामुळे व्यक्ती किंवा कुटुंबाला खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. सुरुवातीला लहान प्रमाणात घेतलेले कर्ज हळूहळू वाढत जाते, कारण परतफेड करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न उपलब्ध नसते. परिणामी, व्यक्ती कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकते. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांवर याचा अधिक परिणाम होतो. अनियमित रोजगार, कमी मजुरी आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव यामुळे त्यांना वारंवार कर्ज घ्यावे लागते. काही वेळा सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जावर जास्त व्याजदर आकारले जातात, ज्यामुळे आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट होते.

### सरकारी तिजोरीवर ताण :

बेरोजगारीचा परिणाम केवळ व्यक्ती किंवा कुटुंबापुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो थेट सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थेवरही होतो. जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर लोक बेरोजगार असतात, तेव्हा त्यांच्या उत्पन्नात घट होते आणि परिणामी सरकारला मिळणारे कर उत्पन्न (Income Tax, GST इ.) कमी होते. यामुळे महसुलात घट होऊन सरकारी तिजोरीवर ताण निर्माण होतो.

याचवेळी, बेरोजगार नागरिकांना आधार देण्यासाठी सरकारला विविध कल्याणकारी योजना राबवाव्या लागतात. उदाहरणार्थ, रोजगार हमी योजना, अन्न सुरक्षा योजना, अनुदाने आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे सरकारी खर्च वाढतो आणि महसूल कमी होतो—या दुहेरी परिणामामुळे वित्तीय तुटीचा दबाव वाढतो.

### बेरोजगारी कमी करण्यासाठी उपाय योजना :

कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून युवकांना उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते. तांत्रिक, व्यावसायिक आणि डिजिटल कौशल्ये आत्मसात केल्यास रोजगाराच्या संधी वाढतात. उदाहरणार्थ, संगणक कौशल्ये, डेटा विश्लेषण, मेकॅनिकल दुरुस्ती, इलेक्ट्रिकल कामे, तसेच सेवा क्षेत्रातील कौशल्ये यांना आज मोठी मागणी आहे. यामुळे युवक स्वयंरोजगार किंवा नोकरी दोन्ही पर्याय निवडू शकतात.

शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. पारंपरिक सैद्धांतिक शिक्षणाऐवजी प्रात्यक्षिक आणि कौशल्याधारित शिक्षणाला अधिक महत्त्व देणे गरजेचे आहे. उद्योग-शिक्षण समन्वय

मजबूत केल्यास विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव (internship, apprenticeship) मिळू शकतो, ज्यामुळे त्यांची रोजगारक्षमता वाढते.

पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) विकास हा बेरोजगारी कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आणि दीर्घकालीन उपाय मानला जातो. रस्ते, पूल, रेल्वे, बंदरे, वीज, पाणीपुरवठा, दळणवळण आणि डिजिटल नेटवर्क यांसारख्या सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठ्या प्रमाणावर थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होते. पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीदरम्यान बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कामगारांची गरज भासते, ज्यामुळे अल्पकालीन रोजगार निर्माण होतो. याशिवाय, या सुविधा पूर्ण झाल्यानंतर उद्योग, व्यापार आणि सेवा क्षेत्राला चालना मिळते, ज्यामुळे दीर्घकालीन रोजगाराच्या संधी वाढतात.

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी ग्रामीण आणि कृषी विकास हा अत्यंत प्रभावी आणि सर्वसमावेशक उपाय मानला जातो. भारतातील मोठा लोकसंख्या वर्ग ग्रामीण भागात राहतो आणि शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे या क्षेत्राचा विकास केल्यास मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती शक्य होते. कृषी क्षेत्राचा विकास केल्यास थेट रोजगाराच्या संधी वाढतात. सुधारित बियाणे, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा आणि यंत्रीकरण यांचा वापर केल्यास उत्पादनक्षमता वाढते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारते. तसेच, पीक विविधीकरण, सेंद्रिय शेती आणि बागायती शेती यामुळे वर्षभर रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. याशिवाय, शेतीपूरक उद्योग जसे की दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशी पालन आणि लघुउद्योग यांना प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण भागात अतिरिक्त रोजगारनिर्मिती होते. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत मिळतात आणि बेरोजगारी कमी होते.

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी देशात गुंतवणूक (Investment) वाढविणे हा एक प्रभावी आणि दीर्घकालीन उपाय आहे. जेव्हा देशात देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूक वाढते, तेव्हा नवीन उद्योग, व्यवसाय आणि सेवा क्षेत्र विकसित होतात, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होते.

डिजिटल साक्षरतेमुळे व्यक्तींना संगणक, इंटरनेट, मोबाईल ॲप्स आणि विविध डिजिटल साधनांचा प्रभावी वापर करता येतो. यामुळे ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सेवा, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, फ्रीलान्सिंग, कंटेंट क्रिएशन यांसारख्या क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी वाढतात. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील युवकांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म रोजगाराचे नवीन दालन उघडतात.

बेरोजगारी ही समस्या अनेकदा वाढत्या लोकसंख्येशी संबंधित असते. लोकसंख्या वेगाने वाढल्यास उपलब्ध संसाधने, रोजगाराच्या संधी आणि पायाभूत सुविधा यांच्यावर ताण येतो. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रभावी उपाय अवलंबल्यास बेरोजगारी कमी करण्यास मदत होऊ शकते. लोकसंख्या

नियंत्रणासाठी सर्वात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे जनजागृती. कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व, लहान कुटुंबाचे फायदे आणि आरोग्यदायी जीवनशैली याबद्दल समाजात जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि कमी साक्षरतेच्या भागात याबाबत प्रभावी प्रचार करणे गरजेचे आहे.

### विषयाची निवड :

या विषयाची निवड करतांना भारतातील बेरोजगारीचा वाढता आलेख, त्याची कारणे व देशाच्या स्थितीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन निवड करण्यात आली. वैश्विकरण होत असतांना भारताची आर्थिक स्थिती बदलत असली तरी मनुष्यबळाचा देशाच्या विकासात पाहिजे त्या प्रमाणात उपयोग होतांना दिसत नाही त्यामुळे या सर्व विषयांची कारणीमांसा करणे आवश्यक आहे. बेरोजगारी मध्ये कमी यावी या करिता त्या विषयीच्या उपाययोजनांच्या अभ्यासाची आवश्यकता देखील दिसून येते.

### साहित्य परीक्षण :

प्रस्तुत शोध पत्र लेखनाकरिता विविध प्रकारचे पुस्तक, शोधग्रंथ व ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करण्यात आला. तसेच बेरोजगारी संदर्भातील आकडेवारी तपासण्यासाठी शासनाच्या वेबसाईटची मदत घेण्यात आली तसेच विभिन्न शासकीय अहवाल, पंचवार्षिक योजना संदर्भातील माहिती देखील अभ्यासण्यात आली.

### मुलभूत शोध प्रश्न :

1. भंडारा जिल्ह्यात बेरोजगारी निर्माण कोणते घटक कारणीभूत आहेत ?
2. भंडारा जिल्ह्यात व्याप्त बेरोजगारीचे समाज जीवनावर कोण-कोणते परिणाम पडलेले दिसून येतात ?
3. भंडारा जिल्ह्यातील बेरोजगारी थांबवण्यासाठी कोण-कोणत्या उपाय योजनांची आवश्यकता ?

### मुलभूत शोध उद्देश :

1. भंडारा जिल्ह्यातील बेरोजगारीसाठी कारणीभूत घटकांचे अभ्यास करणे.
2. भंडारा जिल्ह्यातील व्याप्त बेरोजगारीचे समाज जीवनावर पडणाऱ्या परिणामाचे अध्ययन करणे.
3. भंडारा जिल्ह्यातील बेरोजगारी थांबवण्यासाठी आवश्यक उपाय योजनांचे अभ्यास करणे.

### अध्ययनाचे भौगोलिक क्षेत्र :

प्रस्तुत शोध पत्रात भौगोलिक क्षेत्र म्हणून भंडारा जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे.

### संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत संशोधनपत्रात भंडारा जिल्ह्यातील बेरोजगारीचे कारणे, परिणाम व त्या संबंधातील उपाय योजनांचे अध्ययन केले आहे. या संशोधनात वर्णनात्मक संशोधन आराखड्याचा उपयोग मूल्यांकनात्मक दृष्टिकोनातून वास्तव परिस्थितीची तपासणी करण्यासाठी करण्यात आला आहे.

तसेच, या संशोधन कार्यात मिश्र (गुणात्मक आणि मात्रात्मक) संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. अभ्यास करताना संरचित मुलाखत अनुसूचीचा उपयोग करून बेरोजगारीची वर्तमान स्थिती त्याची कारणे व त्यात कमी येण्यासाठी उपाय योजना तपासण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

### तथ्य संकलन पद्धती :

प्रस्तुत शोध पत्रात भंडारा जिल्ह्यातील बेरोजगारीची स्थिती तपासण्यासाठी प्राथमिक स्रोतांचा वापर करण्यात आला ज्यात सर्वेक्षण पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला.

द्वितीयक स्रोतांच्या माध्यमातून माहिती मिळवण्यासाठी पुस्तके, लिंक व शोध पत्रांचा उपयोग करण्यात आला.

### अध्ययनाचे विश्व :

प्रस्तुत शोध पत्रात भंडारा जिल्ह्यातील वय वर्ष 20 ते 30 वयोगटातील युवा वर्गाची अध्ययनाचे विश्व म्हणून निवड करण्यात आली आहे .

### नमुना निवड :

प्रस्तुत शोध पत्रात संशोधनाचे विश्व लक्षात घेता असंभाव्यता नमुना निवड पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला आहे.

### सांख्यिकीय विश्लेषण :

भंडारा जिल्ह्यातील बेरोजगारीची कारणे, परिणाम व उपाय -योजना तपासण्यासाठी संरचित मुलाखत अनुसूची तयार करण्यात आली होती. या प्रश्नावलीत एकूण 11 प्रश्नांचा समावेश असून हे प्रश्न जिल्ह्यातील बेरोजगारीची कारणे, परिणाम व उपाय योजना दर्शवितात. उत्तरदाते म्हणून जिल्ह्यातील 80 युवकांनी (वय वर्ष : 20 ते 30 ) या संबंधित संख्यात्मक माहिती दिली असून तक्ता क्र.1मध्ये समाविष्ट आहे.

**तक्ता क्र.1 भंडारा जिल्ह्यातील बेरोजगारीची कारणे, परिणाम व उपाय-योजना**

अ.क्र	वक्तव्य	अजिबात नाही	अंशतः	मध्यम	पूर्णपणे	एकूण
1	कौशल्य आधारित शिक्षणाची व्यवस्था नसल्याने जिल्ह्यात बेरोजगारी वाढलेली दिसून येते का ?	12	3	39	26	80
		15.0	3.8	48.8	32.5	100
2	जिल्ह्यात मोठ्या उद्योगांची कमी असल्यामुळे बेरोजगारी दिसून येते का ?	7	9	20	44	80
		8.8	11.3	25.0	55.0	100
3	जिल्ह्यातील लघु व कुटीर उद्योगांत आलेली कमी बेरोजगारीसाठी कारणीभूत आहे का ?	9	17	33	21	80
		11.3	21.3	41.3	26.3	100
4	जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा उदासीनपणा बेरोजगारीसाठी कारणीभूत असल्याचे दिसून येते का?	13	15	9	43	80
		16.3	18.8	11.3	53.8	100
5	गाव किंवा जिल्हा सोडून इतरत्र नोकरी करणार नाही, ही भावना युवकांमध्ये दिसून येते का ?	8	30	28	14	80
		10.0	37.5	35.0	17.5	100
6	डिजिटल साक्षरतेचा अभाव बेरोजगारीस कारणीभूत असल्याचे दिसून येते का ?	12	24	32	12	80
		15.0	30.0	40.0	15.0	100
7	कृषीवर आधारित रोजगार असल्यामुळे हंगामी बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो का ?	9	6	41	24	80
		11.3	7.5	51.3	30.0	100
8	जिल्ह्यात रोजगाराची कमी असल्यामुळे मोठ्या शहराकडे स्थलांतरण होतांना दिसत आहे का ?	1	15	36	28	80
		1.3	18.8	45.0	35.0	100

9	बेरोजगारीमुळे गुन्हेगारीत वाढ झाल्याचे दिसून येते का ?	8	17	33	22	80
		10.0	21.3	41.3	27.5	100
10	कौशल्यधारित महाविद्यालय व औद्योगिक कंपन्या स्थापन केल्यास जिल्ह्यातील बेरोजगारी कमी होईल असे आपणास वाटते का ?	5	19	27	29	80
		6.3	23.8	33.8	36.3	100

- तक्ता क्र.1 मधील प्राप्त आकडेवारीनुसार सर्वाधिक 48.8 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, कौशल्य आधारित शिक्षणाची व्यवस्था नसल्याने जिल्ह्यात बेरोजगारी वाढली असून याचे प्रमाण मध्यम आहे तर सर्वात कमी 3.8 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की यामुळे अंशतः बेरोजगारी वाढली दिसून येते.
- सर्वाधिक 55.0 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, जिल्ह्यात मोठ्या उद्योगांची कमी असल्यामुळे पूर्णपणे बेरोजगारी वाढल्याचे दिसून येते तर सर्वात कमी 8.8 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, याचे प्रमाण अंशतः आहे.
- सर्वाधिक 41.3 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, जिल्ह्यातील लघु व कुटीर उद्योगांत आलेली कमी बेरोजगारीसाठी मध्यम प्रमाणात कारणीभूत आहे तर सर्वात कमी 11.3 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, या कारणामुळे अजिबात बेरोजगारी वाढली नाही.
- सर्वाधिक 53.8 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा उदासीनपणा बेरोजगारीसाठी पूर्णपणे कारणीभूत असल्याचे दिसून येते तर सर्वात कमी 11.3 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, या कारणामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण मध्यम आहे .
- सर्वाधिक 37.5 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, गाव किंवा जिल्हा सोडून इतरत्र नोकरी करणार नाही, ही भावना अंशतः युवकांमध्ये दिसून येते तर सर्वात कमी 10.0 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, अजिबात ही भावना दिसून येत नाही.
- सर्वाधिक 40.0 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, डिजिटल साक्षरतेचा अभाव मध्यम प्रमाणात बेरोजगारीस कारणीभूत असल्याचे दिसून येते तर सर्वात कमी 12.5 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, अजिबात कारणीभूत दिसून येत नाही.

- सर्वाधिक 51.3 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, कृषीवर आधारित रोजगार असल्यामुळे मध्यम प्रमाणात हंगामी बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो तर सर्वात कमी 7.5 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, अंशतः सामना करावा लागतो.
- सर्वाधिक 45.0 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, जिल्ह्यात रोजगाराची कमी असल्यामुळे मोठ्या शहराकडे स्थलांतरण होतांना दिसत आहे हे कारण मध्यम असून सर्वात कमी 1.3 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे स्थलांतरनासाठी हे कारण अजिबात लागू होत नाही.
- सर्वाधिक 41.3 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, बेरोजगारीमुळे गुन्हेगारीत वाढ झाल्याचे दिसून येते हे कारण मध्यम प्रमाणात लागू होत असून सर्वात कमी 10.0 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की बेरोजगारीमुळे अजिबात गुन्हेगारी वाढली नाही .
- सर्वाधिक 36.3 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, कौशल्याधारित महाविद्यालय व औद्योगिक कंपन्या स्थापन केल्यास जिल्ह्यातील बेरोजगारी पूर्णपणे कमी होईल तर सर्वात कमी 6.3 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की बेरोजगारीमुळे अजिबात कमी होणार नाही.

### निष्कर्ष :

या संशोधनाच्या माध्यमातून भंडारा जिल्ह्यातील बेरोजगारीची कारणे, परिणाम व बेरोजगारी कमी करण्यासाठीच्या उपाय योजना या विषयात चिकित्सक अध्ययन करण्यात आले असून संशोधनातून पुढील प्रकारचे निष्कर्ष समोर आले आहेत;

जिल्ह्यात कौशल्य आधारित शिक्षणाची व्यवस्था नसल्याने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढलेली दिसून येते तर जिल्ह्यातील मोठ्या उद्योगांची कमी पूर्णपणे बेरोजगारी वाढण्यासाठी कारणीभूत आहे. जिल्ह्यातील लघु व कुटीर उद्योग बंद पडल्याने बेरोजगारी वाढल्याचे दिसून येते तसेच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा उदासीनपणा बेरोजगारी वाढण्यास कारणीभूत असल्याचे या अध्ययनातून निदर्शनास आले. गाव किंवा जिल्हा सोडून इतरत्र कुठेही रोजगारासाठी जाणार नाही ही भावना देखील बेरोजगारीस चालना देत असून डिजिटल साक्षरतेचा अभाव देखील बेरोजगारी वाढण्यात कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील रोजगार कृषीवर आधारित असल्यामुळे हंगामी बेरोजगारी असल्याचे देखील या अध्ययनातून लक्षात येते. जिल्ह्यात रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतरणाचे प्रमाण देखील दिसून येते. जिल्ह्यातील बेरोजगारी गुन्हेगारी वृत्ती वाढण्यास कारणीभूत असल्याचे देखील अध्ययनातून निष्कर्षास येत असून कौशल्याधारित महाविद्यालय व औद्योगिक कंपन्या स्थापन केल्यास जिल्ह्यातील बेरोजगारीत कमी येईल असे या अध्ययनातून निष्कर्ष प्राप्त झाले आहे.

## संदर्भ ग्रंथसूची

1. गुप्ता.अ. (2022). बेरोजगारी का संकट और उपाय. लोकायत प्रकाशन.
2. मगन.र. (2021). बेरोजगारी. अस्तित्व प्रकाशन.
3. <https://www.rncollegehajipur.in/rn/uploads/products/Unemployment%20by%20Dr.%20Priyanka%20Singh.pdf>
4. <https://www.etashasociety.org/causes-of-unemployment-in-india/>
5. <https://www.investopedia.com/terms/u/unemployment.asp>
6. <https://digitalcommons.du.edu/irbe/vol4/iss2/53/>

## बायोगॅस वापराची वर्तमान स्थिती, समस्या व ग्रामीण विकासात याचे उपयोग विशेष संदर्भ: भंडारा जिल्हा

शैलेश साऊसाखरे

पीएच-डी संशोधक, आठवले समाज कार्य महाविद्यालय, भंडारा

### सारांश:

बायोगॅस उर्जेचे महत्वपूर्ण माध्यम असून ग्रामीण भागातील शेतकरी मुख्यत्वे मोठ्या प्रमाणात याचा उपयोग करतात असे असले तरी बायोगॅस वापरात अनेक प्रकारच्या समस्या व आव्हाने दिसून येतात. त्या समस्यांवर तोडगा काढला असता प्रदूषण विरहित उर्जेचे महत्वपूर्ण माध्यम बायोगॅस ठरेल. अलीकडे ग्रामीण विकासाची संकल्पना तांत्रिक युगात बदलत चालली असून शहरांचा प्रभाव ग्रामीण जीवनशैलीवर पडत असल्याचे दिसून येते अशा स्थितीत ग्रामीण स्वावलंबी प्रयोग म्हणून बायोगॅस उपयोगी ठरते त्याचा उपयोग या अध्ययनाच्या माध्यमातून समोर येईल.

ग्रामीण विकासासाठी शासन विभिन्न प्रकारच्या योजना राबवत असून त्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या समस्या बायोगॅस योजनेला सुद्धा लागू होतात. शेतकरी पूरक उर्जा व्यवस्था म्हणून बायोगॅस चा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

**मुख्य शब्द :** बायोगॅस, ग्रामीण विकास, बायोगॅस वापरात येणाऱ्या समस्या

### प्रस्तावना :

बायोगॅस चे वापर ग्रामीण भागात इंधनासाठी केल्या जात असून हे एक प्रकारचे उर्जा स्रोत आहे. जैविक कचऱ्याच्या वापरातून तयार होणारे हे अक्षय तंत्रज्ञान आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात पशुधन मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात बायोगॅसचा अधिक वापर केला जातो. भारत सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) यांनी दिनांक 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम अधिसूचित केला आहे. हा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश देशातील नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीला चालना देणे हा आहे. ग्रामीण व शहरी

भागात बायोगॅस संयंत्रांची उभारणी वाढवणे, सेंट्रिय कचऱ्याचे ऊर्जेमध्ये रूपांतर करणे, स्वच्छ, शाश्वत व पर्यावरणपूरक ऊर्जा उपलब्ध करून देणे, ऊर्जा स्वावलंबन वाढवणे

शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आर्थिक फायदा मिळवून देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. भारत सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत बायोगॅस कार्यक्रमांमध्ये संयंत्राच्या क्षमतेनुसार खालील प्रकारचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.<sup>2</sup>

(अ) विशेष श्रेणी (डोंगराळ/ईशान्य राज्ये, द्वीप, SC/ST)

क्षमता (m <sup>3</sup> /दिवस)	CFA (₹)
1 m <sup>3</sup>	17,000
2-4 m <sup>3</sup>	22,000
6 m <sup>3</sup>	29,250
8-10 m <sup>3</sup>	34,500
15 m <sup>3</sup>	63,250
20-25 m <sup>3</sup>	70,400

या श्रेणीत समाविष्ट राज्ये: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लडाख, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड इत्यादी.

(ब) इतर सर्व राज्ये व श्रेणी

क्षमता (m <sup>3</sup> /दिवस)	CFA (₹)
1 m <sup>3</sup>	9,800
2-4 m <sup>3</sup>	14,350
6 m <sup>3</sup>	22,750
8-10 m <sup>3</sup>	23,000
15 m <sup>3</sup>	37,950
20-25 m <sup>3</sup>	52,800

<sup>2</sup> <https://biogas.mnre.gov.in/about-the-programmes>

### क) अतिरिक्त निश्चित अनुदान

खालील परिस्थितींमध्ये प्रत्येक संयंत्रासाठी अतिरिक्त ₹1,600 अनुदान दिले जाते

- बायोगॅस संयंत्र शौचालयाशी जोडले असल्यास
  - MNRE मान्यताप्राप्त बायोगॅस स्लरी फिल्टर युनिटशी जोडले असल्यास
- काही मोठ्या क्षमतेच्या संयंत्रांसाठी (20–25 m<sup>3</sup>) काही बाबतीत “NA” लागू असू शकते.

### ड) टर्नकी जॉब शुल्क

संयंत्र उभारणीसाठी (बांधकाम + देखरेख + सुरूवात + 5 वर्षे देखभाल) खालीलप्रमाणे शुल्क दिले जाते

- 1 ते 10 m<sup>3</sup> संयंत्र: ₹3,000 प्रति संयंत्र
- 15 ते 25 m<sup>3</sup> संयंत्र: ₹5,000 प्रति संयंत्र

हे शुल्क फक्त खालील प्रकारांसाठी लागू आहे—

- ऑन-साइट बांधकाम असलेले संयंत्र
  - दीनबंधू मॉडेल (Fixed Dome)
  - KVIC मॉडेल (Floating Gas Holder)

पूर्वनिर्मित (Prefabricated) संयंत्रांसाठी हे लागू नाही.

### ई) प्रोत्साहन

- ₹10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाते
- अट: बायोगॅस आधारित जनरेटर सेट / वॉटर पंपिंग सिस्टम (BPS) वापरले पाहिजे, शेतीसाठी वीज निर्मिती आणि पाणी पंपिंगसाठी वापर

### बायोगॅस वापरामोरील प्रमुख आव्हाने :

पर्यावरणीय दृष्ट्या लाभकारी असले तरी बायोगॅस वापरात मोठ्या प्रमाणात आव्हाने दिसून येतात त्यामुळे ग्रामीण भागात देखील याच्या वापराचे प्रमाण अतिशय कमी आहे.

### अत्याधिक खर्चिक :

बायोगॅस संयंत्र उभारण्यासाठी लागणारा प्रारंभिक खर्च हा अतिशय जास्त आहे. वेळो-वेळी संयंत्राची देखभाल आणि जैविक पदार्थांची प्रक्रिया त्रासदायक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात सुद्धा इंधन म्हणून नैसर्गिक गैस चा उपयोग केला जातो. सरकारी अनुदान प्राप्त होत असल्यामुळे बरेच शेतकरी बायोगॅस वापरसाठी समोर येत आहेत पण अनुदानाची प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट असल्याने त्या प्रमाणात देखील कमी आलेली दिसून येते.

### **बायोगॅस साठी लागणारा जैविक कच्च्या मालाची कमतरता :**

बायोगॅस तयार होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शेणाची आवश्यकता लागते हा पुरवठा नियमित करावा लागतो. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्याकडे मोठ्या प्रमाणात जनावरे आहेत त्यांच्यासाठी हे शक्य आहे परंतु ज्यांच्याकडे जनावरे कमी आहेत अशासाठी हे आव्हानात्मक आहे.

### **पाण्याची अत्याधिक आवश्यकता :**

जैविक कचरा नियमित ओला राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता लागते अशा परिस्थितीत शुष्क व ज्या प्रदेशात पाण्याची कमतरता आहे अशा ठिकाणी बायोगॅस चालविणे आव्हानात्मक आहे.

### **सामाजिक मानसिकता :**

बायोगॅस संदर्भात अजूनही समाजात जागरूकता निर्माण झाली नसून शौचालयाला जोडलेल्या बायोगॅस विषयी लोकांमध्ये सामाजिक संकोच दिसून येतो.

### **देखभाल संबंधी समस्या :**

बायोगॅसची नियमित साफसफाई व फीडिंग आवश्यक आहे. तसेच वेळोवेळी होणारे तांत्रिक बिघाड आव्हानात्मक वाटते.

### **ग्रामीण विकासात बायोगॅसचे महत्व :**

ग्रामीण भागात बायोगॅस चा वापर नवीकरणीय उर्जा निर्माणाचे महत्वपूर्ण माध्यम असून प्रदूषण विरहीत उर्जा निर्मितीचे महत्वपूर्ण माध्यम आहे.

### **इंधन म्हणून लाकडासाठी पर्यायी वापर :**

ग्रामीण व आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात लाकडाचा वापर केला जातो. त्यामुळे वृक्षतोड आणि जळाऊ लाकडातून उत्सर्जित होणाऱ्या वायूमुळे प्रदूषण याला पर्याय म्हणून बायोगॅस उपयोगी ठरते.

### **कच्चा मालाची सहज उपलब्धता :**

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे कृषी आणि पशुपालनावर आधारित आहे त्यामुळे बायोगॅस साठी लागणारा कच्चा माल सहज उपलब्ध होतो.

### **उच्च दराच्या सेंद्रिय खताची निर्मिती :**

बायोगॅस साठी वापरण्यात येणारे शेणखत अधिक कुजते ज्यामुळे खतावर अधिक प्रक्रिया होऊन उच्च दर्जाचे सेंद्रिय खतनिर्मिती होते. बरेच शेतकरी गांदूळ खतनिर्मितीसाठी याचा वापर करतात. या खतामुळे रासायनिक खतामध्ये कमी येऊन जमिनीचा पोत सुधारतो.

### विजेसाठी उपयोग :

ग्रामीण भागात बायोगॅस पासून वीजनिर्मिती देखील होते. अतिदुर्गम भागात वीजेची सुविधा निर्माण होऊन प्रकाशासाठी अत्यंत उपयोगी ठरत आहे.

### विषयाची निवड :

विषयाची निवड करताना बायोगॅस वापराची वर्तमान स्थिती, समस्या व ग्रामीण विकासात याचे उपयोग याचे सविस्तर अध्ययन केले आहे. उर्जेचे विभिन्न प्रकारचे स्रोत असून बायोगॅस अक्षय उर्जेचे प्रमुख व महत्वपूर्ण स्रोत आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात अधिक उपयोगी असल्यामुळे शासन याच्या वापराकरिता विभिन्न प्रकारच्या योजना व अनुदान देते ज्यामुळे अलीकडे मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात याचा उपयोग केला जातो.

बायोगॅस उभारणीची प्रक्रिया आणि चालवण्याची पद्धत यामध्ये बऱ्याच प्रकारचे आव्हान दिसून येते त्यामुळे या विषयावर अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

### साहित्य परीक्षण :

प्रस्तुत शोध पत्र लेखनाकरिता विविध प्रकारचे पुस्तक, शोधग्रंथ व ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करण्यात आला.

### सेंगर.स. बायोगॅस. गोडवा कृषी प्रकाशन.

प्रस्तुत पुस्तकात लेखकाने बायोगॅस वापराचे उपयोग, सरकारी अनुदान, तोटे, संयंत्राची उभारणी या विषयी सविस्तर लेखन केले असून. बायोगॅस प्रकल्प उभारणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी ही पुस्तक मार्गदर्शन करते.

### देवधर.प्र. बायोगॅस-जैविक इंधन.व्यास क्रिएशन्स.

लेखक ग्रामीण विकासासाठी सामाजिक संस्था चालवत असून प्रामुख्याने ग्रामीण विकासासाठी कार्य करतात. प्रस्तुत पुस्तकात त्यांनी बायोगॅस वापरासंबंधीचे उपयोग उदाहरणासाहित मांडले आहेत.

### घनवाटी.ह. (2018). बायोगॅस. स्प्रिंगर प्रकाशन.

विविध प्रकारच्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीबाबत हे पुस्तक एक सर्वसमावेशक संदर्भ मार्गदर्शक म्हणून कार्य करते. यात अॅनअरोबिक डायजेशन तंत्रज्ञानाच्या विविध पैलूंचा समावेश आहे—मूलभूत घटकांपासून, म्हणजे सूक्ष्मजैविक बाबीं पासून ते बायोगॅस उत्पादन प्रणाली नियंत्रित करणाऱ्या प्रमुख घटकांपर्यंत. तसेच, या प्रणालींच्या कार्यपद्धतीची मुख्य तत्त्वे, विश्लेषण, प्रक्रिया नियंत्रण आणि अडचणींचे निराकरण यांचाही सखोल आढावा घेतला आहे.

### मुलभूत शोध प्रश्न :

1. भंडारा जिल्ह्यातील बायोगॅस वापराची वर्तमान स्थिती कशी आहे ?
2. बायोगॅस वापरतांना बायोगॅस धारकांना कोण-कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
3. बायोगॅसचे ग्रामीण विकासात योगदान आहे का ?

### मुलभूत शोध उद्देश :

1. भंडारा जिल्ह्यातील बायोगॅस वापराच्या वर्तमान स्थितीचे अध्ययन करणे.
2. बायोगॅस वापरतांना बायोगॅस धारकांना येणाऱ्या अडचणींचे अध्ययन करणे.
3. बायोगॅसचे ग्रामीण विकासात असलेले योगदान तपासणे.

### अध्ययनाचे भौगोलिक क्षेत्र :

प्रस्तुत शोध पत्रात भौगोलिक क्षेत्र म्हणून भंडारा जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे.

### संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत संशोधनपत्रात भंडारा जिल्ह्यातील वापराच्या स्थितीचे अध्ययन केले आहे. या संशोधनात वर्णनात्मक संशोधन आराखड्याचा उपयोग मूल्यांकनात्मक दृष्टिकोनातून वास्तव परिस्थितीची तपासणी करण्यासाठी करण्यात आला आहे.

तसेच, या संशोधन कार्यात मिश्र (गुणात्मक आणि मात्रात्मक) संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. अभ्यास करताना संरचित मुलाखत अनुसूचीचा उपयोग करून बायोगॅस वापराची वर्तमान स्थिती त्यात येणाऱ्या अडचणी आणि ग्रामीण विकासात याचे योगदान तपासण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

### तथ्य संकलन पद्धती :

प्रस्तुत शोध पत्रात बायोगॅस ची स्थिती तपासण्यासाठी प्राथमिक स्रोतांचा वापर करण्यात आला ज्यात सर्वेक्षण पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला.

द्वितीयक स्रोतांच्या माध्यमातून माहिती मिळवण्यासाठी पुस्तके, लिंक व शोध पत्रांचा उपयोग करण्यात आला.

### अध्ययनाचे विश्व :

प्रस्तुत शोध पत्रात भंडारा जिल्ह्यातील बायोगॅस धारक विश्व असून 80 बायोगॅस धारकांची अध्ययनाचे विश्व म्हणून निवड करण्यात आली आहे .

### नमुना निवड :

प्रस्तुत शोध पत्रात संशोधनाचे विश्व लक्षात घेता असंभाव्यता नमुना निवड पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला आहे.

### सांख्यिकीय विश्लेषण :

भंडारा जिल्ह्यातील बायोगॅस ची वर्तमान स्थिती, आव्हाने व ग्रामीण विकासात याचे योगदान तपासण्यासाठी

संरचित मुलाखत अनुसूची तयार करण्यात आली होती. या प्रश्नावलीत एकूण 7 प्रश्नांचा समावेश असून हे प्रश्न

बायोगॅसची वर्तमान स्थिती दर्शवितात. उत्तरदाते म्हणून जिल्ह्यातील 80 बायोगॅस धारकांनी या संबंधित संख्यात्मक माहिती दिली असून तक्ता क्र.1 मध्ये समाविष्ट आहे

**तक्ता क्र.1 :भंडारा जिल्ह्यातील बायोगॅस ची वर्तमान स्थिती, आव्हाने व ग्रामीण विकासात याचे योगदान**

अ.क्र	वक्तव्य		अजिबात नाही	अंशतः	मध्यम	पूर्णपणे	एकूण
1	बायोगॅस उभारणीचा प्रारंभिक खर्च अधिक असल्याने शेतकरी वापराकडे दुर्लक्ष करतात असे आपणास वाटते का ?	वारंवारता	48	11	13	8	80
		टक्केवारी	60.0	13.8	16.3	10.0	100
2	जैविक कच्च्या मालाच्या (शेण) कमतरतेमुळे बायोगॅस नियमित चालवणे आव्हानात्मक आहे का ?	वारंवारता	17	20	33	10	80
		टक्केवारी	21.3	25.0	41.3	12.5	100

3	बायोगॅस उभारणीसाठी मिळणारी अनुदान राशी कमी आहे असे आपणास वाटते का?	वारंवारता	32	20	21	7	80
		टक्केवारी	40.0	25.0	26.3	8.8	100
4	शौचालयाला बायोगॅस जोडल्याने सामाजिक संकोच निर्माण होतो का ?	वारंवारता	24	11	23	22	80
		टक्केवारी	30.0	13.8	28.8	27.5	100
5	ग्रामीण भागात इंधणासाठी लाकडाच्या जागी बायोगॅस पर्यायी ठरत आहे का ?	वारंवारता	6	10	10	54	80
		टक्केवारी	7.5	12.5	12.5	67.5	100
6	अत्याधिक जागेच्या वापरामुळे लोक बायोगॅसकडे पाठ फिरवत आहेत का ?	वारंवारता	22	15	37	6	80
		टक्केवारी	27.5	18.8	46.3	7.5	100
7	बायोगॅस ची नियमित देखभाल डोकेदुखी ठरते का?	वारंवारता	44	18	16	2	80
		टक्केवारी	55.0	22.5	20.0	2.5	100

तक्ता क्र.1 मध्ये प्राप्त माहिती अनुसार सर्वाधिक 60.0 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, बायोगॅस उभारणीचा प्रारंभिक खर्च अधिक असल्याने अजिबात शेतकरी याच्या वापरामुळे दुर्लक्ष करत नाही तर सर्वात कमी 10.0 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात.

सर्वाधिक 41.3 उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की जैविक कच्च्या मालाच्या (शेण) कमतरतेमुळे बायोगॅस नियमित चालवणे आव्हानात्मक आहे.याचे प्रकार मध्यम आहे तर सर्वात कमी 12.5 टक्के लोकांचे मानणे आहे की पूर्णपणे आव्हानात्मक आहे.

तक्ता क्र.1 मधील तिसऱ्या प्रश्नाविषयी 40.0 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, बायोगॅस उभारणीसाठी मिळणारी अनुदान राशी अजिबात कमी नाही तर सर्वात कमी 8.8 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, पूर्णपणे कमी आहे.

सर्वाधिक 30.0 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की शौचालयाला बायोगॅस जोडल्याने अजिबात सामाजिक संकोच निर्माण होत नाही तर सर्वात कमी 13.8 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की अंशतः संकोच निर्माण होतो.

सर्वाधिक 67.5 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, ग्रामीण भागात इंधणासाठी लाकडाच्या जागी बायोगॅस पूर्णपणे पर्यायी ठरत आहे. तर सर्वात कमी 12.5 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, असे प्रमाण अंशतः व मध्यम आहे.

सहाव्या प्रश्नाविषयी प्राप्त आकडेवारीतून लक्षात येते की, 46.3 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, अत्याधिक जागेच्या वापरामुळे लोक बायोगॅस पाठ फिरवत आहेत याचे प्रमाण मध्यम आहे तर सर्वात कमी 7.5 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की पूर्णपणे पाठ फिरवत आहेत.

सर्वाधिक 55.0 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की, बायोगॅस ची नियमित देखभाल अजिबात डोकेदुखी ठरत नाही तर सर्वात कमी 2.5 टक्के उत्तरदात्यांचे मानणे आहे की पूर्णपणे डोकेदुखी ठरत आहे.

### निष्कर्ष :

भंडारा जिल्ह्यातील बायोगॅस ची वर्तमान स्थिती, आव्हाने व ग्रामीण विकासात याचे योगदान या विषयी केलेल्या अध्ययनातून पुढील निष्कर्ष समोर आले;

बायोगॅस उभारणीचा प्रारंभिक खर्च अधिक जरी असला तरी शेतकरी याच्या वापरकडे दुर्लक्ष करत नाही तर जैविक कचऱ्या मालाच्या (शेण) कमतरतेमुळे बायोगॅस नियमित चालवणे पूर्णपणे आव्हानात्मक नसले तरी ही महत्वाची समस्या दिसून येते. सरकार द्वारा बायोगॅस उभारणीसाठी मिळणारी अनुदान राशी समाधानकारक असली तरी त्याच्यात वाढ होणे आवश्यक असल्याचे अध्ययनातून निष्कर्षास आले. शौचालयाला बायोगॅस जोडल्याने सामाजिक संकोच निर्माण होतो परंतु याचे प्रमाण कमी असल्याचे निदर्शनास आले. बायोगॅस धारकांचे मानणे आहे की ग्रामीण भागात इंधणासाठी लाकडाच्या जागी मोठ्या प्रमाणात बायोगॅस पर्यायी ठरत आहे. अत्याधिक जागेच्या वापरामुळे लोक बायोगॅस पाठ फिरवत आहेत असे देखील अध्ययनातून निदर्शनास आले. बायोगॅस ची नियमित देखभाल डोकेदुखी जरी ठरत असली तरी याचे प्रमाण खूप कमी आहे असे अध्ययनातून समोर आले.

संदर्भ ग्रंथसूची :

1. सेंगर.स. बायोगॅस. गोडवा कृषी प्रकाशन.
2. देवधर.प्र. बायोगॅस-जैविक इंधन.व्यास क्रिएशन्स.
3. घनवाटी.ह. (2018). बायोगॅस. स्प्रिंगर प्रकाशन.
4. <https://biogas.mnre.gov.in/about-the-programmes>
5. <http://puneresearch.com/media/data/issues/600be9e927d3f.pdf>
6. <https://agrowon.esakal.com/agro-special/biogas-plants-offer-sustainable-energy-model-for-rural-areas-sai29>

# शिक्षणात ए-आय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) च्या वाढत्या वापरामुळे शिक्षकांच्या अध्यापन पद्धती वर पडणारा प्रभावाचे विश्लेषणात्मक अध्ययन

भागवत भांगे

शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग, रा.तु.म नागपूर विद्यापीठ नागपूर

## सारांश :

वर्तमान युग तंत्रज्ञानाचे युग असून अनेक प्रकारचे बदल वेगवेगळ्या क्षेत्रात होतांना दिसून येत आहेत. ए-आय चा वापर मानवी जीवनाचे अविभाज्य अंग बनत चालला असून शिक्षण क्षेत्रावर याचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडलेला दिसून येत आहे. अध्यापन पद्धतीत अमुलाग्र बदल होतांना दिसत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्थितीवर व प्राध्यापकांच्या अध्यापन कौशल्यावर यामुळे सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पडतांना दिसून येत असून प्रस्तुत अध्ययनाच्या माध्यमातून ए-आय चा अतिवापर आणि अध्यापन पद्धतीत झालेले बदल याविषयी विश्लेषणात्मक अध्ययन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास या संदर्भातील विविध घटकांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

**मुख्य शब्द :** ए-आय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), अध्यापन पद्धत, शैक्षणिक विकास, शिक्षक-विद्यार्थी आंतरक्रिया, विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती

## प्रस्तावना :

वर्तमान काळाला “कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI)” चे युग म्हटले जाते, आणि ते योग्यही आहे, कारण आजच्या काळात एआय तंत्रज्ञानाचा प्रभाव जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात स्पष्टपणे दिसून येतो. विज्ञान, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, शेती, व्यापार, संप्रेषण आणि प्रशासन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये एआयचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. ही तंत्रज्ञान प्रणाली केवळ कामे सुलभ आणि जलद करत नाही, तर त्यामध्ये अचूकता (accuracy) आणि स्वायत्तता (automation) देखील वाढवते.

एआयचा मुख्य उद्देश संगणक आणि यंत्रांना मानवी बुद्धिमत्तेसारखी विचार करण्याची, शिकण्याची, तर्क करण्याची आणि निर्णय घेण्याची क्षमता प्रदान करणे हा आहे. मशीन लर्निंग (Machine Learning), डीप लर्निंग (Deep Learning) आणि नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया (Natural Language Processing) यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानांच्या साहाय्याने एआयने जटिल समस्यांचे निराकरण करणे शक्य केले आहे. उदाहरणार्थ, आरोग्य क्षेत्रात एआयच्या मदतीने रोगांचे लवकर आणि अचूक निदान केले जात आहे, तर शिक्षण क्षेत्रात वैयक्तिक शिकण्याच्या (personalized learning) पद्धती विकसित होत आहेत. उद्योग क्षेत्रात उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि खर्च कमी करणे यासाठीही एआय अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.

विशेषतः संगणक विज्ञान (Computer Science) या क्षेत्रावर एआयचा मोठा प्रभाव पडला आहे. सॉफ्टवेअर विकास, डेटा विश्लेषण, सायबर सुरक्षा आणि रोबोटिक्स या क्षेत्रांमध्ये एआयमुळे नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. आज एआय प्रणाली मानवी बुद्धिमत्तेच्या विविध पैलूंना—जसे की तर्कशक्ती (reasoning), समस्या सोडवणे (problem solving) आणि निर्णयक्षमता (decision making)—आंशिक स्वरूपात कार्यान्वित करू शकतात.

तथापि, प्रत्येक तंत्रज्ञानाप्रमाणे एआयचेही दोन पैलू आहेत—सकारात्मक आणि नकारात्मक. एआयचा योग्य वापर समाजाच्या प्रगतीस आणि मानव जीवनाच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यास मदत करतो, परंतु त्याचा दुरुपयोग गंभीर समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतो. उदाहरणार्थ, बनावट बातम्या (fake news) पसरवणे, सायबर गुन्ह्यांमध्ये (cyber crimes) वाढ, वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग (privacy issues) आणि स्वयंचलित शस्त्रनिर्मिती (autonomous weapons) या एआयच्या दुरुपयोगाच्या उदाहरणांमध्ये गणले जातात. याशिवाय, अतिस्वयंचलनामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होण्याची भीतीही व्यक्त केली जाते.

या सर्व गोष्टींचा विचार करता, एआयच्या वापरात नैतिकता (ethics) आणि जबाबदारी (responsibility) यांना विशेष महत्त्व देणे आवश्यक आहे. सरकार, संशोधक आणि समाज यांनी एकत्र येऊन योग्य धोरणे आणि नियम तयार करणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे एआयचा वापर मानवकल्याणासाठी होईल आणि त्याच्या दुरुपयोगावर नियंत्रण ठेवता येईल.

### शिक्षण क्षेत्रात ए-आय ((Artificial Intelligence) च्या वाढत्या प्रभावाची कारणे :

सर्व प्रकारच्या क्षेत्रात ए-आय लोकप्रिय होत चालले असून माणसांची जागा ए-आय घेणार का ? असा प्रश्न समाजाला पडला आहे असे असले तरी कार्याची सुलभता, स्पष्टता व बौद्धिक कष्ट कमी करण्यासाठी ए-आय अधिक उपयोगी ठरत आहे. काही ठळक कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत;

## बौद्धिक सटीकता :

ए-आय (Artificial Intelligence - AI) च्या माध्यमातून प्राप्त होणारे ज्ञान हे पारंपरिक माहिती स्रोतांच्या तुलनेत अधिक सटीक, स्पष्ट आणि मुद्देसूद स्वरूपाचे आढळते. AI प्रणाली मोठ्या प्रमाणातील डेटाचे जलद व कार्यक्षम विश्लेषण करून आवश्यक माहिती संक्षिप्त आणि व्यवस्थित पद्धतीने सादर करतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना अल्प वेळेत अधिक प्रमाणात आणि गुणवत्तापूर्ण माहिती मिळण्यास मदत होते.

तसेच, AI द्वारे दिली जाणारी माहिती ही विविध विश्वसनीय स्रोतांवर आधारित असल्यामुळे तिची विश्वासार्हता आणि अचूकता अधिक असते. विशेषतः सांख्यिकीय आकडेवारी, ट्रेंड विश्लेषण, आणि तुलनात्मक माहिती यांचा समावेश असल्यामुळे ज्ञान अधिक सखोल आणि अभ्यासपूर्ण बनते. यामुळे संशोधनामध्ये वस्तुनिष्ठता राखण्यास मदत होते.

AI चा वापर केल्यामुळे ज्ञानातील मानवी त्रुटी कमी होतात, तसेच जटिल संकल्पना सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याची क्षमता वाढते. त्यामुळे विद्यार्थी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील इतर घटकांना निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक अचूक आणि प्रभावी बनवता येते.

याशिवाय, AI प्रणाली सतत अद्ययावत माहिती पुरवतात, ज्यामुळे शिक्षणात नवीन घडामोडी आणि आधुनिक दृष्टिकोन समाविष्ट करणे शक्य होते. परिणामी, ज्ञान निर्मितीची गुणवत्ता सुधारते आणि शिक्षण अधिक परिणामकारक ठरते.

## भाषांतर :

भारत विविध भाषिक देश आहे. भारताची राष्ट्रीय भाषा हिंदी असली तरी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिक भाषेत शिक्षणाची व्यवस्था आहे शिवाय वैश्विक भाषा म्हणून इंग्रजी भाषेला महत्व आहे म्हणूनच भाषांतरातून शिक्षण पद्धती ज्ञानात वृद्धी घालते. ए-आय मुळे भाषांतर प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली असून विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानाची दालने खुली झाली आहेत.

## सर्व प्रकारच्या माहितीचे स्रोत :

ए-आय च्या माध्यमातून सर्व प्रकारची माहिती चुटकी सरशी उपलब्ध होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हे ज्ञानाचे महासागर वाटू लागले आहे. एरवी ज्ञानार्जनासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या पुस्तकांचा संदर्भ, शिक्षक किंवा तज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे लागे ए-आय नी आता मार्गदर्शकाची जागा घेतली आहे.

## शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक :

ए-आय शिक्षकांना शैक्षणिक साहित्य तयार करणे तसेच वेगवेगळ्या प्रकारची नवीन माहिती उपलब्ध करून देते त्यामुळे शिक्षकांमध्ये सुद्धा हे लोकप्रिय होत आहे.

### आभासी शिक्षण :

ए-आय मुळे आभासी शिक्षण प्रणालीमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. विशेषतः ऑनलाईन शिक्षणाच्या क्षेत्रात AI ने शिक्षण प्रक्रियेला अधिक गतिमान, सुलभ आणि वैयक्तिक बनवले आहे. विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म, ई-लर्निंग साधने आणि स्मार्ट तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विद्यार्थ्यांना कोणत्याही वेळेत आणि कोणत्याही ठिकाणाहून शिक्षण घेणे शक्य झाले आहे.

### ए-आय चे अध्यापन प्रणाली वर पडणारे प्रभाव

ए-आय ची शिक्षण क्षेत्रात वाढती लोकप्रियता शिक्षण व्यवस्थेत मुलभूत बदल घडवून आणत आहे.

### सकारात्मक प्रभाव

1. विद्यार्थी केंद्रित अध्ययन पद्धती
2. वैयक्तिकीकृत शिक्षण
3. स्वयं मूल्यमापन
4. विद्यार्थ्यांना त्वरित अभिप्रायाची अपेक्षा
5. शिक्षकांवरील कामाचा ताण कमी होतो.
6. शिक्षणातील कठीण संकल्पना सोप्या पद्धतीने समजावून सांगता येतात.
7. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्थितीचे विश्लेषण.
8. ऑनलाईन शिक्षणाला चालना मिळते.
9. डिजिटल साधनांचा अधिक वापर वाढतो.

### नकारात्मक प्रभाव

1. ज्ञान सहज उपलब्ध झाल्याने विद्यार्थ्यांमधील जिज्ञासा वृत्ती कमी होते.
2. शिक्षकांपेक्षा तंत्रज्ञानावर अधिक विश्वास.
3. गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना खर्चिक
4. दुर्गम भागात नेटवर्क ची समस्या

### शिक्षकांसाठी आव्हाने :

1. नवीन तंत्रज्ञान प्रणालीशी सुसंगत अध्ययन क्षमता विकसित करणे.
2. डिजिटल साक्षरतेची आवश्यकता.
3. ए-आय साधनांच्या वापरासाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता.
4. पारंपारिक अध्यापन पद्धतीत बदल करणे.
5. अध्यापनातून मानवी विश्वास कमी होण्याची भीती.

6. सतत अपडेट राहणे.
7. तांत्रिक अडचणी
8. वेळेचे व्यवस्थापन

### विषयाची निवड :

विषयाची निवड करताना वर्तमान स्थितीत ए-आय चा वाढता प्रभाव व त्याचा शिक्षण क्षेत्रात होत असलेला अत्याधिक वापर लक्षात घेतला असून त्याचे सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम अध्यापन पद्धतीवर पडताना दिसून येत आहेत.

विषयाची निवड करताना प्रामुख्याने अध्यापन पद्धतीत होणारे बदल त्याचा शिक्षकांवर होणारा परिणाम केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला आहे.

### साहित्य परीक्षण :

प्रस्तुत शोध पत्र लेखनाकरिता विविध प्रकारचे पुस्तक, शोधग्रंथ व ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करण्यात आला.

### तांबे.स.(2022). कृत्रिम बुद्धिमत्ता: तंत्र, मंत्र आणि अनुप्रयोग.

या पुस्तकात लेखकाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, व्यवसाय, अर्थकारण, राजकारण इत्यादींचेच नव्हे, तर युद्धाचे सुद्धा नियम बदलत आहेत याचे सविस्तर वर्णन केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राबद्दल मूलभूत स्वरूपाचे आणि सर्वसमावेशक ही वैशिष्ट्ये यांचा या पुस्तकात सहभाग आहे.

### वाळवलकर.ग.(2025). आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स. माय मिरर पब्लिशिंग हाउस प्रायव्हेट लिमिटेड.

या पुस्तकात ए-आय चे फायदे व तोटे नमूद केले असून लेखकांनी बदलत्या काळात विविध क्षेत्रातील ए-आय च्या भूमिकेचे वर्णन केले आहे.

### शुक्ला.सं. (2025). कृत्रिम बुद्धिमत्ता.एआयएसईसिटी पब्लिकेशन.

ही पुस्तक संतोष कुमार शुक्ला यांनी लिहिलेली असून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गुंतागुंती समजून घेण्यासाठी एक सविस्तर मार्गदर्शक म्हणून कार्य करते. यात AI चे मूलभूत तत्त्व, त्याचे विविध उपयोग आणि आजच्या समाजात त्याचे वाढते महत्त्व स्पष्ट केले आहे.

### मुलभूत शोध प्रश्न :

1. ए – आय च्या वापरामुळे विद्यार्थी तंत्रज्ञान केंद्रित होत आहे का ?
2. ए -आय मुळे पारंपारिक अध्यापन पद्धतीत बदल होत आहे का ?

3. ए-आय मुळे अध्यापन पद्धतीत आव्हान निर्माण झाले आहे का ?

### मुलभूत शोध उद्देश :

1. ए - आय च्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांमधील वाढत्या तंत्रज्ञानाविषयीचे अध्ययन करणे.
2. ए-आय मुळे पारंपारिक अध्यापन पद्धतीत झालेल्या बदलाचे अध्ययन करणे.
3. ए-आय मुळे अध्यापन पद्धतीत निर्माण झालेल्या आव्हानांचे अध्ययन करणे.

### अध्ययनाचे भौगोलिक क्षेत्र :

प्रस्तुत शोध पत्रात भौगोलिक क्षेत्र म्हणून नागपूर शहर निवडले आहे.

### संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत संशोधनपत्रात नागपूर शहरातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे ए-आय बदलचे मत अभ्यासले आहे. या संशोधनात वर्णनात्मक संशोधन आराखड्याचा उपयोग मूल्यांकनात्मक दृष्टिकोनातून वास्तव परिस्थितीची तपासणी करण्यासाठी करण्यात आला आहे.

तसेच, या संशोधन कार्यात मिश्र (गुणात्मक आणि मात्रात्मक) संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. अभ्यास करताना संरचित मुलाखत अनुसूचीचा उपयोग करून सर्वेक्षण पद्धतीच्या माध्यमातून ए-आय चे अध्यापन पद्धतीवर झालेले परिणाम तपासण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

### तथ्य संकलन पद्धती :

प्रस्तुत शोध पत्रात ए-आय चा अध्यापन पद्धतीवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी प्राथमिक स्रोतांचा वापर करण्यात आला ज्यात सर्वेक्षण पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला.

द्वितीयक स्रोतांच्या माध्यमातून माहिती मिळवण्यासाठी पुस्तके, लिंक व शोध पत्रांचा उपयोग करण्यात आला.

### अध्ययनाचे विश्व :

प्रस्तुत शोध पत्रात नागपूर शहरातील विभिन्न महाविद्यालयातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक अध्ययनाचे विश्व असून 80 शिक्षक उत्तरदाता म्हणून निवडण्यात आले.

### नमुना निवड :

प्रस्तुत शोध पत्रात संशोधनाचे विश्व लक्षात घेता असंभाव्यता नमुना निवड पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला आहे.

**सांख्यिकीय विश्लेषण :**

**तक्ता क्र.1 नवीन तंत्रज्ञान प्रणालीशी सुसंगत अध्ययन क्षमता विकसित करणे आपल्याला आव्हानात्मक वाटते का ?**

वक्तव्य	वारंवारता	टक्केवारी
अजिबात नाही	5	6.3
अंशतः	45	56.3
मध्यम	21	26.3
पूर्णपणे	9	11.3
एकूण	80	100

तक्ता क्र.1 मधील प्राप्त आकडेवारीनुसार सर्वाधिक 56.3 टक्के शिक्षकांचे मानणे आहे की नवीन तंत्रज्ञान प्रणालीशी सुसंगत अध्ययन क्षमता विकसित करणे **अंशतः** आव्हानात्मक वाटते. सर्वात कमी 6.3 टक्के शिक्षकांचे मानणे आहे की **अजिबात** आव्हानात्मक वाटत नाही.

**तक्ता क्र.2 ए-आय साधनांच्या वापरासाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता वाटते का ?**

वक्तव्य	वारंवारता	टक्केवारी
अजिबात नाही	0	0
महिन्यातून एकदा	19	23.8
वर्षातून दोन वेळा	55	68.8
वर्षातून एकदा	6	7.5
एकूण	80	100

तक्ता क्र.2 मधील प्राप्त आकडेवारीनुसार सर्वाधिक 68.8 टक्के शिक्षकांचे मानणे आहे की ए-आय साधनांच्या वापरासाठी **वर्षातून दोन वेळा** प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. सर्वात कमी 7.5 टक्के शिक्षकांचे मानणे आहे की **वर्षातून एकदा** प्रशिक्षण घेण्यात यावे.

तक्ता क्र.3 ए-आय मुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षकांविषयीची विश्वासाहता कमी होत आहे का ?

वक्तव्य	वारंवारता	टक्केवारी
अजिबात नाही	13	16.3
अंशतः	55	68.8
मध्यम	12	15.0
पूर्णपणे	0	0
एकूण	80	100

तक्ता क्र.3 मधील प्राप्त आकडेवारीनुसार सर्वाधिक 68.8 टक्के शिक्षकांचे मानणे आहे की ए-आय मुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षकांविषयीची विश्वासाहता अंशतः कमी होत आहे. सर्वात कमी 15.0 टक्के शिक्षकांचे मानणे आहे की याचे प्रमाण मध्यम आहे.

तक्ता क्र.4 ए-आय मुळे अध्यापन पद्धती सुलभ झाली आहे का ?

वक्तव्य	वारंवारता	टक्केवारी
अजिबात नाही	1	1.3
अंशतः	23	28.8
मध्यम	54	67.5
पूर्णपणे	2	2.5
एकूण	80	100

तक्ता क्र.4 मधील प्राप्त आकडेवारीनुसार सर्वाधिक 67.5 टक्के शिक्षकांचे मानणे आहे ए-आय मुळे अध्यापन पद्धती सुलभ होण्याचे प्रमाण मध्यम आहे सर्वात कमी 1.3 टक्के शिक्षकांचे मानणे आहे की अजिबात सुलभ झाली नाही.

**तक्ता क्र.5** ज्ञान सहज उपलब्ध झाल्याने विद्यार्थ्यांमधील जिज्ञासा वृत्ती कमी होत आहे का ?

वक्तव्य	वारंवारता	टक्केवारी
अजिबात नाही	1	1.3
अंशतः	7	8.8
मध्यम	30	37.5
पूर्णपणे	42	52.5
एकूण	80	100

तक्ता क्र.5 मधील प्राप्त आकडेवारीनुसार सर्वाधिक 52.5 टक्के शिक्षकांचे मानणे आहे की, ए-आय मुळे ज्ञान सहज उपलब्ध झाल्याने विद्यार्थ्यांमधील जिज्ञासा वृत्ती **पूर्णपणे** कमी झाली आहे. सर्वात कमी 1.3 टक्के लोकांचे मानणे आहे की **अजिबात कमी** झाली नाही

**तक्ता क्र.6** ए-आय मुळे पारंपारिक अध्यापन प्रणालीत बदल होत आहे का ?

वक्तव्य	वारंवारता	टक्केवारी
अजिबात नाही	1	1.3
अंशतः	3	3.8
मध्यम	57	71.3
पूर्णपणे	19	23.8
एकूण	80	100

तक्ता क्र.6 मधील प्राप्त आकडेवारीनुसार सर्वाधिक 71.3 टक्के शिक्षकांचे मानणे आहे की ए-आय मुळे पारंपारिक अध्यापन प्रणालीत **मध्यम** प्रमाणात बदल होत नाही. सर्वात कमी 1.3 टक्के लोकांचे मानणे आहे की **अजिबात बदल** होत नाही आहे.

तक्ता क्र.7

वक्तव्य	वारंवारता	टक्केवारी
अजिबात नाही	1	1.3
अंशतः	12	15.0
मध्यम	66	82.5
पूर्णपणे	1	1.3
एकूण	80	100

तक्ता क्र.7 मधील प्राप्त आकडेवारीनुसार सर्वाधिक 82.5 टक्के शिक्षकांचे मानणे आहे की ए-आय मुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षकांकडून त्वरित अभिप्रायाची अपेक्षा **मध्यम** प्रमाणात दिसून येते. सर्वात कमी 1.3 टक्के लोकांचे मानणे आहे की **अजिबात** दिसून येत नाही. असे ही 1.3 टक्के असे ही शिक्षक आहे ज्यांचे मानणे आहे की **पूर्णपणे** अपेक्षा दिसून येते.

**निष्कर्ष :**

प्रस्तुत अध्ययनातून प्राप्त आकडेवारी व तथ्यानुसार निष्कर्ष प्राप्त होते की, नवीन तंत्रज्ञान प्रणालीशी सुसंगत अध्ययन क्षमता विकसित करणे शिक्षकांसाठी आव्हानात्मक नाही. वर्षातून दोन वेळा तांत्रिक प्रशिक्षणाची सोय केल्यास ए-आय वापरणे सोपे होईल. ए-आय मुळे विद्यार्थ्यांमधील विश्वासाहता पाहिजे त्या प्रमाणात कमी होतांना दिसून येत नाही. ए-आय मुळे अध्यापन पद्धतीत सुलभता येत असून अजूनही पूर्णपणे सुलभता आली नाही असे शिक्षकांचे मानणे आहे. ए-आय च्या अधिक वापरामुळे विद्यार्थ्यांमधील जिज्ञासा वृत्ती कमी होत चालली असून हा चिंतेचा विषय आहे. पारंपारिक अध्यापन पद्धतीची जागा कौशल्याधीष्टीत शिक्षण पद्धती घेत आहे. त्यामुळे पारंपारिक शिक्षण पद्धतीत बदल होतांना दिसून येत आहे. ए-आय मुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षकांकडून त्वरित अभिप्रायाची अपेक्षा वाढत चालली असून येणाऱ्या काळात याचे प्रमाण अधिक वाढेल.

एकंदरीत प्रस्तुत अध्ययनातून ए-आय च्या वापरामुळे अध्यापन पद्धतीत अनेक प्रकारचे बदल होतांना दिसून येत आहेत.

**संदर्भ ग्रंथ सूची**

1. तांबे.स.(2022). कृत्रिम बुद्धिमत्ता: तंत्र, मंत्र आणि अनुप्रयोग.
2. वाळवलकर.ग.(2025). आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स. माय मिरर पब्लिशिंग हाउस प्रायवेट लिमिटेड.

3. शुक्ला.सं. (2025). कृत्रिम बुद्धिमत्ता.एआयएसईसिटी पब्लिकेशन.
4. <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>
5. <https://www.drishtias.com/hindi/loksabha-rajyasabha-discussions/artificial-intelligence-9>
6. <https://www.visionias.in/blog-hindi/subject-strategy-hindi/artificial-intelligence-ai-and-ethical-dilemmas>

# अनुसूचित जनजाति में धनगर आरक्षण के मांग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

किशोर विश्वासराव पाटील

## सारांश

भारत में आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण करना है। समय-समय पर बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस होती रही है। महाराष्ट्र में धनगर समाज के आरक्षण से जुड़ा मुद्दा इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। धनगर समुदाय, जो मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर है, अपनी आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल होने की मांग करता रहा है।

इस शोध में धनगर और “धनगड ” नामक जनजाति के बीच समानता एवं भिन्नता, संवैधानिक प्रावधानों, तथा आरक्षण प्रक्रिया की जटिलताओं का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, अन्य अनुसूचित जनजाति समुदायों के विरोध, राजनीतिक हस्तक्षेप, तथा प्रशासनिक अड़चनों को भी अध्ययन में शामिल किया गया है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि धनगर आरक्षण का मुद्दा केवल आर्थिक आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और कानूनी पहलुओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु संतुलित नीति, प्रमाण-आधारित निर्णय और सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वय आवश्यक है।

**बीज शब्द :** धनगर आरक्षण, विदर्भ, धनगर आरक्षण, अनुसूचित जनजाति

## प्रस्तावना :

महाराष्ट्र राज्य में धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण देने की मांग एक अत्यंत संवेदनशील तथा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरी है। परंपरागत रूप से धनगर समुदाय ने घुमंतू एवं पशुपालक जीवनशैली अपनाई है, जिसमें मुख्यतः भेड़

और बकरियों का पालन शामिल है। इस प्रवासी जीवनशैली के कारण ऐतिहासिक रूप से उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, स्थायी रोजगार और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पर्याप्त पहुँच नहीं मिल सकी, जिसके परिणामस्वरूप उनका दीर्घकालीन हाशियाकरण हुआ है।

भारतीय संविधान सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु सकारात्मक भेदभाव (affirmative action) के रूप में आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल किए जाने से धनगर समुदाय को शिक्षा, सरकारी रोजगार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में धनगर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अनुसूचित जनजातियों के समान होने के कारण, यह समुदाय कई दशकों से ST श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग करता रहा है। इस मांग की जड़ें ऐतिहासिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारकों में निहित हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान “धनगर” और “धनगड़” शब्दों के बीच उत्पन्न विसंगति के कारण प्रशासनिक भ्रम पैदा हुआ। परिणामस्वरूप, कुछ राज्यों में धनगर के समान समुदायों को ST श्रेणी में शामिल किया गया, जबकि महाराष्ट्र में उन्हें इससे वंचित रखा गया। इस असंगति के कारण धनगर समुदाय में अन्याय की भावना उत्पन्न हुई है, क्योंकि समान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों वाले समुदायों को विभिन्न राज्यों में अलग-अलग संवैधानिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

समय के साथ इस आरक्षण आंदोलन को व्यापक राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त हुआ है। धनगर समुदाय ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर विभिन्न आंदोलनों, रैलियों और सरकारी स्तर पर प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी आवाज उठाई है। हालांकि, इस मांग का विरोध मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदायों द्वारा भी किया गया है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि धनगरों के शामिल होने से उनके आरक्षण के लाभों में कमी आ सकती है। इस प्रकार, यह स्थिति एक जटिल नीति-निर्माण चुनौती प्रस्तुत करती है, जिसमें राज्य को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए विभिन्न हितों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

धनगर समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का गहन विश्लेषण करने पर उनकी निरंतर पिछड़ापन स्पष्ट रूप से सामने आता है। इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। कम साक्षरता दर, उच्च शिक्षा में सीमित भागीदारी तथा औपचारिक रोजगार क्षेत्रों में न्यून प्रतिनिधित्व इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। इसके अतिरिक्त, उनकी घुमंतू जीवनशैली बच्चों की शिक्षा में निरंतरता को बाधित करती है, जिससे दीर्घकालीन सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक प्रगति प्रभावित होती है।

भौगोलिक दृष्टि से भी धनगर समुदाय मुख्यतः ग्रामीण, दूरस्थ एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में निवास करता है, जहाँ विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छ पेयजल और परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। परिणामस्वरूप, उनका समग्र विकास सीमित रह जाता है। यदि उन्हें ST श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो वे जनजातीय समुदायों के लिए उपलब्ध विशेष योजनाओं—जैसे छात्रवृत्तियाँ, आश्रम विद्यालय, तथा वित्तीय सहायता कार्यक्रम—का लाभ उठा सकेंगे।

अतः, धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रश्न केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक असमानताओं के सुधार तथा समान विकास से जुड़ा एक व्यापक मुद्दा है। इस विषय पर संतुलित, तथ्य-आधारित और संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिससे सभी संबंधित पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत एवं दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

### आरक्षण के मांग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

महाराष्ट्र में धनगर आरक्षण का इतिहास सामाजिक न्याय, राजनीतिक घटनाक्रमों तथा प्रशासनिक निर्णयों की जटिल प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुआ है। इस इतिहास को समझने के लिए औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक समय के आंदोलनों तक की यात्रा का अध्ययन करना आवश्यक है।

### शाब्दिक अपभ्रंश :

ब्रिटिश काल में भारतीय समाज का वर्गीकरण विभिन्न जातियों और जनजातियों में किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान अनेक बार नाम, उच्चारण तथा स्थानीय भिन्नताओं के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। “धनगर” और “धनगड़” शब्दों के बीच का अंतर इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। कुछ अभिलेखों में “धनगड़” नाम से समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, जबकि “धनगर” समुदाय इससे अलग रह गया। इससे आगे चलकर आरक्षण के संदर्भ में एक गंभीर प्रशासनिक और ऐतिहासिक समस्या उत्पन्न हुई।

### स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात :

स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची निर्धारित की गई। वर्ष 1950 के राष्ट्रपति आदेश (Presidential Order) के माध्यम से विभिन्न राज्यों की जनजातियों को ST श्रेणी में शामिल किया गया। महाराष्ट्र में धनगर समुदाय को इस सूची में शामिल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत रखा गया। इस निर्णय के कारण धनगर समुदाय ST वर्ग को प्राप्त विशेष सुविधाओं और योजनाओं से वंचित रह गया।

### आरक्षण से सम्बंधित आयोगों का गठन :

1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के पश्चात धनगर समुदाय की आरक्षण संबंधी मांग अधिक स्पष्ट रूप से सामने आने लगी। समाज के नेताओं, संगठनों और कार्यकर्ताओं ने सरकार को बार-बार ज्ञापन देकर ST श्रेणी में शामिल करने की मांग की। 1970 और 1980 के दशक में यह मांग एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। विभिन्न मोर्चों, आंदोलनों और जनजागरण कार्यक्रमों के माध्यम से यह मुद्दा राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने लगा।

1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद OBC आरक्षण को मजबूती मिली, लेकिन धनगर समुदाय की ST श्रेणी में शामिल होने की मांग बनी रही। इसी दौरान “धनगड़” और “धनगर” नामों से संबंधित ऐतिहासिक भ्रम पर पुनः चर्चा प्रारंभ हुई। कई विद्वानों एवं समितियों ने इस विषय पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, किंतु ठोस निर्णय लेने में विलंब होता रहा।

### वर्ष 2000 के बाद की स्थिति, राजनितिक दलों का हस्तक्षेप :

2000 के बाद धनगर आरक्षण का मुद्दा और अधिक तीव्र हो गया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनावों के दौरान धनगर समुदाय को ST का दर्जा देने का आश्वासन दिया। इस कारण यह मुद्दा केवल सामाजिक न रहकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडा बन गया। 2014 के बाद इस विषय पर विशेष ध्यान दिया गया तथा सरकार द्वारा कई अध्ययन समितियों का गठन किया गया। फिर भी, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना ST सूची में संशोधन संभव नहीं होने के कारण यह मामला अब भी लंबित है।

इसी दौरान, वर्तमान अनुसूचित जनजाति समुदायों द्वारा इस मांग का विरोध भी किया गया। उनका मानना है कि यदि धनगर समुदाय को ST में शामिल किया गया, तो उनके आरक्षण के हिस्से में कमी आ सकती है। इस कारण यह मुद्दा और अधिक संवेदनशील बन गया है तथा सामाजिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना भी व्यक्त की जाती है।

हाल के वर्षों में धनगर समुदाय ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन, उपवास, महामोर्चे तथा अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों के द्वारा अपनी मांग को और अधिक प्रबल रूप से प्रस्तुत किया है। यद्यपि सरकार द्वारा समय-समय पर आश्वासन दिए गए हैं, फिर भी अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय तथा संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है।

इस प्रकार, महाराष्ट्र में धनगर आरक्षण का इतिहास केवल एक समुदाय की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक असंगतियों, प्रशासनिक चुनौतियों तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति

का संयुक्त परिणाम है। इस समस्या के समाधान के लिए गहन अध्ययन, वस्तुनिष्ठ आंकड़ों तथा सभी संबंधित पक्षों के हितों के संतुलन पर आधारित दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

### साहित्य पुनरावलोकन :

प्रस्तुत शोध पत्र के लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तक, शोध पत्रिका तथा इंटरनेट का उपयोग किया गया।

**बघेल.जे.पी. (2005). महाराष्ट्राचे अस्तित्वहीन धनगर: आरक्षण विमर्श. कल्पवृक्ष**

### पब्लिशिंग हाउस. मुम्बई

डॉ. जे. पी. बघेल द्वारा लिखित इस पुस्तक में महाराष्ट्र में धनगर समुदाय के कानूनी, ऐतिहासिक तथा सामाजिक-राजनीतिक हाशियाकरण का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में यह तर्क दिया गया है कि “धनगड़” नामक समुदाय, जिसे 1956 से आधिकारिक अभिलेखों में अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, वास्तव में महाराष्ट्र में अस्तित्वहीन है। इसके विपरीत, वास्तविक समुदाय—धनगर—सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा तथा ऐतिहासिक रूप से जनजातीय स्वरूप का होने के बावजूद ST दर्जे से वंचित रखा गया है। पुस्तक में यह विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार विभिन्न सरकारों, राजनीतिक नेताओं तथा स्वयं समुदाय के कुछ आंतरिक नेतृत्व ने इस त्रुटि को सुधारने में विफलता दिखाई है या जानबूझकर इसे टालते रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप धनगर समुदाय को व्यापक अन्याय का सामना करना पड़ा है।

### बिडगर.अ. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा अभ्यास. सनय प्रकाशन. पुणे

महाराष्ट्र में धनगर समाज का अध्ययन इस शोधग्रंथ के माध्यम से करते समय उसमें अनेक विशिष्ट विशेषताएँ स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। जैसे-जैसे हम इस ग्रंथ के पृष्ठों को आगे बढ़ाते जाते हैं, वैसे-वैसे इसके शोध का दायरा व्यापक रूप से विस्तार करता हुआ दिखाई देता है, जो इस शोधग्रंथ की प्रमुख विशेषता है। समग्र रूप से, इस ग्रंथ के माध्यम से धनगर समाज के आंतरिक एवं बाह्य पक्षों को विश्वविद्यालयीय शोध की पद्धति एवं अनुशासन के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है।

### शोध प्रश्न :

1. क्या महाराष्ट्र के धनगर समाज की अनुसूचित जनजाति वर्ग में आरक्षण की मांग को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ?
2. धनगर आरक्षण को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है ?
3. धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित करने में कौनसी चुनौतिया आ रही है ?

### शोध उद्देश्य :

1. महाराष्ट्र के धनगर समाज की अनुसूचित जनजाति वर्ग में आरक्षण के मांग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना ।
2. धनगर आरक्षण की वर्तमान स्थिति को जांचना।
3. धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित करने में आ रही चुनौतियों का अध्ययन करना ।

### अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र :

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन के भौगोलिक क्षेत्र के रूप में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को चयनित किया गया है ।

### शोध प्ररचना:

प्रस्तुत शोध पत्र में विदर्भ क्षेत्र के 11 जिलों में सर्वेक्षण के माध्यम से धनगर आरक्षण का अध्ययन किया गया है। संदर्भित शोध में वर्णनात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग मूल्यांकनात्मक अध्ययन दृष्टी से अध्ययन विश्व के यथार्थ की जाँच परख करने के लिए किया गया है । तथा इस शोध कार्य में मिश्रित (गुणात्मक एवं मात्रात्मक) शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन करते समय संरचित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग कर धनगर आरक्षण की स्थिति को जांचने की कोशिश की गई है ।

### अध्ययन की इकाई :

प्रस्तुत शोध पत्र में उल्लेखित भौगोलिक क्षेत्र के धनगर आरक्षण से सम्बंधित स्थिति का अध्ययन किया गया है।

### अध्ययन का समग्र :

प्रस्तुत शोध पत्र में विदर्भ के 11 जिलों से धनगर वर्ग (जाती ) से आनेवाले 100 उत्तरदाता अध्ययन के समग्र बने है।

### इकाई चयन :

प्रस्तुत शोध पत्र में अनुसंधान के समग्र को समझते हुए गैर -संभाव्यता प्रतिदर्श चयन पद्धति का उपयोग किया गया है।

### डेटा विश्लेषण :

प्रस्तुत शोध पत्र में अनुसूचित जनजाति में धनगर आरक्षण के मांग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण के माध्यम से संकलन किया गया जिसमे 08 प्रश्न सम्मिलित किए गए यह प्रश्न

धनगर आरक्षण से सम्बंधित स्थिति को दर्शाते हैं; उससे सम्बंधित डेटा सारणी क्र.1.12 में दिया गया है।

**सारणी क्र.1.12 धनगर आरक्षण से संबंधित स्थिति**

अ.क्र.	वक्तव्य	विल्लकुल नहीं	अंशतः	मध्यम	पूर्णतः	कुल
1	विदर्भ क्षेत्र में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों और आम (सार्वत्रिक) चुनावों में धनगर समाज की महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है क्या ?	8	13	22	57	100
		8.0	13.0	22.0	57.0	100
2.	विदर्भ क्षेत्र में धनगर समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा घुमंतू जाति-जनजाति (VJNT-C) प्रवर्ग के अंतर्गत प्राप्त आरक्षण पर्याप्त है क्या ?	43	16	14	27	100
		43.0	16.0	14.0	27.0	100
3	धनगर समाज के आरक्षण की मांग का क्या विभिन्न राजनीतिक दल केवल चुनावी मुद्दे के रूप में उपयोग करते हैं?	8	1	9	82	100
		8.0	1.0	9.0	82.0	100
4		55	22	10	13	100

	क्या धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल करने के लिए सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों की भूमिका सकारात्मक दिखाई देती है?	55.0	22.0	10.0	13.0	100
5	क्या ‘र’ और ‘ड’ (धनगर / धनगड़) के शब्दात्मक अपभ्रंश के कारण धनगर समाज को केंद्र सूची में अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल करने में कोई प्रशासनिक या कानूनी बाधा उत्पन्न हो रही है?	14	15	15	56	100
		14.0	15.0	15.0	56.0	100
6	क्या धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल किए जाने पर आदिवासी समुदाय को यह आशंका है कि उन्हें मिलने वाले कुल लाभों का विभाजन हो जाएगा?	9	4	24	63	100
		9.0	4.0	24.0	63.0	100
7	क्या धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल करने की मांग की कोई पृष्ठभूमि है?	7	13	20	60	100
		7.0	13.0	20.0	60.0	100
8	क्या धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति (ST)	37	21	24	18	100

श्रेणी में शामिल करने के प्रति सरकार की उदासीन भूमिका के कारण उनका सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास बाधित हो रहा है?	37.0	21.0	24.0	18.0	100
---	------	------	------	------	-----

- ऊपर्युक्त सारणी के प्रथम पहलू में सर्वाधिक 57.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की विदर्भ क्षेत्र में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों और आम (सार्वत्रिक) चुनावों में धनगर समाज की महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है वही 8.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की बिल्कुल भी सक्रिय भागीदारी देखने को नहीं मिलती ।
- द्वितीय पहलू में सर्वाधिक 43.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की विदर्भ क्षेत्र में धनगर समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा घुमंतू जाति-जनजाति (VJNT-C) प्रवर्ग के अंतर्गत प्राप्त आरक्षण पर्याप्त है वही 14.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की इसका प्रमाण मध्यम है ।
- तीसरे पहलू में सर्वाधिक 82.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की धनगर समाज के आरक्षण की मांग का विभिन्न राजनीतिक दल पूर्णतः केवल चुनावी मुद्दे के रूप में उपयोग करते हैं वही 1.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की इसका प्रमाण अंशतः है।
- चौथे पहलू में सर्वाधिक 55.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल करने के लिए सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों की भूमिका बिल्कुल भी सकारात्मक दिखाई नहीं देती है वही 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की इसका प्रमाण मध्यम है।
- पाचवे पहलू में सर्वाधिक 56.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है ‘र’ और ‘ड’ (धनगर / धनगड़) के शब्दात्मक अपभ्रंश के कारण धनगर समाज को केंद्र सूची में अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल करने में कोई प्रशासनिक या कानूनी पूर्णतः बाधा उत्पन्न हो रही है वही 15.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की यह प्रमाण अंशतः है।
- छठे पहलू में सर्वाधिक 63.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल किए जाने पर आदिवासी समुदाय को पूर्णतः आशंका है कि उन्हें मिलने वाले कुल लाभों का विभाजन हो जाएगा वही 4.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की इसका प्रमाण अंशतः है।

- सातवे पहलू में सर्वाधिक 36.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल करने की मांग की पूर्णतः पृष्ठभूमि है वही 7.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की बिल्कुल भी पृष्ठभूमि नहीं है।
- आठवे पहलू में सर्वाधिक 37.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल करने के प्रति सरकार की उदासीन भूमिका के कारण उनका सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास बिल्कुल भी बाधित नहीं हो रहा है वही 18.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है की इसका प्रमाण पूर्णतः है।

### निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध के द्वारा अनुसूचित जनजाति में धनगर आरक्षण के मांग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र विशेषतः विदर्भ क्षेत्र में धनगर समाज का आरक्षण संबंधी प्रश्न अत्यंत जटिल, संवेदनशील एवं बहुआयामी स्वरूप का है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि धनगर समाज राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय है तथा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं और सामान्य चुनावों में उनकी सहभागिता उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। यह उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी को दर्शाता है।

इसके बावजूद, वर्तमान में OBC तथा VJNT-C प्रवर्ग के अंतर्गत प्राप्त आरक्षण को अधिकांश उत्तरदाता अपर्याप्त मानते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि धनगर समाज की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान व्यवस्था के माध्यम से पूर्णतः नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि अनुसूचित जनजाति (ST) प्रवर्ग में शामिल होने की मांग को व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है।

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि धनगर आरक्षण का मुद्दा बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी मुद्दे के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह विषय केवल सामाजिक न्याय तक सीमित न रहकर राजनीतिक हितों से भी जुड़ गया है। साथ ही, सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों की भूमिका को लेकर उत्तरदाताओं में असंतोष परिलक्षित होता है, क्योंकि उनकी भूमिका को अपेक्षित रूप से सकारात्मक नहीं माना गया है।

“धनगर” और “धनगड़” के शब्दात्मक अंतर को भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं कानूनी बाधा के रूप में देखा गया है, जो इस मांग के समाधान में विलंब का कारण बन रहा है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति समुदायों में यह आशंका भी विद्यमान है कि यदि धनगर समाज को ST में शामिल किया गया, तो उनके मौजूदा लाभों का विभाजन हो सकता है, जिससे सामाजिक संतुलन प्रभावित होने की संभावना है।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि धनगर समाज की ST में समावेश की मांग का ऐतिहासिक एवं सामाजिक आधार मौजूद है। इसके बावजूद, सरकारी उदासीनता को लेकर यह धारणा प्रबल है कि इसके कारण धनगर समाज का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास बाधित हो रहा है।

अतः समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि धनगर आरक्षण का प्रश्न केवल एक आरक्षण संबंधी मांग नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक विसंगतियों के सुधार, प्रशासनिक स्पष्टता तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति से जुड़ा हुआ एक व्यापक मुद्दा है। इसके समाधान के लिए संतुलित, तथ्याधारित तथा संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी संबंधित पक्षों के हितों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि दीर्घकालीन एवं न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. बघेल.जे.पी. (2005). महाराष्ट्राचे अस्तित्वहीन धनगर: आरक्षण विमर्श. कल्पवृक्ष पब्लिशिंग हाउस. मुम्बई
2. बिडगर.अ. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा अभ्यास. सनय प्रकाशन. पुणे
3. <https://www.academia.edu/>

## विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में शिक्षा तथा कौशल विकास का महत्व

सौरभ चंद्र सानू

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल,

### सारांश:

भारत को वर्ष 2047 तक एक सशक्त, आत्मनिर्भर, समृद्ध और आधुनिक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत 2047 की जब हम पर कल्पना करते हैं ऐसे में शिक्षा तथा कौशल विकास की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। भारत पूरे विश्व का सर्वाधिक युवाओं वाला देश है किसी भी राष्ट्र का भविष्य युवा ही निर्धारित करते हैं कि वह कैसे होगा, इसीलिए इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल विकास आधारित शिक्षा उपलब्ध करवाया जाना बेहद जरूरी है। वर्ष 2020 में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 % थी इस साक्षरता दर को बढ़ाने की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार अपने स्तर से कार्य कर रही है परंतु धरातल स्तर पर अभी भी सरकारी स्कूलों की हालत कमजोर बनी हुई है तथा शिक्षकों की कमी स्पष्ट तौर पर देखी गई है जिसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने से तथा इस पर ध्यान देने से भारत का विकास संभव है इसके साथ-साथ भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो पाएगा जिसके लिए जरूरी है कि भारत में कौशल विकास पर काम करना होगा।

यह शोध पत्र द्वितीय स्रोतों पर आधारित है जिसमें मुख्यतः शोध पत्रिकाओं, विभिन्न सरकारी रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक मजबूती के साथ धरातल स्तर पर कार्य करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत को शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्र में जीडीपी प्रतिशत में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से ही वैश्विक स्तर पर भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है।

**मुख्य शब्द :-** विकसित भारत 2047, शिक्षा, कौशल विकास तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.

### परिचय

भारत ने वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके माध्यम से वह अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने तक सशक्त, आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं आधुनिक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है। विकसित भारत की परिकल्पना का क्षेत्र सिर्फ आर्थिक विकास आधार ना रखते हुए सर्वांगीण विकास जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय, तकनीकी प्रगति, पर्यावरणीय संतुलन, समावेशी विकास, और मानव कल्याण हो सके रखा गया है। इसके लिए भारत को लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है ताकि प्रत्येक नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सके।

किसी भी राष्ट्र के विकास में युवाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है जो कि उस राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करता है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसमें लगभग 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। ऐसे स्थिति में यदि भारत देश में युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले जिसके लिए बेहद जरूरी है कि एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ व्यवहारिक कौशल विकास आधारित ज्ञान दिया जाना चाहिए तो हम विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का लक्ष्य आसानी से पूरा कर सकते हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 % थी इस साक्षरता दर को बढ़ाने की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार अपने स्तर से कार्य कर रही है परंतु धरातल स्तर पर अभी भी सरकारी स्कूलों की हालत कमजोर बनी हुई है तथा शिक्षकों की कमी स्पष्ट तौर पर देखी गई है जिसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने से तथा इस पर ध्यान देने से भारत का विकास संभव है इसके साथ-साथ भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो पाएगा जिसके लिए जरूरी है कि भारत में कौशल विकास पर काम करना होगा।

वर्ष 2020 में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने का कार्य भारत में किया जा रहा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यावहारिक, समावेशी, लचीला और आधुनिक बनाना है, ताकि विद्यार्थी बदलते समय और रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार हो सकें।

शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित सरकारी पहल

भारत सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रारंभ की हैं—

1. नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) – शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और कौशल आधारित बनाना।
2. स्किल इंडिया मिशन (2015) – युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) – युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देना।
4. डिजिटल इंडिया अभियान – डिजिटल शिक्षा और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना।
5. स्टार्टअप इंडिया – युवाओं में उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना।

किसी भी देश को विकसित तब माना जाता है जब वहाँ के लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ सभी के लिए उपलब्ध हों, रोजगार के पर्याप्त अवसर हों और आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। विकसित भारत की परिकल्पना भी इन्हीं आधारों पर आधारित है। विकसित भारत की कल्पना में शिक्षा और कौशल विकास की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन पर निर्भर करती है। यदि देश के नागरिक शिक्षित और कुशल होंगे, तो वे नई तकनीकों को अपनाने और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार करने में सक्षम होंगे। इसलिए वर्तमान समय में शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी देश के विकास में सक्रिय योगदान दे सके। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रबुद्ध और जागरूक मानव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका मानना था कि शिक्षक को विद्यार्थियों में जिज्ञासा, नवाचार, रचनात्मकता, उद्यमिता और नैतिक नेतृत्व जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ ही उनके भीतर मजबूत नैतिक मूल्यों का विकास करना भी आवश्यक है। इन दोनों गुणों के माध्यम से ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है और एक जिम्मेदार तथा संवेदनशील नागरिक का निर्माण संभव हो पाता है।

### **विकसित भारत 2047 की परिकल्पना।**

विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उद्देश्य यह है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक ऐसा देश बनाया जाए जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और तकनीकी रूप से पूरी तरह विकसित हो। जब किसी देश के नागरिकों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, पर्याप्त रोजगार के अवसर और सुरक्षित वातावरण मिलता है, तभी वह देश सही अर्थों में विकसित माना जाता है। इसलिए विकसित भारत 2047 की सोच में यह प्रयास किया जा रहा है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे और कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। देश की बड़ी आबादी युवाओं की है, जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। यदि युवाओं को सही दिशा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यक कौशल प्रदान किए जाएँ, तो वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए शिक्षा और कौशल विकास को विकसित भारत की परिकल्पना में विशेष महत्व दिया गया है।

## शिक्षा का महत्व

शिक्षा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है तथा उसे एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास को भी सुनिश्चित करना होता है। जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह समाज के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनता है। इसी कारण शिक्षा को समाज और राष्ट्र के विकास का आधार माना जाता है।

डॉ. अब्दुल कलाम का मानना था कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं में रचनात्मकता, नवाचार और नेतृत्व की भावना विकसित करे। वे मानते थे कि शिक्षित और कुशल युवा ही राष्ट्र को विकसित बना सकते हैं।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्तियों और क्षमताओं का विकास होता है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का निर्माण करना होना चाहिए।

शिक्षा मानव संसाधन के विकास का प्रमुख साधन है। इसके माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान, तकनीकी दक्षता और व्यावहारिक कौशल प्राप्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है, तो वह अपने कार्य को अधिक कुशलता और समझदारी के साथ कर सकता है। इससे न केवल उसकी व्यक्तिगत प्रगति होती है, बल्कि समाज और देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान मिलता है। इसी कारण शिक्षा को मानव संसाधन विकास का आधार माना जाता है। मानव संसाधन किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण पूँजी मानी जाती है। किसी राष्ट्र की प्रगति केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों या आर्थिक साधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके नागरिकों की क्षमता, ज्ञान और कौशल पर भी निर्भर करती है। इसलिए मानव संसाधन के विकास में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता, कौशल और व्यक्तित्व का विकास करता है, जिससे वह समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देने में सक्षम बनता है। नेल्सन मंडेला ने शिक्षा को “दुनिया को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार” माना है, जो व्यक्तिगत विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार है। उनका मानना था कि शिक्षित नागरिक ही किसी देश को सही मायने में विकसित कर सकते हैं।

## कौशल विकास का महत्व

जब हम कौशल विकास की बात करते हैं तो सब से पहले हमें कौशल को समझने की आवश्यकता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को अभ्यास, ज्ञान और अनुभव के आधार पर अच्छी तरह करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो उसे कौशल कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा समय के साथ किसी कार्य को लगातार करने के बाद उस कार्य में महारत हासिल हो जाना ही कौशल है। कौशल केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें व्यावहारिक अनुभव और कार्य करने की क्षमता भी शामिल होती है।

कौशल का विकास शिक्षा, प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में लगातार अभ्यास करता है और नई-नई बातें सीखता है, तो उसकी कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसी प्रक्रिया को कौशल विकास कहा जाता है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। क्योंकि वर्तमान समय के अनुरूप अब सिर्फ शैक्षणिक डिग्री प्राप्त होने से रोजगार प्राप्त करना आसान नहीं है इसके साथ-साथ कौशल का होना भी बेहद जरूरी है। अतः कौशल विकास आधारित ज्ञान का मिलना युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।

विश्व बैंक की कई रिपोर्टों में यह बताया गया है कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिपोर्ट के अनुसार यदि युवाओं को सही प्रकार का तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। ILO के अध्ययन में बताया गया है कि कौशल विकास श्रम बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## प्रमुख चुनौतियां

विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी कई सारी चुनौतियां धरातल स्तर पर अभी भी मौजूद हैं जिनका हम सभी को मिलकर समाधान करने की आवश्यकता है।

1. **शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता :-** भारत देश विषमताओं वाला देश है देश के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता एक समान देखने को नहीं मिलती है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के बीच एक बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में शिक्षा के अवसर तथा संसाधन अधिक मौजूद हैं जबकि भारत जैसे राष्ट्र में अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र में आता है।

2. **शिक्षकों की कमी :-** वर्तमान समय में भारत में मौजूद विद्यालय में शिक्षकों की कमी है भारत की शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के सीखने के स्तर पर पड़ता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक-छात्र अनुपात अधिक है और कुछ स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक पूरे विद्यालय को संभाल रहे हैं। विशेषकर प्राथमिक शिक्षा में देखा जाए तो संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 10 लाख शिक्षकों की अतिरिक्त आवश्यकता है।
3. **कौशल प्रशिक्षण के प्रति जागरूकता की कमी:-** वर्तमान समय में भारत देश में अभी भी व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि पारंपरिक शिक्षा को दिया जाता है जिस वजह से युवा कौशल प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
4. **औपचारिक कौशल प्रशिक्षण की कमी :-** भारत के Economic Survey के अनुसार देश के युवाओं में औपचारिक कौशल प्रशिक्षण बहुत कम है। रिपोर्ट बताती है कि केवल लगभग 4.4% युवाओं को ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, जबकि बड़ी संख्या में युवा बिना किसी प्रमाणित प्रशिक्षण के काम कर रहे हैं।
5. **तकनीकी संसाधनों की कमी :-** भारत में कई शिक्षण संस्थानों में अभी भी आधुनिक तकनीकी सुविधाओं की कमी मौजूद है इसके साथ-साथ प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी भी स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है जिस कारण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती।

### सुझाव:

1. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता। :- देश में मौजूद सभी व्यक्तियों को अच्छी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए सरकार का फर्ज होना चाहिए कि आधुनिक तकनीक, शिक्षण पद्धतियों और प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने का काम करे।
2. शिक्षा के क्षेत्र में भारत की जीडीपी प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता :- भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है जो कि भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, समावेशी और कौशल आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है परंतु वर्तमान में सरकारी विद्यालय की हालतों में सुधार करने की आवश्यकता है तथा उन्हें औरत अत्यधिक मजबूत करने की जरूरत है तभी हम NEP 2020 को साकार कर सकते हैं इसके लिए सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी के हिस्से को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में पहले से अधिक तीव्र गति से कार्य हो सके।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का विस्तार करने की :- ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्र में शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण की सुविधा को बढ़ाने की जरूरत है ताकि इन छात्रों में रहने वाले युवाओं को भी समान अवसर प्राप्त हो सके तथा वे भी इसका लाभ ले पाए व भारत के विकास में अपना योगदान दे सके।
4. शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्य :- सरकार को समय समय पर शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्य करने की जरूरत है ताकि उनकी विकास क्षमता और नई शिक्षण तकनीक के उपयोग में सहायता मिल सके।
5. गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता :- विकसित भारत की परिकल्पना में शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्र सरकार अकेले पूर्ण रूप से काम नहीं कर सकती ऐसे में जरूरी है कि सरकार गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर क्षेत्र में कार्य करे तथा कार्य की मॉनिटरिंग खुद करें ताकि किसी प्रकार की लापवाही ना हो सके।

### निष्कर्ष:

विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में शिक्षा तथा कौशल विकास का महत्व बेहद महत्वपूर्ण है बिना इसके विकसित भारत 2047 की परिकल्पना कर पाना संभव नहीं। भारत में शिक्षा तथा कौशल विकास अथक प्रयास किये जा रहे हैं परंतु अभी भी धरातल स्तर पर कई सारी समस्या बनी हुई है भारत को शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्र में जीडीपी प्रतिशत में वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके तथा कौशल विकास में युवाओं का हस्तक्षेप पहले की तुलना में अधिक बढ़ पाए। इसके माध्यम से ही वैश्विक स्तर पर भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है तथा वर्ष 2047 तक निर्धारित विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है।

### संदर्भ:

1. भारत सरकार। (2011)। भारत की जनगणना 2011: प्रारंभिक जनसंख्या आंकड़े। रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, भारत।
2. भारत सरकार। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा मंत्रालय।
3. विश्व बैंक। (2019)। विश्व विकास रिपोर्ट 2019: कार्य की बदलती प्रकृति। विश्व बैंक।
4. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। (2017)। निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में कौशल एवं रोजगार असंगति। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
5. नीति आयोग। (2022)। विकसित भारत 2047 के लिए दृष्टि दस्तावेज।

6. Nelson Mandelal (2003)। एक बेहतर भविष्य की ओर मार्गदर्शन (Mindset Network के शुभारंभ अवसर पर दिया गया भाषण, जोहान्सबर्ग)।
7. प्रेस सूचना ब्यूरो। (तिथि उपलब्ध नहीं)। भारत में युवाओं से संबंधित तथ्य पत्रक। प्राप्त स्रोत: <https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149107&reg=3&lang=2>
8. A. P. J. Abdul Kalam। (2011)। टर्निंग पॉइंट्स: चुनौतियों के माध्यम से एक यात्रा। हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स।
9. संसदीय स्थायी समिति (शिक्षा)। (2024)। रिपोर्ट।
10. यूनेस्को। भारत में शिक्षक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।
11. सिंह, वी. (2025)। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य प्राप्ति में एक प्रगतिशील एवं समावेशी शिक्षा प्रणाली की अनिवार्यता। अभिगम, (34)।
12. रामकृष्ण, वी., सुजाता, एन., एवं गोपालकृष्ण, एम। (2024)। विकसित भारत @2047: एक दृष्टिकोण।

## हिंदी सिनेमा: एलजीबीटी समुदाय का प्रतिनिधित्व और मानवाधिकार

गया सी एस

शोधार्थी, हिंदी विभाग

श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालडी।

सिनेमा और समाज के बीच एक अटूट संबंध है। समाज के बिना सिनेमा का कोई अस्तित्व नहीं है। सिनेमा समाज से जुड़ा हुआ है। सिनेमा दरअसल एक नई सच्चाई है। सिनेमा के संबंध में विनोद दास का कहना है – ‘सिनेमा एक कला और अन्य कलाओं की तरह यह भी हमारे समय और समाज की बुनियादी तथा तत्कालीन चिंताओं-जिज्ञासाओं को अपनी सृजनशीलता का एक अनिवार्य अंश बनाता रहा है।’

भारतीय सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में हिंदी सिनेमा का एक प्रमुख स्थान है; जहाँ एक ओर यह मनोरंजन का साधन है, वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक संरचनाओं, रीति-रिवाजों और स्वीकार्यताओं को भी दर्शाता है। इसके अलावा, बदलती सोच और विचारों के अनुरूप यह अपनी कहानियों में विविध लैंगिक पहचानों और विषयों को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। लंबे समय तक LGBT समुदाय से जुड़े विषयों और व्यक्तियों को अक्सर मजाक का पात्र बनाकर ही प्रस्तुत किया जाता था। हालाँकि, अब हिंदी सिनेमा ने LGBT समुदाय को एक विशिष्ट पहचान और एक अनोखी छवि प्रदान की है।

मानवाधिकारों के नज़रिए से देखें तो LGBT समुदाय सदियों से अन्याय और अत्याचार का शिकार रहा है। उनकी लैंगिक पहचान और यौन रुझान के आधार पर उन्हें उन कई बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से मिलने चाहिए—जैसे समानता, स्वतंत्रता और गरिमा। इस संदर्भ में सिनेमा एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरता है, जो अपनी कहानियों में इन मुद्दों को केंद्र में रखकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समाज और आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम करता है और साथ ही मानवाधिकारों के प्रति एक संवेदनशील और उदार दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

वर्तमान समय में हिन्दी सिनेमा में स्पष्ट परिवर्तन देखा जा रहा है। अब कई सिनेमा में LGBT समुदाय का चित्रण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ‘लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर’ जैसे अन्य लोग भी शामिल हैं। एल.जी.बी.टी समुदाय को लेकर समाज में लंबे समय से बहुत गलत अवधारणाएँ हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों का जीवन नरक बना हुआ है। किन्तु अब हिन्दी सिनेमा उन्हें मुख्यधारा में स्थान देने का प्रयास कर रहा है।

भारतीय संस्कृति भी विषमलैंगिकता को अधिक महत्व देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य और पशु-पक्षियों में सामान्य रूप से देखे जाने वाले यौन संबंधों को ‘विषमलैंगिकता’ कहा जाता है। लोगों की नज़र में केवल स्त्री-पुरुष के बीच होने वाला प्यार ही पवित्र है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक स्त्री और दूसरी स्त्री तथा एक पुरुष और दूसरे पुरुष के बीच भी वैसा ही प्यार हो सकता है, जैसा एक स्त्री और पुरुष के बीच होता है। यह कोई हँसी-मज़ाक की बात नहीं है। इस प्रकार की यौन रुचि रखने वालों को समलैंगिक कहा जाता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं—एक ‘लेस्बियन’ और दूसरा ‘गे’। आज समलैंगिकता कानूनी अपराध नहीं है। लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने IPC 377 से समलैंगिकता को हटा दिया है। परंतु लड़ाई अब भी बहुत लंबी है। इस लंबे सफ़र में सिनेमा का योगदान अविश्वसनीय है।

सिनेमा के क्षेत्र में ‘फायर’ (1996) ‘दीपा मेहता’ द्वारा निर्देशित एक महत्वपूर्ण सिनेमा है। स्त्री समलैंगिक संबंधों को दर्शाने वाला एक प्रमुख सिनेमा है फायर। फायर वास्तव में सीता (नंदिता दास) और राधा (शबाना आज़मी) नामक दो स्त्रियों के जीवन पर आधारित कहानी है, जिनकी शादी एक ही घर के दो भाइयों से हुई है। सीता के पति को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। राधा के पति ने तो संन्यास ले लिया होता है। ऐसे में सीता और राधा एक-दूसरे के अकेलेपन का सहारा बन जाती हैं। वे दोनों दोस्त बन जाती हैं और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इस सिनेमा को लेकर काफी विवाद पैदा हुआ था। इस सिनेमा पर भारतीय संस्कृति को दूषित करने का आरोप भी लगा था। फिर भी इस सिनेमा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब नाम कमाया और कई पुरस्कार भी जीते।

इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाला एक और खास सिनेमा है ‘शुभ मंगल ज़्यादा सावधान’। जिसका निर्देशन 2020 में ‘हितेश केवल्या’ द्वारा किया गया है। यह सिनेमा पुरुष समलैंगिक संबंधों के विषय को प्रमुखता से प्रस्तुत करता है।

इस सिनेमा की कहानी दो प्रमुख पात्रों अमन और कार्तिक के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। कार्तिक एक आत्मनिर्भर और खुले विचारों वाला समलैंगिक व्यक्ति है, जबकि अमन एक पारंपरिक परिवेश में पला-बढ़ा साधारण युवक है। दोनों के स्वभाव और पारिवारिक पृष्ठभूमि में भिन्नता होने के बावजूद उनके बीच गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित होता है। अमन का परिवार

पारंपरिक और रूढ़िवादी सोच से प्रभावित है, जिसके कारण वे उनके संबंध को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। उनके दृष्टिकोण में केवल स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध ही सामाजिक रूप से मान्य और उचित माना जाता है। सिनेमा में यह प्रभावी ढंग से दिखाया गया है कि किस प्रकार अमन और कार्तिक अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए सामाजिक दबावों और पारिवारिक विरोध का सामना करते हैं। साथ ही, यह भी दर्शाया गया है कि न्यायिक निर्णयों और बदलते सामाजिक दृष्टिकोण के प्रभाव से अंततः परिवार के विचारों में परिवर्तन आता है और वे इस संबंध को स्वीकार करने लगते हैं।

असल में, ये दोनों सिनेमा न सिर्फ़ समलैंगिक लोगों के बीच के प्रेम को दिखाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि प्यार करने का अधिकार हर इंसान का एक बुनियादी मानवाधिकार है, चाहे उसकी लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास कुछ भी हो। हर एक इंसान को बराबरी, इज्जत और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी या इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार है। इस तरह, ये दोनों सिनेमा समलैंगिक लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं।

एल.जी.बी.टी समुदाय के अंतर्गत आने वाले तीसरा वर्ग है ‘उभयलिंगी’। उभयलिंगी को अंग्रेजी में ‘Bisexual’ कहा जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान रुचि रखने वाले व्यक्ति को ‘उभयलिंगी’ कहा जाता है। इन्हें भी समाज की मुख्यधारा की ओर ले आने में सिनेमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

‘शोनाली बोस’ के निर्देशन में 2015 में ‘मार्गरीटा विद ए स्ट्रॉ’ नामक एक सिनेमा का निर्माण हुआ। इसमें उन्होंने सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित लैला (कल्कि कोचलिन) के जीवन को दर्शाया गया है। इसके अलावा, उभयलिंगी प्रेम को भी चित्रित किया गया है। यह पूरी सिनेमा लैला पर केंद्रित है। सिनेमा में उसके जीवन-संघर्ष को दिखाया गया है। साथ ही, उसे अपनी सेक्सुअलिटी का भी एहसास होता है। जब लैला कॉलेज में पढ़ती है, उस समय वह अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी स्वयं या कभी किसी लड़के के साथ होने की कोशिश करती है। बाद में, लैला अपनी उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में जाती है। वहाँ उसकी टाइपिंग में सहायता के लिए ‘जैरेड’ नामक एक युवक को रखा जाता है। धीरे-धीरे, जैरेड के प्रति उसके मन में एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है। इसी बीच, उसकी मुलाकात एक सक्रियतावादी लड़की ‘खानुम’ से होती है। खानुम एक अंधी लड़की है। वे दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगती हैं। लेकिन फ़िल्म में एक संदर्भ में लैला को यह एहसास होता है कि वह ‘उभयलिंगी’ है, क्योंकि खानुम के साथ रहते हुए भी जैरेड के प्रति उसे आकर्षण का अनुभव होता है। वास्तव में, इस फ़िल्म को लेस्बियन और उभयलिंगी—दोनों श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्रस्तुत फ़िल्म भी उभयलिंगी वर्ग के प्रति समाज के नज़रिए में एक प्रकार का बदलाव लाने में सक्षम है।

‘ट्रांसजेंडर’ भी एल.जी.बी.टी समुदाय के अंतर्गत आने वाला एक ओर समुदाय है। स्त्री और पुरुष को सृष्टि का आधार मानने वाला यह समाज इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि इन दोनों के अलावा इस संसार में एक अन्य वर्ग भी है, जिन्हें संसार वालों ने दोगम दर्जे का इंसान मानकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। जिन्हें ‘ट्रांसजेंडर’ कहा जाता है। वास्तव में ट्रांसजेंडर मुद्दों पर कई साहित्यिक रचनाएं उपलब्ध हैं। लेकिन इन सबके अलावा आजकल सिनेमा ने भी इस विषय को केंद्र में रखकर फ़िल्में बनानी शुरू कर दी हैं।

‘चंडीगढ़ करे आशिकी’ नामक सिनेमा इस जॉनर में आने वाला एक सिनेमा है। यह सिनेमा मनु (आयुष्मान खुराना) और मानवी (वाणी कपूर) के प्यार की कहानी है। मनु ने एक जिम खोल रखा है और मानवी वहाँ ज़ुम्बा ट्रेनर के रूप में आती है। मनु और मानवी एक-दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। मनु उससे शादी भी करना चाहता है। लेकिन अचानक मानवी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसके सामने रखती है कि वह एक ट्रांसवुमन है, यानी एक ट्रांसजेंडर। यह सुनने के बाद मनु टूट जाता है और उसके अंदर एक प्रकार की घृणा उत्पन्न होती है कि उसने एक लड़के से प्यार किया है। लेकिन मानवी बार-बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अब एक पुरुष नहीं, बल्कि एक महिला है। फिर भी मनु इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। उसके अंदर अब भी उसके प्रति वही प्यार है, लेकिन वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए मनु इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देता है, जैसे—ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? पूरी दुनिया में ये लोग क्या कर रहे हैं? उनका जीवन कैसा है? आदि। इसके बाद वह एक ट्रांसजेंडर से बात करता है। उनकी बातचीत से उसे पता चलता है कि प्यार तो प्यार होता है और उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। प्यार शुद्ध और सच्चा होना चाहिए। इसलिए मानवी खुलकर सच बताती है कि वह एक ट्रांसवुमन है, क्योंकि वह इस रिश्ते में ईमानदार रहना चाहती है।

यहाँ निर्देशक यह व्यक्त करना चाहता है कि किसी व्यक्ति की जेंडर और सेक्सअलिटी का निर्धारण उसकी शारीरिक बनावट से नहीं, बल्कि उसके भीतर की पहचान से होता है। अंत में मनु इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है और उसके साथ एक खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है।

असल में, सभी ट्रांसजेंडर्स को संविधान द्वारा दिए गए सभी मानवाधिकारों के साथ समाज में सम्मान और बिना किसी डर के जीने का अधिकार है। वे भी बाकी लोगों की तरह खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं।

## निष्कर्ष

हिंदी सिनेमा के बदलते परिदृश्य में, आजकल LGBT समुदाय लगातार एक अभिन्न और स्थायी उपस्थिति के रूप में उभरकर सामने आया है। हालाँकि, अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा अक्सर इस समुदाय को हास्य, भय या विकृति के नज़रिए से चित्रित करता था। इस तरह के चित्रण के परिणामस्वरूप, उन्हें समाज के भीतर विभिन्न प्रकार के अन्याय, शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा; इसके अलावा, उनके बारे में नकारात्मक धारणाएँ भी गहरी जड़ें जमा गईं।

हालाँकि, बदलते सामाजिक दृष्टिकोण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति, और शिक्षा के प्रसार ने इस स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। समकालीन हिंदी सिनेमा अब LGBT समुदाय को अधिक मानवीयता, यथार्थ और संवेदनशीलता के साथ चित्रित करता है। यह उनके जीवन के संघर्षों, पहचान की तलाश, सामाजिक स्वीकृति की खोज और आत्म-सम्मान की चाह को एक अनोखे और विशिष्ट अंदाज़ में प्रस्तुत करता है।

मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में, यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के बराबर अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान मिलना चाहिए। किसी के साथ भी लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

इस संदर्भ में, मुख्यधारा के सिनेमा ने अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए भी इस दिशा में काफी हद तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजकल कई हिंदी फ़िल्मों ने परिवार, समाज और प्यार के नज़रिए से क्वीर समुदाय के लोगों की भावनाओं, चुनौतियों और अधिकारों को चित्रित किया है। इसके अलावा, सिनेमा ने यह एहसास भी दिलाया है कि बराबरी सिर्फ़ अधिकारों तक सीमित नहीं है; यह अधिकारों से आगे बढ़कर इंसानों की मानवीयता पर जोर देती है।

इस प्रकार, हिंदी सिनेमा और क्वीर समुदाय की कहानियों का मेल समाज में मानवाधिकार की भावना को मज़बूत करता है और हमें याद दिलाता है कि हर इंसान, चाहे उसका यौन अभिविन्यास या पहचान कुछ भी हो, इस समाज में इज्जत, गरिमा और बराबर मौकों का हक़दार है। यह न केवल समाज को संवेदनशील बनाता है, बल्कि मानवाधिकारों के प्रति लोगों का नज़रिया भी मज़बूत करता है।

## संदर्भ ग्रंथ

1. जयप्रकाश चौकसे, सिनेमा और सितारों का मायाजाल, प्रभाव प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015.
2. डॉ. टी. शशिधरन, सिनेमा के चार अध्याय, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014.
3. सं. डॉ. विजेंद्र प्रताप सिंह, रवि कुमार गोंड॰, भारतीय साहित्य एवं समाज में तृतीय लिंगी विमर्श, अमन प्रकाशन, कानपुर, 2016.

4. आलोक पांडेय, समाज में सिनेमा (‘मीडिया विमर्श’, सिनेमा विशेषांक 1, दिसंबर, 2012), पृ. 02
5. विनोद भारद्वाज, सिनेमा कल, आज, कल, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006.
6. दिनेश श्रीनेत, पश्चिम और सिनेमा वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012.

## मेलघाट परिक्षेत्र में कुपोषण: एक पुनरावलोकन

नीता उघड़े

शोधार्थी, वर्धा समाज कार्य संस्थान,  
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

### सारांश

मेलघाट लगभग 314 छोटे गांवों का पहाड़ी और वन क्षेत्र है और महाराष्ट्र राज्य में सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता है। संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008 के आदेश के अनुसार, क्रमांक 41 मेलघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धरनी तहसील, चिखलदरा तहसील और अचलपुर तहसील (भाग), राजस्व मंडल-परतवाड़ा से बना है। कुपोषण आमतौर पर जीवित रहने के लिए आवश्यक 2400 से 2500 कैलोरी न मिलने के कारण होता है। विद्वानों के अनुसार भारत जैसे देश में एक वयस्क के लिए प्रतिदिन 2737 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति की दैनिक भोजन की आवश्यकता इस मात्रा में पूरी नहीं होती है, तो वह धीरे-धीरे कुपोषण का शिकार हो जाता है।

उद्देश्य एवं शोध प्रविधि : प्रस्तुत आलेख पीएचडी शोध का हिस्सा है। इसमें शोधार्थी द्वारा किए गए साहित्य पुनरावलोकन के आधार पर मेलघाट की कुपोषण के समस्या की स्थिति कैसी है? को समझने के उद्देश्य से किया गया है। शोध आलेख पूरी तरह से द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। शोध आलेख हेतु वर्ष 2013 से 2023 तक के गूगल स्कॉलर पर उपलब्ध शोध आलेखों का चुनाव सुविधाजनक पद्धति से किया गया है।

साहित्य समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि मेलघाट क्षेत्र के कोरकू लोग स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल से वंचित होने के मामले में एक विशिष्ट उदाहरण हैं। क्षेत्र में पिछड़ेपन और गरीबी की लगातार समस्या स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रतिबिंबित होती है। कुपोषण की समस्या का समाधान को लेकर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है तथा समाज कार्य हस्तक्षेप संबंधी सूचनाओं का भी अभाव देखा गया है।

**मुख्य शब्द :** मेलघाट, कुपोषण, कोरकू, साहित्य समीक्षा

### प्रस्तावना:

स्वास्थ्य संवर्धन के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध न हो तो कुपोषण होता है। इस प्रकार, कुपोषण किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन यह मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है। कुपोषण का प्रसार 6 माह से 3 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे अधिक है। कुपोषण अपर्याप्त आहार, शरीर के पोषण के लिए संतुलित आहार का खंडित होना, या संतुलित आहार से संबंधित विकार, शरीर के लिए आवश्यक भोजन की कमी, अपाच्य भोजन का सेवन या आहार में हानिकारक भोजन का समावेश है। शरीर के लिए आवश्यक कैलोरी (ऊर्जा) का उत्पादन न होने से शरीर और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप, शारीरिक प्रदर्शन कम हो जाता है। ऐसा व्यक्ति 'कुपोषित' व्यक्ति होता है। कुपोषण आमतौर पर जीवित रहने के लिए आवश्यक 2400 से 2500 कैलोरी न मिलने के कारण होता है। विद्वानों के अनुसार भारत जैसे देश में एक वयस्क के लिए प्रतिदिन 2737 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति की दैनिक भोजन की आवश्यकता इस मात्रा में पूरी नहीं होती है, तो वह धीरे-धीरे कुपोषण का शिकार हो जाता है।

मेलघाट लगभग 314 छोटे गांवों का पहाड़ी और वन क्षेत्र है और महाराष्ट्र राज्य में सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता है। संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008 के आदेश के अनुसार, क्रमांक 41 मेलघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धरनी तहसील, चिखलदरा तहसील और अचलपुर तहसील (भाग), राजस्व मंडल-परतवाड़ा से बना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 300,000 से अधिक लोगों का निवास वाला यह क्षेत्र मुख्य रूप से कोरकू जनजातियों का घर है, जिनकी आबादी 75% से अधिक है। यहां की आबादी शांत, कानून का पालन करने वाली, ईमानदार और मेहनती है और पारंपरिक रूप से मेलघाट के जंगलों में श्रम कार्य से निकटता से जुड़ी हुई है। जबकि कृषि एक प्रमुख व्यवसाय रहा है, पहाड़ी और उबड़-खाबड़ इलाके के कारण उपज कम है। इसलिए, श्रम गतिविधियाँ प्राथमिक व्यवसाय का समर्थन करती हैं। वनों की कमी, कानूनों के प्रतिबंध और पर्याप्त वैकल्पिक स्रोतों की कमी के कारण वन और वन्यजीवों पर आधारित भोजन और औषधियों के पारंपरिक स्रोतों के विघटन से पोषण और औषधि की एक संक्रमणकालीन कमी पैदा हो गई जो आसानी से वनों से प्राप्त होती थी। अल्पपोषण इस अवधि की एक घटना प्रतीत होती है क्योंकि यह किसी भी पिछले दस्तावेज़ में लिखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है। मेलघाट एक विशाल वन क्षेत्र है जो अपने बाघों के लिए जाना जाता है और संयोग से पिछले दो से तीन दशकों में उच्च पोषण, शिशु और मातृ मृत्यु दर के लिए भी जाना जाता है।

मेलघाट में 2022-23 में कुपोषण के कारण हर दूसरे दिन औसतन एक बच्चे की मौत हुई है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने विधान परिषद में बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के

दौरान मेलघाट में 175 बच्चों की मौत हुई है। जबकि कुपोषण से होने वाली मौतों की दुखद घटनाओं ने मेलघाट को वर्षों से परेशान किया है, बावजूद इसके इस क्षेत्र में आक्रामक सरकारी हस्तक्षेप का प्रभाव पड़ रहा है और 2018-19 की तुलना में बाल मृत्यु दर में लगभग 50% की कमी आई है। उस अवधि के दौरान, 309 बाल मृत्यु के मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2022-23 अप्रैल-जनवरी के उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि 77 मौतें एक महीने से कम उम्र के बच्चों की थीं। इसी अवधि में 1 महीने से 1 वर्ष की आयु के बीच बाल मृत्यु के मामले 42 दर्ज किए गए हैं, जबकि 1-6 वर्ष की आयु समूह के लिए, दर्ज की गई मौतों की संख्या 38 है। बावजूद इसके इस परिक्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत इस समस्या के निबटान के लिए गंभीर कार्य हो रहा है।

**उद्देश्य एवं शोध प्रविधि :** प्रस्तुत आलेख पीएचडी शोध का हिस्सा है। इसमें क्षोदधारथी द्वारा किए गए साहित्य पुनरावलोकन के आधार पर मेलघाट की कुपोषण के समस्या की स्थिति कैसी है? को समझने के उद्देश्य से किया गया है। शोध आलेख पूरी तरह से द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। शोध आलेख हेतु वर्ष 2013 से 2023 तक के गूगल स्कॉलर पर उपलब्ध शोध आलेखों का चुनाव सुविधाजनक पद्धति से किया गया है।

### साहित्य पुनरावलोकन

**Datta, S. S., & Mail, I. D. (2013)** मेलघाट 312 छोटे गांवों का पहाड़ी वन क्षेत्र है, जिसे महाराष्ट्र के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता है। मेलघाट में रोजगार शोषणकारी, गुलाम बनाने वाला और लैंगिक भेदभावपूर्ण है। 92-97 में मेलघाट में अनुमानित 5,000 आदिवासी बच्चे कुपोषण से मर गये। शोध का उद्देश्य मेलघाट में बाल मृत्यु दर की स्थिति का पता लगाना और किसी भी कम रिपोर्टिंग की जांच करना, और गुणात्मक रूप से बाल स्वास्थ्य के निर्धारकों का पता लगाना। अध्ययन मेलघाट क्षेत्र के पांच पीएचसी क्षेत्रों अर्थात् सदरवाड़ी, बैरागढ़, दुलघाट रेलवे, टेम्बुरसोंडा और हटरू में आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण आँकड़ों पर डेटा अप्रैल-जुलाई 2008 और वर्ष 2007 की इसी अवधि के लिए एकत्र किया गया था। इस अवधि के दौरान होने वाली सभी बच्चों की मृत्यु की लाइन लिस्टिंग किसी भी कम रिपोर्टिंग का पता लगाने के लिए की गई थी। ऐसी मौतों के लिए जिम्मेदार अंतर्निहित कारकों का पता लगाने के लिए एक पीएचसी गांव में सामाजिक शव परीक्षा सहित मौतों की मौखिक और सामाजिक शव परीक्षा की गई थी। डेटा का विश्लेषण एटलस का उपयोग करके किया गया। सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक कारकों का मैट्रिक्स बनाने के लिए टीआई 5.5 और एंथ्रोपैक 4.98।

अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि अध्ययन क्षेत्र से 6 साल से कम उम्र के कुल 73 मौतें और 911 जीवित जन्मों की सूचना मिली। इस प्रकार इस अवधि के लिए क्षेत्र में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की

मृत्यु दर 80.1 है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 66.9 थी। इसलिए, महत्वपूर्ण आंकड़ों के अनुसार, मेलघाट में 6 साल से कम उम्र की मृत्यु दर देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक नहीं थी, अगर अंडर रिपोर्टिंग न हो। इसके अलावा, नवजात शिशुओं की मृत्यु 6 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर का केवल 39.7% थी। बच्चों के पालन-पोषण की अनुचित प्रथाएं, गर्भवती महिलाओं द्वारा खराब आहार का सेवन, कम उम्र में विवाह, बच्चों में कम अंतर, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता की कमी, पर्याप्त आय और क्रय शक्ति बाल स्वास्थ्य की अनिश्चित स्थिति के कारण हैं। निष्कर्ष: सरकार के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। नरेगा और जननी सुरक्षा योजना जैसी नीतियों के साथ-साथ सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को लोकप्रिय बनाने और गरीबी-अशिक्षा-सूचना की कमी के चक्र पर जोर देने से घाट क्षेत्र में विकास में तेजी आएगी।

**Talapalliwar, M. R., & Garg, B. S. (2014). The Indian Journal of Pediatrics. 81, 1151-1157.** 0-6 वर्ष के आदिवासी बच्चों में कुपोषण की भयावहता और महामारी संबंधी निर्धारकों का पता लगाने के उद्देश्य से यह अध्ययन किया गया। शोध में मध्य भारत के मेलघाट के गांवों में एक समुदाय आधारित क्रॉस सेक्शनल अध्ययन किया गया था। 0-6 वर्ष आयु वर्ग के 540 बच्चों की जानकारी एकत्र की गई। नए विकसित WHO विकास मानकों का उपयोग कुपोषण (कम वजन, बौनापन और बर्बादी) के पारंपरिक सूचकांकों और एंथ्रोपोमेट्रिक विफलता (CIAF) के समग्र सूचकांक की गणना के लिए किया गया था। कुपोषण के सहसंबंधों का पता लगाने के लिए यूनियवैरिएट और मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन विश्लेषण का उपयोग किया गया। शोध के परिणाम दर्शाते हैं कि इन आदिवासी बच्चों में कम वजन, बौनेपन और कमजोरी के मामले में कुपोषण की व्यापकता क्रमशः 60.9%, 66.4% और 18.8% थी। एंथ्रोपोमेट्रिक विफलता के समग्र सूचकांक (सीआईएएफ) के संदर्भ में कुपोषण 76.3% था। इस अध्ययन से सामने आने वाले कुपोषण के महत्वपूर्ण सहसंबंध थे बच्चे की उम्र, पहली गर्भावस्था के समय माँ की उम्र 20 वर्ष से कम, कोलोस्ट्रम न खिलाने की प्रथा, कैलोरी की कमी वाला आहार, एनीमिया और दस्त और तीव्र श्वसन संबंधी बीमारियाँ। निष्कर्षतः यह कहा गया कि आदिवासी बच्चों में कुपोषण की व्यापकता अधिक थी। बच्चों में एनीमिया और अन्य रुग्णताओं के शीघ्र निदान और त्वरित उपचार के लिए ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत किया जाना चाहिए। इस समुदाय में बच्चे पैदा करने की उम्र में देरी करने और स्तनपान प्रथाओं में सुधार करने के लिए रणनीतियों की आवश्यकता है।

**Birdi, T. J., Joshi, S., Kotian, S., & Shah, S. (2014).** भारत के महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित मेलघाट एक आदिवासी क्षेत्र है जहाँ कुपोषण के सबसे अधिक मामले हैं। यह पेपर मेलघाट के धरनी ब्लॉक में कुपोषण के संभावित कारणों पर केंद्रित है। मात्रात्मक सर्वेक्षण में समुदाय में

कुपोषण, किचन गार्डन (केजी) प्रथाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भोजन प्रावधान, आंगनवाड़ी सेवाओं और स्वच्छता/स्वच्छता के मौजूदा बोझ को दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त पोषण, सांस्कृतिक मान्यताओं, खर्च करने की आदतों और कुपोषण में योगदान देने वाले अन्य कारकों पर समुदाय के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए एक गुणात्मक अध्ययन किया गया। कुपोषण सभी आयु समूहों में अत्यधिक प्रचलित पाया गया, जिसमें 1-5 वर्ष की आयु के 54% बच्चे और 20 वर्ष की आयु के 43% वयस्क गंभीर से मध्यम कम वजन के थे। बच्चों में कुपोषण का एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण बाल देखभाल प्रथाएँ थीं। खाद्य प्रावधान के आंकड़ों से पता चला है कि जहां समुदाय की कैलोरी की जरूरतें अनाज और दालों की खपत से काफी हद तक पूरी हो जाती हैं, वहीं हरी पत्तेदार सब्जियों (जीएलवी) की न्यूनतम खपत से समुदाय में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। केजी, जो जीएलवी प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से मानसून (98%) में खेती की जाती थी जो गर्मियों में घटकर केवल 4% रह गई। कुपोषित बच्चों पर लक्षित होने के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ अक्सर पूरे परिवार को मिलता था और इस तरह यह कम हो जाता था। मुख्य निष्कर्ष यह था कि पोषण संबंधी हस्तक्षेपों को पूरे परिवार को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए और उचित पोषण शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसके बिना भोजन वितरित करने या आय बढ़ाने पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।

**Sanjay, S. (2014).** यह लेख भारत के मेलघाट, महाराष्ट्र में कोरकू जनजाति के बीच कुपोषण के लक्षणों, कारणों और दुष्प्रभावों के साथ-साथ संबंधित मृत्यु दर की समीक्षा करता है। कुपोषित बच्चों की माताओं की आर्थिक स्थिति, शादी की उम्र और अन्य बीमारियों तथा इन बच्चों के टीकाकरण और चिकित्सा उपचार की स्थिति की जांच की जाती है। इस आबादी में कुपोषण को दूर करने के लिए सिफारिशें दी गई हैं।

**Choudhary, H. R., & P, A. A. E. (2020).** यह लेख भारत के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में पाई जाने वाली सबसे वंचित आदिवासी आबादी में से एक, कोरकू जनजाति के परेशान करने वाले सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक मुद्दों का दस्तावेजीकरण करने का एक प्रयास है। यह लेख 1 वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र के 10 गांवों में किए गए व्यापक नृवंशविज्ञान क्षेत्र कार्य का एक उत्पाद है। समुदाय के जीवन, जीवनशैली और सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक सूचकांकों पर बारीकी से जांच की गई। फ़्रील्डवर्क के प्रतिबिंब हतोत्साहित करने वाले रुझानों को रेखांकित करते हैं और समुदाय के सर्वव्यापी सामाजिक और विकास संबंधी मुद्दों को दर्शाते हैं। बुनियादी सुविधाओं, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीतिक मामलों की स्थिति के साथ कोरकस के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रमुख बदलावों का विवरण दिया गया है। इसके अलावा, बच्चों और

महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जोर दिया जाता है। अध्ययन के साक्ष्य समुदाय के लिए विकासात्मक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

**Das, M. (2010).** कोरकू मध्य भारत के आदिवासी लोग हैं जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में केंद्रित हैं। पिछले कुछ दशकों के शोध अध्ययनों से पता चला है कि कोरकू गंभीर कुपोषण के दुःख से जूझ रहे हैं। 1992 से 1997 के बीच महाराष्ट्र के मेलाघाट में इस समुदाय के अनुमानित 5000 आदिवासी बच्चों की कुपोषण से मृत्यु हो गई। आज भी इन क्षेत्रों में स्थिति गंभीर है। यह अध्ययन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कोरकू जनजातियों के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति पर असर डालने वाली सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने का एक प्रयास है। परिणामों से पता चला कि नर और मादा कोरकू में पोषक तत्वों की भारी कमी है, जो मुख्य रूप से दालों, दूध और दूध उत्पादों, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, वसा और तेल, और चीनी और गुड़ के कम सेवन के कारण है। अध्ययन से पता चलता है कि इसकी आवश्यकता है पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए कोरकू जनजातियों की खान-पान की आदतों में बदलाव लाना।

**Mohod, P. R. (2013).** समाज के अधिशेष का आकलन बच्चे और महिला की स्थिति से किया जा सकता है। बालक को राष्ट्र का स्तंभ माना जाता है। मेलघाट क्षेत्र की जंगली पहाड़ियों में कुपोषण एक पर्यायवाची शब्द है, जहां ज्यादातर कोरकू आदिवासी रहते हैं। 2005 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चिखलधारा और धरनी तालुकों वाले क्षेत्र में हर साल 0 से 6 वर्ष की आयु के 400-500 बच्चे मर जाते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व मध्य भारत में अमरावती जिले में स्थित है। यह चिकलधारा से 25 किमी दूर दक्षिण सतपुड़ा रेंज में एक पहाड़ी रिसॉर्ट है जिसे गविलगढ़ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह मुंबई से 760 किमी उत्तर पूर्व और नागपुर से 225 किमी पश्चिम में है। इस अभयारण्य में 80 बाघ हैं जो 1,674 वर्ग किमी विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। वे अधिकतर रिजर्व के अंदरूनी हिस्सों में रहते हैं जहां तक पहुंचना मुश्किल है। मेलघाट टाइगर रिजर्व की स्थापना 1967 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में की गई थी और 1974 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके ऊबड़-खाबड़ इलाके और चट्टानी घाटियाँ शिकारियों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। तापी नदी रिजर्व की उत्तरी सीमा है। यहां बंदरों और अन्य जीवों के अलावा बाघ, स्लॉथ भालू और उड़ने वाली गिलहरियां भी देखी जा सकती हैं। यह रिजर्व 2,000 गौर का घर है जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा है। मेलघाट प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। मेलघाट के रूप में महाराष्ट्र क्षेत्र सबसे समृद्ध और प्रकृति के उपहारों में से एक है। सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति की सुंदरता निस्संदेह आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन साथ ही दुनिया के मानचित्र पर प्रसिद्ध राष्ट्र की स्थिति को देखकर दुख भी महसूस होता है, जहां कुपोषण जैसी सामाजिक बुराइयों पर जीवन और सम्मान का अधिकार मुश्किल से ही हावी है। यह भयानक था जब सितंबर 2011

में, एक जनहित याचिका के जवाब में, राज्य ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि मेलघाट में 14,500 बच्चे कुपोषित हैं और पिछले 4 महीनों में 266 बच्चों की मौत हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि मेलघाट में 320 गांव हैं, लेकिन चौकाने वाली बात यह है कि एक आरटीआई से पता चला है कि इस क्षेत्र में 370 एनजीओ पंजीकृत हैं। कुपोषण से लड़ने के घोषित उद्देश्य के साथ भारी धनराशि, बड़े दानदाता आते हैं। बुनियादी मानव अधिकार का उल्लंघन आसानी से किसी की आंखों से देखा जा सकता है और इसलिए समाज का ध्यान आकर्षित होता है। प्रस्तुत शोध पत्र उन बाघों के भोजन के अधिकार के पहलू पर विचार करने के लिए तैयार किया गया है जो वास्तविक बाघ के साथ रहते हैं लेकिन भुखमरी से पीड़ित हैं।

**Chandrakar, M., & Pachlore, G. (2023).** सिकल सेल रोग पूरे विश्व में व्यापक रूप से पाया जाता है। सिकल सेल रोग लगभग 12 भारतीय राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया है और इसकी व्यापकता दर मध्य भारत में सबसे अधिक पाई गई है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों सहित कई राज्यों में सिकल सेल रोग के लिए आबादी की स्क्रीनिंग कई शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। मेलघाट क्षेत्र महाराष्ट्र में है जहां बहुसंख्यक आबादी आदिवासियों की है। चूंकि इस क्षेत्र के गाँव बहुत अंदरूनी हैं और सड़कों से सीधे जुड़े नहीं हैं, इस क्षेत्र से वस्तुतः कोई अध्ययन नोट नहीं किया गया है। वर्तमान अध्ययन में, लगभग 392 व्यक्ति जो स्क्रीनिंग के इच्छुक थे, उन्हें सिकल सेल परीक्षण के लिए चुना गया था। 392 व्यक्तियों में से लगभग 271 मरीजों के रक्त की जांच में सिकलिंग टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इन व्यक्तियों के रक्त को सिकल सेल रोग के लिए आगे की पुष्टिकरण परीक्षणों के अधीन किया गया था। हीमोग्लोबिन वैद्युतकणसंचलन के अधीन 271 रक्त नमूनों में से कुल 135 व्यक्तियों को सकारात्मक बताया गया। 77 व्यक्तियों ने 'एस' प्रकार का हीमोग्लोबिन बैंड पैटर्न दिखाया। ये व्यक्ति सिकल सेल जीन के प्रबल वाहक हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद 58 रक्त नमूनों में एसएस बैंड पैटर्न प्रदर्शित पाया गया। बताया गया कि ये लोग सिकल सेल रोग से पीड़ित थे। इस क्षेत्र में अध्ययन की गई जनसंख्या में सिकल सेल रोग की व्यापकता 34.43% (135/392) पाई गई। जिनमें से 42.96% (58/135) एचबीएसएस (सिकल सेल एनीमिया) थे और 57.04% (77/135) एचबीएस (सिकल सेल वाहक) पाए गए। इस मेलघाट क्षेत्र में, केवल दो नैदानिक विशेषताएँ हावी पाई गईं। लगातार स्प्लेनोमेगाली की व्यापकता 85% और पीलिया की व्यापकता 48% देखी गई है। उपरोक्त निष्कर्ष की पुष्टि वर्तमान अध्ययन में भी की गई जिसमें पुरुष: महिला अनुपात (75.86%): (24.13%) पाया गया। प्रस्तुत अध्ययन में इस क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले जनजातीय समुदायों का अध्ययन किया गया। सिकल सेल रोग की व्यापकता इस प्रकार देखी गई: कोरकू में 8.62%, गोंड में 3.44%, बलाई में 39.65%, गवलन में 20.68%, निहाल में 3.79%, रूठवा में 5.17%, पारधी में 1.72% और गवली में 6.8%।

**Mahure, P., Gurjar, Y., & Sawkar, J. (2017).** अंतर्गर्भाशयी और प्रसवोत्तर देखभाल की कमी के कारण, आहार संबंधी प्रथाओं से शैशव काल में कई रुग्णताएं हो सकती हैं। समुदाय में शिशु देखभाल चिकित्सा और आर्थिक कारणों के अलावा विशिष्ट क्षेत्र में प्रचलित सांस्कृतिक प्रथाओं से प्रभावित होती है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के संदर्भ में प्रस्तुत शोध किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली आदिवासी माताओं के बीच प्रचलित भोजन प्रथाओं को समझना और इन प्रथाओं के पीछे के कारणों का पता लगाना था। यह समुदाय-आधारित क्रॉस-अनुभागीय वर्णनात्मक अध्ययन अमरावती जिले के उत्तरी आदिवासी क्षेत्र में किया गया था। अध्ययन के लिए कुल 312 माताओं को यादृच्छिक रूप से चुना गया। संरचित साक्षात्कार का उपयोग करके उन माताओं के आमने-सामने साक्षात्कार के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया जिनके पास 3 वर्ष से कम उम्र का बच्चा था। अध्ययन के परिणाम में यह पाया गया कि लगभग 35% माताओं ने जन्म के 1 घंटे के बाद बच्चे को कोलोस्ट्रम दिया। जबकि 39% माताएं पारिवारिक परंपरा या बड़ों की सलाह के कारण बच्चे को कोलोस्ट्रम नहीं खिलाती पाई गईं और 68% ने कोलोस्ट्रम खिलाने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह साफ नहीं है। 90% माताओं ने 6 से 8 महीने की उम्र के बीच बच्चे को पूरक आहार देना शुरू कर दिया, जबकि 59% बच्चे अध्ययन से ठीक पहले 6 महीने के दौरान बीमारी से पीड़ित थे। निष्कर्ष: भारत के जनजातीय क्षेत्र में शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए अनुचित आहार प्रथाओं को ठीक करने की आवश्यकता है।

**Deore, A. U., & Zade, S. B. (2014).** प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य न केवल सिकल सेल रोग (एससीडी) की वर्तमान प्रसार दर को प्रकट करना था, बल्कि मध्य भारत की कोरकू आबादी में इसके उच्च प्रसार और उनके स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का सबसे संभावित कारण भी बताना था। अध्ययन के दौरान, विभिन्न आयु समूहों (0-60 वर्ष) से संबंधित कुल 865 विषयों को उनमें सिकल सेल जीनोटाइप की घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए यादृच्छिक रूप से नमूना लिया गया था। सभी (n=865) व्यक्तियों से रक्त के नमूने एकत्र किए गए और सकारात्मक नमूनों को उनके पैटर्न की पुष्टि के लिए पीएच 8.6 पर सेलूलोज एसीटेट एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अधीन किया गया। तैयार प्रश्नावली और पिछली चिकित्सा रिपोर्टों का उपयोग सिकल सेल रोग की नैदानिक प्रस्तुतियों के निदान के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया था। अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि कोरकू लोगों में सिकल सेल विशेषता की व्यापकता 5.3% (46/865) पाई गई, जिनमें से 4.4% विषमयुग्मजी जीन एएस (वाहक) के साथ जबकि 0.9% समयुग्मजी अप्रभावी जीन एसएस (रोग) के साथ पाए गए। सिकल सेल रोग जीन की आवृत्ति पुरुषों और कम आयु वर्ग में अधिक बताई गई है, विशेषकर 0-25 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में। समयुग्मजी व्यक्तियों में से 87.8% को दर्द संकट या रक्त आधान का कोई इतिहास नहीं था। विषमयुग्मजी

रोगियों में सबसे अधिक देखी जाने वाली नैदानिक विशेषताएं शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बुखार, पेट में दर्द, पीलापन और सीने में दर्द और रुक-रुक कर होने वाले पीलिया की सीमित शिकायतें थीं। पित्त पथरी की कोई शिकायत सामने नहीं आई। डेटा विशेषकर बच्चों में मृत्यु दर की उच्च दर को भी दर्शाता है। अतः शोध इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उच्च स्तर की रक्तसंबंधी भावना और सिकल सेल विकार के बारे में ज्ञान की कमी कोरकू आदिवासियों के बीच उच्च सिकल सेल रोग जीन आवृत्ति का प्रमुख कारण है। इसकी व्यापकता की दर को कम करने के लिए विवाह पूर्व जांच और आनुवंशिक परामर्श को उपकरण के रूप में माना जाना चाहिए।

### निष्कर्ष

साहित्य समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि मेलघाट क्षेत्र के कोरकू लोग स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल से वंचित होने के मामले में एक विशिष्ट उदाहरण हैं। क्षेत्र में पिछड़ेपन और गरीबी की लगातार समस्या स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रतिबिंबित होती है। यह क्षेत्र स्वास्थ्य समस्याओं और विभिन्न बीमारियों के प्रसार के लिए कुख्यात है। इस क्षेत्र के आदिवासियों, विशेषकर कोरकू के बीच पाई जाने वाली महत्वपूर्ण समस्या कुपोषण की है। चयनित अधिकतर अध्ययन महिला एवं बालकों के कुपोषण पर केन्द्रित है। लगभग सभी अध्ययन कोरकू जनजाति की कुपोषण के साथ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को दर्शाती है। यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि कोई भी अध्ययन कोरकू जनजाति के बेहतर स्वास्थ्य अभ्यास पर बात नहीं करता है तथा न ही उनके लिए किए जा रहे प्रयासों की आलोचनाओं के अलावा सफलता को बहुत कम कर के आँका गया है, ऐसा प्रतीत होता है। कुपोषण की समस्या का समाधान को लेकर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है तथा समाज कार्य हस्तक्षेप संबंधी सूचनाओं का भी अभाव देखा गया है।

### संदर्भ

1. Datta, S. S., & Mail, I. D. (2013). A study to explore the determinants of child health in Melghat, Maharashtra. *Health*, 1(2), 36-41.
2. Talapalliwar, M. R., & Garg, B. S. (2014). Nutritional status and its correlates among tribal children of Melghat, Central India. *The Indian Journal of Pediatrics*, 81, 1151-1157.
3. Birdi, T. J., Joshi, S., Kotian, S., & Shah, S. (2014). Possible causes of malnutrition in Melghat, a tribal region of Maharashtra, India. *Global journal of health science*, 6(5), 164.
4. Sanjay, S. (2014). Malnutrition is problem of Korku tribe with reference to Melghat in Maharashtra. *Golden Research Thoughts*, 3(9).

5. Choudhary, H. R., & P, A. A. E. (2020). *The Korku tribe of Melghat region in India and their current state: an ethnographic study. The Oriental Anthropologist, 20(1), 97-112.*
6. Das, M. (2010). *Study of nutritional status of Korku tribes in Betul district of Madhya Pradesh. Studies of Tribes and Tribals, 8(1), 31-36.*
7. Mohod, P. R. (2013). *Bliss of Right to Food or Grief of Malnutrition—A Study of Melghat Region in Maharashtra. Available at SSRN 2317835.*
8. Chandrakar, M., & Pachlore, G. (2023). *Status Of Sickle Cell Anemia Among Tribal Population Of Melghat Region, Maharashtra, India. Journal of Experimental Zoology India, 26(1).*
9. Mahure, P., Gurjar, Y., & Sawkar, J. (2017). *Feeding practices among tribal mothers of malnutrition prevalent region of Amravati District in India. Indian Journal of Child Health, 523-526.*
10. Deore, A. U., & Zade, S. B. (2014). *Distribution of sickle cell gene in Korku tribe of central India. National Journal of Community Medicine, 5(03), 270-272.*

## महिला सशक्तिकरण के माध्यम से सतत ग्रामीण विकास: चुनौतियाँ, अवसर एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य

डॉ. छोटे लाल

### सारांश

महिलाएँ सतत ग्रामीण विकास की प्रक्रिया का अभिन्न एवं अनिवार्य अंग हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को भारतीय समाज में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। ग्रामीण विकास की परिकल्पना तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती, जब तक महिलाओं को शिक्षा, सांसाधनों, नवीनतम तकनीक तथा मूलभूत सुविधाओं तक समान और सुलभ पहुँच प्रदान न की जाए। महिला सशक्तिकरण के बिना सतत ग्रामीण विकास की कल्पना करना मात्र एक आदर्शवादी विचार ही प्रतीत होता है। ग्रामीण भारत की महिलाओं के समक्ष अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें समझने और दूर करने के लिए एक बहुआयामी एवं लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जल, ईंधन एवं स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी ग्रामीण महिलाओं की प्रमुख और गंभीर समस्याओं में से एक है। उपलब्ध आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल लगभग 36 प्रतिशत आबादी को ही सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसका प्रत्यक्ष और असमान प्रभाव उन 86 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों पर पड़ता है, जहाँ जल संग्रहण की जिम्मेदारी मुख्यतः महिलाओं और किशोरियों पर होती है। पानी और स्वच्छता से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूर-दराज और असुरक्षित मार्गों से होकर आवागमन करने के दौरान महिलाओं और लड़कियों को शारीरिक श्रम, समय की हानि के साथ-साथ यौन उत्पीड़न एवं हिंसा जैसे गंभीर सामाजिक जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। यह स्थिति न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा को प्रभावित करती है, बल्कि उनके शिक्षा, आजीविका और सामाजिक सहभागिता के अवसरों को भी सीमित करती है। अतः स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर जल, स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाओं से संबंधित नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन ही सतत ग्रामीण विकास को वास्तविक रूप प्रदान कर सकता है।

**मुख्य शब्द :** महिला सशक्तिकरण, सतत ग्रामीण विकास, चुनौतियाँ, अवसर, नीतिगत परिप्रेक्ष्य, ग्रामीण भारत

### परिचय:

भारत में सतत ग्रामीण विकास की प्रक्रिया सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों के जटिल अंतर्संबंधों से प्रभावित होती है, जिनमें महिला सशक्तिकरण एक केंद्रीय तत्व के रूप में उभरकर सामने आता है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर पुरुषों का प्रवासन रोजगार एवं

आजीविका के अवसरों की खोज में निरंतर बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण परिवारों की सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। इस प्रवासन के कारण ग्रामीण समुदायों में महिलाओं पर पारंपरिक घरेलू दायित्वों के साथ-साथ कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। तथापि, गहराई से व्याप्त पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों के कारण महिलाएँ अब भी निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में सीमित भागीदारी रखती हैं।

ग्रामीण भारत में महिलाएँ भोजन, जल और ईंधन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाएँ जैसे सूखा, बाढ़ एवं अनियमित वर्षा इन जिम्मेदारियों को और अधिक जटिल बना देती हैं। उपलब्ध शोध साहित्य यह संकेत देता है कि ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं और किशोरियों का कार्यभार असमान रूप से बढ़ जाता है, जिससे वे शिक्षा, कौशल विकास एवं सामाजिक सहभागिता जैसे विकासात्मक अवसरों से वंचित हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के कारण ईंधन संग्रहण हेतु महिलाओं को अधिक समय और श्रम व्यय करना पड़ता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता पर पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, अनुसंधान यह भी दर्शाता है कि ग्रामीण महिलाओं के पास चरम मौसमी घटनाओं के प्रति अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण और पूर्व-तैयारी के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। निर्धन ग्रामीण महिलाएँ धान की खेती, मछली पकड़ने तथा अन्य कृषि-आधारित आजीविकाओं में सक्रिय रूप से संलग्न हैं, जो बदलते जलवायु पैटर्न के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। परिणाम स्वरूप, आजीविका के नुकसान की संभावना बढ़ जाती है और उनकी सामाजिक-आर्थिक भेद्यता और अधिक गहरी हो जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में यह अध्ययन यह प्रतिपादित करता है कि महिला सशक्तिकरण को जलवायु-संवेदनशील एवं लिंग-संवेदनशील नीतिगत ढाँचे के साथ एकीकृत किए बिना सतत ग्रामीण विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है।

### अध्ययन का औचित्य:

भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ सामाजिक-आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर लगभग 58.8 प्रतिशत है, जो ग्रामीण पुरुषों (78.6 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम है। यह शैक्षिक असमानता महिला सशक्तिकरण और सतत ग्रामीण विकास दोनों के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। आर्थिक स्तर पर NSS के आँकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी सीमित है और अधिकांश महिलाएँ कृषि एवं असंगठित क्षेत्र में कम आय एवं सामाजिक सुरक्षा के अभाव में कार्यरत हैं। वहीं NFHS के अनुसार ग्रामीण परिवारों में लगभग 80-85 प्रतिशत मामलों में पानी संग्रहण की जिम्मेदारी महिलाओं और किशोरियों पर होती है, जिससे उनके शिक्षा, कौशल विकास एवं आजीविका के अवसर प्रभावित होते हैं।

जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं—जैसे सूखा, बाढ़ और अनियमित वर्षा का असमान प्रभाव ग्रामीण महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि उनके पास अनुकूलन एवं जोखिम प्रबंधन के सीमित संसाधन होते हैं। इन परिस्थितियों में महिला सशक्तिकरण की उपेक्षा सतत ग्रामीण विकास की

प्रक्रिया को बाधित करती है। अतः यह अध्ययन महिला सशक्तिकरण और सतत ग्रामीण विकास के अंतर्संबंधों का आँकड़ा-आधारित एवं नीतिगत विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक और प्रासंगिक है।

**उद्देश्य :**

**प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:**

- 1 ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
- 2 सतत ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका और योगदान को स्पष्ट करना।
- 3 महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों की पहचान करना।
- 4 उपलब्ध अवसरों और सरकारी नीतियों का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
- 5 महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने हेतु नीतिगत एवं व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

**महिला सशक्तिकरण की अवधारणा (Concept of Women Empowerment):**

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी गतिशील और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा संस्थागत स्तर पर समान अधिकार, अवसर और संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण प्राप्त होता है। इस अवधारणा का केंद्र महिलाओं की स्वतंत्र निर्णय-क्षमता, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सहभागिता को सुदृढ़ करना है, ताकि वे अपने जीवन और समुदाय से जुड़े विकासात्मक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा सकें। वैश्विक विकास विमर्श में महिला सशक्तिकरण को सतत विकास का प्रमुख आधार माना गया है। संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार विश्व की लगभग 43 प्रतिशत कृषि श्रम शक्ति महिलाएँ हैं, किंतु भूमि और उत्पादक संसाधनों पर उनका स्वामित्व अत्यंत सीमित है। इसी प्रकार, विश्व बैंक के आकलन के अनुसार यदि महिलाओं को पुरुषों के समान आर्थिक अवसर प्रदान किए जाएँ, तो किसी भी देश की उत्पादक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। ये तथ्य इस बात को रेखांकित करते हैं कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक समानता का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक और विकासात्मक अनिवार्यता भी है।

राजनीतिक सशक्तिकरण के संदर्भ में भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 से 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था ने यह सिद्ध किया है कि जब महिलाओं को निर्णय-निर्माण में भागीदारी मिलती है, तो स्थानीय शासन अधिक उत्तरदायी और समावेशी बनता है। यह अनुभव महिला सशक्तिकरण की उस अवधारणा को बल देता है, जिसमें महिलाओं को विकास की निष्क्रिय लाभार्थी के बजाय विकास की सहभागी और नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार, महिला सशक्तिकरण की अवधारणा यह स्थापित करती है कि महिलाओं की समान भागीदारी के बिना न तो सामाजिक न्याय संभव है और न ही सतत एवं समावेशी विकास। अतः महिला सशक्तिकरण को विकास नीतियों और कार्यक्रमों के केंद्र में रखना आधुनिक विकास चिंतन की एक अनिवार्य आवश्यकता है।

### सतत ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका:

सतत ग्रामीण विकास आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय संरक्षण और संस्थागत सुदृढ़ता पर आधारित है। इस प्रक्रिया में महिलाएँ ग्रामीण समाज की केंद्रीय संवाहक हैं। कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य-पोषण, शिक्षा और सामुदायिक नेतृत्व में उनकी सक्रिय भागीदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिरता और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करती है। ग्रामीण भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 40-45 प्रतिशत है, जो सतत आजीविका के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने महिलाओं को वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म उद्यमिता और सामूहिक निर्णय-निर्माण के अवसर प्रदान किए हैं। करोड़ों ग्रामीण महिलाओं की SHG नेटवर्क से सहभागिता ने आय-वृद्धि, बचत-ऋण तक पहुँच और सामाजिक नेतृत्व को मजबूत किया है, जिससे ग्रामीण विकास अधिक समावेशी और टिकाऊ बना है।

पर्यावरणीय आयाम में जल, वन और भूमि संसाधनों के संरक्षण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। जल संग्रहण, ईंधन प्रबंधन और स्थानीय अनुकूलन उपायों में उनकी भागीदारी जलवायु-लचीले ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है। स्वास्थ्य-पोषण के क्षेत्र में भी महिलाएँ परिवार और समुदाय के निर्णयों की प्रमुख निर्धारक हैं, जिससे मानव विकास संकेतकों में सुधार होता है। साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं में 33-50 प्रतिशत आरक्षण ने स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ किया है।

SDGs के संदर्भ में, महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से SDG-1 (गरीबी उन्मूलन), SDG-2 (भूखमुक्ति), SDG-3 (स्वास्थ्य), SDG-5 (लैंगिक समानता), SDG-6 (स्वच्छ, जल), SDG-8 (सम्मानजनक आजीविका), SDG-13 (जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही) और SDG-16 (समावेशी संस्थान) की प्राप्ति से सीधे जुड़ी हुई है।

### महिला सशक्तिकरण से जुड़ी चुनौतियाँ

#### 1. सामाजिक असमानता:

ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सामाजिक असमानता एक गंभीर बाधा है। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के कारण महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। आज भी बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएँ निरक्षर हैं, लिंग-आधारित भेदभाव व्यापक है तथा कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ अनेक क्षेत्रों में विद्यमान हैं। आज भी पुत्रों को आर्थिक सहारा और वंश-विस्तार का माध्यम माना जाता है, जबकि पुत्रियों को प्रायः आर्थिक बोझ समझा जाता है। यह मानसिकता महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णय-निर्माण में भागीदारी को सीमित करती है।

#### 2. हाशिए पर रहने वाली महिलाएँ और सामाजिक भेदभाव:

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, शहरी गरीब, अकेली एवं विस्थापित महिलाएँ बहुस्तरीय भेदभाव का सामना करती हैं। दलित महिलाएँ जाति, वर्ग और लिंग के त्रि-आयामी उत्पीड़न से पीड़ित हैं, जबकि अल्पसंख्यक महिलाओं को पारिवारिक और सामाजिक

असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है। आदिवासी महिलाओं की सामाजिक स्थिति कुछ मामलों में बेहतर होने के बावजूद विस्थापन, विकास परियोजनाओं और आजीविका के नुकसान का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन वर्गों की महिलाओं को पोषण, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सेवाएँ और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की विशेष आवश्यकता है।

### 3. शिक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ:

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला निरक्षरता सशक्तिकरण की एक प्रमुख बाधा है। विद्यालयों में नामांकन बढ़ने के बावजूद लड़कियों का विद्यालय में टिके रहना एक चुनौती बना हुआ है। घरेलू जिम्मेदारियों, छोटे भाई-बहनों की देखभाल, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव और महिला शिक्षकों की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। क्रेच सुविधा, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पुस्तकें-वर्दी, पृथक शौचालय और बालिका-अनुकूल विद्यालय वातावरण लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं।

### 4. महिलाएँ और स्वास्थ्य सेवा:

ग्रामीण महिलाओं को गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान पर्याप्त पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पाती। कुपोषण और एनीमिया व्यापक समस्याएँ हैं, जिनका प्रतिकूल प्रभाव मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्तनपान, प्रसव-पूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल की कमी से महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति कमजोर बनी रहती है। स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन सेवाओं तक समान पहुँच महिला सशक्तिकरण की अनिवार्य शर्त है।

### 5. अवसर और संभावनाएँ:

इन चुनौतियों के बावजूद महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। जल, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर न केवल उनकी स्थिति सुधारी जा सकती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन में भी सकारात्मक योगदान संभव है। शोध संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से महिला-केंद्रित विकास मॉडल प्रभावी हो सकते हैं।

### 6. लिंग-संवेदनशील योजना एवं बजट:

लिंग-संवेदनशील योजना और बजट यह सुनिश्चित करता है कि विकास संसाधनों का वितरण पुरुषों और महिलाओं दोनों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। जब महिलाएँ ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर योजना एवं बजट प्रक्रिया में भाग लेती हैं, तो जल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में अधिक न्यायसंगत निर्णय संभव होते हैं। सामुदायिक सहभागिता और पारदर्शिता इस प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है।

### 7. स्वयं सहायता समूह (SHGs):

स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम हैं। इनके माध्यम से महिलाओं को वित्तीय साक्षरता, सूक्ष्म उद्यमिता, बाजार तक पहुँच और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त होती है। बढ़ी हुई आय से महिलाओं को परिवार और समुदाय में सम्मान मिलता है, जिससे सशक्तिकरण का चक्र और मजबूत होता है।

## 8. महिला संगठन और राजनीतिक भागीदारी:

महिला संघों और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से स्थानीय शासन अधिक समावेशी बनता है। कार्यस्थल पर महिला-अनुकूल परिस्थितियाँ, स्वास्थ्य-पोषण में सुधार और शिक्षा का विस्तार महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका को सुदृढ़ करता है। महिलाएँ घरेलू श्रम की वास्तविक कठिनाइयों को बेहतर समझती हैं, इसलिए नीति निर्माण और समाधान प्रक्रिया में उनकी भागीदारी अनिवार्य है।

## 9. सतत ग्रामीण ऊर्जा और महिलाओं की भूमिका:

ग्रामीण भारत में ऊर्जा की कमी महिलाओं के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जाकृतैसे सौर ऊर्जा और जैव-ईंधन महिलाओं के लिए आजीविका और नेतृत्व के नए अवसर उत्पन्न कर सकती है। ग्राम ऊर्जा समितियों में महिलाओं की भागीदारी, सौर पैनल स्थापना एवं रखरखाव का प्रशिक्षण और जैव-ईंधन आधारित गतिविधियाँ महिला सशक्तिकरण तथा पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को बढ़ावा देती हैं।

## अवसर एवं संभावनाएँ:

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उपलब्ध अवसर और संभावनाएँ सतत ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने की महत्वपूर्ण क्षमता रखते हैं। शिक्षा और कौशल विकास के विस्तार से महिलाओं की कार्यक्षमता, रोजगार योग्यता और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि संभव है। डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता प्रशिक्षण और तकनीकी नवाचार महिलाओं को पारंपरिक आजीविकाओं से आगे बढ़कर आय-विविधीकरण के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं।

आर्थिक क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएँ और महिला-केंद्रित आजीविका कार्यक्रम महिलाओं को वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म उद्यमिता और बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराते हैं। इससे न केवल महिलाओं की आय में वृद्धि होती है, बल्कि उनकी निर्णय-निर्माण क्षमता और सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है।

पर्यावरणीय दृष्टि से जल, वन और ऊर्जा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी जलवायु-लचीले ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करती है। नवीकरणीय ऊर्जा, जैव-ईंधन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण से जुड़ी पहलों में महिलाओं की भूमिका पर्यावरणीय स्थिरता और आजीविका सृजन दोनों को सशक्त बनाती है।

संस्थागत एवं राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं, महिला संगठनों और सामुदायिक मंचों में महिलाओं की सहभागिता से स्थानीय शासन अधिक समावेशी और उत्तरदायी बनता है। लिंग-संवेदनशील योजना और बजट, बहु-क्षेत्रीय सहयोग तथा सरकारी गैर-सरकारी भागीदारी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को दीर्घकालिक और टिकाऊ रूप दिया जा सकता है।

## नीतिगत परिप्रेक्ष्य

भारत में महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने हेतु नीतिगत हस्तक्षेपों का दायरा हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप से विस्तृत हुआ है, विशेषकर वित्तीय समावेशन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छता और लैंगिक उत्तरदायी बजटिंग के क्षेत्रों में। इन नीतियों का उद्देश्य महिलाओं की दैनिक जीवन स्थितियों में सुधार के साथ-साथ उन्हें विकास प्रक्रिया की सक्रिय सहभागी बनाना है।

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए कुल बैंक खातों में से लगभग 56-57 प्रतिशत खाते महिलाओं के नाम पर हैं। इससे महिलाओं की औपचारिक बैंकिंग सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और बचत की आदतों में वृद्धि हुई है। यह नीति महिलाओं की आर्थिक पहचान और निर्णय-क्षमता को संस्थागत आधार प्रदान करती है।

स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में प्रधानमंत्री उज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन महिलाओं के नाम पर प्रदान किए गए हैं। इस हस्तक्षेप से ग्रामीण महिलाओं का समय और श्रम बचा है, घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है तथा स्वास्थ्य जोखिम घटे हैं जो महिला सशक्तिकरण के सामाजिक और स्वास्थ्य आयाम को मजबूत करता है।

स्वच्छता और गरिमा से जुड़ी नीतियों में स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ है। इससे महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान में सुधार हुआ है तथा खुले में शौच से जुड़ी असमानताओं में कमी आई है। यह नीति महिलाओं के जीवन-स्तर में प्रत्यक्ष सुधार का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

लैंगिक उत्तरदायी बजटिंग के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। केंद्रीय बजट में Gender Budget Statement के अंतर्गत कुल बजटीय व्यय का लगभग 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सा महिलाओं और बालिकाओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया जाता है। यह नीतिगत प्रवृत्ति विकास संसाधनों के वितरण में लैंगिक दृष्टिकोण को संस्थागत रूप प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों जैसे सौर ऊर्जा आधारित घरेलू प्रणालियाँ ने महिलाओं की उत्पादक गतिविधियों, घरेलू सुरक्षा और सूचना तक पहुँच को बढ़ाया है। ऊर्जा-सुलभता ने महिलाओं के लिए शिक्षा, घरेलू उद्यम और सामुदायिक सहभागिता के नए अवसर खोले हैं।

समेकित रूप से, ये नवीन नीतिगत आँकड़े यह दर्शाते हैं कि महिला सशक्तिकरण अब केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं रह गया है, बल्कि वित्तीय, ऊर्जा, स्वच्छता और बजटीय निर्णयों का अभिन्न अंग बन चुका है। अतः सतत ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है कि भविष्य की नीतियाँ लैंगिक उत्तरदायी, डेटा-आधारित और महिलाओं की वास्तविक आवश्यकताओं पर केंद्रित हों, जिससे महिलाएँ विकास की लाभार्थी ही नहीं, बल्कि उसकी सक्रिय सहभागी और निर्णयकर्ता बन सकें।

## निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करता है कि महिला सशक्तिकरण और सतत ग्रामीण विकास के बीच गहरा, पारस्परिक एवं पूरक संबंध विद्यमान है। ग्रामीण भारत में महिलाएँ कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, आजीविका संवर्धन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य—पोषण, शिक्षा तथा स्थानीय शासन की आधारशिला हैं। इसके बावजूद सामाजिक असमानता, पितृसत्तात्मक संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, आर्थिक निर्भरता तथा संसाधनों और निर्णय—निर्माण तक सीमित पहुँच जैसी बाधाएँ उनके पूर्ण सशक्तिकरण को अवरुद्ध करती रही हैं।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि जहाँ महिलाओं को शिक्षा, वित्तीय समावेशन, तकनीकी संसाधनों, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छता तथा संस्थागत भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, वहाँ ग्रामीण विकास अधिक समावेशी, लचीला और दीर्घकालिक सिद्ध हुआ है। महिला—केंद्रित आजीविका पहलें, सामुदायिक संगठन, स्थानीय शासन में भागीदारी और लिंग—संवेदनशील नीतियाँ न केवल महिलाओं की सामाजिक—आर्थिक स्थिति में सुधार लाती हैं, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज की विकास क्षमता को भी सुदृढ़ करती हैं।

नीतिगत विश्लेषण यह संकेत देता है कि महिला सशक्तिकरण को केवल कल्याणकारी हस्तक्षेप के रूप में देखने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसे विकास की रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। सतत ग्रामीण विकास के लक्ष्य तभी साकार हो सकते हैं जब नीतियाँ स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित हों, बहु-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा दें और महिलाओं को विकास की निष्क्रिय लाभार्थी के बजाय सक्रिय सहभागी, नेतृत्वकर्ता एवं निर्णयकर्ता के रूप में स्थापित होगा।

## सन्दर्भ सूची

1. *Government of India. (2011). Census of India 2011: Primary census abstract. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.*
2. *Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Human Resource Development.*
3. *Government of India. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5) 2019–21. Ministry of Health and Family Welfare.*
4. *Government of India. (2022). Gender budget statement. Ministry of Finance.*
5. *Government of India. (2023). Rural development statistics. Ministry of Rural Development.*
6. *Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Development and Change, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>*
7. *Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.*
8. *Sharma, S., & Gupta, S. (2018). Women empowerment and sustainable rural development in India. Indian Journal of Social Development, 18(2), 245–258.*

9. Singh, R., & Srivastava, R. (2020). *Role of self-help groups in women empowerment: A study of rural India*. *Journal of Rural Development*, 39(3), 456–472.
10. *United Nations*. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. *United Nations*.
11. *United Nations Development Programme*. (2020). *Gender equality and women’s empowerment*. *UNDP*.
12. *World Bank*. (2012). *World development report 2012: Gender equality and development*. *World Bank*.
13. *World Bank*. (2020). *Women, business and the law 2020*. *World Bank Publications*.
14. Agarwal, B. (2010). *Gender and green governance: The political economy of women’s presence within and beyond community forestry*. *Oxford University Press*.
15. Desai, S., & Andrist, L. (2010). *Gender scripts and age at marriage in India*. *Demography*, 47(3), 667–687. <https://doi.org/10.1353/dem.0.0118>
16. Kumar, A., & Singh, P. (2019). *Climate change and women in rural India*. *International Journal of Rural Studies*, 26(1), 1–10.

## स्त्री देह यौनिकता और सामाजिक नैतिकता : एक समाज शास्त्रीय अध्ययन

गोपीका पी.

शोधार्थी, हिंदी विभाग

श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालडी, केरल

### सारांश

इस शोध-पत्र में स्त्री देह और उसकी यौनिकता पर समाज द्वारा स्थापित नियंत्रण, मान्यताओं और नैतिक मूल्यों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री देह को किस प्रकार नैतिकता, मर्यादा और सम्मान के साथ जोड़कर नियंत्रित किया गया है तथा उसकी यौनिकता को सीमित और विनियमित किया गया है। स्त्री की देह को केवल जैविक इकाई न मानकर सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के रूप में देखा जाता है, जिस पर पुरुष-प्रधान व्यवस्था का वर्चस्व बना रहता है। स्त्री की ‘पवित्रता’ को उसके शरीर से जोड़कर उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया लंबे समय से चलती आ रही है। इस संदर्भ में स्त्री को अपनी यौनिकता के कारण कई विरोधाभासों का सामना करना पड़ता है, जहाँ उसे एक ओर आकर्षक और ‘आदर्श’ दिखने का दबाव होता है, वहीं दूसरी ओर उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है। समाज में स्त्री की यौनिक स्वतंत्रता को अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, जबकि पुरुषों के लिए अलग मानदंड बनाए जाते हैं। धर्म, परंपरा और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर स्त्री को द्वितीयक स्थिति में स्थापित किया है, जिससे उसकी अस्मिता और स्वायत्तता प्रभावित होती है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक समाज तक स्त्री के शरीर का वस्तुकरण और नियंत्रण विभिन्न रूपों में विद्यमान है। नारीवादी दृष्टिकोण के माध्यम से इस शोध में स्त्री देह की स्वायत्तता, अधिकार और स्वतंत्रता के प्रश्नों को भी उठाया गया है। गर्भपात, गर्भनिरोध और यौनिक अधिकारों जैसे मुद्दों को स्त्री की स्वतंत्र पहचान से जोड़कर देखा गया है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य, धर्म और समाज के बीच स्त्री शरीर एक संघर्ष का केंद्र बना हुआ है।

**मुख्य शब्द:** यौनिकता, सामाजिक नैतिकता, पितृसत्ता, देह का वस्तुकरण, सामाजिक नियंत्रण, नारीवाद, सांस्कृतिक मान्यताएँ

स्त्री देह को समाज ने अपने नियमों और मान्यताओं के अनुसार परिभाषित किया है। स्त्री देह एक प्रकार से पितृसत्ता में अधिक शोषित की जा रही है। स्त्री की पवित्रता को उसके शरीर से जोड़ने का प्रयास किया गया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री की देह को नैतिकता, मर्यादा और सम्मान के साथ जोड़कर देखा गया है; इससे सदियों से स्त्री देह पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। यह एक प्रकार से व्यक्तिगत न होकर सामाजिक नियंत्रण का विषय भी बन जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्त्री देह को पवित्र मानने की प्रक्रिया के साथ-साथ उसे अपवित्र बनाने की कोशिश भी की जाती है। स्त्री के शरीर और यौनिकता को हमेशा नियंत्रित किया गया है। “पितृसत्तात्मक समाज-व्यवस्था पर आधारित पुरुषप्रधान संस्थाओं और आर्थिक सामाजिक जगत में उनके वर्चस्व के कारण स्त्री अधीनस्थ स्थिति में रहने को बाध्य है। सत्ता की भाषा और संस्कृति के पुरुषप्रधान होने से पुरुष के यौन अनुभवों को ही प्रधान माना गया है। ऐसी सत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री का अपनी यौनिकता के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। चूँकि संस्कृति उसे एक ‘चीज’ मानती है अतः वह खुद भी अपनी देह को वस्तु में ही आँकती है, उसे सजाती-सँवारती है। यहाँ तक कि बचपन से वृद्धावस्था तक वह दूसरों की नजर से ही स्वयं को तोलने की इतनी आदी हो जाती है कि देह ही उसके कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है”।<sup>3</sup>

अपनी यौनिकता के कारण स्त्री को बड़े विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। इसके सम्बन्ध में प्रभा खेतान का कथन है “ अपनी यौनिकता के कारण स्त्री को कितना बड़ा विरोधाभास झेलना पड़ता है, यह चिंतनीय है। उसे नाजुक और कमनीय दिखना है और संघर्ष भी करना है। क्या दोनों बातें उसके लिए संभव हैं? मगर क्या यह सच नहीं कि जो देह से कमजोर होगा, वह हिंसा का शिकार ज्यादा होगा। हालाँकि आज स्त्री अपनी मांसपेशियों की ताकत आजमाना सीख रही है। चालीस की उम्र में भी स्त्री तन्वी रूप में रहना चाहती है। यदि उसकी कमर तीस इंच की है, यदि बेटे के कपड़े उसको अटते हैं तो क्या कहने? इसे बनाए रखने के लिए इतना तगड़ा अनुशासन कि एक टुकड़ा मिठाई तक नहीं खाती ! उनकी देह भरी हुई औरत की देह न लगे, बल्कि कुँआरी लड़की की देह लगे, चेहरे पर अनुभव और परिपक्वता की लकीरें न हों, बल्कि भोलापन और मासूमियत हो। औरत अपने-आपको कमसिन दिखाती

<sup>3</sup> खेतान प्रभा, 2022, उपनिवेश में स्त्री, मुक्ति- कामना की दस वार्ताएँ, राजकमल प्रकाशन, ( पृ.141)

रहे। और उससे ऐसी माँग कौन कर रहा है? इतरलिंगी यौनिकता से अनुकूलित मानस जो स्त्री की देह और उसकी यौनिकता को आतंकित करता रहता है, जो चाहता है कि स्त्री ताउम्र हस्वीकरण की प्रक्रिया में बनी रहे-कम खाए, कम स्थान घेरे, भोगवाद में पूरी तरह रत रहे। देह से भी तो हैसियत का पता चलता है”<sup>4</sup>। यह एक प्रकार से स्त्री के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना है। अतीतकाल में स्त्री पर अधिपत्य अलग प्रकार से किया जाता था। कालांतर में उस आधिपत्य का ज़ोर कम होता आया है, लेकिन समाज की निगरानी आज भी बनी हुई है। यदि एक स्त्री अपनी यौनिकता का समर्थन करती है, तो एक प्रकार से उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। समाज के नज़रिए में यदि स्त्री को यौनिक स्वतंत्रता दी जाए, तो उसे हाथ से निकली हुई औरत समझा जाता है। स्त्री को अपने शरीर पर अधिकार से वंचित किया जाता है।

किसी भी लिंग के लिए यौनिकता पर बात करना एक प्रकार से उसके चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाला माना जाता है। विशेष रूप से यदि स्त्री हो, तो उसकी यौनिक स्वतंत्रता को उसे वेश्या तक बना देने के रूप में देखा जाता है। यह एक दोहरा मापदंड है कि पुरुष के लिए इस प्रकार की धारणा नहीं बनाई जाती। इस प्रकार चरित्र का हनन करना स्त्री को सीमित दायरों में बाँधने का प्रयास है। “स्त्री की यौनिकता को नियंत्रित करने और उसे पुरुष की वंश-शुद्धि के अनुरूप संतानोत्पत्ति के एक साधन के रूप में सीमित करने के प्रयास ही पातिव्रत्य और एक-पत्नीव्रत जैसी व्यवस्थाएँ थीं। वैदिक हिंदू धर्म ने स्त्रीत्व को संस्थागत रूप प्रदान किया। संगठित धर्म के रूप में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को स्वरूप देने वाली मनुस्मृति, ब्राह्मणवादी परंपरा के रूप में हिंदू धर्म को परिवर्तित करने वाली, पुरुष-प्रधान और स्त्री-विरोधी थी। ज्ञान पर एकाधिकार केवल सवर्ण पुरुषों तक सीमित रहा, जिससे स्त्री की अस्मिता और कर्तृत्व को केवल पुनरुत्पादन तथा गृह-कार्य और पति-सेवा तक ही सीमित कर दिया गया। अर्थशास्त्र और इतिहास-पुराणों ने भी पुरुष-प्रधानता को सुदृढ़ किया। स्त्री को वैदिक अनुष्ठान करने के अधिकार से वंचित, विद्वानों की सभाओं के लिए अयोग्य तथा पुरुष को प्रलोभित करने वाली के रूप में चित्रित किया गया”<sup>5</sup>।

समाज में ऐसे मूल्य और संस्थाएँ विद्यमान हैं, जो स्त्री के अस्तित्व को स्वीकार करने के बजाय उसे द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में स्थापित करती हैं। इससे स्त्री की आत्मचेतना और सामाजिक

<sup>4</sup> खेतान प्रभा, 2022, उपनिवेश में स्त्री, मुक्ति- कामना की दस वार्ताएँ, राजकमल प्रकाशन, ( पृ.143)

<sup>5</sup> जोस जिस, स्त्रीवाद सौदार्यशास्त्र प्रयोगवुम प्रतिनिधिनावुम, विज्ञानमुद्रणम् प्रेस, ( पृ 51)

स्थिति दोनों ही कमजोर पड़ती हैं। इस प्रक्रिया में धर्म, दर्शन और साहित्य की भूमिका भी एकसमान दिखाई देती है।

भारतीय प्राचीन ग्रंथों—जैसे वेद और उपनिषद—में स्त्री के कर्म-अधिकार का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसके लिए केवल सीमित क्षेत्रों को ही निर्धारित किया गया है। इन ग्रंथों में पातिव्रत्य और पति-सेवा को स्त्री के प्रमुख गुणों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वैदिक काल में कन्यत्व को केवल शारीरिक न मानकर सामाजिक और राजनीतिक मूल्य के रूप में भी देखा गया।

वर्ण-व्यवस्था के अंतर्गत स्त्रियों को जो स्थान मिला, उसके प्रति असहमति या विरोध प्रकट करने की संभावनाएँ उनके लिए लगभग नहीं थीं। उनसे मौन आज्ञाकारिता और अधीनता की ही अपेक्षा की जाती थी। समाज के अनुसार ‘अच्छी स्त्री’ वही होती है, जो अपनी यौनिकता को दबाकर रखती है और समाज द्वारा निर्धारित नैतिक सीमाओं का पालन करती है। इसके विरुद्ध स्त्रियों को पौराणिक काल से संघर्ष करना पड़ा है। पौराणिक काल में स्त्री सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो एक प्रकार से उसके शरीर पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया है। सौंदर्य की वस्तुएँ अन्य लोगों के आनंद के लिए मानी जाती हैं; इसी प्रकार स्त्री को उसके देह के सौंदर्य तक सीमित कर दिया गया। शालीन, सुंदर स्त्री को अक्सर ‘अच्छी स्त्री’ के रूप में हमारे मन में स्थापित किया गया है, जबकि काले रंग या सौंदर्य रहित स्त्री पात्र को लोगों के मन में ‘बुरी स्त्री’ के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टिकोण सदियों से हमारे भीतर रूढ़ रूप में बना हुआ है। “फूको के अनुसार अनुशासित देह समर्पित देह है, आधारहीन है। और यह समर्पण केवल पुरुष के प्रति ही नहीं, बल्कि विशिष्ट संस्थागत नियमों द्वारा स्त्री की देह को यौन संतुष्टि के लिए ‘उत्पादन’ एवं ‘काम’ लायक बनाया जाता है। यह एक प्रकार का सहेजकर रखा गया पूरा लेख है, जिसे निर्मित करने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि स्त्री के ऊपर पुरुष सत्ता की एक तरह की निगरानी है, जिसे हम मनोप्टीकाम की अवधारणा से समझ सकते हैं”<sup>6</sup>।

आधुनिक समय में देखा जाए तो नारी के देह का वस्तुकरण किया जा रहा है। इस संस्कृति के खिलाफ नारीवादियों का हमेशा विरोध देखा जा सकता है। “नारीवादियों ने महिलाओं के शरीर को एक ऐसे केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया है, जिसके इर्द-गिर्द कई आंदोलनों का संचालन हुआ है। महिला शरीर की स्वायत्तता के अधिकार को गर्भपात, गर्भनिरोध और प्रसव विधियों के संदर्भ में प्रस्तुत किया

<sup>6</sup> खेतान प्रभा, 2022, उपनिवेश में स्त्री, मुक्ति- कामना की दस वार्ताएँ, राजकमल प्रकाशन, ( पृ.142)

गया है। महिला शरीर के बारे में ज्ञान का अधिकार, उसके स्वास्थ्य का अधिकार, तथा उसके स्वतंत्र आनंद के अधिकार पर भी नारीवादियों ने विभिन्न संदर्भों में जोर दिया है। इन ‘अधिकारों’ को प्राप्त करने या स्थापित करने के प्रयासों में अक्सर चर्च और राज्य—दोनों के प्रत्यक्ष विरोध का सामना करना पड़ा है। प्रारंभिक महिला मुक्ति आंदोलन का नारा ‘व्यक्तिगत ही राजनीतिक है’ उस समय एक अतिरिक्त और अप्रिय अर्थ ग्रहण कर गया, जब वे कार्य, जिन्हें महिलाएँ व्यक्तिगत चयन मानती थीं, राज्य द्वारा निषिद्ध या दंडनीय बना दिए गए। यह स्थिति महिला के शरीर और राज्य के बीच संबंध के प्रश्न को उठाती है। महिला शरीर पर इस सामाजिक और राजनीतिक ध्यान के बावजूद, मैं यह तर्क दूँगा/दूँगी कि नारीवादियों ने शरीर के संबंध में एक सुसंगत सिद्धांत बहुत कम प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से, महिलाओं के शरीर और राज्य के बीच संबंध—अर्थात् स्त्री शरीर और राजनीतिक संरचना के बीच संबंध—के वैचारिक पक्ष पर बहुत कम आलोचनात्मक कार्य हुआ है। ऐसे सिद्धांत के अभाव में, शरीर के बारे में जो सांस्कृतिक रूप से प्रचलित धारणाएँ हैं, उन्हीं के आधार पर, अनजाने में, कई नारीवादी कार्य करते हैं<sup>7</sup>।

भारत की अनेक संस्कृतियों में आज भी यौनिकता को एक वर्जित विषय माना जाता है। इसमें स्त्री देह का अधिक प्रयोग किया गया है। स्त्री की देह का उपभोग की वस्तु बनना एवं उसका शोषण भी इसी धार्मिक मापदंड का परिणाम है। स्त्रियों में विवाह संस्था के प्रति विरोध भी इसी के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। धार्मिक क्षेत्र में स्त्री की देह को मान्यता नहीं मिली है। इसके संबंध में रोहिणी अग्रवाल का कथन है: “भारतीय ही नहीं, समूचा वैश्विक इतिहास पौराणिक ग्रंथों-मिथकों-संस्कृतियों के जरिए बताता रहा है कि पुरुष तंत्र का अर्थ है स्त्री की स्वायत्तता और अस्मिता पर पुरुष की नृशंसता, शारीरिक सबलता और षड्यंत्रकारी मानसिकता की विजय का महानुष्ठान। परिवार, विवाह, न्याय, धर्म जैसी संस्थाएँ इसके बाद की सामाजिक संरचनाएँ हैं जो तत्परता से पुरुष के निजी हितों की रक्षा और संवर्धन के कार्य में जुट कर उसी अनुपात में स्त्री को हीन और कुलटा साबित करती रहती हैं। चूंकि किसी भी व्यक्ति के मनोबल को तोड़ने के लिए उसकी देह को ही हथियार बनाया जाता है, अतः पुरुष तंत्र ने स्त्री के मातृत्व को उसकी दुर्बलता, योनि को कलंक और यौन उन्मुक्तता को नैतिक वर्जना बनाकर इस रूप में प्रस्तुत किया कि तमाम प्रतिरोध भूल आदर्श नारी के रूप में वह स्वयमेव इन आरोपित मानदंडों की कसौटी बन

<sup>7</sup> Gatens moira, Imaginary Bodiès, Ethics, Power and Corporeality, Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge, (page no49)

बैठी”<sup>8</sup>। जब स्त्रीत्व और स्त्री के शरीर को पुरुष की जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार परिभाषित किया जाता है, तब धीरे-धीरे स्त्री की समाज में स्थिति कमजोर होने लगती है। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी स्त्रियों को पुरुष की यौन आवश्यकताओं से जोड़कर देखा गया और उन्हें अलग-अलग वर्गों में बाँटा गया। इससे स्त्रियों की निर्भरता और बढ़ी। यहाँ तक कि कुलीन और पतिव्रता स्त्रियों को भी अपने शरीर से जुड़े निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी गई। उनके आनंद और इच्छाओं को महत्व नहीं दिया गया। इसी तरह, अन्य ग्रंथों में भी स्त्री के शरीर को पुरुष के उपयोग की वस्तु के रूप में देखा गया और उसकी यौनिकता को पुरुष के नजरिए से समझा गया।

भारत में यौनिकता जैसे विषयों पर खुली चर्चा राष्ट्रीय आंदोलन के समय अधिक शुरू हुई। महात्मा गांधी ने यौन संयम को बहुत महत्वपूर्ण माना। उनका विश्वास था कि इससे व्यक्ति अपनी ऊर्जा को समाज और देश के कामों में बेहतर तरीके से लगा सकता है। स्वामी विवेकानंद के विचार भी कुछ हद तक ऐसे ही थे। गांधीजी ने स्त्रियों के लिए एक आदर्श रूप सोचा, जिसमें वे अपनी इच्छाओं को दबाकर परिवार और राष्ट्र के लिए समर्पित रहें। इस सोच में स्त्री की अपनी जरूरतों और उसकी यौनिकता को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। लेकिन धर्म हमेशा स्त्री देह को वस्तु ही मना है। “केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि सभी धर्म स्त्रीत्व को सीमित और बंद ढाँचों में बाँधते हैं। वे धार्मिक नियमों और परंपराओं के माध्यम से स्त्री की यौनिक अधीनता को स्थापित और मजबूत करने का प्रयास करते रहे हैं और आज भी करते हैं”<sup>9</sup>।

### निष्कर्ष :

स्त्री देह और यौनिकता पर स्थापित सामाजिक नियंत्रण को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि समाज में समानता, न्याय और संवेदनशीलता के मूल्यों को विकसित किया जाए। स्त्री को अपने शरीर, इच्छाओं और पहचान के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यही एक संतुलित, समतामूलक और प्रगतिशील समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। समाज में पुरुष-प्रधान व्यवस्था ने नियमों और परंपराओं के माध्यम से स्त्री की यौनिकता को नियंत्रित किया और उसे खुलकर व्यक्त होने से रोका। इस कारण स्त्रियों को अपनी पहचान और विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अवसर कम मिलते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए जरूरी है कि स्त्री और पुरुष के संबंधों में समानता और न्याय स्थापित किया जाय।

<sup>8</sup> अग्रवाल रोहिणी, स्त्री लेखन का स्वप्न और संकल्प, राजकलम प्रकाशन, (पृ. 307)

<sup>9</sup> जोस जिस, स्त्रीवाद सौदार्यशास्त्रम प्रयोगवुम प्रतिनिधिनावुम, विज्ञानमुद्रणम् प्रेस, ( पृ53

# भारत के आदिवासी जीवन: पहचान, संस्कृति और संघर्ष का बहुआयामी अध्ययन

श्रीलक्ष्मी के.एस.  
शोधार्थी, हिंदी विभाग  
श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय,  
कालडी एर्नाकुलम, केरल

## प्रस्तावना

भारत की सांस्कृतिक विविधताओं में आदिवासी समाज एक महत्वपूर्ण जीवनधारा है, जो प्रकृति, संस्कृति, परंपरा और सामूहिक जीवन का अद्वितीय संयोजन प्रस्तुत करता है। भारत की प्राचीन आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहर आज भी आदिवासी समाज में सुरक्षित है। आदिवासी समाज न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संतुलित जीवन का संदेश भी देता है। अंततः कहा जा सकता है कि आदिवासी समाज अन्य समाजों से भिन्न है, और यह भिन्नता उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं के कारण है। प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन उनकी विशेषता है। किंतु बढ़ते बाहरी हस्तक्षेप, औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव ने उनके जीवन के संतुलन को प्रभावित किया है।

आज आदिवासी समाज अपनी प्राकृतिक जीवनशैली और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए संघर्षरत है। उनका संघर्ष केवल जंगल और प्रकृति की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए भी है। इस प्रकार, आदिवासी समाज का समग्र अध्ययन केवल उनके जीवन को समझने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके संरक्षण और समावेशी विकास के उपायों पर भी गंभीर विचार किया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक योगदान संभव हो सके।

**बीज शब्द:** आदिवासी संस्कृति, संघर्ष, पहचान, भाषा, अस्मिता, वैश्वीकरण, प्राकृतिक प्रदूषण।

भारत में ‘आदिवासी’ शब्द एक विशिष्ट समाज के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनका इतिहास उतना ही पुराना है जितना आर्यों के आगमन से पूर्व भारत का इतिहास है। ‘आदिवासी’ शब्द ‘आदि’ और ‘वासी’ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ‘मूल निवासी’ या ‘आदिनिवासी’। यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो भारत के मूल निवासी हैं। ‘आदिवासी’ शब्द अंग्रेजी के ‘Aboriginal’ के समतुल्य माना जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासियों के लिए ‘वनवासी’ और ‘आत्विका’ शब्दों का प्रयोग किया गया है। महात्मा गाँधी ने इनके लिए ‘गिरिजन’ शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय संविधान में आदिवासियों को ‘अनुसूचित जनजाति’ की संज्ञा दी गई है, तथा वर्ष 1950 में उन्हें इस रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार, “भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% (लगभग 10.45 करोड़) जनजातीय नागरिक हैं।”<sup>10</sup>

ये लोग भारत के पहाड़ी एवं घने जंगलों में निवास करते हैं। प्रत्येक आदिवासी समूह की अपनी भाषा, संस्कृति एवं रीति-रिवाज होते हैं। प्रत्येक आदिवासी समाज अपने आप में स्वतंत्र, उन्मुक्त एवं प्रकृति के निकट जीवन जीना पसंद करता है। सामान्यतः आदिवासियों के लिए ‘आदिवासी’ शब्द ही प्रचलित है, किंतु मध्य और पूर्व आदिवासियों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कुछ जनजातीय समुदाय स्वयं को ‘ट्राइबल्स’ कहलाना अधिक पसंद करते हैं। भारत के आदिवासियों के बीच अनेक भिन्नताएँ पाई जाती हैं, इसलिए सभी आदिवासियों को एक ही सिद्धांत के अंतर्गत रखना कठिन है। “पूर्वोत्तर के नागा-मोजो, खासी या अरुणाचल की न्यीशी, गालोंड और आदी जनजातियों के लोग अपने लिए आदिवासी नाम को पसन्द नहीं करते, इस नाम से नफरत करते हैं जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश या राजस्थान के आदिवासी इसी नाम को अपने लिए गौरवपूर्ण मानते हैं। पूर्वोत्तर के समुदाय खुद को ट्राइबल कहते हैं। उनकी नजर में आदिवासी का मतलब काले रंगवाले, दीन-हीन, गरीब और गुलाम लोग है। वे खुद को ट्राइबल कहते हुए गौरव का अनुभव करते हैं क्योंकि उनकी नजर में ट्राइबल का मतलब है स्वतंत्र, आजाद कौम, जो अपने इलाके का शासन खुद करते हैं।”<sup>11</sup>

भारत के मूल निवासी होते हुए भी मुख्यधारा का समाज उन्हें हीन दृष्टि से देखता है। ‘जंगली’ और ‘वनवासी’ जैसे शब्दों का प्रयोग करके उन्हें असभ्य सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। मुख्यधारा समाज से दूर रहने के कारण वे आधुनिक विकास की दृष्टि से भले ही पिछड़े प्रतीत होते हों, किंतु भारतीय

<sup>10</sup>press Information Bureau. (2024, July 25). Empowering tribal communities. Government of India. <https://pib.gov.in>.

<sup>11</sup> तलवार वी. भा, 2025, उत्पीड़कों के विमर्श, राजकमल प्रकाशन, (पृ. 30 -31)

संस्कृति और परंपराओं का मूल बीज आज भी इन्हीं आदिवासी समाजों में सुरक्षित है। इसलिए भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने वाले समाज के रूप में इन्हें उचित प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए।

भारत के इतिहास में इन मूल निवासियों को प्रायः पराजित वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किंतु इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी समाज अपने आप में स्वतंत्र, निडर और सशक्त व्यक्तित्व वाला रहा है, जो भारत की मूल संस्कृति का वाहक है। सांस्कृतिक हास के इस समय में भी वे अपनी संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। “आर्य-अनार्य संघर्ष में कुछ अनार्यों अर्थात् भारत के मूलनिवासियों ने आर्यों से कभी पराजय स्वीकार नहीं की। उन्होंने आर्यों को अधिक शक्तिशाली पाकर आर्यों की गुलामी से बचने के लिए और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए वनों और पर्वतों की शरण ले ली। ऐसी अनार्य जातियों को आज अनुसूचित जनजाति अर्थात् एस.टी. कहा जाता है। इस आदिवासी समाज ने ही इस देश की मूल संस्कृति को आज तक संरक्षित करके रखा है।”<sup>12</sup>

आदिवासी समाज पूर्णतः जंगलों पर निर्भर है। जंगल के अभाव में आदिवासी केवल नाम मात्र रह जाएंगे, क्योंकि उनकी संपूर्ण संस्कृति जंगल पर आधारित है। भारतीय संस्कृति का मूल बीज आदिवासियों में निहित माना जाता है। प्रत्येक आदिवासी समाज की अपनी भाषा, संस्कृति और मान्यताएँ होती हैं। यही विशिष्टता उन्हें अन्य समाजों से अलग बनाती है, किंतु वर्तमान समय में यह पहचान धीरे-धीरे मिटती हुई दिखाई दे रही है। वैश्वीकरण, बाजारीकरण, औद्योगिकीकरण और विकास योजनाएँ आदिवासी पहचान को लगातार प्रभावित कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विकास परियोजनाओं के कारण उनकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो रही है। आदिवासी जीवन पूर्ण रूप से जंगलों पर निर्भर करता है। जंगल के संसाधनों का संग्रह, खेती, पशुपालन और वनोपजों की बिक्री के माध्यम से वे अपनी आजीविका चलाते हैं। जंगलों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप उनकी नैसर्गिक जीवनशैली पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसका सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। “प्रकृति के साथ आदिवासियों के घनिष्ठ सम्बन्ध, उसके प्रति उनकी जीवन-दृष्टि और धर्मदृष्टि का मूल कारण सारा समय उनका प्रकृति के बीच रहना और अपने जीवन-यापन के लिए उस पर, खासकर जंगलों पर, निर्भर करना है। किसी दार्शनिक कारण से नहीं बल्कि आर्थिक कारणों से वे जंगलों की रक्षा करते हैं क्योंकि जंगल उनकी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है।”<sup>13</sup>

वैश्वीकरण का आदिवासी जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। विकास के नाम पर उदारीकरण, निजीकरण, बाजारवाद और उपभोक्तावाद ने आदिवासी जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया है। विकास की शुरुवात आदिवासी भूमि से शुरू होता है। इसके परिणामस्वरूप आदिवासियों को अपनी

<sup>12</sup> कठेरिया कमल किशोर, 2015, भारतीय संस्कृति का पुनर्लेखन अस्मिताओं का संघर्ष, वाणी प्रकाशन, (पृ.100)

<sup>13</sup> पाण्डेय म, 2022, हाशिए का समाज एवं आदिवासी साहित्य, चिंतन प्रकाशन, (पृ. 19)

भूमि से वंचित होना पड़ा, उनकी आजीविका नष्ट हुई और वे बेघर होकर जीविका के लिए शहरों की ओर पलायन करने को विवश हुए। इस प्रकार आदिवासी समाज हशिए पर धकेल दिया गया। “उस मानवता जो प्राचीन काल से जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा करते हुए अपनी जीवन-शैली में आदिम सरोकारों व संस्कारों के साथ जीवन जी रही है, वह नष्ट कर किया जा रहा है। विकास के नाम पर जिस औद्योगीकरण, सेज, बाँध परियोजनाओं, राजमार्गों के निर्माण की बात की जाती है, उसकी शुरुआत आदिवासियों की जमीन के अधिग्रहण के साथ होती है जो उनकी आजीविका का स्रोत है। यहीं से प्रारंभ हो जाता है समाज के एक हिस्से का भरपूर विकास और देश की बुनियाद आदिवासी समाज को हाशिए पर धकेलने का प्रयास।”<sup>14</sup>

भारत की विकास योजनाएँ प्रायः मुख्यधारा तक सीमित रही हैं। आदिवासियों के लिए विकास का अर्थ विस्थापन और पलायन। आदिवासी जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति तथा आदिवासी एक-दूसरे के पूरक हैं। जन्म से मृत्यु तक उनके जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया—त्योहार, पर्व, भोजन और आजीविका—प्रकृति पर आधारित होती है। आदिवासी अर्थव्यवस्था का मूल जंगल है, किंतु वर्तमान में हो रहा प्राकृतिक दोहन उनके जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। जंगलों की कटाई, कारखानों से निकलने वाली विषैली धुआँ और जल, प्लास्टिक का कचरा तथा खनन से उत्पन्न मलबा आदिवासी जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। खनन के पश्चात गड्ढों को बिना भरे छोड़ देने से उनमें पानी भर जाता है, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। कारखानों से निकलने वाला विषैला जल जब जलस्रोतों में मिल जाने पर पानी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार आदिवासियों का स्वच्छ एवं स्वच्छंद प्राकृतिक जीवन धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। लक्ष्मण प्रसाद सिन्हा ने झारखंड का उदाहरण देकर कहते हैं कि “कभी बाहर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जानेवाला वर्तमान झारखण्ड क्षेत्र समतल मैदानों की तरह तपता नजर आ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। औद्योगिक कचरों से यहाँ की सभी नदियाँ इतना प्रदूषित हो गया है कि इनका पानी पीने लायक नहीं रह गया है। चन्द्रपुरा जैसे कोयला क्षेत्रों में हवा का प्रदूषण इस हद तक बढ़ा हुआ है कि उन क्षेत्रों में काम करनेवाले 50 प्रतिशत से अधिक लोग श्वास रोगों से पीड़ित हैं। कहीं कहीं (जादू गोडा के यूरेनियम खान एवं अन्यत्र) विकास और खतरनाक खनिजों की अनियन्त्रित खुदाई का असर विकलांग शुरु के रूप में दिखायी देने लगा है। यह असंतुलन जितना ही बढ़ रहा है, उतना ही यहाँ के आदमी का पलायन भी और प्रकृति पोषक मानवीय संवेदना के घटने के अनुपात में ही उसके विनाश की प्रक्रिया भी घनिभूत होती जा रही है।”<sup>15</sup>

14 बेरली, के. पी. (2018), आदिवासी साहित्य: विविध संदर्भ, शंकराचार्य यूनिवर्सिटी प्रेस, (पृ. 33)

15 सिन्हा, लक्ष्मण प्रसाद, (2010), भारतीय आदिवासी, जयभारती प्रकाशन, (पृ.30)

हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर है, किंतु इस प्रगति का आदिवासी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। जंगलों के विनाश से प्राप्त होने वाली प्रगति आदिवासी समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि

जंगल के बिना उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। वर्तमान विकास योजनाएँ आदिवासी समाज के लिए संकट का कारण बन रही हैं। विकास और आदिवासियों के बीच संतुलन का अभाव है। उदाहरणस्वरूप, पिछले कई वर्षों से झारखंड जैसे राज्यों में विभिन्न विकास परियोजनाएँ लागू की गई हैं, किंतु इनका लाभ आदिवासी जनता को पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। इन परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभावों की अपेक्षा नकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिलते हैं। इन विकास योजनाओं के कारण आदिवासियों को अपनी पैतृक भूमि से बेदखल होना पड़ा है। यद्यपि सरकार भूमि अधिग्रहण के समय उचित मुआवजे और पुनर्वास का आश्वासन देती है, किंतु यह प्रायः कागज़ों तक ही सीमित रह जाता है। झारखंड के अनेक आदिवासी समाजों को विस्थापित कर खदानें, बाँध और सड़कें बनाई गई हैं, जो इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। “विकास के नाम पर बने डैम और दूसरी परियोजनाओं में झारखंडियों की जमीन ली गयी, लेकिन आज, वर्षों गुजर जाने के बाद भी उन्हें उनकी जमीन का उचित दाम नहीं दिया गया, उन्हें रोजगार नहीं दिया था, उन्हें फिर से दूसरी जगह बसाने की बात तो दूर रही। इसलिए जो भी झारखंडियों को यह विश्वास दिलाता है कि सरकार उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा देगी और उन्हें फिर से बसाएगी वह झारखंडी जनता को बरगलाता है, धोखा देता है, वह सरकार का दलाल है।”<sup>16</sup> वर्तमान समय में पूँजीपतियों के साथ-साथ सत्ता भी शोषक वर्ग का रूप लेती प्रतीत होती है। सरकार द्वारा लागू की गई नीतियाँ प्रायः व्यवहार में प्रभावी नहीं हो पातीं और कागज़ों तक ही सीमित रह जाती हैं। नेहरू द्वारा एल्विन के विचारों के आधार पर बनाई गई नीतियाँ भी सामंतों और पूँजीपतियों के दबाव में असफल सिद्ध हुईं। सरकारी नीतियाँ आज पूँजीपतियों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश का माध्यम बनती जा रही हैं। सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव के कारण उन्हें अपनी भूमि छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है। अपनी भूमि की रक्षा के लिए आदिवासी समाज लंबे समय से संघर्ष करता आ रहा है। 1855-56 के संधाल विद्रोह तथा 1900 ई में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए आंदोलनों को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप बनाए गए नियम और कानून भी आज अधिकांशतः कागज़ों तक सीमित रह गए हैं। आदिवासी भूमि के अधिग्रहण के पीछे पूँजीपतियों के साथ-साथ सत्ता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। “उद्योग खोलने के लिए, खदान खोलने के लिए, कामर्शियल फार्मिंग करने के लिए, सारी दुनिया में जमीनें खरीदी जा रही हैं और ये राष्ट्रीय सरकारों ही हैं, जो कमजोर आदिवासियों और गरीब किसानों की जमीनें इन कम्पनियों को दिलाती हैं। पूँजीपति इन जमीनों को सीधे

<sup>16</sup> तलवार वी. भा, 2019, झारखंड के आदिवासियों के बीच एक एक्टिविस्ट का नोट्स, वाणी प्रकाशन, (पृ. 129)

तौर पर नहीं खरीदते। वे राज्य पर दबाव डालते हैं क्योंकि वह आदिवासियों और किसानों से जमीन अधिग्रहण कर सस्ते दर पर इन कम्पनियों को दे सकता है। पूँजीवादी कम्पनियाँ राज्य की सरकारों पर दबाव डालती हैं कि अपनी भूमि अधिग्रहण की नीति को और उदार बनाओ। ऐसे कानून बदलो या खतम करो जो जमीन अधिग्रहण करने में रुकावट बनते हैं।”<sup>17</sup>

आदिवासी समाज अपने आप में विशिष्ट है। इस विशेषता का कारण उनकी भाषा संस्कार और मान्यताएँ हैं। लेकिन आजकल की बदलती परिस्थितियाँ, अपने पैतृक संपत्ति से विस्थापन, पलायन आदि कई समस्याओं से इनकी संस्कृति संकट से हैं। इनकी भाषा लुप्त हो रही है, संस्कृति घटती जा रही है। भाषाओं की दृष्टि से देखा जाए तो आदिवासी भाषाएँ उनकी विशिष्ट संस्कृति का वाहक है। प्रत्येक समाजों के लिए अपनी खुद की भाषा होती है। आदिवासी की विलुप्ति का मतलब इन भाषाओं का लुप्त होना है। “दो सौ भाषाएँ पिछले पचहत्तर वर्षों में खतम हो चुकी हैं। उनका अस्तित्व मिट चुका है। बाकी बची भाषाओं में 2500 भाषाएँ संकटग्रस्त हैं। उनका अस्तित्व मिटने की ओर जा रहा है। इन 2500 भाषाओं में से 196 भाषाएँ भारत की हैं और इन 196 भाषाओं में 62 भाषाएँ 1950 के बाद से अभी तक यानी हिन्दुस्तान में जब से लोकतंत्र आया है, मिटने की कगार पर पहुँच चुकी हैं, और 9 भाषाएँ खतम हो चुकी हैं। जो 9 भाषाएँ खतम हुई हैं, सब-की-सब भाषाएँ आदिवासी भाषाएँ हैं।”<sup>18</sup> भाषा और संस्कृति का खत्म होने का अर्थ है आदिवासी समाज का खत्म होना इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत की आदिवासी समाज आज विलुप्त के कगार पर पहुँच गई है।

### निष्कर्ष

भारत के इतिहास और परंपरा में आदिवासियों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति के निकट रहकर वृक्षों, नदियों, पहाड़ों और पशु-पक्षियों को अपने सखा के रूप में मानने वाले आदिवासी समाज सरल और संतुलित जीवन व्यतीत करते रहे हैं। उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएँ और मान्यताएँ उन्हें अन्य समाजों से विशिष्ट बनाती हैं।

आदिवासी समाज सदियों से अपने अधिकारों से वंचित रहा है। वर्तमान में उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान संकट में है। उनकी भाषा लुप्त हो रही है और संस्कृति क्षीण होती जा रही है। भाषा और संस्कृति का समाप्त होना आदिवासी समाज के अस्तित्व के समाप्त होने के समान है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत का आदिवासी समाज विलुप्ति के कगार पर पहुँचता दिखाई दे रहा है। यह उनकी केवल अलग पहचान ही नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व भी है।

<sup>17</sup> तलवार वी. भा, 2025, उत्पीड़कों के विमर्श, राजकमल प्रकाशन, (पृ. 69 )

<sup>18</sup> तलवार वी. भा, 2025, उत्पीड़कों के विमर्श, राजकमल प्रकाशन, (पृ. 66 )

वैश्वीकरण, उदारीकरण और विकास परियोजनाओं ने आज आदिवासी अस्मिता को संकट में डाल दिया है। अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनका संघर्ष पहले की अपेक्षा अधिक तीव्र हो गया है। जंगलों में कारखानों की स्थापना, सड़कों और बाँधों का निर्माण तथा खनिज संपदाओं के दोहन ने उनके जीवन के संतुलन को बिगाड़ दिया है। इन परिस्थितियों के कारण वे अपनी भूमि से विस्थापित होकर पलायन करने के लिए विवश हो रहे हैं। अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए वे निरंतर संघर्षरत हैं।

आज आदिवासी अस्मिता लुप्त होती हुई प्रतीत हो रही है। विकास नीतियाँ, जो उनके हित में बनाई गई थीं, लेकिन वह आज उनके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। अतः यह आवश्यक है कि सरकार समावेशी नीतियाँ बनाए, जिससे आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति और जीवनशैली को कोई क्षति न पहुँचे और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। आदिवासी समाज के ज्ञान और जीवनशैली को मुख्यधारा में उचित स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके, जहाँ उन्हें समान सम्मान और अधिकार प्राप्त हों।

## नारी शक्ति : बदलाव की ओर कदम

रानी कुमारी

शोधार्थी, इतिहास विभाग

बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर

### सारांश :

भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है। जैसे तो आजादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्रों में पहल तेज हुई है। इसके लिए समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत व सशक्त किया जा रहा है और समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है, इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ० अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही-सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियां किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। समाज की आदिम संरचना से सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया है। स्त्रियों को दोयम दर्जे के रूप में देखने की कवायद इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

**मुख्य शब्द :** इतिहास, स्त्री, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानव संसाधन।

### परिचर्चा

आधुनिक भारत में स्त्रियों का प्रश्न उन्नीसवीं सदी के मध्यवर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलनों के एक हिस्से के रूप में उदित हुआ। उन्हें प्रायः मध्यवर्गीय सुधार आंदोलन की संज्ञा इसलिए दी जाती थी कि इन सुधारकों में से बहुत से लोग नए उभरते हुए पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग से थे। वे अक्सर आधुनिक पश्चिम के उदारवादी लोकतांत्रिक आदर्शों और अपने स्वयं के अतीत की लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा प्राप्त करते हुए इन सुधारों के लिये प्रेरित हुए थे। इन सुधारक नेताओं में कुछ प्रमुख थे

जैसे – बंगाल में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा विरोधी अभियान का नेतृत्व किया; ज्योतिबा फुले ने जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहाँ के अग्रणी सुधारक रानाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिये आंदोलन चलाया, इसी प्रकार सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया, दयानंद सरस्वती ने महिलाओं को शिक्षा देने के विचार का समर्थन किया। इनके अतिरिक्त कई महिलाओं ने भी स्वतंत्रता के पूर्व पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों का सशक्त विरोध किया। इनमें से कुछ महिलाओं यथा ताराबाई शिंदे ने अपनी कृति स्त्री-पुरुष तुलना, बेगम रोकेया सखावत हुसैन ने अपनी रचना सुल्तानाज ड्रीम के माध्यम से स्त्री विषयक मुद्दों को दुनिया के समक्ष रखा।

भारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में होकर भी केन्द्र से दूर है। सिमोन द बोउवार का कथन है, “स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।” समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार स्त्री को ढालता आया है। उसके सोचने से लेकर उसके जीवन जीने के ढंग को पुरुष अभी तक नियंत्रित करता आया है और आज भी करने की कोशिश करता रहता है। पितृसत्तात्मक समाज ने वह सब अपने अनुसार तय किया है। जब-जब सशक्तिकरण का सवाल उठता है तब-तब समाज ही कठघरे में खड़ा होता है। समाज में लगातार बदलावों के लिए संघर्ष चलता रहता है।

भारत में महिलाओं की स्थिति का इतिहास : हिंदू धर्म में श्रद्धा के रूप में जानी जाने वाली सभी चीजों को स्त्री कहकर संबोधित किया गया है। स्त्री को शक्ति का रूप भी माना गया है। महिलाओं का भारतीय संस्कृति में अद्वितीय स्थान है और उन्हें शक्ति के प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया गया है। गौतम बुद्ध ने समाज में महिलाओं को सर्वोपरि स्थान दिया है। उसी प्रकार, महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। वैदिक काल में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन मध्यकालीन युग में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। जिसमें महिलाओं को कई बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा। भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, पर्दा प्रथा, राजस्थान के राजपूतों में महिलाओं की जौहर प्रथा, हिंदू क्षत्रिय शासकों की बहु विवाह प्रथा, मंदिरों में महिलाओं के यौन शोषण की देवदासी प्रथा, इत्यादि। उन्नीसवीं सदी के आरंभ से ही महिलाओं की समस्याओं ने समाज सुधारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। महिलाएं प्राचीन काल से ही अपनी अद्भुत शक्ति, प्रतिभा, चातुर्य, स्नेहशीलता, धैर्य, समझ और सौंदर्य के कारण पुरुष से आगे रही है। लेकिन मध्यकालीन महिलाओं के पतन की गाथा के बाद महिलाओं को विभिन्न प्रकार के संघर्षों से जूझना पड़ा। भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पुरुषों द्वारा शुरुआत की गई।

भारत में नारीवाद के इतिहास को हम तीन महत्वपूर्ण तरंगों/लहरों में विभाजित कर सकते हैं।

- पहली लहर 1850 से 1915 तक
- दूसरी लहर 1915 से 1947 तक
- तीसरी लहर 1947 से आज तक

भारतीय सामाजिक संरचना, उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के कारण भारत का नारीवादी आंदोलन पश्चिम से भिन्न है। भारत का नारीवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत में पहला नारीवादी आंदोलन समाज में विद्यमान अंधविश्वासों रूढ़ परंपराओं जैसे – सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि को समाप्त करने के उद्देश्य पर केंद्रित था। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, ताराबाई शिंदे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई, सर सैय्यद अहमद खान आदि विचारकों और समाज सुधारकों ने महिलाओं से जुड़े हुए प्रश्नों को प्रमुखता दी तथा विभिन्न संगठनों और कानूनी सुधार के माध्यम से स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और स्त्री अधिकार की दिशा में समर्पित प्रयास किया।

दूसरा चरण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से जुड़ा हुआ है। इस दौर में महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर श्रमिक आंदोलन में भी शामिल होने लगीं। इस चरण में भारतीय महिला संघ (1917) जैसे विभिन्न संगठनों की स्थापना हुई और शारदा एक्ट (1929) जैसे कानूनी सुधार हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और डॉ० अंबेडकर के महिला उत्थान की दिशा में किए गए प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जहां महात्मा गांधी ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत व विधवाओं के शोषण का मुखर विरोध किया वहीं डॉ० अंबेडकर ने कानूनी सुधार (प्रसूति अवकाश, मताधिकार) व संवैधानिक प्रावधानों (समानता का अधिकार और लैंगिक विभेद का अंत) के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में व्यावहारिक प्रयास किया। इस दौर में प्रमुख नारीवादियों में कामिनी राय, सरला देवी चौधरानी, दुर्गाबाई देशमुख की भूमिका उल्लेखनीय रही है।

भारत में नारीवादी आंदोलन का तीसरा चरण आजादी के बाद सार्वजनिक और निजी जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। यह प्रमुख रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, शिक्षा तक पहुंच, संपत्ति में अधिकार तथा लैंगिक विभेद के अंत से जुड़ा हुआ है।

यदि हम वर्तमान में भारतीय नारीवादी विचारकों और आंदोलनकारियों की बात करें तो मेघना पंत, वृंदा करात, मधु किश्वर, मेधा पाटकर, गीता सहगल, वंदना शिवा, निवेदिता मेनन, नीरा देसाई, रूथ वनिता का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है।

## स्वतंत्रता के पश्चात् प्रमुख महिला आंदोलन :-

सेवा’ (SEWA: Self Employed Women’s Association) : महिलाओं द्वारा कार्यरत एक ट्रेड यूनियन के रूप में 1972 में उभरी। इसका इतिहास टेक्स्टाइल लेबर एसोसिएशन जो 1920 में सबसे बड़ी यूनियन अनुसूया साराभाई द्वारा शुरू की गई थी, उससे संबंधित थी। इस आंदोलन के द्वारा परिवार में दोकाम करने वाली घरेलू महिलाओं की मदद की जा सकी। सेवा घर में काम करने वाली महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण जैसे – सिलाई, कढ़ाई, कटाई, प्रेस, रचना, टंकण आशुलिपि इत्यादि देती है। यह एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है। यह एक महिला स्वरोजगार श्रमिकों का एक संगठन है। सेवा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है – पूर्ण रोजगार – मजदूरों को काम की सुरक्षा, आय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, महिला आत्मनिर्भरता। गांधीवादी सोच और सामाजिक बदलाव, सेवा के गरीब स्वरोजगार सदस्यों के लिए मार्गदर्शक बल है। सेवा महिलाओं के नेतृत्व, उनके आत्मविश्वास, नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व और उनके अस्तित्व की एक पहचान है।

1974 में गुजरात में नव निर्माण आंदोलन की शुरुआत हुई। यह एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था। यह आंदोलन असंतुष्ट छात्रों और मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा बढ़ते दाम, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया गया आंदोलन था। अहमदाबाद में युवक और युवतियों ने नव निर्माण युवक समीति का भी गठन किया था। इसमें हजारों मध्यम वर्गीय महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया।

1972-1973 में विकसित चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन था जिसका उद्देश्य वृक्षों के संरक्षण से था। चिपको आंदोलन अक्सर ठेकेदारों की कुल्हाड़ियों से उत्तराखंड की वन पारिस्थितिकी के बचाने के लिए महिला आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया। अहिंसा की गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित यह आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाने की बात कहता था। इस आंदोलन के अग्रदूतों में सी.पी. भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नाम उल्लेखनीय हैं। इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई क्योंकि वह इससे सबसे ज्यादा प्रभावित थीं। ग्रामीण महिलाओं के लिए अपने पर्यावरण को बचाना, अपनी आजीविका को बचाने जैसा था। प्राथमिक भोजन, ईंधन, पानी, मरुस्थलीकरण इत्यादि महिलाओं के विशेष हित में शामिल थे।

इसी प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन भी 1985 में महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। यह आंदोलन मेधा पाटेकर ने भारत में गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध जनजातीय लोगों, आदिवासियों, किसानों, पर्यावरणवेत्ताओं और मानव अधिकार के सक्रिय कार्यकर्ताओं की सहायता से चलाया था। नर्मदा नदी के पानी को मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बांध बनाने की योजना को मंजूरी दे दी गई थी। अक्टूबर

1969 में भारत सरकार द्वारा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई ताकि जल विवाद का निर्णय किया जा सके। दिसंबर 1979 को सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के साथ-साथ 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांधों के निर्माण की अनुमति मिल गई थी। यह आंदोलन आदिवासियों के विस्थापन, किसानों की उपजाऊ भूमि के छीने जाने, दलित श्रमिकों और महिलाओं-बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में चलाया गया था। इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं, दलित महिलाओं ने अपने भूमि के अधिकार के लिए संघर्ष किया था।

### **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय :**

महिला एवं बाल विकास की स्थापना 1985 में महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई थी। इस विभाग को 30 जनवरी 2006 से मंत्रालय के रूप में शुरू किया गया। इस मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास करना है। नोडल मंत्रालय होने के नाते इसका मुख्य कार्य योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम और अधिनियम बनाना तथा विधानों में संशोधन करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों संगठनों का मार्गदर्शन करता है। इनके कार्यक्रम मुख्यतः कल्याण, सहायता सेवाएं, रोजगार, आय के सृजन के साधन, जागरूकता अभियान, जेंडर संवेदनशीलता इन सभी मुद्दों पर कार्यरत हैं। इस मंत्रालय में 6 स्वायत्त संगठन सम्मिलित हैं –

1. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान,
2. राष्ट्रीय महिला आयोग,
3. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
4. केंद्रीय दत्तक संसाधन एंजेसी,
5. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और
6. राष्ट्रीय महिला कोष।

महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय मिशन के तहत महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्रों का निर्माण 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के लिए नीति और कार्यों की योजनाएं बनाना, धनराशि का प्रबंध करना, संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना, ढांचागत सुविधाओं का सृजन करना, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना इत्यादि है। इसकी अन्य वर्तमान योजनाओं में सबला और अहिंसा मैसेंजर बहुत उपयोगी योजनाएं हैं।

## राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) :-

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में भारत सरकार महिला आयोग अधिनियम, 1990 ( 1990 की एक्ट संख्या 20 ) के अंतर्गत एक सांविधानिक निकाय के रूप में की गई थी। आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना, उनकी शिकायतों के निवारण हेतु सुविधा प्रदान करना, महिलाओं के नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना और मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या को रोकना इत्यादि हैं। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी विभिन्न नीतियों के द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। कानूनी सेवाओं के माध्यम से महिलाओं की शिकायतों के निवारण में उनकी मदद, करना, देश के विभिन्न भागों में पारिवारिक महिला लोक अदालतों का आयोजन कर महिलाओं को तुरंत न्याय उपलब्ध कराना संवैधानिक कानूनों में समयानुसार फेर-बदल करना, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रचार गतिविधियों का आयोजन करना, संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना, विभिन्न घटनाओं के अंतर्गत महिलाओं के अस्तित्व की रक्षा करना और घटना अनुसार कार्यवाही स्वरूप नोटिस जारी करना, महिलाओं से संबंधित मामलों का केस अध्ययन करना, भेदभाव और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, धरने देना और उत्पन्न स्थिति की जांच करना, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के तरीके सुझाना, शैक्षिक अनुसंधान कार्य करना, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया पर सलाह करना, संघ और किसी राज्य में महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, महिला कैदियों की सुरक्षा, सुधारात्मक कार्यवाही, रिमांड होम, वकील या मुकदमे में शामिल धन या निधि का प्रबंध करना।

निष्कर्षतः भारत के इतिहास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। महिलाओं को समय-समय पर अपने घर से बाहर निकल कर समाज में अपने स्थान को बनाने में कई वर्षों तक, कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा। भारत में महिला आंदोलन विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न मुद्दों, पड़ावों और चुनौतियों से गुजरा। कभी समस्या सती प्रथा मुद्दों की थी, तो कभी बाल विवाह की, कभी बाल कन्या शिक्षा की समस्या थी तो कभी विधवा पुनर्विवाह। महिलाओं ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तो कभी महिला एसोसिएशनों का भी निर्माण किया। सभी परिस्थितियों में भारतीय महिलाओं ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। चाहे वे क्षेत्र शिक्षा का हो या लैंगिक समानता का, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो या गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय महिलाओं ने रैलियों द्वारा, हड़तालों में भाग लेकर, प्रदर्शन करके, सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर हरसंभव कोशिशों से, कठिन-से-कठिन परिस्थितियों का सामना किया है।

महिला आंदोलनों के साथ-साथ सरकार भी महिलाओं के संदर्भ में प्रगतिशीलता के पथ पर आगे ही बढ़ी है, किसी रूढ़िवादिता के मार्ग पर चलकर पीछे नहीं लौटी है। हां, पितृसत्तात्मक प्रभुता को बनाए रखने वाली इकाइयों, यथा परिवार और समाज के स्तर पर यदि सरकारी प्रयासों से कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो पाए तो महिलाओं के लिए जेंडर समानता और विकास दोनों के द्वार खुल जाएंगे।

### संदर्भ-ग्रंथ: .

1. शर्मा, वीरेंद्र प्रकाश. “भारतीय समाज में नारी”, पंचशील प्रकाशन, जयपुर.2017
2. शर्मा प्रज्ञा “महिला विकास और सशक्तिकरण”. आविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर.2009
3. चौरसिया, भानु प्रताप “भारत में महिलाओं की स्थिति : नीतियों और कार्यक्रम”. चुग प्रकाशन.2007
4. कुमार,राधा, “स्त्री संघर्ष का इतिहास”1800-1990, काशी प्रकाशन,नई दिल्ली,2004
5. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनीलोकनीता, “नारीवादी राजनीति : संघर्ष एवं मुद्दे”, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय,2001
6. दीपाबिष्ट, “नारी सशक्तिकरण के सोपान”, अंकित प्रकाशन,नई दिल्ली,2009
7. डॉ० गोपाजोशी, “ भारत में स्त्री और असमानता ” एक विमर्श, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली,2006

## प्रगतिशील लेखक संघ और युगीन चेतना से सरोकार

ऋषिकेश कुमार

शोधार्थी, हिंदी विभाग

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

### शोध सार :

प्रगतिशील लेखक संघ (1936) भारतीय साहित्यिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्भव औपनिवेशिक शोषण, सामाजिक विषमता और वैश्विक स्तर पर उभरती समाजवादी विचारधाराओं की पृष्ठभूमि में हुआ। इसने साहित्य को केवल सौंदर्यबोध का माध्यम न मानकर उसे सामाजिक परिवर्तन के औजार के रूप में स्थापित किया। उस समय देश भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तीव्र चरण से गुजर रहा था, जिसमें आर्थिक शोषण, जातिगत भेदभाव और सांप्रदायिक तनाव जैसी समस्याएँ व्यापक थीं। निस्संदेह, वर्ग-संघर्ष और सामाजिक समानता के विचारों में मार्क्सवादी प्रभाव उपस्थित था, परंतु भारतीय संदर्भ में इसे सीधे आयातित रूप में नहीं अपनाया गया। यहाँ की बहुस्तरीय सामाजिक संरचना—विशेषकर जाति व्यवस्था—ने इसे विशिष्ट रूप दिया। अतः प्रगतिशील लेखक संघ न तो शुद्ध रूप से पश्चिमी विचारधारा की उपज था, न ही केवल वैचारिक आयात; बल्कि यह भारतीय समाज की अंतर्विरोधी परिस्थितियों से उपजा एक सृजनात्मक आंदोलन था, जिसने मार्क्सवादी दृष्टि को भारतीय यथार्थ के अनुरूप ढालकर एक नई साहित्यिक दिशा दी

**बीज शब्द:** समाजवाद, मार्क्सवाद, स्वतंत्रता, मध्यवर्ग, संस्थागत साहित्य, प्रतिबद्ध, सामाजिक अंतर्विरोध, सामंती मानसिकता, सर्वहारा, साम्प्रदायिक, सरलीकरण।

### प्रस्तावना :

‘प्रगतिशील लेखक संघ’ की स्थापना 10 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुई थी। इसकी स्थापना की प्रेरणा वर्ष 1934 में गोर्की के नेतृत्व में स्थापित सोवियत लेखक संघ और 1934 में हेनरी बारबुज के नेतृत्व में आयोजित विश्व लेखक अधिवेशन से मिली। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 1935 में समाजवादी विचारधारा के कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों ने लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ बनाने का निर्णय लिया, इसको कार्यान्वित करने का दायित्व सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद को सोपा

गया था। मुल्कराज आनंद अध्यक्ष चुने गए और सज्जाद जहीर सेक्रेटरी। इस बैठक में घोषणा पत्र तैयार किया गया और घोषणा पत्र की प्रतियां हिंदुस्तान के सभी प्रमुख लेखकों और संपादकों के पास भेजी गईं। मुंशी प्रेमचंद इन गतिविधियों को बहुत नजदीक से देख रहे थे और पूरी हमदर्दी दे रहे थे साथ ही साथ हंस के माध्यम से इस लेखक संघ के उद्देश्यों को प्रचारित भी कर रहे थे। उन्होंने जनवरी 1936 के हंस में लंदन में बने प्रगतिशील लेखक संघ की घोषणा पत्र का सारांश प्रकाशित किया। किन्तु इतने भर से प्रगतिशील लेखक संघ की शुरुआत नहीं होती है। यह एक पूर्ण रूपेण आयातित विचार पद्धति नहीं है इसके सृजन में तत्कालीन भारतीय पृष्ठभूमि का भी महत्वपूर्ण अवदान है। इसलिए राम विलास शर्मा कहते हैं कि : “जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है!”<sup>19</sup> अतः प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना तभी सार्थक हो सकती थी जब वह भारतीय संस्कार से उत्पन्न हो।

विदेशी दासता और सामंती जुए के नीचे छटपटाती भारत की उत्पीड़ित जनता सन् 30 के बाद संघर्ष के जिस दौर से गुजर रही थी, उसमें प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का संगठित होना स्वाभाविक था। लेखकों को संगठित करने का प्रयास ‘हिंदी साहित्य सम्मेलन’ की ओर से भी हो रहा था। उद्देश्य विशेष को लेकर लेखकों का संगठन कोई नई बात नहीं थी, आधुनिक हिंदी साहित्य में देश की परिस्थितियां जब जब संक्रमण के दौर से गुजरी हैं इस तरह के संगठन की बात हुई है; स्वतंत्रता के मूल्यों से बद्ध होकर सन् 57 के क्रांति के बाद भारतेन्दु मंडल की स्थापना हो या बीसवीं शताब्दी के आरंभ में द्विवेदी मंडल की स्थापना हो। इसी तरह 1930 के बाद देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में कई तरह के बदलाव महसूस किए जा रहे थे जिसका एक स्वाभाविक प्रस्फुटन वर्ष 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के रूप में हुआ। साहित्यिक परिवर्तन की बात करें तो यह भी प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से आगामी प्रगतिशील साहित्य के आने की सूचना दे रहा था। हिंदी के व्यक्तिवादी और मध्यवर्गीय साहित्यकार; किसान, मजदूर और स्त्रियों के प्रति गहरा लगाव महसूस कर रहे थे। इसको देखते हुए ही दिनकर ने कहा था कि “पुराने और नए स्कूल के प्रतिनिधियों के बीच का संघर्ष 1928 में मुखर रूप ले चुका था।”<sup>20</sup> उग्र के चॉकलेट के यथार्थवाद को घासलेटी साहित्य कह एक आंदोलन चलाया जाना इसी विभाजन का उदाहरण है। वर्ष 1929 में साहित्य सम्मेलन के पदाधिकारियों के चुनाव में नई पीढ़ी के प्रतिनिधियों की विजय होती है। गणेश शंकर विद्यार्थी अध्यक्ष और रामवृक्ष बेनीपुरी प्रचार मंत्री चुने जाते हैं। इस नवीन सक्रिय युवा भागीदारी का ही परिणाम था कि ब्रिटिश हुकूमत ने सन् 1932 में

<sup>19</sup> शर्मा, रामविलास, परंपरा का मूल्यांकन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ 9

<sup>20</sup> शर्मा, रामविलास, परंपरा का मूल्यांकन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ 9

जागरण और हंस से जमानत वसूल करती है, क्योंकि इनमें सामाजवाद, जनजागरण, किसानों की मुक्ति स्वाधीनता की बातें की जा रही थीं। राजद्रोह कानून के अंदर 1930-1934 के बीच 348 समाचारपत्रों के प्रकाशन बंद कर दिए गए।<sup>21</sup> इस बात को जागरण में प्रेमचंद लिखते हैं “लेकिन यहां इतना कह देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि ऐसे वातावरण में जबकि हर एक संपादक के सर पर तलवार लटक रही हो राष्ट्र का सच्चा राजनीतिक विकास नहीं हो सकता।”<sup>22</sup> इसके बाद स्वयं प्रेमचंद एक लेखक संघ की जरूरत महसूस करने लगे। 1934 में प्रेमचंद ने रामचंद्र टंडन के साथ मिल कर एक लेखक संघ बनाने की योजना बनाई जिसके लिए राम नरेश त्रिपाठी, किशोरीदास दास वाजपेई और प्रेमचंद संयोजक बनाए गए, परन्तु आपसी मनमुटाव से यह संगठन नहीं बन पाया।

इस बीच प्रगतिशील चेतना की साहित्यिक रचना भी तेजी से हो रही थी। यहां स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रगतिशीलता से अभिप्राय रुढ़ियों के विरुद्ध आवाज और पद दलित वर्गों की आवाजों को साहित्यिक स्वर देने से है। इस संदर्भ में निराला की वह तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, शक्तिपूजा और प्रसाद का ध्रुवस्वामिनी नाटक, कामायनी और महादेवी के गद्य महत्वपूर्ण हैं। रामचंद्र शुक्ल भले ही मार्क्सवादी साहित्य की व्यंग्यात्मक अवहेलना अपने इतिहास ग्रंथ में करते हैं परन्तु संवेदना के स्तर पर उनका लोकमंगल मार्क्सवादी साहित्य के सर्वहारा सिद्धांत के अनुकूल ही है।

देश के राजनीतिक वातावरण को देखा जाए तो, वर्ष 1934 में ‘हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी’ को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सारी पार्टी को भूमिगत होना पड़ा। इसके अधिकांश कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के भीतर ही 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की और लखनऊ से संघर्ष नामक पत्र निकालने का निर्णय लिया। हालांकि इसका प्रकाशन 1936 से ही शुरू हुआ। दूसरी ओर 1936 के कांग्रेस अधिवेशन का सभापतित्व महात्मा गांधी के हाथ में जाना था किन्तु जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जिनका रुझान समाजवादी विचारधारा के प्रति स्पष्ट रूप से था। अतः देश के राजनीतिक और साहित्यिक नेतृत्व का प्रगतिशील रूपांतरण अत्यंत जैविक रूप से हो रहा था; यह कोई यांत्रिक बदलाव नहीं था। जिसको लेकर पट्टाभि सीतारमैया लिखते हैं कि : “हर जगह नौजवानों में समाजवादी विचारधारा हावी हो रही थी। छात्र फेडरेशन और युवकों की लहर जोर पकड़ रही थी।”<sup>23</sup> सत्य अहिंसा की कार्यनीति पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा था जिसका उदाहरण कामायनी और

<sup>21</sup> अवस्थी, रेखा, प्रगतिवाद और समानांतर साहित्य, राजमकल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 22

<sup>22</sup> वही, पृष्ठ 24

<sup>23</sup> वही, पृष्ठ 09

राम की शक्तिपूजा दोनों में हिंसा और अहिंसा के द्वंद्व के रूप में सामयिक स्थितियों का साहित्यिक रूपांतरण के रूप में मिल जाता है।

देश में बलवती होती सांप्रदायिक स्थितियों ने भी प्रगतिशील मंच की आवश्यकता को और तेज किया। एक तरफ हिंदी और उर्दू के विभाजन के कारण देश में भाषा का सांप्रदायिककरण जोरों से हो रहा था, महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद और प्रेमचंद जहां हिन्दुस्तानी के पक्षधर थे वहीं मदन मोहन मालवीय विशुद्ध हिंदी के। इसके साथ ही साथ गोलमेज सम्मेलन के बाद अलग अलग प्रतिनिधित्व के कारण धार्मिक और जातीय विभाजन से देश में हलचल थी। अतः इन स्थितियों में दर्शन और वेदांत के सहारे समस्याओं का हल नहीं ढूंढा जा सकता था, इस बात का पहले-पहले अनुभव दर्शनिक छायावादी कवियों ने ही किया। प्रेमचंद के साहित्यिक और संस्थागत प्रयोग से इस बात को और बल मिला। प्रेमचंद ने हिन्दुस्तानी एकेडमी द्वारा किए जा रहे हिंदी - उर्दू एकता के प्रयासों का अनुमोदन कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई।

इसकी स्थापना भी एक सरलीकरण के रूप में हमें बता दिया जाता है जो है नहीं। संघ के बनने की कहानी अत्यंत जटिल है। लंदन के एक रेस्तरां से शुरू हुई कहानी लखनऊ में आकर पूरी होती है। मुल्कराजआनंद और सज्जाद ज़हीर ने भारत में प्रेमचंद से संपर्क किया और प्रेमचंद ने उनको अपना समर्थन दिया। प्रेमचंद के साथ फिराक गोरखपुरी, दया नारायण निगम, जोश महिलाबादी और अहमद अली ने संघ के ड्राफ्ट मेनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया, इस प्रकार प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। शिवदान सिंह चौहान के अनुसार तो इसके ड्राफ्ट मेनिफेस्टो पर निराला और पंत ने भी हस्ताक्षर किया था।<sup>24</sup>

प्रगतिशील लेखक संघ मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। अपने स्थापना के साथ इसने कुछ मूल्य और सिद्धांत निर्धारित किए जिसके आधार पर सोदेश्य साहित्य की रचना हो सके। इस आलोक में हमें दो बातों को ध्यान रखना चाहिए कि संघ को आधिकारिक उद्देश्य क्या थे? और प्रेमचंद का अध्यक्षीय भाषण क्या था? सर्व प्रथम प्रेमचंद के वक्तव्य की चर्चा करते हैं - प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है। यानी साहित्य का उद्देश्य पश्च की संस्कृति खड़ी करना है जिससे मानवीयता को और सुदृढ़ किया जा सके। इसी बात कि दूसरी कड़ी है ‘ प्रगतिशील नाम ही गलत है, साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है।’ प्रेमचंद का यह कथन निश्चित रूप से साहित्यकार की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और उसे किसी संस्था की कठपुतली बनने से रोकता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि ‘ हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी वह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी !’ चौथी बात साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि

<sup>24</sup> सीतारमैया, पद्मिनि, दि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, खंड 2, पद्म प्रकाशन, मुंबई, 1947, पृष्ठ 423

राजनीति के आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद के वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने साहित्य को जागरण के अर्थ में लिया और संस्था का उद्देश्य भी किसी खास विचारधारा के साथ प्रतिबद्धता में ना मान कर लोक के साथ कदमताल करके चलने में स्वीकार किया है।<sup>25</sup>

अब हम प्रगतिशील लेखक संघ के उद्देश्य की चर्चा करते हैं जिसे 1936 में प्रकाशित किया गया था, वे हैं - 1. भारत के तमाम प्रगतिशील लेखकों की संस्थाएं संगठित करना और साहित्य छापकर अपने उद्देश्यों का प्रचार करना। 2. प्रगतिशील लेखकों और अनुवादकों को प्रोत्साहित करना और प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करके देशवासियों के स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाना। 3. स्वतंत्रता और स्वतंत्र विचार की रक्षा करना।<sup>26</sup>

प्रथम दृष्टया ये विचार अत्यंत प्रभावशाली लगते हैं जिसका प्रभाव तत्कालीन महत्वपूर्ण लेखकों पर हुआ भी, जैसे पीसी जोशी और सज्जाद जाहिर के अनुरोध पर सुमित्रानंदन पंत 1936 में संघ में शामिल हो गए। प्रेमचंद ने तो हंस को संघ के लिए ही समर्पित कर दिया। किन्तु संस्थागत साहित्य कैसा भी हो उसमें रूढ़ियों का आगमन हो ही जाता है जो भारतेन्दु मंडल में भी देखा गया और द्विवेदी मंडल में भी। विचारधारा के प्रति अत्यधिक समर्पण और कलात्मक प्रयोग में शुष्कता के कारण प्रगतिशील साहित्य संघ को अगले पंद्रह वर्षों तक अत्यधिक रचनात्मक सफलता नहीं मिली। जब उन्हें आलोचक के रूप में राम विलास शर्मा और कृतिकार के रूप में केदारनाथ अग्रवाल तथा नागार्जुन मिले तब उसका वास्तविक रचनात्मक प्रस्फुटन होता है। क्योंकि इन दोनों साहित्यकारों ने संघ को भारतीय संस्करण का दर्शन करवाया। इस तत्व पर बल दिया कि यह सिर्फ मार्क्स के सिद्धांतों के सहारे भारतीय संवेदना को नहीं धारण कर सकता है अपितु इसे सरहपा, कबीर, तुलसी, भारतेन्दु और निराला के चिंतन के साथ भी तादात्म्य स्थापित करना होगा।

हालांकि वर्ष 1936 में प्रगतिशील साहित्य की स्थापना साहित्यिक संवेदना में हो रहे अपूर्व बदलाव की सूचना देता है। यह वर्ष 1936 के प्रतिनिधि साहित्यकारों के भांति ही संस्था के रूप में सम्राज्यवादी और सामंतवादी विरोधी साहित्यिक हस्तियों को संस्थागत संबल देता है। भारत के लिए इसे स्वजातीय घोषित करती हुई रेखा अवस्थी लिखती हैं कि : “प्रगतिशीलता की भावना का उद्भव हिंदुस्तान की अपनी परिस्थितियां, जन आंदोलनों, ब्रिटिश हुकूमत के दमन चक्र के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता और समाजवादी विचारधारा के तेजी से प्रसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के विरुद्ध व्यापक रूप से फैले हुए जनाक्रोश आदि कारणों से हुआ। 1929 के बाद हिंदुस्तान की परिस्थितियों में

<sup>25</sup> अवस्थी, रेखा, प्रगतिवाद और समानांतर साहित्य, राजमकल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 27

<sup>26</sup> वही, पृष्ठ 72

और जनता की आत्मचेतना में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे थे।”<sup>27</sup> रामवृक्ष बेनीपुरी भी इसे भारतीय परिस्थितियों से उत्पन्न मानते हैं “छायावाद का जन्म 1921 की राजनीतिक पराजय की पृष्ठभूमि में हुआ था। 1934 में किसानों और मजदूरों का जो व्यापक आंदोलन हुआ, उसके कोलाहलों में प्रगतिवाद का जन्म हुआ।”<sup>28</sup> अतः प्रगतिशील लेखक संघ अपने उद्देश्य में राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुकूल ही था, उसकी स्थापना भी युगीन स्थितियों के अनुरूप हुई थी। हाँ संघ के तरीकों से साहित्य को हत होने की संभावना थी। समाजवादी अनुगूँज भारतीय राजनीति में भी दिखाई पड़ रहा था, जैसे जहाँ एक तरफ़ सविनय अवज्ञा आंदोलन विफल रहा वही शोलापुर में एक लाख चालीस हजार निवासियों ने जिसमें 40 हजार सूती मजदूर थे, शहर पर कब्जा कर लिया। पुलिस के बदले मजदूरों ने अपना राज कायम किया।<sup>29</sup> इस तरह प्रगतिशील लेखक संघ मजदूर और किसानों में उत्पन्न व्यवस्था के प्रति रोष और उनकी सक्रिय सहभागिता के मनोवृत्ति का वाहक था।

प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना (1936) हिंदी साहित्य के इतिहास में किसी आकस्मिक वैचारिक हस्तक्षेप के रूप में नहीं, बल्कि साहित्य के भीतर लंबे समय से विकसित हो रहे स्वाभाविक रुझानों की संगठित अभिव्यक्ति के रूप में समझी जानी चाहिए। यह संस्था न तो बाहर से आयातित विचारधारा का परिणाम थी और न ही केवल राजनीतिक आंदोलनों की अनुकृति; बल्कि यह उस ऐतिहासिक स्थिति की उपज थी जहाँ साहित्य, समाज और स्वतंत्रता संघर्ष एक-दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते थे। प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा-पत्र में साहित्य को सामाजिक यथार्थ, वर्ग-संघर्ष और मानवीय मुक्ति से जोड़ने की बात कही गई। यह वही दृष्टि थी जो गोदान, कफ़न, युगांत, राम की शक्तिपूजा और कामायनी जैसी कृतियों में पहले से सक्रिय थी। अंतर केवल इतना था कि जो आलोचनात्मक चेतना अब तक व्यक्तिगत रचनात्मक स्तर पर प्रकट हो रही थी, उसे 1936 में एक सामूहिक और संगठित वैचारिक मंच प्राप्त हो गया। इस अर्थ में प्रगतिशील लेखक संघ ने हिंदी साहित्य की अंतर्निहित प्रवृत्तियों को नाम, भाषा और कार्यक्रम दिया। अतः प्रगतिशील लेखक संघ मानो पहले से मौजूद दस्तावेजों पर सरकारी मुहर सा था। यानी जो विचारधारा उपरोक्त साहित्यकारों के कृतियों में विद्यमान था, उन पर समाजवादी विशेषण की मुहर लगाना के अर्थ में ही प्रगतिशील लेखक संघ को लेना चाहिए। उसने उस वक्त नवीन साहित्यिक धारा को बस एक राजनीतिक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया अन्यथा यह भी उन्ही सामाजिक उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहा था जिससे स्वर्णिम साहित्य की सृजना होती है।

<sup>27</sup> वही, पृष्ठ 73

<sup>28</sup> वही, पृष्ठ 36

<sup>29</sup> दत्त, पाम रजनी, आज का भारत, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 2015, पृष्ठ 355

यदि प्रतिबद्धता की अतिशयता को अगर किनारे कर दिया जाए तो प्रगतिशील लेखक संघ ने सामाजिक अंतर्विरोध को साहित्य का केंद्रीय विमर्श बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जिन प्रश्नों से कांग्रेस बच रही थी उन अंतर्विरोध को आगे बढ़ाने में संघ की बड़ी भूमिका रही है। तत्कालीन राजनीति की सहज जटिलता ने आम जन को जिस दुश्चक्र में फँसा रखा था उसका सहज भंडाफोड़ प्रगतिशील लेखक संघ करता है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रगतिशील लेखक संघ का राष्ट्रवाद भावनात्मक या सांस्कृतिक गर्व तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से जुड़ा हुआ था। रूस की समाजवादी क्रांति, यूरोपीय यथार्थवाद और उपनिवेश-विरोधी आंदोलनों का प्रभाव उसके चिंतन में दिखाई देता है। फिर भी, यह प्रभाव भारतीय यथार्थ के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। किसान आंदोलन, मजदूर संघर्ष, स्त्री प्रश्न और दलित चेतना—ये सभी स्वतंत्रता संघर्ष के भीतर उभर रहे वे मुद्दे थे, जिन्हें मुख्यधारा की राजनीति अक्सर हाशिए पर रख देती थी। प्रगतिशील लेखक संघ ने साहित्य के माध्यम से इन्हें केंद्र में लाने का कार्य किया।

इस प्रकार प्रगतिशील लेखक संघ को स्वतंत्रता आंदोलन का वैचारिक अनुचर नहीं, बल्कि उसका आलोचनात्मक सहयात्री कहा जा सकता है। इसने समतामूलक साहित्य के सृजन हेतु ईंधन रूपी संस्थागत सहयोग और वैचारिक दृढ़ता दी। प्रगतिशील लेखन संघ के उत्पत्ति की स्वाभाविकता पर प्रकाश डालते हुए रेखा गुप्ता लिखती हैं कि “प्रगतिशीलता की भावना का उद्भव हिंदुस्तान की अपनी परिस्थितियों, जन आंदोलनों, ब्रिटिश हुकूमतों के दमनचक्र के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता और समाजवादी विचारधारा के विरुद्ध तेजी से प्रसार, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के हनन के विरुद्ध व्यापक रूप से फैले हुए जन आक्रोश आदि करणी से हुआ। 1929 के बाद हिन्दुस्तान की परिस्थितियों में और जानता की आत्मघात चेतना में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे थे।”<sup>30</sup> उपरोक्त विवेचन से हमें युगीन स्थिति की जानकारी मिलती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि मार्क्स के सिद्धांतों का साहित्यिक निरूपण होते हुए भी प्रगतिशील लेखक संघ भारत की परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार गठित हुआ था न कि कोई आयातित वस्तु के रूप में। इसने तत्कालीन साहित्य में नवीन ऊर्जा का भी प्रसार किया जिससे वर्षों से शोषित और पीड़ित वर्ग साहित्य के केंद्र में आ जाते हैं।

<sup>30</sup> अवस्थी, रेखा, प्रगतिवाद और समानांतर साहित्य, राजमकल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 36

## Challenges and Problems of Construction Workers: A Study in Visakhapatnam

**Dr. N. Komali Salomi**

Assistant Professor, Department of  
Social Work, Andhra University

**Dr. P. Ravi Ratna Prakasa Rao**

Assistant Professor, Department of  
Sociology, Andhra University

---

### ABSTRACT

Construction Workers are one of the labour force sectors in India who make a development through infrastructure development. The present study analyse the socio-economic and demographic characteristics, working conditions, occupational health concerns, and level of awareness regarding welfare measures among construction workers in Visakhapatnam city. The study is based on a quantitative research approach and follows a descriptive research design. Primary data were collected from a sample of 64 construction workers through a purposive sampling technique, using a structured interview schedule as the main tool of data collection. The study found that majority of the respondents has low level of education. The majority of the workers are engaged in daily wage labour, characterised by low and irregular income patterns. The study also found that a low level of awareness among workers regarding available welfare schemes and social security provisions. In terms of working conditions, the study reveals several inadequacies, including extended working hours, lack of protective and safety equipment, insufficient basic amenities at worksites, and restricted access to healthcare facilities. A considerable number of workers reported experiencing

occupational health issues and workplace-related accidents, reflecting the hazardous nature of their work environment.

**Keywords:** Construction Workers, Informal Sector, Occupational Health, Working Conditions, Welfare Schemes

## Introduction

Construction workers are individuals engaged in various activities related to the construction, repair, maintenance, and demolition of infrastructure such as buildings, roads, bridges, and other physical structures. They form the backbone of the construction industry and contribute significantly to economic development by creating essential infrastructure facilities (Kantharia & Yadav, 2024). The construction workforce typically includes workers performing different roles such as manual labourers, technicians, electricians, masons, carpenters, and other skilled or semi-skilled personnel involved in construction activities (Bajracharya et al., 2023). According to the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (BOCW Act), A construction worker is defined as any person engaged in skilled, semi-skilled, or unskilled manual, supervisory, technical, or clerical work in connection with building or construction activities, excluding those in managerial or administrative roles (Poornamathi & Marish Kumaran, 2025) Additionally, construction workers can be categorized into four types: Unskilled workers, Semi-skilled workers, Skilled workers, Highly skilled workers based on their level of training, experience, and expertise (Bharawala, 2023).

The construction industry employs approximately 31 million workers, making it the second-largest employer after agriculture (Bharawala, 2023). Other studies estimate that the workforce is even larger, with nearly 50 million workers engaged in construction activities (Poornamathi & Marish Kumaran, 2025). According to NSSO estimates, about 5 crore (50 million) workers are involved in construction work, accounting for around 10% of India’s total workforce (Poornamathi & Marish Kumaran, 2025). Approximately 80–90% of construction workers are

employed in the informal sector, lacking job security and social protection (Poornamathi & Marish Kumaran, 2025). The sector provides employment to more than 49.5 million people and is a major source of livelihood for migrant and economically weaker populations (Roopa, 2015). Nearly 7.5% of the global workforce is part of the Indian construction labour force, indicating its global significance (Bharawala, 2023). A significant proportion of workers are migrants, with studies showing over 60% of construction workers migrate from rural to urban areas in search of employment (Bharawala, 2023). Less than 10% of workers receive formal training, which contributes to safety risks and low productivity (Poornamathi & Marish Kumaran, 2025).

Construction workers in India represent a vast and diverse labour force that plays a critical role in national development. Despite their significant contribution, the majority of workers remain in the informal sector, facing issues such as lack of training, job insecurity, and poor working conditions. The statistics highlight both the scale of employment and the vulnerabilities associated with this sector, emphasizing the need for stronger policy implementation and worker welfare measures.

### **Review of Literature**

Bharawala (2023), in the study titled “*A Study Highlighting Macro Issues of the Construction Workers in Indore (The Cleanest Indian City)*”, conducted in Indore, Madhya Pradesh, aimed to examine the various physical, psychological, and economic problems faced by construction workers. The study employed a quantitative research design using survey methods and personal interviews with around 100 construction workers. The objective was to analyse workers’ living conditions, work environment, and socio-economic challenges. The findings revealed that a majority of workers were migrants, lacked proper training, and were not provided with adequate safety equipment such as PPE kits.

Poornamathi N.C. and Marish Kumaran C.M. (2025), in their study “*A Critical Analysis of Problems Faced by Building and Other Construction Workers in India*”, examined the structural and legal challenges faced by construction workers across India. The study primarily adopted a descriptive and analytical approach based on secondary data and legal frameworks. The objective was to analyse issues such as job insecurity, lack of social security, unsafe working conditions, and inadequate enforcement of labour laws. The findings indicated that nearly 80–90% of construction workers are part of the informal sector, with minimal access to healthcare, insurance, and welfare benefits.

Kantharia and Yadav (2024), in the study “*A Study on Challenges Faced by Workers in Construction Field*”, conducted across various regions, aimed to explore the diverse challenges affecting construction workers and their impact on well-being and productivity. The study used a mixed-methods approach, combining quantitative surveys and qualitative interviews. The objectives included identifying challenges, understanding their root causes, and assessing their impact on workers’ mental and physical health. The findings revealed that construction workers face severe safety hazards, long working hours, inadequate training, low wages, and job insecurity.

Dr. Roopa K. (2015), in the study “*Issues and Challenges of Construction Industry Workers*” conducted in Mangalore, Karnataka, aimed to analyse the socio-economic conditions and challenges of construction workers. The study used qualitative methods, including interpretative phenomenological analysis and semi-structured interviews. The objectives were to highlight the characteristics, trends, and issues of construction labour. The findings showed that most workers come from poor, illiterate, and migrant backgrounds, with unstable employment and lack of training. The study also identified industry-level challenges such as material shortages, poor management, lack of safety measures, and inadequate labour policies, which negatively affect workers’ livelihoods and working conditions.

Bajracharya et al. (2023), in their review article “*Occupational Health and Safety Issues in the Construction Industry in South Asia*”, examined the status of occupational health and safety among construction workers in South Asian countries, including India, Nepal, and Bangladesh. The study adopted a systematic review methodology using secondary data sources. The objective was to identify key occupational hazards and suggest improvements. The findings revealed that construction workers are exposed to high levels of risk, including accidents, respiratory diseases, and musculoskeletal disorders, due to poor working conditions, lack of awareness, and inadequate safety training.

The reviewed studies collectively highlight that construction workers in India and South Asia are predominantly part of the informal sector and face multiple interrelated challenges, including unsafe working conditions, lack of training, job insecurity, and inadequate access to social security benefits. Across different geographical contexts such as Indore and Mangalore, workers are largely migrants from economically weaker backgrounds, experiencing poor living conditions and limited welfare support. The literature consistently emphasizes occupational health risks, including accidents, respiratory issues, and physical strain, primarily due to the absence of proper safety measures and enforcement of labour laws.

### **Research Gap**

Although existing studies have extensively documented the problems faced by construction workers, there are several notable gaps. Most studies focus broadly on challenges at a national or regional level, with limited in-depth analysis at the micro or local level. There is a lack of empirical research examining the socio-economic conditions and lived experiences of construction workers in specific regions or cities. Additionally, few studies integrate both socio-demographic variables and occupational factors to understand their combined impact on workers’ well-being. There is also limited focus on evaluating the effectiveness of existing welfare schemes and policies from the perspective of the workers themselves.

## **Need for the Study**

The construction sector is one of the largest employment generators in India, yet the workers remain one of the most vulnerable groups. Given the persistent issues of poor working conditions, lack of safety, and inadequate welfare measures, there is a pressing need to conduct focused research to understand the real-life problems faced by construction workers. Such a study is essential to generate region-specific data, assess the effectiveness of existing policies, and identify gaps in implementation. Understanding these aspects will help policymakers, social workers, and stakeholders design targeted interventions to improve the living and working conditions of construction workers.

## **Objectives of the Study**

1. To study the socio-economic and demographic profile of construction workers.
2. To examine the working conditions and occupational health issues faced by construction workers.
3. To analyse the socio-economic factors influencing the well-being of construction workers.
4. To assess the availability and awareness of welfare measures and social security schemes among construction workers.
5. To provide the suggestions to improve working conditions of construction workers.

## **Research Methodology**

The present study adopts a quantitative research approach to systematically examine the socio-economic conditions, working environment, and challenges faced by construction workers. A descriptive research design is employed to provide a detailed account of the characteristics and issues experienced by the respondents without manipulating any variables. The study is based on primary data collected from a sample of 64 construction workers in Visakhapatnam city selected through purposive sampling. An interview schedule was used as the main

tool for data collection, consisting of structured questions to gather information on demographic profile, working conditions, health issues, and awareness of welfare measures. The collected data were organized, tabulated, and analysed using simple statistical techniques such as frequency and percentage to draw meaningful conclusions.

### Results and Discussion

**Age:** The study found that the majority of the respondents in this study are belonging to 26–45 years age group accounting for nearly 59.3% of the sample. Followed by the 18-25 years age people have also demand to because they will fast than the other groups.

**Table 1: Distribution of the respondents by their Education**

Education	Frequency	Percentage
Illiterate	18	28.1%
Primary	20	31.2%
Secondary	16	25.0%
Higher Secondary	8	12.5%
Graduate	2	3.2%
Total	64	100%

The data in the table 1 show that the significant proportion of construction workers possess low levels of education, with nearly 59.3% being either illiterate or having only primary education. Secondary and higher secondary respondents represented 37.5%. It indicated that the low education people may work in the construction industry.

**Working hours:** The study found that a majority (78.1%) of workers are engaged in work beyond the standard 8-hour workday, with 25% working more than 10 hours daily. This is very difficult to work that much hours in the construction industries which may lead to fatigue, reduced productivity, and increased risk of occupational hazards.

**Monthly Income:** The income distribution reveals that the majority of construction workers earn between ₹18000 - ₹21000 per month, indicating modest and unstable earnings. A significant proportion (34.4%) earns below ₹18000, highlighting economic vulnerability. As we know that the low income levels directly affect their living standards, access to healthcare, and overall well-being.

**Nature of employment:** the study found that a majority (59.4%) of construction workers are employed on a daily wage basis, followed by a small proportion (12.5%) of the respondents has yearly bond. Most of the time the rural youth who are not in a position to complete their education may become construction workers in house construction industry.

**Table 2: Availability of Safety Equipment (PPE)**

Availability of PPE	Frequency	Percentage
Yes	18	28.1%
No	46	71.9%
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>

The table 2 reveals that a significant majority (71.9%) of workers do not have access to safety equipment at their workplace. This lack of protective measures increases the risk of accidents and occupational injuries. This occupation is included with lots of risks because they work on the higher buildings.

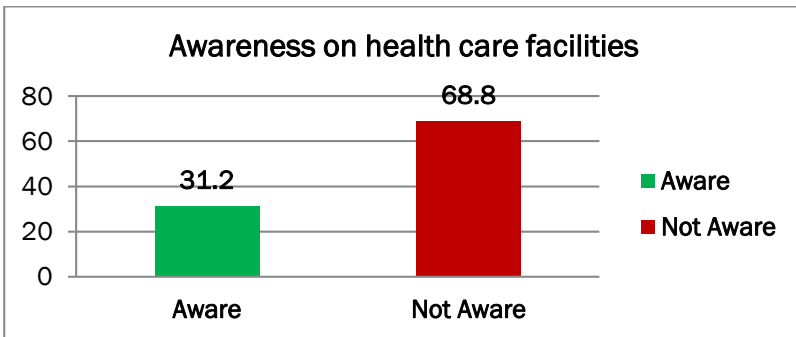
**Availability of Basic Facilities at Worksite:** The study found that the majority (68.8%) of the respondents reported inadequate basic facilities such as drinking water, sanitation, and rest areas at worksites. This reflects poor working conditions and neglect of workers’ basic needs, which may adversely affect their health, hygiene, and overall well-being. This finding is inline with the study of K. P. Kannan (2018) who reported that the informal sector workers, especially in construction, often work under conditions where basic facilities are either inadequate or completely absent, reflecting systemic neglect of labour welfare

provisions. Similarly, S. K. Panda (2015) reported that lack of sanitation, drinking water, and rest shelters at construction sites is a widespread issue in India, significantly impacting workers’ health and hygiene.

The problem faced by construction workers: the study found that low wages (25%) and job insecurity (21.9%) are the most significant problems faced by construction workers. Health issues and poor living conditions are also notable problems of the respondents. This indicates that workers face multiple overlapping challenges, both economic and occupational, which collectively impact their overall well-being. The study is inline with the study of Mopeli & Abraham, 2022 who reported that the homeless population involved in the unorganised sector may get health problems. Similarly, R. K. Srivastava (2016) emphasized that informal construction workers face chronic job insecurity and low wages due to the absence of formal contracts and regulatory protection. In another study, K. N. Vaid (2014) highlighted that unsafe working conditions and lack of protective measures significantly contribute to occupational hazards in the construction industry.

Access to Medical Facilities: **the study found that a** majority (65.6%) of workers reported not having access to medical facilities in the work place, indicating serious gaps in healthcare support for construction labourers.

**Figure 1: Awareness on Welfare Schemes**



The figure indicates that a majority (68.8%) of construction workers are unaware of welfare schemes and social security benefits available to them. Because, majority of the respondents have been migrated from other areas of Andhra Pradesh. They do not have local identification proofs to access government social welfare schemes. This finding is inline with the study of Kumar and Mishra (2019) who reported that more than 60% of construction workers in urban India were unaware of welfare board schemes due to inadequate communication strategies and low literacy levels. Similarly, S. R. Babu (2018) found that poor dissemination of information and lack of proactive engagement by labour department’s significantly contributed to low enrolment in welfare programs. Mehrotra and Sinha (2017), Manas (2018), Mohammed (2018) highlighted that informal sector workers, especially in construction, often remain excluded from social protection due to weak institutional outreach and absence of awareness campaigns. Furthermore, International Labour Organization (2020) also emphasized that lack of awareness is one of the major barriers preventing informal workers from benefiting from social security schemes in developing countries.

**Suggested Measures by Workers:** The study found that the large percentage (28.1%) of the respondents were stated that they need better wages. And (25%) of the respondents stated that they need improved healthcare facilities. Safety measures and job security are also significant concerns of the construction workers. These findings highlight the urgent need for comprehensive interventions by the Non-governmental organisations to address both economic and occupational aspects to enhance workers’ quality of life.

### **Suggestions and recommendations**

The government should strengthen the implementation of existing labour laws such as the Building and Other Construction Workers (BOCW) Act to ensure that workers receive adequate protection and welfare benefits. Regular inspections must be conducted at construction sites to enforce safety standards, including the mandatory provision of personal protective equipment (PPE).

The government should also enhance awareness campaigns regarding welfare schemes, health insurance, and social security benefits, as a large proportion of workers remain unaware of these provisions. Additionally, there is a need to introduce skill development and training programs to improve workers’ competencies and reduce occupational risks. Provision of affordable housing, sanitation facilities, and accessible healthcare services for migrant workers should also be prioritized to improve their quality of life.

NGOs should play a proactive role in bridging the gap between construction workers and welfare services by conducting awareness programs and outreach activities. They can organize health camps, safety training sessions, and workshops to educate workers about occupational hazards and preventive measures.

NGOs should also assist workers in registering for welfare schemes and accessing social security benefits. Furthermore, they can advocate for workers’ rights and collaborate with government agencies to ensure effective implementation of policies. Special focus should be given to migrant workers by providing support services such as legal aid, counselling, and temporary shelter facilities.

Construction workers should be encouraged to actively participate in training programs and awareness initiatives to improve their knowledge of safety practices and available welfare schemes. They should adopt the use of safety equipment consistently to minimize the risk of injuries and health issues. There is a lot of scope for the social workers and corporate companies to provide the basic amenities to the construction workers (Abraham & Rangarao, 2018)

Workers should also take collective efforts, such as forming groups or unions, to voice their concerns and demand better working conditions and fair wages. Additionally, improving personal health practices, including avoiding harmful habits and seeking timely medical care, can contribute to better overall well-being.

## Limitations of the Study

The study is based on a relatively small sample size of 64 respondents, which may limit the generalizability of the results to the larger population of construction workers. The study conducted in Visakhapatnam. The findings of the study are more relevant to the geographical condition of Visakhapatnam city.

## References

1. Abraham, M., & Rao, A. R. (2018). Role of CSR Activities in reduction of poverty in Visakhapatnam: A social work perspective. *International Journal of Reviews and Research in Social Sciences*, 6(4), 405-411.
2. Babu, S. R. (2018). Labour welfare schemes and their implementation challenges in India. *Indian Journal of Labour Economics*, 61(3), 421-435.
3. Bajracharya, N., Magar, P. R., Karki, S., Giri, S., & Khanal, A. (2023). Occupational health and safety issues in the construction industry in South Asia: A systematic review and recommendations for improvement. *Journal of Multidisciplinary Research Advancements*, 1(1), 27-31.
4. Bharawala, S. (2023). A study highlighting macro issues of the construction workers in Indore (the cleanest Indian city). *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 26(5), 1-10.
5. International Labour Organization. (2020). *Extending social security to workers in the informal economy: Lessons from international experience*. Geneva: ILO.
6. Kannan, K. P. (2018). *Labour and employment issues in the informal sector in India*. New Delhi: Oxford University Press.
7. Kantharia, I., & Yadav, K. (2024). A study on challenges faced by workers in construction field. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(4), 8523-8528.

8. Kumar, A., & Mishra, S. (2019). *Awareness and utilization of welfare schemes among construction workers in urban India. International Journal of Social Economics*, 46(5), 654–667.
9. Manas, R. N. (2018). *Problems and Prospects of Informalworkers in Formal Sector: A Study of Migrant Women Construction Workers in Bhubaneswar city, Mahila Pratishtha*, 4 (1), 45-54.
10. Mehrotra, S., & Sinha, S. (2017). *Social security for informal workers in India: Issues and challenges. Economic and Political Weekly*, 52(52), 58–66.
11. Mohammed, I. M. (2018). *Construction workers in Hyderabad: A study on Labour addas, Social security and Awareness among them. Desh Vikas*, 4 (4) 25-36.
12. Mopeli, N. E., & Abraham, M. (2022). *Understanding the psycho-social and health problems faced by homeless population in Visakhapatnam City: An empirical study. Research Journal of Humanities and Social Sciences*, 13(2), 105-112.
13. Panda, S. K. (2015). *Working and living conditions of construction workers in India. Indian Journal of Social Work*, 76(3), 345–360.
14. Poornamathi, N. C., & Marish Kumaran, C. M. (2025). *A critical analysis of problems faced by building and other construction workers in India. Indian Journal of Legal Review*, 5(1), 615–618.
15. Roopa, K. (2015). *Issues and challenges of construction industry workers. International Journal of Research and Analytical Reviews*, 2(2), 179–182.
16. Srivastava, R. K. (2016). *Labour market transitions and conditions of informal workers in India. Indian Journal of Labour Economics*, 59(4), 611–632.
17. Vaid, K. N. (2014). *Occupational safety and health conditions of construction workers in India. International Journal of Occupational Safety and Health*, 4(1), 45–52.

# Social Issues and the Need for Creating Awareness in Contemporary Society

**Tonmoy Pran Bez**

Assistant Professor (Fine Arts)  
Assam down town University

---

## **Abstract:**

Contemporary Indian society is encountering various social challenges that affect the nation's overall development. Some of these issues stem from old traditions and historical factors, while others have emerged due to rapid changes in society, economy, and politics. In this context, raising awareness about these problems is crucial. Social awareness refers to understanding social situations, recognizing others' needs and feelings, and acting with care and responsibility. It fosters better relationships, collaboration, and societal harmony. The government, particularly the Ministry of Social Justice and Empowerment, plays a vital role in formulating policies and programs aimed at supporting marginalized or discriminated individuals.

In addition to the government, non-governmental organizations (NGOs) also contribute significantly by working directly with communities to promote awareness, offer education, and advocate for social change. These groups often focus on areas such as education, health, human rights, and community development. Media and advertising are also effective tools for raising awareness about social issues. Through newspapers, television, and the internet, media can highlight important topics like health, education, gender equality, and environmental protection. Social campaigns and advertisements encourage

---

responsible behavior, while visual tools such as posters help convey clear and impactful messages to a wide audience. Addressing social problems requires not only the efforts of groups and the government but also the actions of individuals. Developing skills such as empathy, effective communication, and understanding diverse backgrounds can enhance personal and collective awareness, leading to a more equitable and peaceful society.

**Keywords:** Social Awareness, Social Issues, NGOs, Media and Communication, Social Advertisements, Diversity, Social Development, Public Awareness.

### **Introduction:**

Modern Indian society is characterized by diversity, swift transformation, and ongoing social challenges. While some issues, such as poverty, illiteracy, gender inequality, and societal discrimination, have deep historical roots, others have emerged due to rapid economic, political and technological changes. These challenges continue to impede inclusive growth and equitable development. India, as a developing nation, faces the dual challenge of managing traditional inequalities alongside modern socio-economic pressures. Access to education, healthcare, employment opportunities and basic services remains uneven across regions and communities. Tackling these concerns requires not only policy interventions but also a strong foundation of social awareness among citizens.

Social awareness involves understanding societal conditions, recognizing inequalities and responding with empathy and responsibility. It is closely associated with emotional intelligence, as it encourages individuals to build respectful relationships, appreciate diversity, and actively contribute to social well-being.

### **Objectives of the Study:**

1. To examine significant social issues affecting contemporary Indian society.
2. To understand the role of social awareness in addressing these challenges.
3. To analyze the contributions of the government, NGOs, and media in spreading awareness.

4. To explore the economic dimensions of social issues and their impact on development.
5. To highlight the importance of collective action in achieving social progress.

### **Methodology:**

This study is based on a descriptive and analytical approach, utilizing secondary sources such as academic literature, policy reports, government documents, and media observations. The analysis focuses on understanding the relationship between social awareness and societal development, while also examining the economic implications of social issues.

### **Understanding Social Awareness:**

Social awareness refers to the ability to understand social realities, recognize the needs of others, and behave responsibly in different situations. It includes empathy, respect for diversity, and the ability to navigate complex social relationships.

### **A socially aware individual is better equipped to:**

- I. Communicate effectively
- II. Respect cultural and social differences
- III. Adapt to diverse environments
- IV. Contribute positively to community life. In a diverse country like India, social awareness plays a crucial role in maintaining harmony and fostering mutual understanding.

### **Major Social Issues in India:**

India continues to face several interconnected social challenges, including:

- I. Poverty and economic inequality
- II. Lack of access to quality education
- III. Gender discrimination and inequality
- IV. Caste-based and social discrimination

V. Limited access to healthcare and basic services. These issues are not isolated; they are deeply linked with structural inequalities and economic disparities, making them complex and difficult to resolve.

### **Economic Perspective on Social Issues:**

Social issues in India have a strong economic dimension. Poverty, unemployment, and unequal distribution of resources directly affect social stability and development.

**Poverty and Inequality:** Economic disparities lead to unequal access to opportunities, reinforcing social divisions.

**Education and Employment:** Lack of education reduces employability, which in turn affects income levels and economic mobility.

**Gender Inequality:** When women are excluded from education and employment, it reduces overall economic productivity.

**Healthcare Access:** Poor health infrastructure impacts workforce efficiency and increases economic burdens on families.

Thus, social issues are not only moral or cultural concerns but also significant barriers to economic growth. Addressing them can lead to improved productivity, better human capital, and sustainable development.

### **Role of Government :**

The government plays a central role in addressing social issues through policies and welfare programs. Various ministries and departments work toward inclusive development, especially for marginalized communities. Initiatives related to education, healthcare, skill development, and social justice aim to create equal opportunities. These efforts are designed to reduce inequality and ensure that development benefits all sections of society.

### **Role of NGOs :**

Non-Governmental Organizations (NGOs) act as a bridge between the government and the people. Working at the grassroots level, they reach communities that may not have direct access to institutional support.

NGOs contribute by:

- I. Conducting awareness campaigns
- II. Organizing training and workshops
- III. Promoting education and healthcare
- IV. Advocating for human rights and social justice

Their localized approach helps in addressing specific community needs effectively.

### **Role of Media and Social Advertising :**

Media plays a powerful role in shaping public awareness. Through newspapers, television, radio, and digital platforms, it informs people about social issues and encourages dialogue.

Social advertising, in particular, has been instrumental in promoting public welfare. Campaigns on education, health, sanitation, gender equality, and environmental protection have helped change attitudes and behaviors over time. Posters and visual media are especially effective in reaching diverse populations, including those with limited literacy. By combining strong visuals with simple messages, they communicate ideas quickly and effectively.

The media plays a very constructive role in today’s society. The media plays a very useful role in today's society. Media is the most powerful tool of communication in emerging world and increased the awareness and presents the real stage of society. In this decade of Knowledge and awareness there is a huge and grand role of media, it is all around us when we watch on print and electronic media, everywhere public collect knowledge and information and a part of this media has to present a very responsible role for our society. Without the media, people in societies would be isolated.

Advertisement is easy source which connect with people directly to create awareness. The advertisements which contain publicity about the social concerns of a human being are called Social Advertisements. Social advertising refers to those advertisements which deal with social causes aimed at the welfare and well being of the people. In other words, such advertisements create awareness among the people, inform and educate them about socially relevant issues like, Health, Family Welfare, Literacy, Natural Resources ect. They aim at communicating social causes, social issues, ideas or messages to the people. The tremendous success of commercial products can largely be attributed to advertising. The successful use of advertising for commercial products has paved the way for a gradual increase in the use of advertising for noncommercial products, services and ideas for social causes . This is evident from the fact that even a practical organization like the government has to fall back on advertisements for propagating social causes such as Health, Child Care, Family Welfare, Literacy, etc. As compared to West, Social Ads are of recent origin in India. Way back in 1964 the government of India decided to tackle advertisements on family planning. In the late sixties with the increasing socio-economic problems and popularization of TV, Social ads were given increasing attention. Since then they have become part and parcel of life and the government sanctions some corers of rupees for the telecast of various social ads such as family planning and child care to mention only two. Besides from time to time ads are also shown on communal harmony. Apart from the indigenious advertising which has a major role to play in communicating about social causes to the masses, various government department/ministries, National and International Agencies, Voluntary Organizations and Autonomous Bodies deal with different social causes. Every day there's a new fashion trend, better technologies and various other developments. But, the mindset of the society is something that's taking ages to change. The social evils that we saw 10 years ago are still hovering around us. Coming along the line are the commercial ads creating a new trend with an impactful approach. Doing their bit, they contribute to eradicate certain social

evils. We’ve already seen commercial ads going a notch higher by producing powerful advertisements that revolve around social concerns for instance, the ad by Brooke Bond Red Label where they attempt to change the misconceptions around people of short stature on International Dwarfism Awareness Month and the series of Tata Tea, Jaago Re campaigns. But, we can’t resist talking about how they are getting better and better.

The solving of a social problem depends upon finding out the causes of troublesome social conditions which create the problem. Though every social problem is caused by multiple factors, but it is always possible to find out the chief factor, the cooperative factors and the minor aggravates in the origin and development of the problem. Every problem is likely to be unique and is likely to have individualistic traits which may differentiate it from other problems.

Many a time, the nature of the social problem is such that the control becomes extremely difficult, if not impossible. This happens when a social problem is occasioned by natural factors like droughts or floods or when the conflict of social interests blocks the application of curative programmers, or a revolution is needed to change the existing political or economic systems.

But after understanding and judging social problems, the society has to be effective and has to take some action whether it is by attempting to alter the established social institutions or by trying to alleviate them by adopting measures without trying to change the existing institutions. Further, action can be organized or personalized.

### **Challenges in Addressing Social Issues**

Despite increasing awareness, several challenges remain:

- I. Deep-rooted cultural beliefs and social norms
- II. Economic inequalities and resource constraints
- III. Political and institutional limitations
- IV. Environmental factors such as natural disasters
- V. Conflicts and lack of consensus among groups

These challenges highlight the need for a comprehensive and collaborative approach.

### **Developing Social Awareness**

Building social awareness requires both personal and collective effort. Individuals must develop skills such as:

- I. Active listening and empathy
- II. Respect for diversity
- III. Open and constructive communication
- IV. Self-awareness and emotional regulation

Recognizing differences in culture, language, religion, and background is essential for maintaining social harmony. Mutual respect and understanding are key to peaceful coexistence.

### **Implications**

The study highlights several important implications:

- I. Policy Implication: Effective policies must address both social and economic dimensions of issues.
- II. Educational Implication: Education systems should promote social awareness and ethical values.
- III. Economic Implication: Reducing inequality can significantly boost economic growth and productivity.
- IV. Social Implication: Increased awareness leads to stronger communities and improved social cohesion.
- V. Developmental Implication: Inclusive development is only possible when social issues are addressed collectively.

### **Conclusion:**

In conclusion, being aware of social issues is important for creating a fair, welcoming, and forward-thinking society. It helps people understand the problems in society and make responsible choices. Although the government, non-profit

groups, and the media have important roles to play, everyone's involvement is equally important. To solve social problems, it is not just about knowing about them, but also about understanding why they happen, especially in terms of economic inequality. By showing compassion, valuing diversity, and working together, communities can move toward a better future and lasting peace.

## REFERENCES:

1. *Ahuja, Ram. (2014). Social problems in India (3rd ed.). Rawat Publications.*
2. *Berger, Peter L. (1963). Invitation to sociology: A humanistic perspective. Doubleday.*
3. *Berger, Peter L., & Luckmann, Thomas. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.*
4. *Best, Joel. (2013). Social problems. W. W. Norton & Company.*
5. *Eitzen, D. Stanley., Zinn, Maxine Baca., & Smith, Kelly Eitzen. (2017). Social problems (13th ed.). Pearson Education.*
6. *Giddens, Anthony. (2017). Sociology (8th ed.). Polity Press.*
7. *Leon Guerrero, Anna. (2024). Social problems: Community, policy, and social action (8th ed.). SAGE Publications.*
8. *Mills, C. Wright. (1959). The sociological imagination. Oxford University Press.*
9. *Merton, Robert K., & Nisbet, Robert A. (1976). Contemporary social problems. Harcourt Brace Jovanovich.*
10. *Giroux, Henry A. (1988). Schooling and the struggle for public life: Critical pedagogy in the modern age. University of Minnesota Press.*

# Socio-Economic Aspect of Integral Humanism: An Indigenous Model of Development (A Conceptual Review)

**Nitin Katara**

Ph.d Scholar,  
Cluster Innovation  
Centre University of delhi

**Dr. Ashu Mishra**

Assistant Professor  
Cluster Innovation Centre  
University of Delhi

---

## Abstract

This review paper tries to understand the socio-economic aspects of Pandit Deen Dayal Upadhyaya's Ekatma Manavvaad (Integral Humanism) and views it as a strong indigenous alternative to western development paradigms. India's development journey after independence has sometimes revolved between Socialism and sometimes Liberalism. But these “segmented” models often fail to fully take into account the cultural and spiritual identity of our country. Due to this, problems like increasing inequality, damage to the environment and alienation among people have come to the fore. Qualitative conceptual review approach has been adopted in this study. In this, Upadhyay's lectures (primary data) given in Bombay in 1965 as well as thematic analysis of academic literature from 2010 to 2025 have been done. Additionally, this model has also been viewed from the perspective of decolonial development and indigenous economic thought.

This paper explains the core ideas of Ekatma Arthneeti (Integral Economy), which is based on “Dharmic Artha”—wealth that remains within the framework of ethical

and social responsibility. Its main pillars are Antyodaya (reaching the last man), Gram Swaraj (self-reliance of villages), and moving from “mass production” to “production by the masses”.

The study shows that while Capitalism is more “greed-based” and Socialism is based on “envy-based” thinking, Integral Humanism talks about a “Family Model” in which labour and capital are allies of each other, not opponents. Ultimately, the paper concludes that Ekatma Manavvaad offers a “Third Way” that combines economic growth with spiritual and environmental balance. Decentralized production can be strengthened by making proper use of today's digital tools, which shows a practical path for Atma-nirbhar India. For further research, it has been suggested that such empirical tools should be created by which the impact of Antyodaya-based policies on rural society can be accurately measured.

**Keywords:** *Integral Humanism, Ekatma Manavvaad, Antyodaya, Indigenous Development, Ekatma Arthneeti, Decolonial Economics, Self-Reliance.*

## **Introduction**

Today's world seems to be standing at a strange turning point. For decades we have been taught that the Western “Materialist” lifestyle—where earning and spending are the ultimate goals—is the only path to success. But the Global Financial Crisis of 2008 and the recent COVID-19 pandemic have shattered this thinking to a great extent. Today we are experiencing a kind of “Crisis of Meaning”—where people have money, but no peace of mind, and countries have high GDP, but deep problems also exist within society. Modern research also shows that when we focus only on “outer” wealth and ignore the “inner” aspect of a person, then imbalance occurs in the society (Laddunuri, 2021). If we talk about our country India, the journey after 1947 has largely been like an experiment with ideas that were not entirely our own. After independence we adopted the Socialist model. Big factories were built, plans started being decided from Delhi, but in this process the common man was often left behind and the control of the government increased a lot. Then in 1991 we moved towards Market Liberalism. This brought

malls, foreign brands, technology and jobs increased, but with it also came a different kind of competition. The gap between the rich and the poor increased and gradually our connection with our traditional villages and roots started decreasing (Raj, 2021). The biggest shortcoming of both these models was that they saw man only as a “consumer” or “taxpayer” and did not understand his entire existence.

Amidst such confusion, the philosophy of Pandit Deendayal Upadhyay, called Ekatma Manavvaad (Integral Humanism), gives a new direction. It talks about a “Third Way”, where we are not forced to choose between the state and the market. Instead, it states that a human being is not just a physical entity, but a complete being consisting of body, mind, intellect and spirit (Chanu & Sharma, 2025). Yet, there appears to be a significant gap in our academic literature. In most places, Upadhyay ji is seen only as a political leader, while the depth of his socio-economic views has not been given that much attention. We know what he said, but we understand less about how his “Integral Economy”

(Ekatma Arthneeti) can provide solutions to today's problems—like climate change or unemployment.

This paper is an attempt to fill that gap. In this, we will try to understand how their indigenous model can help in building an India which is not only “rich” in statistics, but is also strong in its values and self-reliance (Uppal & Krishan, 2022)

## **Methodology**

The methodology of this review paper has been designed in such a way that the philosophical principles of Integral Humanism can be understood systematically and it can be seen how relevant they are to today's socio-economic challenges. This is not an empirical study based on field data, but a qualitative conceptual review approach has been adopted. That is, mainly thematic analysis of different academic sources has been done in it.

A structured search was conducted to collect accurate and comprehensive literature. For this, many major academic databases like JSTOR, Google Scholar, Shodhganga and Taylor & Francis were used. In this search, attention was paid to

some specific keywords, so that both traditional and modern aspects of Indian economic thought could be understood. These keywords were:

- a. Ekatma Manavvaad (to understand the main philosophy)
- b. Indigenous Economics (to see it in the context of non-Western economic models)
- c. Decolonial Development (to understand how this model challenges Western universalism)
- d. Antyodaya (to focus on the welfare of the last man in the society)

The search was limited primarily to works published or reprinted between 1965 and 2025, to include original ideas as well as recent academic debates, especially in the context of Scopus-indexed journals .

**The data for this review is divided into two main parts:**

### 1. Primary Data:

The most important basis of this study is the four famous lectures given by Pandit Deendayal Upadhyay in Bombay (now Mumbai) in April 1965. These lectures are considered to be the original source of Ekatma Manavvaad and the foundation of the main philosophical ideas used in this paper also comes from here.

### 2. Secondary Data:

To make this paper a contemporary “review”, modern academic journals and books have also been analysed. These sources include the views of many scholars who have tried to explain Upadhyay's principles in the context of today's issues—such as sustainable technology, rural self-reliance (Gram Swaraj), and global economic inequality.

In this way, this methodology not only helps us understand the original philosophy but also shows how it can be useful in today's times

Philosophical Ontology: “Integral” vs. “Segmented”

There is something very profound at the heart of Ekatma Manavvaad—it completely rejects the “segmented” view of Western thinking in which humans are

divided into separate parts. Upadhyay ji believed that whether it is Capitalism or Socialism, both do not see man as a “whole” but understand him in pieces. In contrast, his “Integral” approach considers the human being as a holistic unit, in which body, mind, intellect and spirit—all four are interconnected. Real development is possible only when there is balanced development of all four together.

### **The Four-Fold Human (Chatushtaya)**

1. **The Body (Prakriti/Sharira):** Western economics often starts with material needs and ends there. But Upadhyay ji considers the body only as the beginning, not the end. They neither talk about asceticism nor are they against wealth. He says that if a person's basic needs are not fulfilled, he will not be able to perform his major duties. But in the Integral model the body is not considered merely a machine of consumption. It is considered a medium (vessel), which requires “minimum necessity” so that man can move towards his higher goals. Here Artha (material prosperity) is considered a means and not the ultimate goal (Laddunuri, 2021).
2. **The Mind:** The mind is the center of our emotions, feelings and desires. Upadhyay ji understood that a person does not become happy just by having his stomach filled. Western models often ignore the impact that constant competition and loneliness have on a person's mind.  
  
In an integral framework, the development of the mind is linked to a society where there is emotional security, community feeling and mental peace. Therefore, the objective of economic policies should not be just to create “jobs”, but to provide “meaningful work” that satisfies the human heart and saves him from alienation.
3. **The Intellect (Buddhi):** Wisdom is the power that teaches to differentiate between right and wrong. This is where the idea of Dharma enters the

economic field. The mind creates many desires, but the intellect decides which desire is right, moral and sustainable.

According to Upadhyay ji, the real strength of a society is seen in its values. Therefore, development should not only mean economic progress but also education that sharpens the intellect, so that people take decisions that are not only for themselves but in the interest of the entire society.

4. **The Soul (Atman):** The soul is the highest level of human existence—it is the true source of consciousness. According to Upadhyay, the western “segmented” human being is somehow cut off from the soul, because he is defined only on the basis of production and consumption.

Atman symbolizes the spiritual quest where man seeks to connect with a truth greater than himself.

Integral Humanism therefore says that the ultimate goal of any socio-economic system should be Moksha (liberation), so that material progress does not suppress spiritual development (Chanu & Sharma, 2025).

### **Chiti and Virat: National Organism**

Going beyond the individual, Upadhyay ji gives two important concepts to explain to the society – Chiti and Virat.

He calls Chiti “National Soul”—that is, the basic nature of a nation, which develops over thousands of years. Just as every person has his own nature, similarly every nation also has a basic character, which decides the direction of its development.

Virat has been called “Awakened National Energy”. When a society runs according to its own will, a collective power is generated in it – this is Virat. This power makes the nation strong, self-reliant and vibrant. But if a country adopts a path of development that goes against its will—like imposing Western hyper-individualism on India—then this Virat weakens and the society gradually starts moving towards decline (Misra & Singh, n.d.).

## **Critical Comparison: Organism vs. Social Contract**

Here a major difference emerges from Western political philosophy. In the West, thinkers like Thomas Hobbes and John Locke gave the “Social Contract” theory. According to this theory, society is a kind of contract, where different individuals come together for their own benefit and security. In this view, society is like an artificial structure—like a company or a club.

On the contrary, Upadhyay ji considers society as a living organism. Just as the hands, eyes and heart in the body are separate yet interconnected, similarly in society there are different individuals and groups, but they are part of the same overall unit. There is no “contract” here, because this relationship is natural and linked by birth.

While the western “Social Contract” model is based on competition and individual rights, Upadhyaya’s “Organism” model is based on cooperation and Dharma (duties). Therefore, true indigenous development is not about balancing the interests of individual people, but about keeping the entire body of society healthy and balanced (Raj, 2021)

## **Ekatma Arthneeti: The Mechanics of an Ethical Economy**

In the views of Pandit Deendayal Upadhyay, the economic system is not a separate running machine, rather it is a part of the entire social organism. On the basis of this thinking, he gave the idea of Ekatma Arthneeti (Integral Economy), which shows a way out of the “either-or” trap of Western economic models. In this part we understand why traditional “isms” fail and how an indigenous model redefines the relationship between wealth, ownership and labor.

## **Limits of Capitalism and Socialism**

Upadhyaya's biggest criticism was that both Capitalism and Socialism ignore the spiritual aspect of man.

According to him Capitalism is a “greed-based” system. In this, man is seen as Homo Economicus— that is, a creature whose main objective is only to increase

his profits. When capital is placed at the top, a thinking like “survival of the fittest” arises. The result is centralization of wealth, exploitation of nature and constant competition and conflict in society.

Seen from an integral perspective, Capitalism fulfills the needs of the body, but leaves the soul empty—due to which the society appears prosperous from outside, but becomes weak from within (Raj, 2021).

On the other hand, Upadhyay considered Socialism and Communism as “envy-based” systems. They talk about equality, but for this they give all the power in the hands of the state. In such a system, the individual's freedom is reduced and he becomes a small part of the government structure. According to Upadhyay ji, Socialism does not eliminate greed, but rather removes it from the capitalist and transfers it to the bureaucrat. In this, man is seen as a “mass”, due to which his intellect and creativity are suppressed.

Both systems are “segmented” because they focus only on material distribution and ignore deeper human needs such as dignity, autonomy, and moral purpose (Laddunuri, 2021).

### **Dharmic Artha: Ethical form of wealth**

There is often a misconception that Indian philosophy is against wealth. But Upadhyay ji clearly said that Artha (Wealth) is one of the four Purusharthas of life. He also pointed out that just as “lack of money” (Artha-Abhav) weakens the society, similarly “excess of money” (Artha-Prabhav) can also lead to moral degradation. Its solution is-Dharmic Artha. That means wealth which is under the control of Dharma (ethics). There is nothing wrong in earning profit in this model, but it is right only when it is in the interest of the society and follows the ethical boundaries.

Here Dharma works like a “checks and balances” for the economy. It ensures that no business makes profits by harming the environment, exploiting workers or selling harmful products. In this thinking, wealth is considered a “Sacred Trust” (which is also connected to Gandhiji’s Trusteeship concept). That means the owner

is actually just the custodian of the resources, and they should be used for the good of the society. Due to this, the economy ceases to be a competitive race and becomes like Yagya (contribution and sacrifice)—where earning is a duty and sharing is a responsibility (Uppal & Krishan, 2022).

### **Ownership and Labour: Toward Industrial Democracy**

The most unique and forward-thinking part of Ekatma Arthneeti is the idea of Industrial Democracy. Upadhyay ji completely rejected the western “master-servant” relationship, where the employer is the owner and the employee remains just a “factor of production” or “labour unit”. He believed that workers should be seen as “partners” in production. For this he talked about decentralized economic structure, where ownership is not limited to a few people but is spread widely.

#### **Some key points include:**

- A. Worker Participation: Workers should get participation in management and profit.
- B. Human-Centric Technology: Upadhyay ji was not against machines, but he believed that technology should help humans, not replace them. Therefore, instead of “mass production” he described “production by the masses” (decentralized model) as better.
- C. Right to Work: Working is a fundamental right in Integral Economy. It is not just a means of earning, but also a means of contributing to the society and nation (Virat).

In this way labour is not considered a commodity, but “living capital”. This may reduce the class conflict seen in western economies.

Finally, Ekatma Arthneeti talks about a “Family Model”, where the interests of the owner, worker and consumer are aligned. This model tries to create a balanced economic system based on harmony and ethics instead of competition (Upadhyay, 2024)

## The Antyodaya Framework: Redefining Poverty

Antyodaya—the upliftment of the last man in society—is a kind of ethical compass of Integral Humanism. In today's time, the talk of development often limits poverty to measuring it only in terms of numbers and income, but Upadhyay ji's perspective is much deeper and humane than this.

They consider poverty not just a problem of “survival” but a problem of “dignity and participation”. Typically in neoliberal economics, poverty is measured by a “poverty line”—such as daily calorie intake or a fixed income. But according to Upadhyay ji, this “segmented” thinking is incomplete. For them, poverty is not just hunger, but lack of respect (Sam-mana) and the ability to participate in society.

When a person is unable to contribute to Virat (National Energy) due to the shortcomings of the system, he becomes a victim of “social exclusion”—which is a kind of mental and spiritual breakdown. According to integral humanism, real development is not how much the upper class of the society has progressed, but what is the condition of the person standing at the bottom. Therefore, eradicating poverty is not a “charity” done from above, but is the Dharma (duty) of the entire society. If the weakest person in the society is hungry or feels humiliated, the entire nation will be considered unhealthy (Kumari, 2025).

## Antyodaya in Modern Policy: From Theory to Practice

In today's India, Antyodaya's thinking is also visible in many government policies. Where earlier planning was mostly “top-down”, now the focus has increased on “last-mile delivery”—that is, on providing convenience to the last person. This change is quite in line with the thoughts of Upadhyay ji.

### Examples:

- A. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: Through this scheme, an attempt was made to connect every person with the banking system. This marked a step towards eliminating the “financial untouchability” that Upadhyaya criticized.

- B. Ujjwala Scheme: Providing clean cooking fuel is not just a health issue, but it is also a way to improve the dignity and standard of living of rural women.
- C. Deendayal Antyodaya Yojana (DAY-NRLM): This scheme works on reducing poverty through selfhelp groups. It promotes community-based empowerment, which is in line with Integral thinking— that is, empowering people themselves, and not just relying on government support (Uppal & Krishan, 2022).

A common shift is visible in all these schemes—from “welfarism” to “empowerment”. The goal is that even the last person in the society becomes Atma-Nirbhar, which is the basic spirit of the indigenous development model.

### **Comparison: Antyodaya vs. Utilitarianism**

Here an important difference is seen between Western Utilitarianism and Indian Antyodaya. In Western thought, thinkers like Jeremy Bentham and John Stuart Mill gave the principle of “greatest good for the greatest number”. This sounds very democratic, but it may also mean that some people—especially the “last few”—are ignored for the benefit of the majority.

Upadhyay ji called this thinking “mathematical cruelty”. He believed that society is an organic whole—just as if there is pain in the little finger of the body, it cannot be ignored even if the rest of the body is fine.

The principle of Antyodaya says—“Good for every individual” (Sarve Bhavantu Sukhinah). No person here is expendable. While Utilitarianism focuses on “average”, Antyodaya thinks “absolute”—that is, the success of any policy will be determined by how much change it brings to the lives of the most vulnerable (Raj, 2021)

### **Decentralization, Gram Swaraj, and Sustainability**

The spatial aspect of Ekatma Arthneeti is based on the principle of decentralization. According to Upadhyay, excessive centralization of economic power—whether in the hands of a few big capitalists or a centralized state—leads to social alienation and environmental problems. In this context, his idea of Gram Swaraj (village-based self-governance) provides an alternative which is more

balanced and sustainable than the Western urbanization model. Upadhyay ji made a clear difference between Western “mass production” and Indian “production by the masses”.

“Mass production” is based on large factories and centralized capital, which often replaces human labor with machines. Due to this, migration of people from villages to cities increases and they are forced to live in urban slums. In this model, man follows the machine.

In contrast, Ekatma Manavvaad talks about a decentralized and labour-intensive economy. Upadhyay ji believed that in a country like India, where the population is very high, the economy should be made in such a way that a person can work in his own community.

“Production by the masses” means promoting production and consumption at the local level. This strengthens localism, that is, production and consumption remain around the same community. This reduces dependence on long and weak supply chains and the wealth generated in the village remains in the village. This develops a self-sustaining local ecosystem (Raj, 2021).

### **Integral approach towards environment**

Integral Humanism gives a different and deeper way of looking at the environment, which becomes very important in today's climate crisis. Upadhyay ji used two words to explain man's relationship with nature – Dohan and Shoshan. In Western “segmented” thinking, nature is often considered a “resource” to be exploited and developed—that is, Shoshan. But Upadhyay ji considered nature as a living entity, which is a part of this entire “Integral” system. He gave the example of cow's milk to explain this—like we take as much milk from the cow as it can comfortably give, and at the same time take care of it. This is Dohan – that is, taking from nature and also protecting it. This thinking goes beyond the common definition of “Sustainability”. Here the aim is not to merely maintain consumption,

but the emphasis is on Regenerative Ecology—that is, human activities should not harm nature, but contribute to making it better (Laddunuri, 2021).

### **Combination of Modern Technology and Gram Swaraj**

It is often said that decentralization or Gram Swaraj is “anti-modern”, but in today’s time technology has made this thinking more possible. In earlier times, artisans and farmers of villages had difficulty in reaching the market, so they had to depend on middle-men and centralized markets. But today digital tools have bridged this distance to a great extent.

- A. AI and E-commerce: Today a village weaver or farmer can directly sell his products in the global market. This reduces the need for exploitative middle-men.
- B. Decentralized Energy: Technologies like solar micro-grids enable villages to generate their own electricity. This is a big step towards Swaraj in the field of energy.
- C. Tele-education and Tele-medicine: Through these facilities, good education and health services can be provided in the villages itself. This reduces the need for people to migrate to cities and their Buddhi (intellectual) and Sharira (physical) development becomes possible there.

If seen in this way, Gram Swaraj is no longer an old or impractical idea, rather in today's time it has become more practical than before. Digital infrastructure can provide the “Virat” (energy) that can make local, ethical and sustainable production the basis of India's future economy (Upadhyay, 2024)

### **Discussion: Challenges of Implementation**

Although the theoretical framework of Ekatma Manavvaad presents a strong and attractive alternative, it is not easy to implement practically in the 21st century. The move from a “segmented” global economy to an “integral” indigenous model is associated with a number of structural challenges—particularly due to the effects of globalization and consumerism.

The first big challenge is to strike a balance between Globalization and Chiti (National Soul). Today we live in a “borderless” digital world, where global capital, data and cultural influences move rapidly from one country to another. In such an environment, it becomes difficult to maintain a development model based on indigenous values. The danger here is that the National Soul (Chiti) may get buried under a kind of “Global Monoculture”, where standardized consumption takes the place of local traditions. Therefore, a balanced approach is necessary to implement Integral Economy. India has to participate in the global market for economic growth (Artha), and at the same time has to preserve its equity. For this, such policies are needed which promote local production and cultural education. The biggest challenge is that we can create a kind of “Digital Swaraj”—where technology strengthens local communities, rather than making them dependent on global tech monopolies (Misra & Singh, n.d.).

The second big challenge is the psychological impact of modern consumerism. Today's digital economy runs on algorithms, which continuously create desires (Kama) in people and inculcate the habit of instant gratification. This thinking is completely opposite to Upadhyay ji's idea of Sanyam (restraint) and “minimum necessity”. It is not easy to live a life of “Need over Greed” in today's times, especially when a person's identity on social media is often determined by his material possessions. If the Integral model is to be implemented, just changing policies will not suffice—we will also have to bring major changes in education and cultural thinking.

We have to move away from the identity of “Homo Economicus” and adopt the thinking of “Integral Man”. This means that mental peace, balance and social contribution should be given more importance in the society, and not just collecting luxury goods (Raj, 2021).

## Conclusion & Future Research

In conclusion, it can be said that Ekatma Manavvaad (Integral Humanism) offers an important “Third Way” for today’s world—especially when people have become frustrated with both individualistic capitalism and state-led socialism. This model of Pandit Deendayal Upadhyay integrates Artha (material progress), Dharma (moral responsibility) and Moksha (spiritual peace). It gives a holistic framework, in which both the individual and the society are seen as a living and interconnected system. The biggest specialty of this indigenous approach is that it shows that economic development is possible without harming the cultural identity and environmental balance. It is important for future research that we not only limit ourselves to its philosophical aspects, but also focus on its quantitative impact—especially in the context of Antyodaya-based policies. We need empirical studies that can measure what impact decentralized and bottom-up schemes have on social mobility, psychological well-being and local economic resilience in rural India. Unless we combine this timeless philosophy with modern data and research, we will not be able to fully achieve a development model that is truly self-reliant (Atmanirbhar), inclusive and humancentric

## References

1. Chanu, P. J., & Sharma, L. B. (2025). *Pandit Deendayal Upadhyaya’s Integral Humanism for contemporary Bharat: Its relevance in modern period*. Department of Philosophy, Manipur University.
2. Kumari, N. (2025). *Deendayal Upadhyaya’s integral humanism: Implementation for social justice*.
3. *International Journal of Social Science Research*, 7(1). <https://doi.org/10.33545/26648652.2025.v7.i1b.159>
4. Laddunuri, M. M. (2021). *Economic theory of Deen Dayalji: A critical study from Indian nonmaterialistic approach*. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.01.677>

5. *Misra, K. K., & Singh, D. (n.d.). Integral humanism and the modern world. School of Humanities, Languages and Social Science, Shri Venkateshwara University.*
6. *Raj, R. (2021). Socio-economic thought of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Education Department, Haryana.*
7. *Upadhyay, M. (2024, November 6). Economic thought of Deen Dayal Upadhyay. International Journal of Innovative Social Science & Humanities Research.*
8. *Upadhyaya, D. (1965). Integral humanism [Four lectures delivered in Bombay, April 22-25, 1965]. Navchetan Press.*
9. *Uppal, G. S., & Krishan, G. (2022). Pandit Deen Dayal Upadhyaya’s perspective on ‘Ektema Arthniti’. Gobindgarh Public College & Khalsa College, 10(6).*

